



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 215]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 18, 2017/श्रावण 27, 1939

No. 215]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 18, 2017/ SRAVANA 27, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2017

अंतिम जांच परिणाम

(प्रवंचनारोधी जांच)

विषय: चीन जन गण, कोरिया, यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान, थाइलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कोल्ड रोल्ड फ्लेट प्रोडक्ट्स ऑफ स्टेनलेस स्टील के आयात के संबंध में प्रवंचनारोधी जांच।

सं. 14/1/2014-डीजीएडी.— समय-समय पर यथा संशोधित, सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात् यहां अधिनियम भी कहा गया है) और उसके समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात् नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे यहां बाद में अधिनियम कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क तथा क्षति के निर्धारण की पहचान, मूल्यांकन और संग्रहण) नियमावली, 1995 (जिसे बाद में यहां पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी, उपर्युक्त नियमावली के तहत नियुक्त वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार (जिसे

यहां प्राधिकारी कहा गया है) ने दिनांक 25 नवंबर, 2008 की अधिसूचना संख्या 14/06/2008-डीजीएडी द्वारा चीन जन गण, कोरिया, यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान, थाइलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका (जिन्हें यहां बाद में संबद्ध देश कहा गया है) से एएसटीएम ए240/ए480एम "सीआर कॉइल्स" (जिन्हें आगे संबद्ध सामान कहा गया है) के 4 एमएम तक की मोटाई वाले (मिल ऐज के लिए +30 एमएम तथा ट्रिम्ड ऐज के लिए +4 एमएम की चौड़ाई टोलरेंस) कोल्ड रोलड (कोल्ड रेड्यूस्ड) की सभी श्रृंखलाओं, जिसने इसके आगे काम नहीं किया कि 600 एमएम से अधिक की चौड़ाई के स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोलड फ्लैट प्रोडक्ट्स के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू की।

2. प्राधिकारी द्वारा 27 मार्च, 2009 की अधिसूचना संख्या 14/06/2008-डीजीएडी द्वारा प्राथमिक जांच परिणाम जारी किए गए थे और केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 22 अप्रैल, 2009 की अधिसूचना संख्या 38/2009-सीमा शुल्क द्वारा अनंतिम शुल्क लगाया गया था। प्राधिकारी द्वारा अंतिम जांच परिणाम दिनांक 24 नवंबर, 2009 की अधिसूचना संख्या 14/06/2008-डीजीएडी द्वारा जारी किए गए थे। अंतिम जांच परिणामों द्वारा प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 14/2010-सीमा शुल्क द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए गए थे जो संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित उपर्युक्त सामानों के आयात पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की तारीख अर्थात् 22 अप्रैल, 2009 से प्रभावी हुए।
3. घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी शुल्कों की मध्यावधिक समीक्षा के लिए आवेदन पत्र दायर किया था और मध्यावधिक समीक्षा 23 जून, 2010 को शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने अपनी 08 जून, 2011 की अंतिम जांच परिणाम संख्या 15/16/2010 द्वारा मिल ऐज के लिए +30 एमएम और ट्रिम्ड ऐज के लिए 4 एमएम की टोलरेंस का उल्लेख कर विचाराधीन उत्पाद स्पष्ट किया। यह स्पष्टीकरण स्वीकार किए गए और वित्त मंत्रालय द्वारा 06.09.2011 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 86/2011 द्वारा संशोधन किए गए।
4. प्राधिकारी ने माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 08 अक्तूबर, 2010 के आदेश के बाद दिनांक 24 नवंबर, 2009 के अंतिम जांच परिणामों की समीक्षा की। दिनांक 05 दिसंबर, 2011 की फाइल संख्या 14/6/2008 द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी की इन संशोधित सिफारिशों को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार किया गया था और 07.02.2012 को शुद्धि पत्र जारी किया गया था।
5. घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी शुल्कों की निर्णायक समीक्षा याचिका के लिए आवेदन पत्र दायर किया था और 23 जून, 2010 को मध्यावधिक समीक्षा शुरू की गई थी तथा घरेलू उद्योग द्वारा दायर किए गए विधिवत रूप से अनुमानित आवेदन पत्र के आधार पर प्राधिकारी ने 17 अप्रैल, 2014 की अधिसूचना संख्या 15/04/2014-डीजीएडी द्वारा पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा शुरू की। प्राधिकारी ने अपने 12 अक्तूबर, 2015 की अंतिम जांच परिणाम संख्या 15/05/2014 द्वारा शुल्कों को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाए जाने की सिफारिश की जिसे केंद्र सरकार ने दिनांक 11.12.2015 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 61/2015 द्वारा स्वीकार कर लिया था।
6. सीमा शुल्क अधिसूचना 61/2015 दिनांक 11.12.2015 के तहत शामिल न किए गए कोल्ड रोलड फ्लैट प्रोडक्ट्स ऑफ विड्थ के आयात के संबंध में धोखाधड़ी के विरुद्ध चल रही जांच में मैसर्स जिंदल स्टेनलेस लि. (जिसे यहां बाद में "याचिकाकर्ता" अथवा "आवेदक" कहा गया है) ने चीन जन गण, कोरिया, यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान, थाइलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका (जिन्हें यहां बाद में संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित, दिनांक 11.12.2015 की सीमा शुल्क अधिसूचना 61/2015 में शामिल न किए गए कोल्ड रोलड फ्लैट प्रोडक्ट्स ऑफ विड्थ (जिन्हें यहां आगे "जांचाधीन उत्पाद" अथवा पीयूआई कहा गया है) के आयात के संबंध में धोखाधड़ी के विरुद्ध जांच शुरू करने के लिए सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 (पाटनरोधी नियमावली) के नियम 26(1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे यहां बाद में प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष दिनांक 21.09.2015 को एक अद्यतन आवेदन दायर किया। आवेदक ने संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित जांचाधीन उत्पाद के संबद्ध सामानों के आयात पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए जाने के लिए अनुरोध किया।

7. जबकि, नियम 26(1) के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर विधिवत आवेदन पत्र के मद्देनजर प्राधिकारी ने लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की तथाकथित धोखाधड़ी की मौजूदगी और प्रभाव निर्धारित करने के लिए तथा जांचाधीन उत्पाद के आयातों में विचाराधीन उत्पाद के आयात पर पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए जाने की सिफारिश पर विचार करने के लिए 19 फरवरी, 2016 की अधिसूचना संख्या 14/1/2014-डीजीएडी द्वारा जांच शुरू की।

ख. प्रक्रिया

8. विषयगत जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:
- i. नई दिल्ली में संबद्ध देशों के दूतावासों को नियम 6(2) के अनुसार शुरू किए जाने के संबंध में सूचित किया गया था।
 - ii. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 6(3) के अनुसार संबद्ध देश के दूतावास और ज्ञात निर्यातकों के आवेदन की अगोपनीय रुपांतरण की प्रतियां उपलब्ध कराईं। आवेदन पत्र के आगोपनीय रुपांतरण की एक प्रति सार्वजनिक फाइल में भी उपलब्ध कराई गई तथा जहां अनुरोध किया गया था वहां अन्य पक्षकारों को दी गई।
 - iii. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात विनिर्माताओं/निर्यातकों (जिनके नाम एवं पते प्राधिकारी को उपलब्ध कराए गए थे) को सार्वजनिक सूचना की एक प्रति उपलब्ध कराई और नियम 6(2) तथा नियम 6(4) के अनुसार उस पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर उनके विचार लिखित में देने के लिए उन्हें अवसर प्रदान किया।

चीन

1. मैसर्स शंघाई क्रुप स्टेनलेस
2. मैसर्स झांगजियागांग पोसको स्टेनलेस स्टील कं. लि.

यूरोपीय संघ

1. मैसर्स एएलजेड एनवी, बेल्जियम
2. यूजिन (यूसिनार का प्रभाग), इम्ब्यूबल पेसिफिक, फ्रांस
3. एक्रिनोक्स एसए, स्पेन
4. एक्रिनोक्स एसए, इटली
5. थाइसन क्रुप निरोस्टा जीएमबीएच, जर्मनी
6. थाइसन क्रुप एसीसीएआई स्पेशलटेरेनी एसपीए, इटली
7. ऑटोकुम्पू स्टेनलेस, यू. के.
8. ऑटोकुम्पू स्टेनलेस, फिनलैंड
9. ऑटोकुम्पू स्टेनलेस एबी, स्वीडन

संयुक्त राज्य अमेरिका

1. ए. के. स्टील कारपोरेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका
2. एल्लेघेनी लुडलम, संयुक्त राज्य अमेरिका
3. नॉर्थ अमेरिकन स्टेनलेस, संयुक्त राज्य अमेरिका
4. जे एंड एल स्पेशियलिटी स्टील, इंक., संयुक्त राज्य अमेरिका

ताइवान

1. यीह यूनाइटेड स्टील कारपोरेशन (युसको)
2. वालसिन लिहवा कारपोरेशन

दक्षिण अफ्रीका

1. कोलंबस स्टेनलेस (पीटीवाई) लि.

कोरिया

1. पोसको

9. जांच की शुरूआत की अधिसूचना के उत्तर में संबद्ध देशों के निम्नलिखित निर्यातकों/ उत्पादकों ने उत्तर दिया है:

- i. ऑटोकम्पू ओई, यूरोप
- ii. यीह यूनाइटेड स्टील कारपोरेशन, ताइवान (यूसको)
- iii. वालसिन लिहवा कारपोरेशन, ताइवान
- iv. यूआन लांग स्टेनलेस स्टील कारपोरेशन, ताइवान (वाईएलएसएस)
- v. तांग एंग आयरन वर्क्स कं. लि., ताइवान
- vi. पोसको, एशिया
- vii. पोसको, कोरिया
- viii. देवू इंटरनेशनल, कोरिया
- ix. हुंडई कारपोरेशन, कोरिया
- x. सैमसंग सी एंड टी, कोरिया
- xi. एस के नेटवर्क्स, कोरिया
- xii. टोयोटा शुशो, कोरिया

10. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/ग्राहकों/ एसोसिएशनों (जिनके नाम एवं पते प्राधिकारी को उपलब्ध कराए गए थे) को सार्वजनिक सूचना की प्रतियां भेजीं और नियम 6(4) के अनुसार उस पत्र किए जाने की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर उनके विचार लिखित में देने के लिए उन्हें सलाह दी।

1. ऑनैस्ट इंटरप्राइज रलि., वडोदरा
2. कुबेर स्टील इम्पैक्स, मुंबई
3. एम. एम. इंटरप्राइज, रायगढ़
4. एडवांस मेटल कारपोरेशन, मुंबई
5. भंडारी फॉइल्स प्रा. लि., देवास
6. एंजिल पाइप्स एंड ट्यूब्स प्रा. लि., मुंबई
7. आईडीएमसी लि., गुजरात
8. ए.एम. के. स्टील सेंटर, रायगढ़
9. रिद्धि सिद्धी इम्पैक्स, मुंबई
10. सलेम स्टेनलेस स्टील सप्लायर्स, चेन्नई
11. वेस्टर्न मेटल (इंडिया), मुंबई
12. स्टाल स्टेनलेस स्टील, मुंबई
13. एडवांस मेटल कारपोरेशन
14. अरिहंत स्टील इंटरप्राइजेज, मुंबई
15. जिदत्त स्टील, मुंबई
16. मद्रास स्टील एजेंसीज, चेन्नई
17. नोबल इम्पैक्स, मुंबई
18. ऑल इंडिया स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्रीज एसोसिएशन
19. स्टेनलेस स्टील एक्सपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन

20. प्रोसेस प्लांट एंड मशीनरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया
11. प्राधिकारी को निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं/अन्य हितबद्ध पक्षकारों से प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोध प्राप्त हुए हैं:
1. पोसको इंडिया चेन्नई स्टील प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड (प्रश्नावली एवं अनुरोध)
 2. पोसको इंडिया दिल्ली स्टील प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड (प्रश्नावली एवं अनुरोध)
 3. पोसको इंडिया पुणे स्टील प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड (प्रश्नावली एवं अनुरोध)
 4. सन मार्क स्टेनलेस प्रा. लि. (अनुरोध)
 5. सन सिटी स्ट्रिप्स एंड ट्यूब्स प्रा. लि. (प्रश्नावली एवं अनुरोध)
 6. सनराइज स्टेनलेस प्रा. लि. (अनुरोध)
 7. सनस,टी शीट्स प्रा. लि. (प्रश्नावली एवं अनुरोध)
 8. श्री रामदेव मेटल मार्ट (प्रश्नावली एवं अनुरोध)
 9. मैसर्स मैक्सग्रो कारपोरेशन (प्रश्नावली एवं अनुरोध)
 10. मैसर्स शक्ति स्टील (प्रश्नावली एवं अनुरोध)
 11. मैसर्स रमानी स्टील हाउस (प्रश्नावली एवं अनुरोध)
 12. मैसर्स मेटल एंड स्टील (इंडिया) (प्रश्नावली एवं अनुरोध)
 13. मैसर्स एनजी इंडस्ट्रीज (प्रश्नावली एवं अनुरोध)
 14. द तमिलनाडु स्टेनलेस स्टील मर्चेन्ट्स एंड मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन
 15. मेटल एंड स्टेनलेस स्टील मर्चेन्ट्स एसोसिएशन
 16. मैसर्स मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (एमएसआईएल)
 17. मैसर्स हीरो मोटो कॉर्प लि.
 18. यूरोपीय आयोग द्वारा पुनः प्रस्तुत करना
 19. कोरिया गणराज्य सरकार द्वारा पुनः प्रस्तुत करना
 20. ताइवान सरकार द्वारा पुनः प्रस्तुत करना
 21. मैसर्स एस्टीरोन स्टील्स प्रा. लि.
 22. ऑल इंडिया स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्रीज एसोसिएशन
 23. मैसर्स सरस्वती स्टील (इंडिया)
 24. मैसर्स आश्विन इम्पैक्स –
 25. मैसर्स इनोक्स स्टेनलेस
 26. मैसर्स जयेश मेटल कारपोरेशन
 27. मैसर्स धनेरा इम्पैक्स
 28. मैसर्स ऑनेस्टी इम्पैक्स
 29. मैसर्स एन जी इंडस्ट्रीज
 30. मैसर्स ध्रुव एक्सिम
 31. मैसर्स सिद्धिविनायक स्टील
 32. मैसर्स नवनिधि स्टील एंड इंजी. कं. प्रा. लि.
 33. मैसर्स बी. वी. एस. ओवरसीज
 34. मैसर्स अम्बुजा मेटल इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
 35. मैसर्स आर. एम. मेटल इंडस्ट्रीज
 36. मैसर्स न्यू मानक ओवरसीज लि.
 37. मैसर्स ऑल इंडिया मेटल कारपोरेशन

38. मैसर्स नवयुग मेटल कारपोरेशन
39. मैसर्स प्रेसिसन इम्पैक्स
40. मैसर्स नेपट्यून स्टील इम्पैक्स
41. मैसर्स नेनावा मेटल कारपोरेशन
42. मैसर्स मीना मेटल इम्पैक्स प्रा. लि. (इंडिया)
43. मैसर्स मैक्सग्रो कारपोरेशन
44. मैसर्स डिवाइन इम्पैक्स
45. मैसर्स ऐसर स्टील
46. मैसर्स मेटल एंड स्टील (इंडिया)
47. मैसर्स स्टेनोक्स अलॉयज प्रा. लि.
48. मैसर्स सिद्धांत स्टील
49. मैसर्स शांघवी इंटरप्राइज
50. मैसर्स ट्रेडपोर्ट स्टेनलेस अलॉयज
51. मैसर्स साची इम्पैक्स
52. मैसर्स ग्लोमेट अलॉयज एलएलपी
53. मैसर्स इंटर सेल्स इंटरप्राइज
54. मैसर्स स्टील लाइन (इंडिया)
55. मैसर्स यूनाइटेड स्टेनलेस
56. मैसर्स रत्नरावी मेटल इम्पैक्स
57. मैसर्स मोडेस्ट मेटल कारपोरेशन
58. मैसर्स अशोक मेटल कारपोरेशन
59. मैसर्स एम एम मेटल इंटरनेशनल
60. मैसर्स एम एम मेटाट्रेड प्रा. लि.
61. मैसर्स शुभलक्ष्मी मेटल्स एंड ट्यूब्स प्रा. लि.
62. मैसर्स वर्ल्ड स्टेनलेस
63. मैसर्स गुड लक
64. मैसर्स इंको स्टील
65. मैसर्स नॉन – फेरस मेटल एसोसिएशन (कर्नाटक)
66. मैसर्स पीएस राज स्टील्स प्रा. लि.
67. मैसर्स इनोक्स स्टेनलेस
68. मैसर्स ग्लोमेट अलॉयज एलएलपी
69. मैसर्स एम. पी. इंडस्ट्रीज
70. मैसर्स डिवाइन इम्पैक्स
71. मैसर्स अशोक मेटल कारपोरेशन
72. मैसर्स नवनिधि स्टील एंड इंजी. कं. प्रा. लि.
73. मैसर्स पेसिफिक मेटल ट्रेडिंग कं.
74. मैसर्स ऐसर स्टील
75. मैसर्स निक्सोन स्टीलियम एलएलपी
76. मैसर्स विशाल ट्यूब्स एंड पाइप्स पी. लि.
77. मैसर्स एक्ज्युरेट स्टील

78. मैसर्स मोडेस्ट मेटल कारपोरेशन
79. मैर्स स्टार स्टेनलेस स्टील
80. मैसर्स आश्विन इम्पैक्स
81. मैसर्स सिद्धिविनायक स्टील
82. मैसर्स मेरिनोक्स इनोक्स
83. मैसर्स एनजी इंडस्ट्रीज
84. मैसर्स एसआई पवन स्टील (इंडिया)
85. मैसर्स यूबिक अलॉयज प्रा. लि.
86. मैसर्स यूनाइटेड स्टील (इंडिया)
87. मैसर्स ध्रुप एक्सिम
88. मैसर्स डोमेट ट्रेडिंग प्रा. लि.
89. मैसर्स द तमिलनाडु स्टेनलेस स्टील मर्चेण्ट्स एंड मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन
90. मैसर्स सरस्वती स्टील (इंडिया)
91. मैसर्स मारवेल इम्पैक्स
92. मैसर्स प्रेसिसन इम्पैक्स
93. मैसर्स स्टेनोक्स अलॉयज प्रा. लि.
94. मैसर्स स्टील इंटरनेशनल
95. मैसर्स यूनाइटेड स्टेनलेस
96. मैसर्स नोसिल स्टील्स
97. मैसर्स नियोन मेटल्स इम्पैक्स प्रा. लि.
98. मैसर्स एस. सी. शाह इंटरप्राइजेज
99. मैसर्स अगोल एसोसिएट्स
100. मैसर्स सलेम स्टील ट्रेडिंग कं.
101. मैसर्स रत्नरावी मेटल इम्पैक्स
102. मैसर्स ट्रस्ट इम्पैक्स
103. मैसर्स गणेश इम्पैक्स
104. मैसर्स शक्ति पंपिंग कं.
105. मैसर्स शिवा ट्रेडिंग कं.
106. मैसर्स नवनिधि स्टील एंड इंजी. कं. प्रा. लि.
107. मैसर्स संतोष स्टील इंडस्ट्रीज
108. मैसर्स नवपड स्टील सेंटर
109. मैसर्स मेटल ट्रेडिंग कारपोरेशन
110. मैसर्स एजिल पाइप्स एंड ट्यूब्स प्रा. लि.
111. मैसर्स सिद्धिविनायक स्टील
112. मैसर्स अनमोल स्टेनलेस प्रा. लि.
113. मैसर्स मिनोक्स मेटल प्राइवेट लिमिटेड
114. मैसर्स शाह फाईल्स लिमिटेड
115. मैसर्स एम. पी. इंडस्ट्रीज
116. मैसर्स बालाजी इम्पैक्स
117. मैसर्स केपीवी इम्पैक्स

118. मैसर्स बीआरजी आयरन एंड स्टील कं. प्रा. लि.
 119. मैसर्स रिलायंस फैब्रिकेशन्स प्रा. लि.
 120. मैसर्स ऑल इंडिया स्टेनलेस स्टील इम्पोर्टर्स एसोसिएशन
 121. मैसर्स मेटल एंड स्टेनलेस स्टील मर्चेन्ट्स एसोसिएशन
 122. मैसर्स सीएमएस स्टेनलेस कंपनी
 123. मैसर्स विक्रम मेटल (इंडिया)
 124. मैसर्स शारदा मोटर इंडस्ट्रीज लि.
 125. मैसर्स ऑल इंडिया स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्रीज एसोसिएशन
 126. मैसर्स रेमी इंडल्सताही ट्यूबलर्स लि.
 127. मैसर्स फॉरिसिया एमिशन्स कंट्रोल टैक्रोलॉजीस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 128. मैसर्स शक्ति स्टील
 129. मैसर्स रमानी स्टील हाउस
 130. मैसर्स शाह फाईल्स लिमिटेड
 131. मैसर्स वेदिक इस्पात प्रा. लि.
 132. मैसर्स स्टेनलेस स्टील इम्पैक्स
 133. मैसर्स रिजेंसी इम्पैक्स (इंडिया)
 134. मैसर्स नेक्सस इम्पैक्स
 135. मैसर्स कमलेश मेटल एंड अलॉय
 136. मैसर्स अनिल मेटल कारपोरेशन
 137. मैसर्स ग्रीनलाइन पाइप एंड फिटिंग
 138. मैसर्स श्री आनंद मेटल
 139. मैसर्स पराग मेटल्स
12. विभिन्न आयातकों/प्रयोक्ताओं तथा उनके एसोसिएशनों द्वारा भारी संख्या में उत्तर दायर किए गए हैं। प्राधिकारी ने प्रकटन में स्पष्ट किया है कि यद्यपि सभी संगत मुद्दे और ऐसी सभी उत्तरदायी कंपनियों को अलग-अलग शामिल किया गया है, तथापि, किसी भी आवेदक द्वारा कोई अनुरोध किए जाने की स्थिति में, जिसे गलती से छोड़ दिया गया हो, का उल्लेख किया जाए ताकि अंतिम जांच परिणाम में उसका समाधान किया जा सके।
 13. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से लिए गए लेन-देन वार आयात आंकड़ों पर वर्तमान धोखाधड़ी जांच में विश्लेषण के लिए विश्वास किया गया है।
 14. जिन निर्यातकों, उत्पादकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने न तो प्राधिकारी को उत्तर दिया है और न ही इस जांच से संगत सूचना दी है, उन्हें प्राधिकारी द्वारा असहयोगी हितबद्ध पक्षकार माना गया है।
 15. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई है। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने, जहां भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और वह सूचना गोपनीय मानी गई है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है। जहां कहीं भी संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार को निर्देश दिया जाता है कि वे गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर दें।
 16. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतर नियम 6(7) के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराए गए थे।
 17. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसरण में मौखिक रूप से संगत जानकारी प्रस्तुत करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को एक अवसर उपलब्ध कराने के लिए 03.07.2017 को सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की। हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से अभिव्यक्त विचारों को लिखित रूप में दायर करें।

18. जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का इस जांच परिणाम में उस सीमा तक समाधान किया गया, जहां तक वे संगत थे तथा साक्ष्यों से पुष्ट थे।
19. प्रतिभागी घरेलू उत्पादक द्वारा प्रस्तुत सूचना और आंकड़ों का सत्यापन आवश्यक होने की सीमा तक किया गया था।
20. जहां भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की अवधि के दौरान पहुँच से इंकार किया है या अन्यथा रूप से आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराई है या उल्लेखनीय रूप से जांच को बाधित किया है, प्राधिकारी ने "सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना" का प्रयोग किया है और ऐसे पक्षकार को असहयोगी माना है।
21. एक आयातक अर्थात् मैसर्स सनसिटी शीट्स प्रा. लि. द्वारा दायर रिट याचिका (डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 3544/2016, सीएम संख्या 15209/2016 और 25402/2016) के संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 27.04.2016 के आदेश के माध्यम से जांच स्थगित कर दी। उपर्युक्त सीएम संख्याओं सहित रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 08.03.2017 के आदेश द्वारा रद्द कर दी गई थी जिससे 08.03.2017 को स्थगन को रद्द किया गया।
22. प्राधिकारी ने 07 अगस्त, 2017 को नियम 16 के तहत एक प्रकटन विवरण जारी किया और 16 अगस्त, 2017 तक प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां देने का अवसर प्रदान किया। घरेलू उद्योग/विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियों का इस जांच परिणाम में समुचित रूप से समाधान कर दिया गया है और तालिकाओं में कुछ संशोधन भी शामिल कर दिए गए हैं।
23. इस अंतिम जांच परिणाम में *** गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना दर्शाता है तथा प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी नियमावली के तहत उसे गोपनीय माना गया है।
24. इस जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि जुलाई, 2014 – सितंबर, 2015 (15 माह) मानी गई है और धोखाधड़ी संबंधी आंकड़ों का प्रयोजन करने के लिए 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 और जांच की अवधि मानी गई है।
25. जांच की अवधि के लिए विनिमय दर प्राधिकारी द्वारा जहां कहीं परिवर्तन की वास्तविक दर उपलब्ध नहीं थी, 63.44 रुपए = 1 अमेरिकी डॉलर ली गई है।

ग. संबंधित प्रक्रिया/न्यायिक कार्यवाही

26. मैसर्स सनसिटी शीट्स लि. द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 3544/2016 के आधार पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27.04.2016 के आदेश के माध्यम से स्थगन आदेश दिया गया था।

आदेश का प्रचालनात्मक पैरा निम्नलिखित है:

"10. सीमा प्रशुल्क अधिनियम पाटनरोधी नियमावली के नियम 25(1) में किसी ऐसी वस्तु के आयात की परिकल्पना है जो "अनअसेंबल्ड, अपरिष्कृत अथवा अपूर्ण रूप" में पाटनरोधी के अध्यधीन हो, जो उसके बाद भारत में "असेंबल, परिष्कृत अथवा पूर्ण" हो। यह उत्तरदायी संख्या 4 का मामला नहीं है जो 1250 एमएम चौड़ाई और उससे अधिक का है जिसे "अनअसेंबल्ड, अपरिष्कृत अथवा अपूर्ण रूप में आयात किया जाता है।" परिणामस्वरूप न्यायालय का प्रथम दृष्टया यह मत है कि दिनांक 19 फरवरी, 2016 की अधिसूचना के अनुसरण में की गई जांच सीमा प्रशुल्क अधिनियम पाटनरोधी नियमावली के नियम 25(1) के अनुसार भी अनुमति योग्य नहीं है।

सुनवाई 27.04.2016, 19.07.2016 और 03.08.2016 को की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय की माननीय डिवीजन बेंच के समक्ष निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा प्रत्युत्तर और स्थगन आदेश को रद्द करने की याचिका दायर की गई। माननीय डिवीजन बेंच ने इस मामले में अपनी अंतिम सुनवाई 15.09.2016 को की और रिट याचिका को माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 08.03.2017 के आदेश द्वारा रद्द किया गया था जिससे स्थगन आदेश रद्द हो गया। इस मामले में स्थगन की कुल अवधि 316 दिन है, चूंकि, 18.02.2017 को एक वर्ष समाप्त हो गया था, अतः निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 26(6) के अनुसार 6 माह अर्थात् 18.08.2017 तक समय बढ़ा दिया।

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अपने दिनांक 08.03.2017 के निर्णय में की गई टिप्पणियां निम्नलिखित हैं:

“10. जांच की शुरुआत से याचिकाकर्ता सहित किसी भी पक्षकार को कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ है क्योंकि नियम 27 के संदर्भ में निर्धारण सभी पक्षकारों से पूरे आंकड़े और सामग्री प्राप्त कर लिए जाने के बाद ही होगा। यदि याचिकाकर्ता प्रश्नावली के उत्तर के माध्यम से यह सिद्ध करता है कि 1250 एमएम से अधिक की चौड़ाई के आयात मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों पर धोखाधड़ी नहीं है तो प्राधिकारी को याचिकाकर्ता सहित किसी भी आयातक पर धोखाधड़ी विरोधी शुल्क की सिफारिश करने का कोई अधिकार नहीं है।

15. यह सामान्य आधार है कि पाटनरोधी शुल्क 1250 एमएम से कम की चौड़ाई वाले सीआरएसएस पर लगाया गया है; यह कि शुल्क अंतिम जांच परिणाम में, ऐसे जांच परिणामों की समीक्षा और निर्णायक समीक्षा कार्यवाहियों में बनाये रखा गया था। याचिकाकर्ता (और हस्तक्षेपकर्ता) शिकायत करते हैं कि प्रवंचना संबंधी कार्यवाही की शुरुआत वास्तव में नहीं पाई गई है और कानूनी तौर पर असुरक्षात्मक भी है। यह भी एक सामान्य आधार है कि प्रवंचनारोधी उपाय पाटनरोधी नियमावली के नियम 25-26 के तहत लिए जा सकते हैं। अतः यहां शिकायत पूरी तरह से क्षेत्राधिकार न होने के संबंध में नहीं है, इसकी बजाए इसकी अनपेक्षित परिपाटी की है, जो कि याचिकाकर्ताओं के अनुसार मामले के इतिहास के संबंध में है। याचिकाकर्ता 1250 एमएम अथवा उससे अधिक चौड़े सीआरएसएस का आयात करने की तकनीकी एवं वाणिज्यिक अर्थक्षमता न होने और फिर उसे भारत में प्रयोग के लिए छोटी-छोटी चौड़ाई में काटने अथवा बांटने के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा कम से कम दो कार्यवाहियों में दोहराई गई टिप्पणियों पर विश्वास करते हैं।

22. याचिकाकर्ता यह तर्क देने में सही हैं कि निर्दिष्ट प्राधिकारी उस प्रश्न पर गए थे और 1250 एमएम से अधिक चौड़े सीआरएसएस स्ट्रिप्स के आयात की आयात योग्यता तथा वस्तु के रूप में प्रयोग के लिए उनके आकार में कमी लाने, जो कि पाटनरोधी शुल्क के विषय हैं, के संबंध में विशेष जांच परिणामों के साथ लौटे। तथापि, जिस जांच की प्रकृति के कारण वे जांच परिणाम (और टिप्पणियां) हुए क्षति की संभावना के संदर्भ में थे। उन कार्यवाहियों के संबंध में शामिल अवधि 2009-2015 थी। उन जांचों के दौरान जिस प्रकार की सामग्री पर विचार किया गया, उसमें उन सभी तत्वों पर जोर दिया गया जिनके लिए जांच की गई थी। तथापि, प्रवंचना संबंधी कार्यवाहियों में जांच की प्रक्रिया पूर्णतः भिन्न है। पाटनरोधी शुल्क के अस्तित्व (और क्षति की स्थापित मौजूदगी) को देखते हुए अन्य उत्पादों के आयात के रूप में कोई ऐसा व्यवहार है जिसे अपनाया जा सकता है अथवा प्रयोग के लिए बदला जा सकता है क्योंकि वे उत्पाद अथवा वस्तु पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन हैं। यद्यपि, विगत उदाहरणों में निर्दिष्ट प्राधिकारी की टिप्पणियों की निर्णयात्मक प्रकृति न्यायालय को स्पष्ट रूप से यह मानने के लिए मजबूर कर रही है कि कोई नई जांच नहीं होनी चाहिए, फिर भी प्रवंचना संबंधी कार्यवाही की भेदकारी प्रकृति विस्मरणशील नहीं हो सकती। इसका सहारा लेने का अधिकार वास्तविक सामग्री पर आधारित होना चाहिए। वर्तमान मामले में जिस सूचना पर उत्तरदायी विश्वास करते हैं वे उस वस्तु की मांग में स्थिरता है जो कि पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन है और सीआरएसएस के आयात में वृद्धि का पैटर्न 1250 एमएम से अधिक चौड़ा है। याचिकाकर्ता का यह तर्क कि पिछले आदेशों और टिप्पणियों की विषय वस्तु प्रवंचना संबंधी कार्यवाहियों में समान है, इस न्यायालय में समझने योग्य नहीं है।

स्टील स्ट्रिप्स को बांटने और काटने की प्रक्रिया की जांच तथा क्या यह अपूर्ण वस्तु अथवा असेंबल न किए गए सामान की “असेंबलिंग” है तो क्या वह मुद्रा बन जाएगा जिसके संबंध में न तो पक्षकार ने औचित्य के आधार पर तर्कों का समाधान किया और न ही आवश्यक तथ्य प्रस्तुत किए। इस तथ्य कि यह सक्षम मंच के समक्ष जांच एवं तर्कों की विषय वस्तु होगी, इस कार्यवाही में नियम न तो बाधनीय है और न ही आवश्यक है जो कि अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा की स्थापित सीमाओं को ध्यान में रखते हुए है, जो कि वैधता, कार्यवाही संबंधी नियमितता, स्वच्छता और उपयुक्त निर्णय के प्रश्न से पृष्ठ है।”

मैसर्स सनसिटी शीट्स प्रा. लि. और मैसर्स ऑटोकुम्पू ओई ने विशेष छूट याचिका के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के दिनांक 08.03.2017 के निर्णय को चुनौती दी थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 21.04.2017 के आदेश द्वारा छूट प्रदान की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जांच पर रोक नहीं लगाई।

घ. विचाराधीन उत्पाद/जांचाधीन उत्पाद और समान वस्तु**विचाराधीन उत्पाद**

27. इस प्रवंचना संबंधी जांच के प्रयोजन के लिए विचाराधीन उत्पाद पूर्व की निर्णायक समीक्षा जांच में परिभाषित किए गए अनुसार समान है जिसके अंतिम जांच परिणाम दिनांक 12.10.2015 की अधिसूचना संख्या 15/04/2014 द्वारा जारी किए गए और जिसे निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है:

“4 एमएम तक की मोटाई वाले कोल्ड रोलड (कोल्ड रेड्यूस्ड) की सभी श्रृंखलाओं के, जिसने इसके आगे काम नहीं किया कि 600 एमएम से 1250 एमएम तक की चौड़ाई के स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोलड फ्लेट प्रोडक्ट्स (मिल ऐज के लिए +30 एमएम तथा ट्रिप्स ऐज के लिए +4 एमएम की चौड़ाई टोलरेंस)”, निम्नलिखित को छोड़कर:

- i. 1250 एमएम से अधिक चौड़ाई के संबद्ध सामान (+ टोलरेंस)।
- ii. ग्रेड्स एआईएसआई 420 उच्च कार्बन, 443, 441, ईएन 1.4835, 1.4547, 1.4539, 1.4438, 1.4318, 1.4833 और ईएन 1.4509
- iii. क्रोमियम निकल मैंगनीज – कॉपर ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील से युक्त लौह निकल वाले सामानों के संबंध में भारतीय पेटेंट संख्या 223848 के तहत आपूर्ति किए गए उत्पाद और चीनी तैपई (ताइवान) के मैसर्स यीह यूनाइटेड स्टील कारपो. (यूसको) द्वारा उत्पादित और आपूर्ति किए गए ग्रेड वाईयू-1 और वाईयू-4 का प्रतिनिधित्व करने वाले उत्पाद।

जांचाधीन उत्पाद

28. वे जांचाधीन उत्पाद, जिनसे पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना होने का आरोप है, ऊपर पैरा 27 में परिभाषित विचाराधीन उत्पाद की तरह समान विवरण की स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोलड फ्लेट उत्पाद हैं परंतु जिसकी चौड़ाई विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के तहत वर्णित तथा शामिल किए गए उत्पादों से अधिक है। ये उत्पाद अर्थात् जांचाधीन उत्पाद उसी उप शीर्ष 7219.31, 7219.32, 7219.33, 7219.34, 7219.35 और 7219.90 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 72 के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने योग्य भी हैं। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और इस जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है। जांचाधीन उत्पाद, जो कि तथाकथित प्रवंचना की विषय वस्तु है, में उसकी चौड़ाई के संदर्भ में केवल अंतर की दृष्टि से पाटनरोधी शुल्कों के अध्याधीन उत्पाद की अनिवार्य एवं आधारभूत सभी विशेषताएं हैं।

उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों और एसोसिएशनों द्वारा किए गए अनुरोध

29. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि जांचाधीन उत्पाद और विचाराधीन उत्पाद समान वस्तु नहीं हैं क्योंकि प्राधिकारी ने मूल जांच में दोनों उत्पादों को समान वस्तु नहीं माना है और 1250 एमएम से अधिक की चौड़ाई वाले सामान को जांच के क्षेत्र से बाहर रखा है। इस बात के मद्देनजर हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया है कि वे विचाराधीन उत्पाद और जांचाधीन उत्पाद को समान वस्तु न मानें।
30. ऑटोकुम्पू ओई और युसको का प्रतिनिधित्व करने वाले मैसर्स ईएलपी के अधिवक्ताओं और न्यायवादियों ने उल्लेख किया है कि याचिकाकर्ताओं ने दिसंबर, 2016 में प्रवंचनारोधी के लिए याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि वे विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक हैं। इस तथ्य के बावजूद कि उपर्युक्त फाइलिंग तथा यहां तक कि जांच की अवधि से पूर्व भी जेएसएचएल को अपनी संपूर्णता में उनका हिसार में अपना संयंत्र था। इसलिए याचिकाकर्ता का दावा पूर्णतः झूठा और अनौचित्यपूर्ण है।
31. मैसर्स सनसिटी शीट्स प्रा. लि., मैसर्स सनसिटी स्ट्रिप्स एंड ट्यूब्स प्रा. लि., मैसर्स सनराइज स्टेनलेस प्रा. लि. और मैसर्स सनमार्क स्टेनलेस प्राइवेट लिमिटेड का प्रतिनिधित्व करने वाले मैसर्स जीटीसी कंसल्टेंट्स ने निम्नलिखित अनुरोध किया है:

- आवेदक ने कार्यवाही की शुरुआत की है क्योंकि वह अंतिम कार्यवाहियों में विस्तारित किए गए विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को प्राप्त करने में विफल रहे। आवेदक के लिए यह मानना गलत है कि पाटनरोधी नियमावली में समान कार्यवाही के संबंध में बहुपक्षीय कार्यवाहियां किए जाने का प्रावधान है। आवेदक ने दिनांक 11.12.2015 की अधिसूचना संख्या 61/2015-सीमा शुल्क के विरुद्ध अपनी अपील दायर की है और उसे समान कार्यवाही के संबंध में बहुविध कार्यवाही करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। जैसा कि पहले बताया गया है कि 11.12.2015 की अधिसूचना जारी किए जाने के बाद भी कोई घटना नहीं हुई जिसके आधार पर वर्तमान कार्यवाही के लिए अलग कार्रवाई शुरू की जाए।
- आवेदक को पूर्ण जानकारी थी कि 1250 एमएम की चौड़ाई से अधिक के सीआरएसएस अलग श्रेणी की वस्तु थी और इसे बार-बार ऐसा माने जाने के लिए कहा गया। यदि कुल मिलाकर ऐसी किसी “वस्तु” के पाटन के विरुद्ध शिकायत थी, तो इस तरह के पाटन की जांच के लिए अलग से कार्यवाहियां शुरू की जा सकती थीं। ऐसा करने में विफल होने पर स्पष्ट कारणों से आवेदक संभवतः घरेलू उद्योग के रूप में अपने आधार का औचित्य नहीं बता सका, उसने प्रवंचनारोधी के लिए आवेदन दायर किया ताकि वह पिछले दरवाजे से जांच की शुरुआत करवा सके, जिसकी अनुमति नहीं है।
- उपर्युक्त के मद्देनजर वर्तमान प्रवंचनारोधी कार्यवाहियों से कानूनी प्रक्रिया पर दाग लगेगा क्योंकि इस एलडी प्राधिकारी द्वारा पहले ही समान मुद्दों की जांच की जा चुकी है तथा आवेदक के विरुद्ध निर्णय लिया है और इसमें जो आधार उपलब्ध है, वह केवल 1250 एमएम से अधिक की चौड़ाई वाले सीआरएसएस पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए नए सिरे से जांच की शुरुआत करने का है।

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

32. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि मूल जांच के दौरान अधिक चौड़ी कॉइलों को इस आधार पर जांच के क्षेत्र से बाहर रखा गया था कि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा पूर्णतः वास्तव में उत्पादन और बिक्री नहीं की गई थी, इसकी बजाए उन्हें तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीय माना गया था। घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद 1250 एमएम से अधिक की चौड़ाई का भारी मात्रा में पाटनरोधी शुल्क के भुगतान के बिना देश में आयात किया जा रहा है। फिर भी अंततः उन्हें कम चौड़ाई में बांटा जाता है। घरेलू उद्योग के अनुसार सामान अब 1250 एमएम से अधिक की चौड़ाई में लाए जाते हैं जो कि अपूर्ण उत्पाद हैं क्योंकि उन्हें आवश्यक रूप से अंतिम ग्राहक द्वारा प्रयोग के लिए कम चौड़ाई (अंतिम पूर्ण उत्पाद) में बांटा जाता है। आयातों के परिवर्तित संगठन इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त व्यवस्था संबंधी सामानों पर पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना के लिए ही की गई है। इसके मद्देनजर घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से अनुरोध किया कि वे कृपया विचाराधीन उत्पाद और जांचाधीन उत्पाद को समान वस्तु मानें।

प्राधिकारी द्वारा जांच

33. प्राधिकारी विभिन्न अनुरोधों को नोट करने के बाद मानते हैं कि प्रवंचना संबंधी जांच के प्रयोजन के लिए विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित रूप में सही परिभाषित है:

“4 एमएम तक की मोटाई वाले कोल्ड रोलड (कोल्ड रेड्यूस्ड) की सभी श्रृंखलाओं के, जिसने इसके आगे काम नहीं किया कि 600 एमएम से 1250 एमएम तक की चौड़ाई के स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोलड फ्लेट प्रोडक्ट्स (मिल ऐज के लिए +30 एमएम तथा ट्रिम्ड ऐज के लिए +4 एमएम की चौड़ाई टोलरेंस)”, निम्नलिखित को छोड़कर:

- 1250 एमएम से अधिक चौड़ाई के संबद्ध सामान (+ टोलरेंस)।
- ग्रेड्स एआईएसआई 420 उच्च कार्बन, 443, 441, ईएन 1.4835, 1.4547, 1.4539, 1.4438, 1.4318, 1.4833 और ईएन 1.4509
- क्रोमियम निकल मैंगनीज – कॉपर ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील से युक्त लौह निकल वाले सामानों के संबंध में भारतीय पेटेंट संख्या 223848 के तहत आपूर्ति किए गए उत्पाद और चीनी तैपई (ताइवान) के मैसर्स यीह यूनाइटेड स्टील कारपो. (यूसको) द्वारा उत्पादित और आपूर्ति किए गए ग्रेड वाईयू-1 और वाईयू-4 का प्रतिनिधित्व करने वाले उत्पाद।

34. वे जांचाधीन उत्पाद, जिनसे पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना होने का आरोप है, ऊपर परिभाषित विचाराधीन उत्पाद की तरह समान विवरण की स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लेट उत्पाद हैं परंतु जिसकी चौड़ाई विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के तहत वर्णित तथा शामिल किए गए उत्पादों से अधिक है। ये उत्पाद अर्थात् जांचाधीन उत्पाद उसी उप शीर्ष 7219.31, 7219.32, 7219.33, 7219.34, 7219.35 और 7219.90 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 72 के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने योग्य भी हैं। फिर भी यद्यपि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और इस जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांचाधीन उत्पाद, जो कि तथाकथित प्रवंचना की विषय वस्तु है, में उसकी चौड़ाई के संदर्भ में केवल अंतर की दृष्टि से पाटनरोधी शुल्कों के अध्याधीन उत्पाद की अनिवार्य एवं आधारभूत सभी विशेषताएं हैं।
35. जहां तक समान वस्तु के मुद्दे का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रवंचना से संबंधित प्रावधानों के तहत प्राधिकारी को इस तरह से जांच करने की अपेक्षा नहीं है कि क्या विचाराधीन उत्पाद और जांचाधीन उत्पाद समान वस्तु हैं अथवा नहीं। नियम 25(1) के अनुसार आवश्यकता केवल यह जांच करने की है कि पाटनरोधी शुल्क के अध्याधीन कोई वस्तु अनअसेंबल्ड, अपरिष्कृत अथवा अपूर्ण रूप में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के प्रयोजन के लिए अधिसूचित निर्यात के देश अथवा मूल देश सहित किसी देश से भारत में आयात की जाती है और भारत में अथवा किसी ऐसे देश में असेंबल्ड, परिष्कृत अथवा पूर्ण की जाती है। फिर भी यह पाया जाता है कि जांचाधीन उत्पाद को पाटनरोधी शुल्क के क्षेत्र से बाहर करने का तर्क प्राधिकारी का जांच परिणाम था कि जांचाधीन उत्पाद जांच की मूल अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचा नहीं जा रहा था। अतः उत्पाद की विशेष श्रेणी का अभिप्राय यह नहीं है कि वे समान वस्तु नहीं हैं क्योंकि उन्हें क्षेत्र से बाहर रखे जाने का आधार उत्पादन प्रक्रिया समान होने के साथ केवल चौड़ाई थी। अतः यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त प्रमाण हैं कि जांचाधीन उत्पाद ने विचाराधीन उत्पादों का स्थान बिना किसी आर्थिक अथवा वाणिज्यिक औचित्य के पर्याप्त मात्रा में ले लिया है। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि समान वस्तु के मुद्दे पर हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध कानूनी प्रावधानों अथवा इस मामले के तथ्यों के संदर्भ में कहीं भी संगत नहीं है।

ङ. घरेलू उद्योग और आधार

36. प्रवंचना संबंधी जांच के लिए मैसर्स जिंदल स्टेनलेस स्टील लि. ने आवेदन पत्र दायर किया है जिनका जांच की अवधि के दौरान कुल घरेलू उत्पादन में भारी अनुपात है। प्राधिकारी के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में विचाराधीन उत्पाद के तीन अन्य ज्ञात उत्पादक हैं, अर्थात् मैसर्स बीआरजी, मैसर्स सलेम स्टील प्लांट (सेल) और मैसर्स शाह अलॉय। वर्तमान जांच में देश में किसी अन्य उत्पादक से घरेलू उद्योग के आवेदन पत्र का कोई विरोध नहीं है।

उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों और एसोसिएशनों द्वारा किए गए अनुरोध

37. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि जिंदल स्टेनलेस लि. (जेएसएल) 31 मार्च, 2014 की अनामेलन योजना के अनुसरण में नियम 2(ख) के तहत विचाराधीन उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग नहीं रहा। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि अनामेलन के अनुसरण में नई-नई बनाई गई कंपनी जेएसएचएल भारत में विचाराधीन उत्पाद के भारी अनुपात में उत्पादन करने वाला बन गया क्योंकि उसी का हिसार में विचाराधीन उत्पाद के लिए संयंत्र पर स्वामित्व एवं प्रचालन है।
38. यह अनुरोध है कि याचिकाकर्ता ने दिसंबर, 2016 में प्रवंचनारोधी जांचों के लिए याचिका दायर की थी, इस तथ्य के बावजूद कि उपर्युक्त फाइलिंग तथा यहां तक कि जांच की अवधि से पूर्व भी जेएसएचएल को अपनी संपूर्णता में उनका हिसार में अपना संयंत्र था।
39. यह अनुरोध है कि याचिकाकर्ता इस निर्धारण के लिए अपने उत्पादन के आंकड़ें दें कि क्या जांच की शुरुआत के समय याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद कुल घरेलू उत्पादन के 25 प्रतिशत से अधिक है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने प्राधिकारी से यह भी अनुरोध किया कि वे जांच की शुरुआत और जांच की अवधि के समय 25 प्रतिशत परीक्षण करें।
40. मैसर्स ईएलपी के अधिवक्ताओं और न्यायवादी ने अनुरोध किया कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 26(1) तथा नियम 2(ख) के अनुसार "घरेलू उद्योग" को कम से कम भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल घरेलू उत्पादन के भारी उत्पादन का विनिर्माता होना चाहिए। वर्तमान याचिकाकर्ता जिंदल स्टेनलेस लि. (जेएसएल) 31 मार्च, 2014 की अनामेलन योजना के अनुसरण में पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत विचाराधीन उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग नहीं रहा। जैसा कि याचिकाकर्ता ने स्वयं दर्शाया है, अनामेलन के अनुसरण में नई-नई बनाई गई कंपनी जेएसएचएल भारत में विचाराधीन उत्पाद का प्रमुख

अनुपात में उत्पादक बन गई है क्योंकि उसी का हिसार में विचाराधीन उत्पाद के लिए संयंत्र पर स्वामित्व एवं प्रचालन है। अतः जिंदल स्टेनलेस हिसार लि. (जेएसएचएल) घरेलू उद्योग बन गया, यदि कुल मिलाकर उसके अपने आधार में उसने हिसार में औपचारिक रूप से अपने संयंत्र का स्वामित्व और प्रचालन रखा जो कि याचिकाकर्ता के लिए पूर्व की जांचों में “घरेलू उद्योग” माना गया है और यह विधिवत भी है कि जब एक पक्षकार विवेकाधीन राहत के लिए न्यायाधिकरण में जाता है तो उसे बहुत सफाई के साथ ही नहीं आना चाहिए बल्कि उसे सर्वोत्तम अच्छी निष्ठा दर्शानी चाहिए और वे सभी वास्तविक तथ्य प्रकट करने चाहिए जो उसकी जानकारी में हैं। यह अनुरोध है कि याचिकाकर्ता स्वयं ही जिंदल स्टेनलेस हिसार लि. के संबंध में सूचना देने में विफल रहा क्योंकि वह एक याचिकाकर्ता से संबंधित पक्षकार है और जेएसएचएल भारत में विचाराधीन उत्पाद का प्रमुख उत्पादक भी है।

41. मैसर्स ईएलपी के अधिवक्ताओं और न्यायवादी ने यह भी अनुरोध किया कि “घरेलू उद्योग” के रूप में अपना आधार सिद्ध करने का दायित्व पूर्णतः याचिकाकर्ता पर है और याचिकाकर्ता सबूत का दायित्व अन्य हितबद्ध पक्षकार पर नहीं डाल सकता। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने सार्वजनिक सुनवाई में माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्देशों की पूर्णतः अवहेलना की है जिसमें माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया था कि वे यह निर्धारित करने के लिए अपने उत्पादन आंकड़ों के जांच की शुरुआत के समय याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद कुल घरेलू उत्पादन के 25 प्रतिशत से अधिक है।

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

42. याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया कि हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क कि जेएसएल घरेलू उद्योग नहीं रहा, पूर्णतः गलत है और कानून एवं तथ्यों के गलत दायरे पर आधारित है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि हितबद्ध पक्षकार इस तथ्य की उपेक्षा करके प्राधिकारी को भ्रम में डालने का प्रयास कर रहे हैं कि आवेदन पत्र की तारीख को दोनों संयंत्र जिंदल स्टेनलेस स्टील (जेएसएल) नाम की उसी कानूनी कंपनी के तहत प्रचालित थे। अतः यह कहना पूर्णतः गलत है कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत परिभाषित किए गए अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से आवेदन पत्र दायर नहीं किया गया था। यह भी अनुरोध किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने इस तथ्य की भी उपेक्षा की कि अनामेलन योजना, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने अनुमोदित कर दिया था, 01 नवंबर, 2015 से प्रभावी की गई थी। दूसरे शब्दों में, 31 अक्तूबर, 2015 के बाद सभी प्रचालन एवं कार्यवाहियां अंतरण करने वाली कंपनी द्वारा किए गए थे। यह नोट करना व्यावहारिक है कि अनामेलन के लिए व्यवस्था की पूरी योजना तभी प्रभावी होनी थी जब इस योजना की धारा V के उप वाक्य 1.5(क) के अनुसार शर्तें पूरी हो जाएं। जैसा कि, स्वयं ही व्यवस्था की योजना से देखा जा सकता है, यह योजना अंतिम अनुमोदन की तारीख से प्रभावी होनी थी। उच्च न्यायालय के आदेश को आरओसी में दायर करने का अंतिम अनुमोदन था जो 01 नवंबर, 2015 को किया गया था। अतः घरेलू उद्योग द्वारा यह अनुरोध किया जाता है कि यह योजना प्रचालनात्मक रूप से 01 नवंबर, 2015 से ही प्रभावी हुई। दूसरे शब्दों में, जिस तारीख को प्रवचना के लिए आवेदन दायर किया गया था, अनामेलन योजना प्रचालनात्मक नहीं थी और कानूनी की नजर में केवल जेएसएल अस्तित्व में था। इसके मद्देनजर यह कहा जा सकता है कि घरेलू उद्योग द्वारा आवेदन दायर नहीं किया गया था।
43. याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया कि किसी भी दशा में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह योजना एक विशेष निर्देश के साथ स्वीकृत की गई थी कि वह सभी संबंधितों पर बाध्यकारी है। अतः हिसार यूनिट के संबंध में जेएसएल द्वारा सभी कानूनी, कर नियामक, अर्धन्यायिक, प्रशासनिक कार्यवाहियां, दावे, अपील, आवेदन अथवा अन्य किसी प्रकृति की कोई भी कार्यवाहियां, जो भी शुरू की गईं, वे जारी रखी गईं, मानो कि उन्हें जेएसएचएल द्वारा ही शुरू किया गया था। अतः इस योजना की व्यवस्था के तहत जेएसएल द्वारा की गई सभी कार्यवाहियां इस योजना के तहत जेएसएचएल द्वारा की गई कार्यवाहियां मानी जानी हैं।
44. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि आधार का मुद्दा प्रवचना संबंधी जांचों में लागू नहीं है, तथापि, घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया है कि वे प्रवचनारोधी याचिका दायर करने के लिए पात्र घरेलू उद्योग हैं क्योंकि वे किसी भी दिए गए समय पर विचाराधीन उत्पाद और जांचाधीन उत्पाद के कुल उत्पादन के 25 प्रतिशत के स्तर से ऊपर हैं।
45. इसके मद्देनजर, यह निस्सन्देह स्पष्ट है कि सितंबर, 2015 में आवेदन दायर करने की तारीख को जेएसएल को ऐसा करने के लिए पूर्ण कानूनी प्राधिकार था। ऐसी मामला होने पर याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया कि नियम 26 की आवश्यकता कि आवेदन “घरेलू उद्योग द्वारा या उनकी ओर से” होना चाहिए था, संतुष्टिपूर्ण था। पूर्वाग्रह के बिना यह अनुरोध किया जाता है कि जेएसएल एकमात्र घरेलू उद्योग की ओर से आवेदन दायर करने की शर्तों को भी पूरा करता था। अतः हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध कानूनी अथवा तथ्यों की दृष्टि से किसी भी औचित्य से विहीन हैं।

प्राधिकारी द्वारा जांच

46. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रवंचनारोधी जांच के लिए तथा जांचाधीन अवधि के आयातों में विचाराधीन उत्पाद के आयात पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क बढ़ाने के लिए याचिका मैसर्स ज़िंदल स्टेनलेस लि. द्वारा निम्नलिखित रूप में पठित नियम 26(1) के अनुसार है:

“(1) जैसा कि यहां नीचे दिया गया है, को छोड़कर, निर्दिष्ट प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से कोई लिखित आवेदन पत्र प्राप्त होने पर अधिनियम की धारा 9 के तहत लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की तथाकथित प्रवंचना की मौजूदगी और उसका प्रभाव निर्धारित करने के लिए जांच शुरू कर सकते हैं।”

47. प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियम 26(1) के अनुसार पहले से लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा दायर की जाने वाली प्रवंचनारोधी याचिका आवश्यक है। इस जांच में मौजूदा पाटनरोधी शुल्क का घरेलू उद्योग मैसर्स ज़िंदल स्टेनलेस लि. था जिन्होंने पूरी जांच की अवधि के दौरान किसी भी संबद्ध देश से कोई जांचाधीन उत्पाद अथवा विचाराधीन उत्पाद आयात नहीं किया था और न ही वे जांचाधीन उत्पाद अथवा विचाराधीन उत्पाद के किसी भी आयातक अथवा निर्यातक से संबंधित थे।
48. जहां तक घरेलू उद्योग के रूप में जेएसएल की पात्रता का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जेएसएल के अनामेलन से संबंधित आदेश 01 नवंबर, 2015 अर्थात् जेएसएल द्वारा प्रवंचनारोधी जांच के लिए आवेदन दायर करने के बाद से प्रभावी थी और वह जांच की अवधि 01.07.2014 से 30.09.2015 तक होने के नाते 01 नवंबर, 2015 से पूर्व भी है। कुछ भी हो, वर्तमान जांच में प्राधिकारी ने जेएसएल और जेएसएचएल, दोनों की ओर से दायर किए गए आंकड़ों पर विचार किया।
49. किसी भी दशा में प्राधिकारी नोट करते हैं कि केवल जेएसएल ही 25 प्रतिशत और 50 प्रतिशत के परीक्षण को पास करता है, फिर भी उपर्युक्त शर्तें नियम 26 के तहत शुरू की गई जांच के लिए लागू नहीं हैं। उपर्युक्त के मद्देनजर, यह माना जाता है कि जेएसएल द्वारा इस मामले में दायर आवेदन पत्र को किसी कानूनी दुर्बलता से नुकसान नहीं हुआ और उसे इस प्रवंचना संबंधी जांच के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से दायर किया गया माना गया है।

च. गोपनीयता और अन्य मुद्दे**घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

50. गोपनीयता के संबंध में, गॉटेमाला – सीमेंट II (डब्ल्यूटी/डीएस156/आर) के मामले में घरेलू उद्योग ने डब्ल्यूटीओ पैनल की रिपोर्ट तथा नियमावली के नियम 7 का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित अनुरोध किया है:
- घरेलू उद्योग ने केवल उस सूचना की गोपनीयता का दावा किया है जो उसकी लागत और कीमतों से संबंधित है। उन्होंने लागत और कीमतों के लिए सूचीबद्ध आंकड़े भी दिए।
 - किसी भी निर्यातक ने वह अगोपनीय रूपांतर नहीं दिया था, जो गोपनीय रूपांतर में उनके उत्तरों का एक सटीक उद्धरण माना गया है। इसके अतिरिक्त, उत्पादकों/निर्यातकों ने सूचना से संबंधित भाग भी गोपनीय रखा था, यहां तक कि गोपनीयता का दावा करने वाला विवरण नहीं दिया गया था।
 - कई हितबद्ध पक्षकारों ने अपने लिखित अनुरोधों के अनुबंधों को भी गोपनीय रखा है जिससे उस पर टिप्पणियां देने के लिए घरेलू उद्योग को अवसर प्राप्त नहीं हुआ।

उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों और एसोसिएशनों द्वारा किए गए अनुरोध

- घरेलू उद्योग द्वारा उसी के लिए कोई ठोस कारण बताए बिना अथवा उसका अगोपनीय सारांश दिए बिना कई व्यौरों के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है।
- पोसको, कोरिया और उसकी संबंधित कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले मैसर्स डीजीएस एसोसिएशन ने अनुरोध किया है कि उन्होंने गोपनीयता का दावा माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अपने दिनांक 09 दिसंबर, 2013 की व्यापार सूचना संख्या

1/2013 में निर्धारित दिशा निर्देशों और पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के अनुसार किया है। इसके विपरीत, यह याचिका साक्ष्य प्रस्तुत कर प्रमाणित करने, जैसा कि पाटनरोधी नियमावली में अनिवार्यता है, के बजाए केवल अटकलों पर आधारित है।

- (iii) चूंकि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, अतः जब तक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश जारी नहीं किए जाते हैं, तब तक इसे स्थगित रखा जाए।
- (iv) मैसर्स विराना पीटीई. लि., सिंगापुर ने उल्लेख किया कि वे एक हितबद्ध पक्षकार होना चाहेंगे तथा यह कि जांच की अवधि 5 माह तक बढ़ाई जाए, जांच का क्षेत्र 304 और 316 तक ही प्रतिबंधित किया जाए क्योंकि आयात कुछ ही ग्रेडों के हैं तथा यह इस जांच से प्रयोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- (v) मैसर्स सनसिटी शीट्स प्रा. लि. वर्तमान कार्यवाहियों की शुरुआत को 2016 की रिट याचिका (सी) संख्या 3544 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर चुनौती दी है कि इस एलडी प्राधिकारी को वर्तमान कार्यवाहियां शुरू करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। यह अनुरोध किया जाता है कि उपर्युक्त रिट याचिका को रद्द करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने इस संबंध में स्पष्ट टिप्पणियां की हैं कि इस एलडी प्राधिकारी को स्टील स्ट्रिप को बांटने और उसको काटने की प्रक्रिया की क्षति का अध्ययन करने की अपेक्षा है तथा यह कि क्या वह असेंबल न किए गए अथवा अपूर्ण वस्तु की “असेंबलिंग” हैं अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त, जहां यह माननीय प्राधिकारी निष्कर्ष पर आते हैं कि वर्तमान मामले में नियम 25 और 26 के तहत निर्धारित स्तर पूरा नहीं किया गया है, वहां प्रवंचनारोधी के लिए यह आवेदन रद्द हो जाएगा तथा नियम 25 और 26 की पूर्व शर्तों की मौजूदगी वर्तमान जांचों में कार्यवाही के लिए अनिवार्य है। तदनुसार, एक सीमित पूछताछ के आधार पर, जैसा कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश में निर्धारित भी है, नियम 25 की पूर्व शर्तों को पूरा करने के संबंध में जांच परिणाम दिया जाना अपेक्षित है।
- (vi) ऑटोकम्पू ओई और युसको का प्रतिनिधित्व करने वाले मैसर्स ईएलपी के अधिवक्ताओं एवं न्यायवादियों ने निम्नलिखित अनुरोध किया है:
- घरेलू उद्योग की प्रश्नावली के उत्तर में माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास 10 अप्रैल, 2017 के पत्र द्वारा अतिरिक्त सूचना दायर की। यह निर्यातक का अनुरोध है कि याचिकाकर्ता ने इस सूचना को सर्वाधिक गोपनीय अन्यायपूर्ण तरीके से दावा किया है जो कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 और दिसंबर, 2013 की व्यापार सूचना संख्या 1/2013 का घोर उल्लंघन है।
 - निर्दिष्ट प्राधिकारी ने वर्तमान जांच की शुरुआत की अधिसूचना द्वारा पैरा 17 में विशेष रूप से उल्लेख किया है कि “किसी सार्थक अगोपनीय रूपांतर के बिना अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में अच्छा कारण देने वाले विवरण के बिना कोई भी अनुरोध प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।”
 - माननीय सेसेट ने **अलकाली मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी 2006 (194) ईएलटी 161 (ट्राई – डेल)** के मामले में निम्नलिखित माना है:

“15.1..... हितबद्ध पक्षकारों को वह आधार अस्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए जिस आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया गया है, कारण गोपनीय नहीं हो सकते, केवल वे आंकड़े गोपनीय रखे जाने होते हैं जिनसे अपने व्यापारिक कार्यों में गोपनीयता का दावा करने वाले पक्षकार को नुकसान पहुँचे। परंतु अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अभ्यावेदनों में किसी निष्कर्ष पर पहुँचने अथवा कारण को स्वीकार करने अथवा किसी आधार पर उसे रद्द करने के कारण गोपनीय नहीं हो सकते और किसी विचार अथवा दी गई सूचना को स्वीकार करने अथवा उसे रद्द करने के लिए उचित कारण निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अपने आदेश में दिए जाने चाहिए।”

- इसके अतिरिक्त, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी **रिलायंस इंडस्ट्रीज बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी 2006 (2002) ईएलटी 23 (एससी)** के प्रमुख मामले में अत्यधिक गोपनीयता का समाधान किया है और माना है कि:
“43. हमारे मत में गोपनीयता के अत्यधिक और अनावश्यक दावे से अपील का अधिकार हार जाता है। परिणामों, आधारों, तर्क और सिद्धांत की जानकारी के अभाव में, जिससे निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने निर्णय पर पहुँचे हैं और अपनी सिफारिशों की हैं, कार्यवाहियों में पक्षकार न्यायाधिकरण अथवा इस न्यायालय के समक्ष अपने अपील के अधिकार को प्रभावी रूप से कार्यान्वित नहीं कर सकते।

पाटनरोधी नियम देश की औद्योगिक प्रगति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसीलिए उसके कार्यान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता एवं स्वच्छता होनी चाहिए।”

- इसके अतिरिक्त, वाणिज्य मंत्रालय ने दिसंबर, 2013 की अपनी व्यापार सूचना संख्या 1/2013 के पैरा vi में यह उल्लेख किया है कि जिन आंकड़ों के आधार पर अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है, उनकी उपेक्षा की जाएगी।
“किसी सार्थक अगोपनीय रूपांतर के बिना अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में अच्छा कारण देने वाले विवरण के बिना कोई भी अनुरोध प्राधिकारी द्वारा नहीं लिया जाएगा।”
- अतः, यह एक तय सिद्धांत है कि जब किसी जांच में कोई पक्षकार गोपनीय सूचना देता है, तो पक्षकार को उसका सार्थक अगोपनीय सारांश देना भी अनिवार्य होता है। ऐसी स्थिति में कि सूचना का सारांश रूप नहीं किया जा सकता, प्रश्रुत पक्षकार से यह अपेक्षा होती है कि वह इस प्रकार के सारांश न किए जाने के कारण होता है।
- मैसर्स ईएलपी के अधिवक्ताओं और न्यायवादियों ने उल्लेख किया है कि विचाराधीन उत्पाद पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की न्यायिक समीक्षा में और प्रवचना संबंधी जांच में अप्रतिभागिता में निर्यातक के भाग न लेने के बीच एक अप्रमाणित और पूर्णतः अतार्किक संबंध लिया गया है। ऑटोकुम्पू ने वाणिज्यिक कारणों से, विशेष रूप से जांच की अवधि, जांच की अवधि के बाद की अवधि तथा अन्य संभावित सूचना के लिए आंकड़े दायर करने हेतु संबद्ध देशों से निर्यातकों/उत्पादकों पर अत्यधिक भार डालने की दृष्टि से निर्णायक समीक्षा में भाग नहीं लिया। निर्यातक का अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्णायक समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद के संबंध में व्यापारिक निर्णय के कारण भाग नहीं लिया गया था और उस जांचाधीन उत्पाद में कोई बाधा नहीं है जो भारत में आयात किया जाता है। वस्तुतः यहां तक कि यदि यह अवधारणा की जाए (बिना स्वीकार किए) कि निर्यातक प्रवचना में लगा हुआ था, निर्यातक ने प्रचुर मात्रा में सूचना दायर करने पर वर्तमान कार्यवाही में इतनी व्यापक रूप से भाग न लिया होता और प्राधिकारी को अपने गोपनीय आंकड़े खोलना प्रवचना का अभाव सिद्ध करता है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, ऑटोकुम्पू एक अंतर्राष्ट्रीय रूप से सुविख्यात तथा स्टेनलेस स्टील का विधिक विनिर्माता है तथा याचिकाकर्ता के झूठे आरोपों को प्राधिकारी द्वारा सीधे-सीधे रद्द किया जाना चाहिए।

प्राधिकारी द्वारा जांच

51. पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में सूचना की गोपनीयता निम्नानुसार है:

गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में निहित किसी बात को होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि गोपनीयता के लिए अनुरोध न्यायसंगत नहीं अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा इसको सामान्य तौर पर अथवा संक्षिप्त रूप में उसे प्रकट करने के लिए अनिच्छुक हो, तो ऐसी सूचना की उपेक्षा की जा सकती है।

52. गोपनीयता के संबंध में संगत माने जाने की स्थिति तक घरेलू उद्योग और विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच प्राधिकारी द्वारा की गई तथा तदनुसार, उनका समाधान किया गया। गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने, जहां भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और वह सूचना गोपनीय मानी गई है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की

गई है। जहां कहीं भी संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार को निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर दें। प्राधिकारी ने सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराए। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपनी व्यापार संबंधी सूचना को गोपनीय होने का दावा किया है जिसे नियमानुसार तथा प्राधिकारी की सतत परिपाटी के अनुसार गोपनीय रखा गया है।

53. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने संबद्ध देशों के सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को भी प्रश्नावली भेजी ताकि वे उन सबको प्रश्नावली, संगत आवेदन उपलब्ध करा सकें जिन्होंने भाग लेने की इच्छा जाहिर की है। किसी भी गैर संबद्ध देश के किसी भी उत्पादक/निर्यातक को नियमानुसार हितबद्ध पक्षकार नहीं माना गया है।
54. जहां तक जांच की वैधता, पाटनरोधी नियमावली में निर्धारित प्रवंचना की शर्तों को पूरा न करने से संबंधित मुद्दे का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 08 मार्च, 2017 के निर्णय में आयातक/निर्यातक द्वारा दायर की गई याचिका को रद्द कर दिया है जिसमें प्रमुखतः ऊपर उल्लिखित वैधता संबंधी मुद्दे हैं। प्राधिकारी विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट करते हैं, जिनमें से अधिकतर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष भी किए गए थे। प्राधिकारी नोट करते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ने अपने 08 मार्च, 2017 के निर्णय में यह माना है कि जांच की प्रक्रिया प्रवंचनारोधी जांच में बिल्कुल भिन्न है तथा यह कि विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के तथ्यों और तर्कों को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखे जाने की आवश्यकता है। प्राधिकारी उपर्युक्त निर्णय के लागू पैरा के मद्देनजर विभिन्न अनुरोधों को नोट करते हैं और उन्होंने इस अंतिम जांच परिणाम में संगत पाटनरोधी नियमावली 25-28 के अनुसार सभी संगत मानदंडों का मूल्यांकन किया।

प्रवंचना का निर्धारण

छ. प्रवंचना के साक्ष्य

संबद्ध देशों के उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों और एसोसिएशनों/दूतावासों द्वारा किए गए अनुरोध

55. प्रवंचना के संबंध में निर्यातकों/आयातकों/प्रयोक्ताओं और एसोसिएशनों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - क. जांचाधीन उत्पाद असेंबल न किए गए, अपरिष्कृत अथवा अपूर्ण रूप में नहीं है और इसीलिए नियम 25(1) के प्रावधानों का आह्वान नहीं किया जा सकता।
 - ख. अलग करने की प्रक्रिया में निहित मूल्य वर्धन बहुत अधिक है, इससे प्रवंचना आर्थिक रूप से और वाणिज्यिक रूप से गैर अर्थक्षम हो जाती है।
 - ग. यूरोपीय संघ के उत्पादक/निर्यातक ने अनुरोध किया है कि वे पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से पूर्व भी 1250 एमएम से अधिक की चौड़ाई वाले सामान की बिक्री कर रहे थे। इसके अतिरिक्त, उनके 1250 एमएम से अधिक की चौड़ाई वाले सामानों का भी अनुप्रयोगों में प्रयोग हो रहा है जो उपयुक्त रूप से 1250 एमएम से अधिक की चौड़ाई के लिए अपेक्षित है।
 - घ. कोरिया, पोसको के उत्पादक/निर्यातक ने उल्लेख किया है कि व्यापक चौड़ाई वाले आयातों के ** प्रतिशत को 600 एमएम से कम की चौड़ाई में बांटा जा रहा है जो कि तकनीकी रूप से विचाराधीन उत्पाद नहीं है, अतः कोई प्रवंचना नहीं है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि वे आयातित वस्तुओं को शुल्क लगाए जाने से पूर्व भी 600 एमएम से कम की चौड़ाई में बांट रहे थे।
 - ङ. यह कि घरेलू बाजार में प्रयोग के पैटर्न में परिवर्तन रहा है और जांचाधीन उत्पाद की मांग में स्वाभाविक वृद्धि है जिसे घरेलू उद्योग द्वारा जांचाधीन उत्पाद के उत्पादन में वृद्धि द्वारा सिद्ध किया जा सकता है।
 - च. यह तथ्य कि याचिकाकर्ता ने जांचाधीन उत्पाद का विनिर्माण करने के लिए संयंत्र की स्थापना की है, जो कि इस तथ्य का प्रमाण है कि जांचाधीन उत्पाद की पर्याप्त मांग है। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि आयात पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और विचाराधीन उत्पाद तथा जांचाधीन उत्पाद, दोनों के आयात में साथ-साथ वृद्धि हुई है।
 - छ. यह कि प्रवंचना वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम नहीं है क्योंकि अपशिष्ट भी होते हैं तथा वेल्डिंग से संबंधित मुद्दे हैं जिनसे लागत में वृद्धि हो सकती है तथा सुरक्षा संबंधी मुद्दे भी उठ सकते हैं।

- ज. हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी तर्क दिया है कि प्रवंचनारोधी प्रावधान लागू करने के लिए जो वस्तु आयात की जा रही है, उसे पाटनरोधी शुल्क के अध्याधीन होना चाहिए और चूंकि, जांचाधीन उत्पाद के आयात पर पाटनरोधी शुल्क नहीं है, अतः यह खंड लागू नहीं है।
- झ. हितबद्ध पक्षकारों ने अभ्यावेदन दिए हैं कि वे न तो जांचाधीन उत्पाद को बांट रहे हैं और न ही उनका पाटनरोधी शुल्कों की प्रवंचना करने का कोई इरादा है।
- ञ. पोसको कोरिया और उसकी संबंधित कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले मैसर्स डीजीएस एसोसिएट्स ने निम्नलिखित अनुरोध किया है:
- यह याचिका पाटनरोधी नियमावली के स्पष्ट प्रावधानों के विपरीत है क्योंकि वह नियम 25 की पूर्व अपेक्षाओं को सिद्ध करने में विफल रहे। भले ही सामान असेंबल न किए गए, अपरिष्कृत अथवा अपूर्ण रूप में आयात किए जाएं तथा इस प्रकार यह जांच क्षेत्राधिकार में नहीं है।
 - पोसको से भारत में आयातित जांचाधीन उत्पाद (पीयूआई) के ** प्रतिशत से अधिक उन उत्पादों की आपूर्ति के लिए उपयोग किए जा रहे हैं जो 600 एमएम से 1250 एमएम (विचाराधीन उत्पाद) के बीच की चौड़ाई के उत्पाद होने के नाते विचाराधीन उत्पाद अथवा जांचाधीन उत्पाद के घेरे में नहीं आते। जैसा कि याचिकाकर्ता ने स्वयं ही दावा किया है कि संबद्ध सामानों की अधिक चौड़ाई वाले के सीमित अनुप्रयोग हैं। ऑटोमोटिव उद्योग में यहां उत्तरदायी हितबद्ध पक्षकार द्वारा अनिवार्य रूप से आपूर्ति पूरी किए जाने वाला उद्योग होने के नाते मांग केवल लंबाई तक काटने अथवा सीटीएल आकारों की है। आयातकों के लिए वांछित सीटीएल आकारों का सीधे ही आयात करना आर्थिक अथवा वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम नहीं है क्योंकि छोटी चौड़ाई वाले सामान का उत्पादन और परिवहन केवल लागत – अप्रभावी ही नहीं है अपितु उसके रद्द किए जाने के खतरे भी हैं क्योंकि परिवहन में क्षति हो सकती है। इस प्रकार, सीटीएल आकार को ग्राहकों के लिए बेकार माना गया है। इसके अतिरिक्त, चूंकि, ऑटोमोटिव उद्योग स्पष्ट रूप से प्रकृति में प्रभावी है, अतः उसके आकार में बढ़ने की अत्यधिक संभावना है जिस आकार में कुछ माह पूर्व ऑर्डर दिया गया था। काँइल की कम वांछित चौड़ाई के सामान का परिवहन भी डिब्बों के माध्यम से होना चाहिए जिससे लागत में काफी वृद्धि ही होगी।
 - इसके अतिरिक्त, यदि निर्यातक अनुरोध किए गए आकारों के काँइल उपलब्ध कराते हैं तो काँइलों का भारत में अंतिम उपयोग से पूर्व “एज ट्रीमिंग प्रोसेस” होना चाहिए, इससे भी कचरे का उत्पादन होगा। अतः ऑटोमोटिव उद्योग के लिए यह सामान्य रूप से संभव नहीं है कि वे ठीक उसी आकार के सीटीएल का आयात करें और उत्पाद की व्यापक चौड़ाई का आयात करना ही पक्षकारों के लिए एक मात्र संभव विकल्प है जिससे आयात आर्थिक रूप से और वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम होंगे। यह बात दोहराई जाती है कि भारत में अपेक्षित आकार में बांटने के लिए बड़े आकार के सामान का आयात करने से उत्पाद की हानि होती है, परिवहन लागत अपशिष्ट होती है तथा लागत वास्तविक आपूर्ति के समय अंतिम प्रयोक्ता को अपने माने गए आधारों को बदलने में लचीलापन मिल जाता है।
 - यह सिद्ध है कि भारत में सीटीएल आकारों के रूप में आपूर्ति किए जाने के लिए अधिक चौड़ाई वाले सामान का आयात करने के लिए वैध आर्थिक अधिकार क्षेत्र मौजूद है। यह भी अनुरोध किया जाता है कि व्यापार पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है क्योंकि संबद्ध सामान ऑटोमोटिव उद्योग की खपत के लिए सीटीएल आकारों में बांटे जाने के लिए व्यापक चौड़ाई में आयात किए गए हैं। जैसा कि लिखित अनुरोधों में पहले ही उल्लेख किया गया है। ऑटोमोटिव उद्योग कुछ ही वर्षों में विकसित हुआ है और वह प्रमुख रूप से गुजरी हुई प्रणालियों के उत्पादन के लिए 600 एमएम से कम की चौड़ाई का उपयोग कर रहा है जहां पोसको द्वारा आपूर्ति किए गए जांचाधीन उत्पाद का प्रयोग किया जाता है। यह प्रयोक्ता उद्योग में एक परिवर्तन है और इसे प्रवंचना नहीं कहा जा सकता, जैसा कि याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है। याचिकाकर्ता संभवतः यह सुझाव नहीं दे रहे हैं कि पूरा बाजार बल पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के परिणामस्वरूप बदल गया है। ऐसा सुझाव अत्यधिक बेहूदा और दूर की बात है।
 - पाटनरोधी नियमावली के तहत प्रवंचनारोधी से संबंधित स्पष्ट प्रावधानों का आह्वान करने का प्रयास करते हुए याचिकाकर्ता कानून में उल्लिखित पूर्व अपेक्षाओं को पूर्ण करने में पूर्णतः विफल रहा है। इसके अतिरिक्त, प्रवंचना का आरोप लगाते समय याचिकाकर्ता ने आयात किए जा रहे जांचाधीन उत्पाद के अंतिम उपयोग की प्रवृत्ति की जांच करने के बारे में नहीं सोचा। जिस विश्लेषण से पर्याप्त रूप से यह सिद्ध होता कि आयात किया जा रहा जांचाधीन

उत्पाद प्रमुख रूप से जांचाधीन उत्पाद के रूप में अथवा 600 एमएम से कम चौड़ाई वाले उत्पाद के रूप में प्रयोग किया जाता है जिससे वह इस जांच के प्रयोजन के लिए विचाराधीन उत्पाद नहीं बनता।

- ईएन 1: 4512 के बड़े हुए आयात के संदर्भ में याचिकाकर्ता को विशिष्टतः पुनः गलत रखा गया है क्योंकि उपर्युक्त ग्रेड का आयात विशेष रूप से ऑटोमोटिव उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा रहा है और 600 एमएम से कम की चौड़ाई के सीटीएल आकार में आपूर्ति किए जाने के लिए जांचाधीन उत्पाद के रूप में आयात किया जा रहा है जो कि विचाराधीन उत्पाद और जांचाधीन उत्पाद, दोनों के क्षेत्र से बाहर है। यह नोट किया जाए कि उपर्युक्त ग्रेड का प्रयोग ऑटोमोटिव उद्योग द्वारा एक्जोस्ट प्रणालियों का विनिर्माण करने के लिए किया जाता है तथा उपर्युक्त विनिर्माण के लिए वर्तमान में प्रयुक्त किए जा रहे सीटीएल आकार 600 एमएम से कम के हैं। यह अनुरोध किया जाता है कि याचिकाकर्ता का पूरा उद्देश्य यह विश्वास करने में इस माननीय प्राधिकारी को दिग्भ्रमित करने का है कि प्रवंचना मौजूद है जबकि वस्तुतः पाटनरोधी शुल्क की कोई प्रवंचना मौजूद नहीं है। याचिकाकर्ता का सख्ती से यह कहना कि जांचाधीन उत्पाद का आयात बढ़ा है, प्रवंचना सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है क्योंकि जिस पर विचार किया जाना चाहिए, वह जांचाधीन उत्पाद का अंतिम उपयोग है।

ट. ऑटोकम्पू ओई और युसको का प्रतिनिधित्व करने वाले मैसर्स ईएलपी के अधिवक्ताओं और न्यायवादियों ने निम्नलिखित अनुरोध किया है:

- याचिकाकर्ता निम्नलिखित सूचना देने में विफल रहे जो कि जांचाधीन उत्पाद का विश्लेषण करने के लिए तथा भारत को निर्यात किए जा रहे विभिन्न श्रृंखलाओं अथवा चौड़ाईयों की प्रवंचना की संभावना का विश्लेषण करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

क) याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित श्रृंखलाओं अथवा चौड़ाईयों का कोई पृथक्करण नहीं।

ख) आयात आंकड़ों का पृथक्करण।

उपर्युक्त सूचना के बिना विचाराधीन उत्पाद और जांचाधीन उत्पाद की आयात प्रवृत्ति प्रभावी रूप से हल नहीं की जा सकती क्योंकि वर्तमान में प्रस्तुत आंकड़े यह दर्शाने में विफल हैं कि चौड़ाई विशेष का कौन-सा उत्पाद आयात किया गया है और विचाराधीन उत्पाद पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की सही मायने में प्रवंचना कर रहे हैं:

- जांचाधीन उत्पाद असेंबल न किया गया, अपरिष्कृत और अपूर्ण रूप में नहीं है जिसके कारण पाटनरोधी नियमावली का नियम 25(1) वर्तमान जांच पर लागू नहीं होता।
- वर्तमान जांच कम से कम निर्यातक के विरुद्ध प्रवंचनारोधी कार्रवाई में रद्द की जानी चाहिए क्योंकि व्यापार के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
- याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप के अनुसार प्रवंचना गैर अर्थक्षम है क्योंकि याचिकाकर्ता अपने प्रवंचना के दावे को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य प्रदान नहीं कर पाए।
- जांचाधीन उत्पाद के आयात की मात्रा में वृद्धि जांचाधीन उत्पाद की खपत में वृद्धि के कारण है और जांचाधीन उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद में बदलने के लिए बांटने के कारण नहीं है।
- याचिकाकर्ता जांचाधीन उत्पाद के संबंध में प्रयोक्ता उद्योग की मांग पूरा करने में असमर्थ रहा है जिसके कारण वर्तमान जांच को समाप्त किया जाना चाहिए।

ठ. मैसर्स सनसिटी शीट्स प्रा. लि., मैसर्स सनसिटी स्ट्रिप्स एंड ट्यूब्स प्रा. लि., मैसर्स सनराइज स्टेनलेस प्रा. लि. और मैसर्स सनमार्क स्टेनलेस प्रा. लि. का प्रतिनिधित्व करने वाले मैसर्स जीटीसी कंसल्टेंट्स ने निम्नलिखित अनुरोध किया है:

- मैसर्स सनसिटी स्ट्रिप्स एंड ट्यूब्स प्रा. लि. ने चीन जन गण, मलेशिया और कोरिया गणराज्य से विचाराधीन उत्पाद को छोड़कर सीआरएसएस का आयात किया है। सीआरएसएस का चौड़ाई वार आयात निम्नलिखित है:

सनसिटी स्ट्रिप्स और ट्यूब्स प्रा. लि. का चौड़ाई-वार आयात

चीन			
वर्ष	चौड़ाई 0-600	600-1250 (टोलरेंस सहित)	1250 और उससे अधिक (टोलरेंस को छोड़कर)
	में मात्रा (मी. टन)	में मात्रा (मी. टन)	में मात्रा (मी. टन)
2008-09	लागू नहीं		
2009-10			
2010-11	****	-	-
2011-12	****	****	****
2012-13	****	****	****
2013-14	****	****	****
2014-15	****	****	****
2015-16	****	****	****
जुलाई, 14 से सितंबर, 15	****	****	****
मलेशिया			
वर्ष	चौड़ाई 0-600	600-1250 (टोलरेंस सहित)	1250 और उससे अधिक (टोलरेंस को छोड़कर)
	में मात्रा (मी. टन)	में मात्रा (मी. टन)	में मात्रा (मी. टन)
2008-09	लागू नहीं		
2009-10			
2010-11	-	-	-
2011-12	-	-	-
2012-13	-	-	****
2013-14	-	-	****
2014-15	-	-	****

2015-16	-	-	****
जुलाई, 14 से सितंबर, 15	-	-	****
कोरिया			
वर्ष	चौड़ाई 0-600	600-1250 (टोलरेंस सहित)	1250 और उससे अधिक (टोलरेंस को छोड़कर)
	में मात्रा (मी. टन)	में मात्रा (मी. टन)	में मात्रा (मी. टन)
2008-09	लागू नहीं		
2009-10			
2010-11	-	-	-
2011-12	-	-	-
2012-13	-	-	-
2013-14	-	-	-
2014-15	-	-	-
2015-16	-	-	****
जुलाई, 14 से सितंबर, 15	-	-	-

उपर्युक्त तालिका से यह नोट करना व्यावहारिक है कि मैसर्स सनसिटी स्ट्रिप्स एंड ट्यूब्स प्रा. लि. ने अपनी शुरुआत से विचाराधीन उत्पाद का आयात कभी नहीं किया है। अतः विचाराधीन उत्पाद की प्रवंचना मैसर्स सनसिटी स्ट्रिप्स एंड ट्यूब्स प्रा. लि. की ओर से आरोपित नहीं की जा सकती तथा चूंकि वे स्टेनलेस स्टील पाइपों के विनिर्माता हैं जिनमें सीआरएसएस मुख्य कच्ची सामग्री है। पाइपों के विनिर्माण के लिए उत्तरदायी को 400 एमएम से अधिक की चौड़ाई की आवश्यकता नहीं होती है न कि 600 एमएम से 1250 एमएम तक की।

- मैसर्स सनसिटी शीट्स प्रा. लि. ने 2012-13 में अपनी शुरुआत से विचाराधीन उत्पाद का आयात कभी नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उत्तरदायी ने केवल चीन जन गण से विचाराधीन उत्पाद को छोड़कर सीआरएसएस का ही आयात किया है। सीआरएसएस का चौड़ाई-वार आयात निम्नलिखित है:

सनसिटी शीट्स प्रा. लि. का चौड़ाई-वार आयात

वर्ष	चौड़ाई 0-600	600-1250 (टोलरेंस सहित)	1250 और उससे अधिक (टोलरेंस को छोड़कर)
	में मात्रा (मी. टन)	में मात्रा (मी. टन)	में मात्रा (मी. टन)
2008-09	लागू नहीं		

2009-10			
2010-11			
2011-12			
2012-13			
2013-14	****	****	****
2014-15	****	****	****
2015-16	****	****	****
जुलाई, 14 से सितंबर, 15	****	****	****

उपर्युक्त से यह नोट किया जा सकता है कि मैसर्स सनसिटी शीट्स प्रा. लि. ने अपनी शुरूआत से कभी भी विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। अतः विचाराधीन उत्पाद की प्रवंचना का आरोप उत्तरदायी पर नहीं लगाया जा सकता।

- क्षेत्राधिकार की पूर्व शर्तों को पूरा किए बिना यह विरोधी अधिसूचना जारी की गई है और यह पूर्णतः क्षेत्राधिकार रहित है। स्वाभाविक रूप से प्रवंचनारोधी कार्यवाहियां ऐसी हैं कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 25 में उल्लिखित आयातों की नई प्रवृत्ति को अधिसूचना के बाद ध्यान में रखा जाना चाहिए था जो कि अधिसूचना द्वारा लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना की मांग करते हैं। वर्तमान मामले में अंतिम अधिसूचना, जिसे प्रवंचनायुक्त होने का आरोप लगाया गया है, 16.12.2015 को ही जारी की गई थी और प्रवंचना के लिए आवेदन उस अधिसूचना के कुछ माह के भीतर दायर किया गया था। आवेदन पत्र किसी नए तथ्य अथवा आंकड़ों पर विश्वास नहीं करता तथा प्रकट करता है कि वर्तमान में विद्यमान आयात की प्रवृत्ति लंबे समय तक बनी रही है, अतः वर्तमान प्रवंचनारोधी जांचें समाप्त किए जाने योग्य हैं क्योंकि इनका कोई क्षेत्राधिकार नहीं है।
- पाटनरोधी नियमावली के नियम 25(1) में पाटनरोधी नियमावली के नियम 26 के तहत प्रवंचनारोधी जांच की शुरूआत के लिए संतुष्ट होने हेतु निम्नलिखित क्षेत्राधिकार संबंधी पूर्व शर्तों की अपेक्षा है।
 - किसी “वस्तु” को पाटनरोधी शुल्क में पहले ही होना चाहिए जो कि किसी भी देश से भारत में की जाती हो।
 - उपर्युक्त “वस्तु” को भारत में असेंबल न किए गए, अपरिष्कृत और अपूर्ण रूप में आयात किया जाना चाहिए और उसे भारत में असेंबल, परिष्कृत अथवा पूर्ण किया जाए।
 - असेंबलिंग, परिष्करण अथवा पूर्ण करने के उपर्युक्त प्रचालन पाटनरोधी जांच शुरू करने अथवा उससे ठीक पूर्व बंद होने पर तथा पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के प्रयोजन के लिए अधिसूचित निर्यात के देश अथवा मूल देश से हिस्से पुर्जे तथा घटक आयात किए जाते हैं; और
 - असेंबलिंग, परिष्करण अथवा पूर्ण करने के प्रचालन के परिणामस्वरूप मूल्य असेंबलड, परिष्कृत अथवा पूर्ण वस्तु की लागत का 35 प्रतिशत से कम हो।
- वर्तमान मामले में कोई भी उपर्युक्त शर्त पूरी नहीं है, जहां तक निम्नलिखित का संबंध है:

- 1250 एमएम से अधिक की चौड़ाई का सीआरएसएस पूर्णतः वस्तु की भिन्न श्रेणी है और यह निर्विवाद है कि उसे पाटनरोधी शुल्क के अध्वधीन नहीं रखा गया है तथा उसके विशिष्ट वाणिज्यिक प्रयोग हैं, अतः 1250 एमएम से अधिक की चौड़ाई के सीआरएसएस का कोई भी आयात उस “वस्तु” के आयात के रूप में नहीं माना जा सकता जो कि पाटनरोधी शुल्क के अध्वधीन है। अतः नियम 25(1) वर्तमान मामले पर किसी भी रूप में लागू नहीं होता।
- 1250 एमएम से अधिक की चौड़ाई के सीआरएसएस परिष्कृत सामान हैं और उनका आयात अनअसेंबलड, अपरिष्कृत अथवा अपूर्ण रूप में नहीं किया जाता है। इस संबंध में आवेदन पत्र में कोई आधार प्रकट नहीं किया गया है कि कार्यवाहियां शुरू करने के औचित्य के लिए यह शर्त प्रथम दृष्टया भी पूर्ण हो।
- 1250 एमएम से अधिक की चौड़ाई के सीआरएसएस के संबंध में भारत में असेंबलिंग, परिष्करण अथवा पूर्ण किए जाने की कोई प्रक्रिया नहीं की जाती है। भारत में आयातित सीआरएसएस परिष्कृत हालत में होते हैं और भारत में कोई और “असेंबलिंग”, “परिष्करण” अथवा “पूर्ण” करने का कार्य नहीं किया जाता है।
- किसी भी दशा में यह प्रचालन पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना के लिए पाटनरोधी जांचों के बाद अथवा ठीक पूर्व आरंभ अथवा बढ़े नहीं हैं:
 - इस एलडी प्राधिकारी के समक्ष दायर आवेदन पत्र के समर्थन में आवेदक द्वारा जिन आंकड़ों पर विश्वास किया गया, यह दर्शाते हैं कि सीआरएसएस के कुल आयात के 70 प्रतिशत से अधिक वर्ष 2010-2011 से आगे से 1250 एमएम से अधिक की चौड़ाई के थे।
 - कार्यवाही की शुरुआत के बाद आयात पैटर्न में कोई दर्शाने योग्य परिवर्तन नहीं है जिससे 12.10.2015 के अंतिम जांच परिणाम के अनुसरण में पाटनरोधी शुल्क लगाया गया। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि निर्णायक समीक्षा में 12.10.2015 के अंतिम जांच परिणाम, जिसके अनुसरण में दिनांक 16.12.2015 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 61/2015 जारी की गई थी, परिपूर्ण जांच थी। जैसा कि नियम 23(3) से भी सिद्ध है जिसमें नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18 और 20 के अनुसार पाटनरोधी नियमावली के तहत पूरी प्रक्रिया अपनाए जाने की अपेक्षा थी। यही वे कार्यवाहियां हैं जिन पर आवेदक ने अपने आवेदन में दावा किया है कि प्रवंचना की जा रही थी। अंतिम जांच परिणामों को जारी करने के बाद आयात पैटर्न में दर्शाने योग्य परिवर्तन, बताने वाले आंकड़े आवेदक द्वारा जांच की शुरुआत के औचित्य हेतु दायर किए गए हैं और जांच की शुरुआत इस बात की परीक्षण किए बिना आवेदन में विवरण केवल स्वीकार करके दिमाग न लगाकर की गई थी कि क्या जांच की शुरुआत के औचित्य हेतु क्षेत्राधिकार संबंधी शर्तें पूरी थीं।
- आवेदन पत्र में लगाए गए आरोप के अनुसार कोई असेंबलिंग, परिष्करण अथवा पूर्णतः का प्रचालन नहीं है, अतः ऐसे प्रचालन के परिणामस्वरूप मूल्य वर्धन का परीक्षण करने का प्रश्न ही नहीं उठता। अन्यथा भी बांटने के प्रचालन की लागत गलत होने के अलावा जांच की शुरुआत की अधिसूचना में जिस पर विश्वास किया गया है, पूर्व की कार्यवाहियों में जांच परिणामों के विपरीत हैं जिसमें इस एलडी प्राधिकारी ने स्वयं ही पाया था कि ऐसे प्रचालनों में भारी लागत शामिल है और उस अत्यधिक कीमत वाली सामग्री की भी हानियां हैं जो लगाई जाएंगी और जिससे ऐसे प्रचालन गैर अर्थक्षम होंगे (24.11.2009 के जांच परिणामों का पैरा 9)।

- पाटनरोधी नियमावली के नियम 25(1) में निहित क्षेत्राधिकार पूर्व शर्तों को वर्तमान मामले में पूर्ण नहीं किया गया है। सीमित पूछताछ में भी यह अनुरोध किया गया है कि वर्तमान कार्यवाहियों को रोक दिया जाए, वर्तमान मामले में किसी भी शुरुआत शब्द को पूरा नहीं किया गया है। यह एलडी प्राधिकारी के ऊपर है कि वे वर्तमान मामले में अन्य मुद्दों के संबंध में निर्णय लेने के लिए कार्यवाही से पूर्व क्षेत्राधिकार के प्रश्न की जांच करें, यदि कोई है। यह कानून की तय स्थिति है कि किसी मामले में औचित्य के आधार पर निर्णय देने से पूर्व क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दे पर निर्णय लिया जाना चाहिए। इस संबंध में भारत संघ ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय बनाम अदानी एक्सपोर्ट्स लि. 2001 (134) ईएलटी 596 (एससी) के निर्णय पर विश्वास किया गया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस आधार पर माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय को दरकिनार कर दिया कि गुजरात उच्च न्यायालय ने क्षेत्राधिकार मानकर औचित्य के आधार पर मामले में निर्णय देने की कार्रवाई की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना कि मामले के औचित्य में जाने से पूर्व एक प्राथमिक मुद्दे के मामले में पहले क्षेत्राधिकार के प्रश्न पर निर्णय लिया जाना चाहिए। विनम्र अनुरोध है कि वर्तमान मामले में भी यह एलडी प्राधिकारी वर्तमान मामले के औचित्य के संबंध में जांच परिणाम देने के बजाए प्राथमिक मुद्दे के रूप में क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर निर्णय लें।
- आवेदक द्वारा आपूर्ति किए गए आयात आंकड़े यह प्रकट करते हैं कि कार्यवाहियां शुरू किए जाने के बाद आयात पैटर्न में कोई दर्शाने योग्य परिवर्तन नहीं है जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 12.10.2015 के अंतिम जांच परिणामों के अनुसरण में पाटनरोधी शुल्क लगाया गया। इसके अतिरिक्त, 2015 से पूर्व की अवधि के लिए आवेदक द्वारा जिन आंकड़ों पर विश्वास किया गया, यह नोट करना व्यावहारिक है कि समय-समय पर आयात की मात्रा में साथ-साथ परिवर्तन हुए हैं जो कि जांचाधीन उत्पाद और विचाराधीन उत्पाद, दोनों के लिए सतत हैं।
- विचाराधीन उत्पाद के आयात की मात्रा में वृद्धि स्पष्ट रूप से स्वाभाविक दिखाई देती है और वह किसी तथाकथित प्रवंचना के कारण नहीं है:
 - जांचाधीन उत्पाद तथा विचाराधीन उत्पाद में समग्र/साथ-साथ वृद्धि हुई है।
 - गैर संबद्ध देशों से भी जांचाधीन उत्पाद के आयातों में वृद्धि हुई है।

अतः विचाराधीन उत्पाद के आयात के पैटर्न में कोई असामान्य परिवर्तन नहीं है और वृद्धि स्वाभाविक है।
- यह अनुरोध है कि अधिकतर आंकड़े, जो तथाकथित रूप से प्रवंचना का आरोप लगाने के लिए आधार हैं, आवेदक द्वारा बिना किसी तर्क के “गोपनीय” होने का दावा किया गया है और यह दावा बिना किसी औचित्य के है तथा इसके अतिरिक्त, पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के विपरीत भी है। यह अनुरोध है कि आवेदन से कोई आगामी स्पष्टीकरण नहीं है कि आवेदक का दावा क्यों स्वीकार किया जाए। यह अन्य बातों के साथ-साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, 2006 (194) ईएलटी 673 (एससी) के मामले में उल्लिखित कानून का तय सिद्धांत है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को सूचना की गोपनीयता के संबंध में पक्षकारों के दावे को स्वतः स्वीकार नहीं करना चाहिए तथा प्राधिकारी से उम्मीद की जाती है कि वे सूचना की प्रकृति के संबंध में अपना दिमाग लगाएं। वर्तमान मामले में, एलडी प्राधिकारी के समक्ष दायर आवेदन पत्र में आवेदक का “गोपनीयता का दावा” आधारहीन है और यह आयातक के अधिकारों का पूर्वाग्रह है तथा तदनुसार, ऐसे दावे को रद्द किया जाना चाहिए।
- यह अनुरोध है कि यह मुद्दा कि क्या 1250 एमएम से अधिक की चौड़ाई का सीआरएसएस वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय वस्तु है अथवा बांटने की प्रक्रिया आदि अर्थक्षम है, के संबंध में निर्णय पूर्व की जांचों में पहले ही ले लिया गया है। एक बार 1250 एमएम से अधिक की चौड़ाई के सीआरएसएस को इस एलडी प्राधिकारी द्वारा विस्तृत जांच परिणाम प्रदान करने सीआरएसएस पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के प्रयोजन के लिए स्पष्ट रूप से अलग कर दिया गया था तो आवेदक के लिए

यह खुली छूट नहीं है कि वे वर्तमान आवेदन की शह में समान मुद्दों को पुनः उकसाएं और पूर्व की जांचों में दिए गए जांच परिणामों को पुनः खोलने के लिए कहें जो कि विस्तृत साक्ष्यों और जांचों पर विचार करने के बाद दिए गए थे। विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में 1250 एमएम से अधिक की चौड़ाई के सीआरएसएस को शामिल करने के लिए आवेदक के अनुरोध को इस एलडी प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से बार-बार रद्द किया गया था और इस पहलू पर आवेदक द्वारा विवाद नहीं किया गया। पूर्व की जांचों के प्रत्येक स्तर पर जांच परिणामों को संक्षिप्तता के लिए यहां तालिका में दिया गया है:

पिछली जांचों का चरण-वार ब्यौरा

विवरण	जांच परिणाम
विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में 1250 एमएम से अधिक की चौड़ाई के सीआरएसएस को शामिल करने के लिए आवेदक के तर्क के संबंध में अंतिम जांच परिणामों की सिफारिश के साथ दिनांक 24.11.2009 की अधिसूचना संख्या 14/06/2008-डीजीएडी	<ul style="list-style-type: none"> अधिक चौड़ाई में विचाराधीन उत्पाद का आयात करने और फिर बांटने की प्रक्रिया करने से अपशिष्ट होगा और लागत अधिक होगी [पैरा 9]; प्रयोक्ता उद्योग मित्वययिता तथा प्रतिस्पर्द्धी बने रहने के लिए अंतिम प्रयोग के लिए लगभग वास्तविक लंबाई में आयात करता है [पैरा 9]; आयात आंकड़ों और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना का विश्लेषण अधिक चौड़ाई की प्लेटों के आयात की काफी मात्रा दर्शाता है [पैरा 10]; अधिक चौड़ाई की प्लेटों की कीमत कम चौड़ाई की सामग्री से अधिक है [पैरा 10]; यहां तक कि उपभोक्ताओं के लिए शीट को कम चौड़ाई की प्लेटों में काटना तकनीकी रूप से व्यावहार्य हो सकता है। तथापि, यह सिद्ध नहीं किया गया है कि वह वाणिज्यिक रूप से तथा तकनीकी रूप से व्यवहार्य है [पैरा 10]; यह सिद्ध करने के लिए उत्पाद की तकनीकी एवं वाणिज्यिक प्रतिस्थापनीयता, दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा पेश किया गया उत्पाद आयातित उत्पादों की वास्तव में समान वस्तु है [पैरा 10]; प्राधिकारी 1250 एमएम (चौड़ाई) तक विचाराधीन उत्पाद का प्रतिबंध बनाए रखते हैं क्योंकि 1250 एमएम से अधिक की चौड़ाई की वास्तविक आपूर्ति का कोई प्रमाण घरेलू उद्योग द्वारा नहीं दिया गया है [पैरा 12.2क]
अंतिम जांच परिणाम संख्या 14/06/2008-डीजीएडी दिनांक 24.11.2009 के संबंध में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के 08.10.2010 के अनुसरण में दिनांक 05.12.2011 का आदेश	<ul style="list-style-type: none"> यद्यपि घरेलू उद्योग द्वारा यह दावा किया गया है कि अधिक चौड़ाई वाले सामान को कम चौड़ाई वाले सामान में बांटना तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य है। तथापि, यह सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य रिकार्ड में नहीं रखा गया है कि यह कम चौड़ाई वाले सामान को अधिक चौड़ाई वाले सामान में बदलने के लिए तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य है [पैरा ट]; यहां तक कि यदि बांटेकर के अधिक चौड़ाई वाले कम चौड़ाई वाले सामान में प्रतिस्थापित करने का दावा स्वीकार किया जाता है तो एक-दूसरे के विपरीत उसे सिद्ध नहीं किया जा सकता [पैरा ट]; 1250 एमएम से अधिक की चौड़ाई के संबद्ध सामान पाटनरोधी शुल्क की परिधि से सही हटाए गए हैं [पैरा 21क]।
दिनांक 12.10.2015 की अधिसूचना संख्या 15/04/2024-डीजीएडी द्वारा	<ul style="list-style-type: none"> इसके अतिरिक्त, यह पाया गया है कि इस मामले में अंतिम जांच परिणाम में परिभाषित किए गए अनुसार और बाद की समीक्षाओं में यथासंशोधित उत्पाद के

निर्णायक समीक्षा के अंतिम जांच परिणाम	<p>क्षेत्र के लिए समीक्षा शुरू की गई। घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र की समीक्षा के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया, जैसा कि उसने 2011 में किया था [पैरा 27];</p> <ul style="list-style-type: none"> • प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में हटाए गए ग्रेडों को शामिल करने के लिए घरेलू उद्योग के तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते [पैरा 27].
---------------------------------------	--

- उपर्युक्त तालिकाबद्ध जांच परिणामों के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि स्पष्ट जांच परिणाम के निमित्त निम्नलिखित मुद्दे अंतिम स्तर तक पहुँच गए हैं:
 - 1250 एमएम की चौड़ाई के सीआरएसएस 1250 एमएम से कम की चौड़ाई वाले सीआरएसएस के साथ तकनीकी अथवा वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय नहीं है; और
 - कम चौड़ाई के सीआरएसएस का विनिर्माण करने के लिए 1250 एमएम से अधिक के सीआरएसएस को बांटना वाणिज्यिक रूप से और आर्थिक रूप से अर्थक्षम नहीं है।

उपर्युक्त जांच परिणाम आयात आंकड़ों तथा विस्तृत जांचों के आधार पर दे दिए जाने के बाद यह विनम्र अनुरोध है कि समान मुद्दों को पुनः उकसाने के लिए और अधिक अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जबकि आवेदक एलडी प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणाम के विरुद्ध सेसटेट, नई दिल्ली के समक्ष सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9g के तहत अपील दायर की है जिसके अनुसार 1250 एमएम से अधिक की चौड़ाई के सीआरएसएस को पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के प्रयोजन से विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर कर दिया गया था।

- ड. जांचाधीन उत्पाद के मुद्दे की जांच पूर्व की मुख्य जांच और परीक्षण में पहले ही की जा चुकी है, अतः इसे रद्द किया जाए।
- ढ. याचिका के एनसीवी रूपांतर में प्रयोग के पैटर्न संबंधी आंकड़े नहीं दिए गए हैं जो कि एक अच्छी समझ नहीं बताता।
- ण. जांच की शुरुआत कानूनी आधार नहीं है क्योंकि जांचाधीन उत्पाद असेंबल, परिष्कृत और पूर्ण रूप में है।
- त. आवेदन में आरोप लगाया गया है कि यह दर्शाने के लिए साक्ष्य हैं कि 1250 एमएम से अधिक की चौड़ाई के आयातों का केवल लगभग 3 प्रतिशत उपयुक्त उपयोग में जा रहा है और शेष आयात का 97 प्रतिशत बांटने के बाद ही प्रयुक्त किया जाता है। आवेदक ने यह भी आरोप लगाया है कि जांचाधीन उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद में बदलने के लिए अपेक्षित मूल्य वर्धन 35 प्रतिशत की शुरुआती सीमा से कम है और यह भी आरोप है कि उपर्युक्त प्रक्रिया के कारण व्यापार के परिकलन में परिवर्तन है। ये दावे सिद्ध नहीं हैं।
- थ. कार्यवाहियों की शुरुआत के बाद व्यापार के पैटर्न में कोई दर्शाने योग्य परिवर्तन नहीं है जो 12.10.2015 के अंतिम जांच परिणाम में चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया होगा।
- द. जांचाधीन उत्पाद में उभार एक सामान्य वृद्धि प्रवृत्ति है और वस्तुतः स्टेनलेस स्टील फ्लेट उत्पादों का आयात 2013-14 में 324460 मी. टन से बढ़कर 2015-16 में 532033 मी. टन हो गया।
- ध. संबद्ध देशों से आयात की मात्रा की जांच अलग-अलग की जाए न कि संचयी रूप से।
- न. मुख्य व्यापारियों ने अनुरोध किया है कि जांचाधीन उत्पादों की बिक्री करने से पूर्व उनका कोई प्रसंस्करण अथवा बांटने का कार्य नहीं किया गया है।
- प. अधिक चौड़ाई का आयात करना और बांटना मितव्ययी नहीं है क्योंकि इससे लागत में 15-20 प्रतिशत जुड़ जाता है जबकि विचाराधीन उत्पाद (600-1250 एमएम) आसानी से घरेलू उद्योग में उपलब्ध है।

फ. मैसर्स मेटल एंड स्टेनलेस स्टील मर्चेण्ट्स एसोसिएशन, जिनकी 5000 से अधिक व्यापारिक कंपनियां उनके सदस्य हैं, ने भारी संख्या में अपने सदस्यों की ओर से निम्नलिखित रूप में अनुरोध दायर किए हैं:

- मैसर्स मेटल एंड स्टेनलेस स्टील मर्चेण्ट्स एसोसिएशन के अनुरोध दिनांक 23.06.2016 को दायर किए गए। हमारे 5000 से अधिक व्यापारी/निर्यातक/आयातक और विनिर्माता सदस्य हैं तथा मुंबई में मेटल और स्टेनलेस स्टील के विभिन्न उत्पादों के व्यापार में लगे हुए हैं। हमारे सदस्यों की लगभग 5000 दुकानें और स्थापनाएं हैं।
- सदस्यों ने जांचाधीन उत्पाद के संबंध में कोई बांटने का क्रियाकलाप नहीं किया है और यह कि बांटने की लागत पर ऐसा करना अर्थक्षम नहीं होगा क्योंकि वह स्थानीय केंद्र के लिए 10 रुपए से 15 रुपए है।
- घरेलू उद्योग पाटनरोधी समीक्षा शुल्क आदि के नए मामलों के साथ पिछले 10-12 वर्ष से बार-बार आवेदन पत्र दे रहा है। मैसर्स जिंदल स्टेनलेस लि. का आपूर्ति और कीमत ताकत को नियंत्रित करने में 85 प्रतिशत बाजार हिस्से पर एकाधिकार है। स्टेनलेस स्टील की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में कृत्रिम रूप से रखी जाती हैं क्योंकि अब कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है।
- घरेलू प्रयोक्ता उद्योग में लघु एकक/एसएमई/एमएसएमई हैं और कच्ची सामग्री की लागत (स्टेनलेस फ्लेट उत्पाद) की अधिक लागत के कारण व्यापार/वितरण के सीमित संसाधनों के कारण नुकसान हो रहा है। घरेलू प्रयोक्ता उद्योग के विनिर्माण क्रियाकलापों में भारी मात्रा में कमी आ रही है जिनमें शामिल हैं: किचनवेयर, कैटलरी, कुकवेयर, होम एप्लियेंसेस विनिर्माण (सिंक, वाशिंग मशीन, गीजर, चिमनी, हॉब्स; वेल्डेड पाइप और ट्यूब विनिर्माण; बिल्डिंग हार्डवेयर, फिटिंग, रेलिंग एवं एसेसरीज; इंडस्ट्रियल टैंक, वेसेल, हीट एक्सचेंजर, बॉयलर; फार्मा मशीनरी एवं लैब उपस्कर; एलीवेटर और एस्केलेटर्स; विभिन्न इंजीनियरी उपस्कर तथा मशीनें; मिल्क डेयरी एवं खाद्य उद्योग के उपस्कर; ऑटोमोबाइल उद्योग और उनके पुर्जों की आपूर्तियां, टूल्स, कार्यालय आपूर्तियां, ब्लेड्स, कैची, उपहार एवं एसेसरीज, भारी इंजीनियरी, विद्युत संयंत्र, पेट्रोकेमिकल एवं फर्टीलाइजर इंडस्ट्रीज; जल शोधन संयंत्र, पंप और वाटर टैंक, रेलवे, शिप बिल्डिंग; विभिन्न अन्य बहुत ही छोटे पैमाने के यूनिट।
- कच्ची सामग्री की उच्च लागत तथा आकार, फिनिश और मोटाई में विभिन्न प्रकार की अनुपलब्धता के कारण उपर्युक्त उत्पाद के भारतीय विनिर्माताओं के बंद होने की कीमत पर पिछले 5-7 वर्षों में उपर्युक्त परिष्कृत वस्तुओं का आयात स्वतः निरंतर बढ़ गया है।
- स्टेनलेस स्टील फ्लेट उत्पाद की कीमत अन्य देशों में लगभग 20 से 30 प्रतिशत कम है।
- विदेशी विनिर्माताओं के पास फिनिश, थिकनेस और चौड़ाई, कम अपशिष्ट, समय पर सुपुर्दगी, कम लागत वाली सामग्री आदि के व्यापक रेंज वाले स्रोतों की आसान पहुँच है जो उन्हें अधिक दक्ष होने में सहायता करते हैं।
- परिष्कृत वस्तुएं भारत में आयात करना अपने-आप में लागत में सस्ता और बेहतर गुणवत्ता तथा फिनिश में अच्छे हैं।
- एक तरफ मुक्त व्यापार करार के तहत रियायती आयात शुल्क के साथ नए-नए विकसित डिजाइन, फिनिश और कम लागत वाले सामान भारतीय बाजार में बाढ़ की तरह बढ़ाए जा रहे हैं। दूसरी ओर, घरेलू विनिर्माताओं के पास कृत्रिम रूप से अधिक कीमतों पर उनके आधारभूत कच्ची सामग्री तथा सीमित आपूर्ति श्रृंखला के संसाधनों के क्षेत्र में एकाधिकार रह जाता है।

- एसटीएस रेलिंग पाइप, वेल्डेड ट्यूब और पाइप यहां उत्पादित करने के बजाए आयात करने में सस्ते हैं; कुकवेयर, किचनवेयर, फ्लास्क और हार्ड एंड कैटलरीज का आयात भारत में बढ़ रहा है; हेवी इंजीनियरी यूनाइटेड्स भारत से बाहर स्थापित हैं (मिडिल ईस्ट); आयातित बिल्डिंग हार्डवेयर, एसेसरीज भारत की अपेक्षा लागत एवं बेहतर फिनिश में सस्ते हैं; एलीवेटर और उसके हिस्से पुर्जे अब भारत में आयात किए जाते हैं तथा भारत में केवल असेंबलिंग और सर्विसिंग का कार्य किया जाता है।
- हमारे विनिर्माता नीचे जा रहे हैं, पिछले कुछ वर्षों में बढ़ नहीं पाए, अतः कोई नए निवेश नहीं दिखाए दिए, उनमें से कुछ अब परिष्कृत वस्तुओं का आयात कर रहे हैं और उनका विपणन कर रहे हैं। शेष या तो बंद हो जाएंगे या दिवालिया हो जाएंगे।
भारतीय वितरक एवं आपूर्ति श्रृंखला सेवा पिछले कुछ वर्षों में विकास नहीं कर पाई है, लगभग पंगु हो गए हैं और सेवा उन्मुख व्यापार से अब सट्टा व्यापार की ओर जा रहे हैं।
- व्यापार/वितरक से महत्वपूर्ण सेवा उपर्युक्त प्रयोक्ता उद्योग को उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वैराइटी की रेंज सीमित मात्रा में उपलब्ध है (चौड़ाई, थिकनेस, फिनिश, डीडीक्यू आदि), अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमतों की तुलना में अधिक उच्च कीमतें, कमी तथा समय पर सुपुर्दगी में कठिनाईयां इस समस्या को और अधिक बढ़ा देती हैं।
यही मुख्य कारण है कि भारतीय विनिर्माता अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढत को खो रहे हैं। सरकार को चाहिए कि वह गैर प्रतिस्पर्द्धी स्रोतों से उच्च कीमतों पर सामग्री खरीद कर उन्हें पंगु न बनाकर लघु एवं मध्यम विनिर्माताओं के हित की सुरक्षा करे।
- प्रवंचनारोधी शुल्क के आवेदन का सत्यापन एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार परिपाटी अधिनियम, 1969 के अध्यधीन किया जाना चाहिए। जिंदल स्टेनलेस स्टील ही एक मात्र ऐसा विनिर्माता है जिसके पास भारत में पूर्णतः एकीकृत संयंत्र है, जो 200, 300 और 400 सीरीज के सीआर फ्लेट प्रोडक्ट्स ऑफ स्टेनलेस स्टील का विनिर्माण कर रहा है। जिंदल स्टेनलेस स्टील (जिंदल स्टेनलेस (हिसार) और ओडिशा यूनिटों) द्वारा 85 प्रतिशत बाजार हिस्से पर नियंत्रण किया जा रहा है और उसका कई आकारों के ग्रेडों के 100 प्रतिशत नियंत्रित एवं एकाधिकार है।
- भारत में गैर विनिर्मित उत्पाद को भी पाटनरोधी में शामिल किया गया है:
200, 300 और 400 सीरीज में 1000 एमएम, 1250 एमएम और 1500 एमएम की चौड़ाई में ब्राइट अनील्ड सीआर स्टेनलेस स्टील कॉइल एवं शीट को पाटनरोधी शुल्क में शामिल किया गया था। फिर भी भारत में किसी विनिर्माता द्वारा उत्पादित नहीं किया जा रहा है।
“बीए” सरफेस स्टेनलेस स्टील शाइनिंग सरफेस फिनिश, लागत बचत और समय के कारण सामान्य सीआर 2बी स्टेनलेस स्टील में ज्यादा प्रमुख है क्योंकि किचनवेयर, कुकवेयर, कैटलरी, सिंक, पाइप और ट्यूब, एलीवेटर, होम एप्लीयंसेस में प्रयुक्त हाथ से पॉलिश करने की आवश्यकता नहीं होती है।
बीए फिनिश स्टेनलेस स्टील की अनुपलब्धता के कारण हम अब भी पारंपरिक पॉलिसिंग के साथ 2बी सरफेस का प्रयोग कर रहे हैं जो कि असमान है और जिसमें मैन्युअल तथा लेबर लगती है; प्रक्रिया में समय लगने के कारण कुल उत्पादन कम होता है; लागत बढ़ती है तथा रद्द होने की मात्राएं अधिक होती हैं; निर्यात आदेश खो जाते हैं और

ग्राहक भी समाप्त हो जाते हैं जबकि बीए फिनिश अनिवार्य है; और बीए फिनिश से बनी विदेशी परिष्कृत वस्तुओं का आयात बढ़ गया था।

प्राधिकारी को तथ्यों का सत्यापन करना चाहिए और बीए फिनिश में कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील सभी मामलों में पाटनरोधी शुल्कों के क्षेत्र से हटा दिया जाना चाहिए।

- स्टेनलेस स्टील शीट – सतह का शोधन किया गया – पॉलिश की गई (डिकोरेविट टीआई कलर, ऐच पैटर्न, पॉलिश मिरर सरफेस) ये सब अत्यधिक तकनीकी रूप से अपेक्षित उत्पाद हैं और इनका प्रयोग एलीवेटरों, एस्केलेटरों, होटलों/कार्यालयों के प्रवेश द्वार, लॉबियों, नामपट्टों आदि में अनिवार्य रूप से किया जाता है, इसे पाटनरोधी में शामिल किया गया था।
- 0.50 एमएम और उससे कम की मोटाई (0.20 एमएम, 0.30 एमएम, 0.40 एमएम आदि) में स्टेनलेस स्टील सीआर कॉइल्स एंड शीट्स 1000 एमएम, 1220 एमएम की चौड़ाई में उपलब्ध नहीं हैं, अतः उसे भी पाटनरोधी में शामिल किया गया।
- चेकर्ड/टियर ड्रॉप/एंटी स्लिप और अन्य ट्रीटेड स्टेनलेस स्टील को फ्लोर प्लेटों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि भारत में उपलब्ध नहीं है।
- प्रवंचना पूर्णतः गैर अर्थक्षम और आधारहीन है।
- कट लेथ शीट को बांटा नहीं जा सकता, वे प्रयोग के लिए तैयार हैं। उन्हें आपूर्ति की गई लंबाई में काटा जाता है और आयात किया जाता है। अतः इसे जांच की शुरुआत से बाहर किया जाना चाहिए।
- विश्वव्यापी मानक चौड़ाई 1220 एमएम, 1250 एमएम, 1500 एमएम, 2000 एमएम है। 1500 एमएम, 2000 एमएम की कीमत हमेशा 3-7 प्रतिशत तक अधिक रहती है। कम चौड़ाई में बांटने में अतिरिक्त कार्य भार परिवहन, कटिंग खर्च और 10-20 प्रतिशत अपशिष्ट/कचरा शामिल होता है।
- 3-7 प्रतिशत अधिक कीमत वाली कॉइलों को कम कीमत वाली कॉइलों + 10-20 प्रतिशत तक कचरा पैदा करने + बांटने, पुनः पैकिंग, लदान और परिवहन जैसे खर्च करना एक मितव्ययी भाव नहीं है। इससे कुल लागत लगभग 20-25 प्रतिशत तक बढ़ेगी।
- ग्राहक राजा होता है, ग्राहक की आवश्यकता ग्राहक की इच्छा तकनीकी परिवर्तन तथा नवाचार, गुणवत्ता नियंत्रण पर निर्भर करते हुए बदलती रहती है। हमें उसकी आपूर्ति करनी होती है जिसकी ग्राहक को आवश्यकता होती है।
- कुल आयात मात्रा कम हो रही है और पाटनरोधी उत्पाद का आयात (सीआर स्टेनलेस फ्लेट प्रोडक्ट 600 एमएम – 1200 एमएम की चौड़ाई) लगभग 70 प्रतिशत तक कम हुआ है जो 2008-09 में 53240 टन था, वह 2014-15 में 18437 टन हो गया। वस्तुतः इसे प्रतिवर्ष 8-10 प्रतिशत के औसत से बढ़ना चाहिए था और प्रयोक्ता उद्योग की कीमत प्रतिस्पर्द्धात्मकता तथा वृद्धि को बनाए रखने के लिए 80000-100000 टन तक पहुँच जाना चाहिए था।
- प्रवंचनारोधी मामला एक बड़े पैमाने के आयातक 7 सर्विस सेंटर – पोसको इंडिया सर्विस सेंटर 400 सीरीज के लिए – ऑटोमोबाइल ग्रेड स्टेनलेस स्टील पर आधारित है।
- चूंकि ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए 600 एमएम से कम चौड़ाई में 400 सीरीज की कॉइलों का प्रसंस्करण किया जाता है, अतः 11.12.2015 की अधिसूचना संख्या 61/2015-सीमा शुल्क के तहत 600 एमएम – 1200 एमएम के

लिए सीआर स्टेनलेस फ्लेट प्रोडक्ट में 200, 300, 400 सीरीज के सभी ग्रेडों के लिए प्रवंचनारोधी शुल्क लगाए जाने का कोई तर्क नहीं है।

- राजस्व और वृद्धि पर बहुपक्षीय दबाव: स्टेनलेस स्टील हाई एंड बॉचेस, सेलफोन, एलईडी टीवी अथवा लग्जरी कार या अन्य लग्जरी ग्राहक सामानों जैसी विलासिता की वस्तुएं नहीं हैं।
- स्टेनलेस स्टील उद्योग के लिए कच्ची सामग्री है - खरीद एवं भंडारण, डि-कॉइलिंग, कटिंग, सिल्टिंग, पॉलिशिंग, बेयर हाउसिंग, खुदरा बिक्री के लिए होलसेल वितरण, पूरे भारत में अंतिम उपभोक्ता के लिए आपूर्ति विश्व व्यापी ग्राहक के लिए निर्यात, शिपिंग और परिवहन इसमें शामिल हैं।
- इसके अतिरिक्त, यह 100 प्रतिशत रिसाइकिल किया जा सकता है तथा इसके कचरे को पिघलाकर तथा नया स्टेनलेस स्टील बनाकर पुनः प्रयोग किया जा सकता है। अतः प्रवंचनारोधी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

- ब. मैसर्स एन. जी. इंडस्ट्रीज, मैसर्स एन. पी. इंडस्ट्रीज और मैसर्स श्री रामदेव मेटल मार्ट का प्रतिनिधित्व करने वाली मैसर्स अगोल एसोसिएट्स ने अनुरोध किया है कि इन कंपनियों ने जांच की अवधि के दौरान उत्पाद की कोई बांटने की प्रक्रिया नहीं की है और सभी मात्राएं बिना किसी बंटवाई/परिवर्तन प्रक्रिया के बेची गई हैं।
- भ. जब 1250 एमएम से अधिक चौड़ाई के उत्पाद को बांटने में किए गए खर्च की तुलना की जाए, तो 600 एमएम से 1200 एमएम के बीच की चौड़ाई वाली सामग्री की लागत कम है और वह घरेलू तथा विदेशी बाजार में आसानी से उपलब्ध है। बांटने की सामान्य लागत किसी सामान्य छोटे स्थानीय सेवा केंद्र में 1 रुपए प्रति किलोग्राम है, परंतु मैसर्स पोसको का सेवा केंद्र 3 रुपए प्रति किलोग्राम लगाता है। इसके अतिरिक्त, यदि बांटने का काम किया जाता है तो कचरा काफी मात्रा में पैदा हो जाता है।
- म. मैसर्स ऑल इंडिया स्टेनलेस स्टील इम्पोर्टर्स एसोसिएशन, जो मेटल्स एंड स्टेनलेस स्टील मर्चेण्ट्स एसोसिएशन के एक भाग के रूप में सदस्य है, के सदस्यों ने भी मेटल्स एंड स्टेनलेस स्टील मर्चेण्ट्स एसोसिएशन द्वारा किए गए अनुरोधों को दोहराया है।
- य. पोसको अपना अधिकतम उत्पादन और वितरण करने के लिए अधिक चौड़ाई का निर्यात कर रहा है। जांचाधीन उत्पाद का 80 प्रतिशत 600 एमएम से कम बेचा जाता है और उसका केवल 20 प्रतिशत विचाराधीन उत्पाद के रूप में बेचा जाता है।
- कक. सभी जांचाधीन उत्पाद शीट और कॉइलों में लंबाई में काटे गए रूप में प्रयोग किया जाता है। कुछ आयातकों ने यह उल्लेख किया है कि वे कई वर्षों से बड़े साइज की चौड़ाई का आयात कर रहे हैं।
- खख. कोरिया के लिए मैसर्स शारदा मोटर्स इंडस्ट्रीज लि. ने भी उल्लेख किया है कि ऑटोमोबाइल एक्जोस्ट बनाने के लिए कोरिया से आयातित कोल्ड रोलड स्टेनलेस स्टील (सीआरएसएस) स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं है और साथ ही घरेलू आपूर्तिकर्ता का उत्पाद अनुमोदित नहीं है तथा उनके परीक्षण विफल रहे हैं। अतः ऐसे आयातों पर प्रवंचनारोधी शुल्क न लगाया जाए।
- गग. मैसर्स फॉरेसिया एमिशन कंट्रोल टैक्रोलॉजीस ने उल्लेख किया है कि ऑटोमोटिव एक्जोस्ट प्रणालियां स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं हैं और न ही उनमें गुणवत्ता है जो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करे तथा साथ ही आपूर्ति के मुद्दे भी हैं। अतः ऑटोमोटिव एक्जोस्ट प्रणाली के लिए सीआरएसएस पर प्रवंचनारोधी शुल्क न लगाया जाए।
- घघ. मैसर्स रिलायंस फैब्रिकेशन्स प्रा. लि. ने उल्लेख किया है कि उन्होंने कहा है कि वे 1250 से अधिक चौड़ाई का इस्तेमाल करते हैं और 1250 एमएम से अधिक पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

- डड. मैसर्स रेमी एडल्सटाही ट्यूबलर्स ने उल्लेख किया है कि उन्हें अधिक डायमीटर वाले पाइपों के लिए 1250 एमएम से अधिक की कॉइलों की आवश्यकता होती है, इनका प्रयोग बिना बांटे किया जाता है। प्रौद्योगिकीय मितव्ययिता के लिए इन आकारों का आयात किया जाता है।
- चच. मैसर्स नेक्सस इम्पैक्स ने दोषपूर्ण जांच की शुरुआत के संबंध में कानूनी अनुरूप दोहराते हुए कहा कि बांटने के कारण कोई प्रवंचना नहीं है और कहा कि बांटने की लागत सामान्यतः स्थानीय केंद्र में 1 रुपए प्रति किलो है और पोसको केंद्र में 3 रुपए प्रति किलो है। घरेलू उद्योग के उनकी कंपनियों में ब्रोशर/व्यवसायिक सामग्री में स्वीकार किया गया कि अधिक चौड़ाई की आवश्यकता बढ़ रही है।
- छछ. प्रयोक्ता उद्योग को अधिकतर अधिक चौड़ाई के आयात जैसे थाइसनकूप/चिंडलर/सुलजर/कोच केमिकल/फ्रांस फेबर बिना बांटे अथवा काटे बेचे जाते हैं।
- जज. अधिक चौड़ाई वाली शीटों से डेयरी टैंक/रासायनिक उपस्करों/एलीवेटरों/तेल एवं गैस तथा ऑटोमोबाइल क्षेत्र में बेहतर उत्पादन होता है।
- झझ. पोसको से आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। याचिकाकर्ता को हुई हानियां उनकी अदक्षताओं के कारण हैं। इसकी जांच की गई है तथा महानिदेशक, सुरक्षा द्वारा प्रकाशित भी किया गया है।
- ञञ. प्रवंचनारोधी शुल्क लगाए जाने से मेक इन इंडिया कार्यक्रम प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा।
- टट. यूरोपीय संघ से जांचाधीन उत्पाद पर शुल्क बढ़ाने की शर्तें पूरी नहीं की जाती हैं क्योंकि यूरोपीय संघ से जांचाधीन उत्पाद का आयात 2009 से 10 प्रतिशत तक कम हुआ है। यहां तक कि यदि कई निर्यातक, उत्पादकों ने इन उपायों की प्रवंचना की है तो सभी देशों को जांचाधीन उत्पाद पर उपाय प्रदान करना उपयुक्त नहीं होगा।

घरेलू उद्योग के विचार

56. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. हितबद्ध पक्षकार यह मानने में विफल रहे हैं कि “अनअसेंबल्ड, अनफिनिस्ड अथवा इनकम्प्लीट फॉर्म” शब्दों का निर्वचन इस तथ्य के संदर्भ में किया जाना है कि क्या ये उत्पाद “असेंबलिंग, फिनिशिंग अथवा कंपलीशन” के रूप में ओर प्रचालन चाहते हैं। एक बार जब आयातित सामान अंतिम रूप से प्रयोग किए जाने से पूर्व भारत में कुछ प्रचालनों के अध्वधीन है तो यह नहीं कहा जा सकता कि आयातित सामान परिष्कृत थे अथवा पूर्ण थे। यह भी अनुरोध है कि जांचाधीन उत्पाद “पूर्ण” अथवा “परिष्कृत” उत्पाद नहीं होंगे, यदि उन्हें प्रयोग में लाने से पूर्व “स्लिटिंग” की अगली प्रक्रिया की आवश्यकता हो और वह भी जब स्लिटिंग की पूर्ण प्रक्रिया 1250 एमएम चौड़ाई से कम की वस्तुओं पर माननीय प्राधिकारी द्वारा लगाए गए पाटनरोधी शुल्कों से बचने के प्रयोजन के लिए शुद्धतः और पूर्णतः की गई हो।
- ख. कोरिया, पोसको के उत्पादक/निर्यातक ने स्वीकार किया है कि 80 प्रतिशत व्यापक चौड़ाई वाले आयात कम चौड़ाई वाले सामानों में बांटे जा रहे हैं। तथापि, उत्पादक/निर्यातक मौखिक सुनवाई के दौरान माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उल्लिखित पत्र की इनपुट पैटर्न में परिवर्तन क्यों किया गया, का उत्तर देने में विफल रहे हैं। घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि प्रवंचनारोधी जांच में कानून के तहत यह जांच किए जाने की आवश्यकता है कि क्या मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों से बचने के लिए आयात पैटर्न में परिवर्तन किए गए हैं। पोसको के अपने अनुरोधों से यह स्पष्ट है कि वे जांचाधीन उत्पाद को कम चौड़ाई के उत्पाद में बांटना स्वीकार कर रहे हैं। यहां तक कि मान रहे हैं परंतु स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से पूर्व 600 एमएम से कम की चौड़ाई प्राप्त करने के लिए

स्लिटिंग कार्य किए गए थे। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने कोई औचित्य पेश नहीं किया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद ही विचाराधीन उत्पाद से जांचाधीन उत्पाद के आयात पैटर्न में परिवर्तन क्यों किया गया है।

- ग. यह सिद्ध है कि व्यापार के पैटर्न में अथवा अनुप्रयोगों में कोई परिवर्तन नहीं है जो पाटनरोधी शुल्कों की प्रवंचना को छोड़कर कम चौड़ाई वाले (विचाराधीन उत्पाद) से अधिक चौड़ाई वाले (जांचाधीन उत्पाद) में आयात के पैटर्न में पूर्ण परिवर्तन को औचित्यपूर्ण बता सके। तथापि, कोई भी हितबद्ध पक्षकार आयात के परिवर्तित पैटर्न के संदर्भ में पाटनरोधी शुल्कों से बचने के अलावा, कोई विश्वसनीय आर्थिक औचित्य देने में सफल नहीं रहा है। घरेलू उद्योग के अनुसार जो देश पाटनरोधी शुल्कों के अध्यक्षीन नहीं हैं, उनसे विचाराधीन उत्पाद और जांचाधीन उत्पाद का अनुपात समान रहा। जैसा कि वह पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से पूर्व था। तथापि, संबद्ध देशों के लिए विचाराधीन उत्पाद और जांचाधीन उत्पाद के आयात का अनुपात ऐसे तरीके से परिवर्तित हुआ कि पाटनरोधी शुल्कों की पूर्ण रूप से प्रवंचना हुई। यह बात पाटनरोधी शुल्कों की प्रवंचना को पूर्णतः निस्सन्देह सिद्ध करती है।
- घ. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि ओडिशा संयंत्र के प्रचालनों के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क कि वह पहले जांचाधीन उत्पाद का प्रमुख रूप से उत्पादन करता था, गलत है। रिकार्ड में पहले से ही उपलब्ध सूचना से यह देखा जा सकता है कि ओडिशा में अधिक चौड़ाई का उत्पादन करने की क्षमता रखने के बावजूद अधिकतर बिक्री जांचाधीन उत्पाद के क्षेत्र में की गई जो स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है कि अकेले जांचाधीन उत्पाद की मांग में उभार नहीं आया है, जैसा कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पेश किए जाने का प्रयास किया जा रहा है।
- ङ. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि गैर संबद्ध देशों से आयात के विचाराधीन उत्पाद और जांचाधीन उत्पाद के बीच का अनुपात घरेलू उद्योग के बिक्री पैटर्न के समान है। घरेलू उद्योग के अनुसार यह तथ्य निस्सन्देह सिद्ध करते हैं कि केवल संबद्ध देशों से पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद जांचाधीन उत्पाद के पक्ष में आयात का अनुपात परिवर्तित हुआ है। एक मात्र अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि बेईमान निर्यातकों और आयातकों ने विचाराधीन उत्पाद पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना का सहारा लिया है।
- च. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि हितबद्ध पक्षकार यह उल्लेख कर प्राधिकारी को एक बार फिर से भ्रम में डाल रहे हैं कि प्रवंचना प्रक्रिया वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम नहीं है। उन्होंने अनुरोध किया कि रिकार्ड में उपलब्ध सामग्री के अनुसार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जांचाधीन उत्पाद की स्लिटिंग की पूरी प्रक्रिया में 2 प्रतिशत से 3 प्रतिशत तक की रेंज में लागत की आवश्यकता होती है जो कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों की तुलना में न्यूनतम है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने आंकड़ों का सत्यापन किया है।
- छ. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क कि प्रवंचनारोधी प्रावधान लागू करने के लिए जो वस्तु आयातित की जा रही है, उसे पाटनरोधी शुल्क के अध्यक्षीन होना चाहिए, पूर्णतः गलत रखा गया है और उसका कोई औचित्य नहीं बनता। यह भी अनुरोध किया गया है कि यदि इस प्रावधान को हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तावित तरीके से पढ़ा जाए तो यह पूरे कानून को घिसा-पिटा बना देगा क्योंकि यदि संबंधित सामान पहले से ही पाटनरोधी शुल्कों के अध्यक्षीन है तो किसी किस्म का प्रवंचनारोधी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी निर्वचन, जो प्रवंचनारोधी कानून को निष्क्रिय बनाता है, उसे सांविधिक प्रावधानों के निर्वचन के तय सिद्धांतों के संदर्भ में रद्द किया जाना होता है।

निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जांच

57. प्राधिकारी ने उपर्युक्त अनुरोधों और पाटनरोधी नियमावली के नियम 25 तथा सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9क(1) अर्थात् संगत अधिनियम/नियामवली के तहत तथाकथित प्रवंचना संबंधी तथ्य को नोट किया है जिसमें निम्नलिखित उल्लेख है:

सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9क(1क), जिसमें केंद्र सरकार, ऐसी जांच, जिसे वह आवश्यक समझे, का यह मत है कि उप धारा (1) के तहत लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना हुई है, या तो विवरण अथवा नाम अथवा उस वस्तु के संगठन में परिवर्तन करके, जो ऐसे पाटनरोधी शुल्क के अध्यक्षीन है अथवा ऐसी वस्तु का आयात अनअसेंबलड अथवा डिसअसेंबलड रूप अथवा उसके मूल देश को बदलकर अथवा निर्यात अथवा किसी अन्य तरीके से किया गया है जिसमें लगाया गया पाटनरोधी शुल्क अप्रभावी रखा गया है, वह ऐसी वस्तु अथवा उस देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क लगा सकती है, जैसी भी स्थिति हो।

पाटनरोधी नियमावली का नियम 25 "पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना – (1) जहां पाटनरोधी शुल्क के अध्यक्षीन किसी वस्तु का पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के प्रयोजन के लिए अधिसूचित निर्यातक देश अथवा मूल देश सहित किसी भी देश से भारत में अनअसेंबलड, अनफिनिशड अथवा इनकम्प्लीट रूप में किया जाता है तथा उसे भारत में अथवा ऐसे देश में असेंबल, फिनिशड अथवा कम्प्लीट" किया जाता है तो ऐसी असेंबलिंग, फिनिशिंग अथवा कम्प्लीशन को लागू पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना माना जाएगा, यदि:

- (क) प्रचालन पाटनरोधी जांच के बाद अथवा ठीक उससे पूर्व प्रारंभ किया गया हो अथवा बढ़ाया गया हो तथा हिस्से पुर्जों एवं संघटकों का पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के प्रयोजन के लिए अधिसूचित मूल देश अथवा निर्यातक देश से आयात किया गया हो,
और
(ख) असेंबलिंग, फिनिशिंग अथवा कम्प्लीशन के कार्य के परिणामस्वरूप मूल्य असेंबलड, फिनिशड अथवा कम्प्लीट वस्तु की लागत के 35 प्रतिशत से कम हो।

व्याख्या-I – मूल्य का अर्थ असेंबलड, फिनिशड अथवा कम्प्लीट वस्तु की लागत में से आयातित हिस्सों पुर्जों अथवा संघटकों का मूल्य घटाकर

व्याख्या-II – "मूल्य" का परिकलन करने के प्रयोजन के लिए बौद्धिक संपत्ति अधिकार, रॉयल्टी, तकनीकी जानकारी शुल्क तथा परामर्शी प्रभारों से संबंधित भुगतानों के निमित्त किए गए खर्चों को हिसाब में नहीं दिया जाएगा।

58. प्राधिकारी गैर स्लिटिंग, प्रयोक्ताओं द्वारा जांचाधीन उत्पाद की अधिक चौड़ाई के वास्तविक उपयुक्त प्रयोग के संबंध में प्रयोक्ता उद्योग द्वारा दायर किए गए विभिन्न अनुरोधों को दायर करते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपाय उत्पादक/निर्यातक विशिष्ट हैं और प्रवंचनारोधी जांच में जो उत्पादक/निर्यातक पाटनरोधी जांच के अध्यक्षीन हैं, उन्हें भाग लेने की आवश्यकता होती है ताकि ये उपाय लगाए जाने के बाद उनके द्वारा विशेष रूप से व्यापार पैटर्न में परिवर्तन का मूल्यांकन किया जा सके। किसी प्रक्रिया द्वारा जांच की जा रही प्रवंचना के ऐसे तथ्य से संबंधित मूल्य वर्धन का भी परिकलन किए जाने की आवश्यकता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादक कोरिया के मामले में पोसको ने अपनी 6 निर्यातक कंपनियों तथा भारत में 3 स्लिटिंग केंद्रों सहित सहयोग किया है। प्राधिकारी ने सहयोगी कंपनियों द्वारा दिए गए आंकड़ों के कारण जांचाधीन उत्पाद को आगे कम आकार में बदलने और उसके निपटान में मूल्य वर्धन, व्यापार पैटर्न में परिवर्तन की जांच की है।
59. पोसको के एक स्लिटिंग केंद्र के लिए मूल्यांकित मूल्य वर्धन को प्रतिनिधि कारक के रूप में माना जाना है और विभिन्न आयातकों/आयातक एसोसिएशन द्वारा किए गए अनुरोध भी इस बात का समर्थन करते हैं कि मूल्य वर्धन 35 प्रतिशत से कम है जो कि संबंधित पाटनरोधी नियमावली में शुरूआती स्तर पर कहा गया है। आयातकों की ये चिंताएं कि अधिक चौड़ाई वाले उत्पादों को स्लिट नहीं किया जाता है और वे उपयुक्त प्रयोग के लिए हैं, उनके वास्तविक निपटान द्वारा सिद्ध नहीं किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, विचाराधीन उत्पाद एवं जांचाधीन उत्पाद के व्यापार पैटर्न में परिवर्तन के लिए उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा औचित्य दिए जाने की आवश्यकता है।

60. जहां तक गुणवत्ता, अनुपलब्धता और सुपुर्दगी अनुसूची के संबंध में कुछ ग्रेडों को अलग करने का संबंध है, प्राधिकारी मानते हैं कि वर्तमान जांच का क्षेत्र केवल चौड़ाई के पहलू के संबंध में “विचाराधीन उत्पाद और जांचाधीन उत्पाद” की जांच करने तक प्रतिबंधित है न कि अन्य मानदंडों तक, जिसे मूल जांच परिणाम में उपयुक्त रूप से लिया जा सकता था। जहां तक व्यापक सार्वजनिक हित/मेक इन इंडिया कार्यक्रम के मुद्दे का संबंध है, प्राधिकारी मानते हैं कि वर्तमान जांच का क्षेत्र स्थापित प्रवंचना के तथ्य के कारण मौजूदा पाटनरोधी उपाय कम होने का मूल्यांकन करना है जो कि किसी सार्वजनिक हित अथवा मेक इन इंडिया कार्यक्रम के प्रति उत्पादक विरोधी नहीं हो सकता।
61. प्राधिकारी ने डीजीसीआईएस आंकड़ों के अनुसार समग्र आधार पर संबद्ध देशों के लिए फरवरी, 2010 से पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद संबद्ध देशों के लिए विचाराधीन उत्पाद को जांचाधीन उत्पाद में व्यापार पैटर्न परिवर्तन का संदर्भ दिया जिसमें किसी उत्पादक/निर्यातक द्वारा कोई उत्तर दायर नहीं किया गया।
62. जिन उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं, उनके मामले में प्राधिकारी ने उत्पादकों/निर्यातकों के आंकड़ों और इस परिवर्तन का मूल्यांकन करने हेतु उसी के लिए संबंधित अनुरोधों के अनुसार विचाराधीन उत्पाद से जांचाधीन उत्पाद में व्यापार पैटर्न परिवर्तन का संदर्भ दिया। व्यापार पैटर्न परिवर्तन मैसर्स पोसको, कोरिया, ऑटोकुम्पू, यूरोपीय संघ और युसको, ताइवान द्वारा प्रस्तुत किया गया है। 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान बाईएलएसएस द्वारा बताए गए निर्यात विचाराधीन उत्पाद अथवा जांचाधीन उत्पाद के रूप में विशेष रूप से स्पष्ट नहीं किए गए हैं और वे डीजीसीआईएस के आंकड़ों से सह संबंध भी नहीं रखते तथा इसीलिए उन पर विचार नहीं किया गया है।
63. जहां तक मैसर्स पोसको, कोरिया और उसके प्रसंस्करण केंद्रों के अनुरोधों का संबंध है, प्राधिकारी 2008-09 से जांच की अवधि तक आयातित विचाराधीन उत्पाद, जांचाधीन उत्पाद और गैर विचाराधीन उत्पाद/गैर जांचाधीन उत्पाद का निपटान नोट करते हैं। प्राधिकारी ने इस उपाय को लगाए जाने से पूर्व विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग पैटर्न विचाराधीन उत्पाद अथवा गैर विचाराधीन उत्पाद के रूप में होने का संदर्भ दिया और विचाराधीन उत्पाद और जांचाधीन उत्पाद का प्रयोग पैटर्न उपायों के बाद विचाराधीन उत्पाद और जांचाधीन उत्पाद के निपटान/बिक्री पैटर्न की जांच करने के लिए संदर्भ दिया।
64. जहां तक प्रवंचना संबंधी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार विचाराधीन उत्पाद के रूप का स्लिटिंग क्रियाकलाप में परिवर्तन का संदर्भ है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि प्रयोक्ता उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद/जांचाधीन उत्पाद का प्रयोग विचाराधीन उत्पाद/जांचाधीन उत्पाद की चौड़ाई पर निर्भर करता है, अतः स्लिटिंग द्वारा परिवर्तन प्रक्रिया फिनिशिंग/परिवर्तन की प्रक्रिया के समान है तथा इसीलिए स्लिटिंग की प्रक्रिया को प्रवंचना की जांच करने के लिए संगत पाटनरोधी नियमावली के तहत शामिल किया गया है।
65. प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियम 25(1) की यह अपेक्षा है कि किसी भी अनअसेंबल्ड, अनफिनिशड अथवा इनकम्प्लीट की फिनिशिंग, कम्प्लीशन और असेंबलिंग भारत में अथवा ऐसे किसी देश में की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, नियम 25(1)(क) की यह अपेक्षा है कि प्रवंचना के तथ्य में आरंभ तथा वृद्धि स्थापित की जाए तथा नियम 25(1)(ख) में यह सिद्ध करने की अपेक्षा है कि उपर्युक्त तथ्य से संबद्ध “मूल्य वर्धन” इस उप नियम में निर्धारित आरंभिक स्थिति के अनुसार है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात पर पूर्व में पात्र पाटनरोधी शुल्क 20.02.2010 की अधिसूचना संख्या 20/2010 द्वारा लगाया गया था। विचाराधीन उत्पाद के आयात के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की गई थी और निर्धारण के बाद केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 11.12.2015 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 61/2015 द्वारा पाटनरोधी शुल्क बढ़ाया गया था। ये लगाए गए शुल्क आज भी लागू हैं। प्राधिकारी ने जांच की और पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद अर्थात्

फरवरी, 2010 से जांच की अवधि तक मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना का मूल्यांकन करने के लिए व्यापार पैटर्न में परिवर्तन को नोट किया। प्राधिकारी ने इस बात की भी जांच की क्या व्यापार के पैटर्न में परिवर्तन है तथा क्या यह परिवर्तन उस परिपाटी, प्रक्रिया अथवा कार्य से उभरा है, जिसके लिए अपर्याप्त उचित कारण अथवा शुल्क लगाए जाने के अलावा आर्थिक औचित्य था। निम्नलिखित तालिका व्यापार परिवर्तन दर्शाती है:

तालिका 1 – 2008-09 से समग्र रूप में संबद्ध देशों से जांचाधीन उत्पाद/विचाराधीन उत्पाद का व्यापार पैटर्न

मी. टन	संबद्ध देश					
	विचाराधीन उत्पाद	जांचाधीन उत्पाद	कुल	विचाराधीन उत्पाद %	जांचाधीन उत्पाद %	कुल
2008-09	53420	19936	73356	73%	27%	100%
2009-10	13105	11820	24925	53%	47%	100%
2010-11	20263	46804	67066	30%	70%	100%
2011-12	29700	69555	99255	30%	70%	100%
2012-13	17908	79346	97254	18%	82%	100%
2013-14	13037	55219	68256	19%	81%	100%
2014-15	18437	67716	86152	21%	79%	100%
जांच की अवधि	20657	75785	96442	21%	79%	100%
वार्षिकीकृत जांच की अवधि	16525	60628	77153	21%	79%	100%

तालिका 1क – 2008-09 से समग्र रूप में प्रत्येक संबद्ध देश से जांचाधीन उत्पाद/विचाराधीन उत्पाद का व्यापार पैटर्न

मात्रा (मी. टन)	चीन जन गण			यूरोपीय संघ			कोरिया		
	विचाराधीन उत्पाद	जांचाधीन उत्पाद	कुल	विचाराधीन उत्पाद	जांचाधीन उत्पाद	कुल	विचाराधीन उत्पाद	जांचाधीन उत्पाद	कुल
2008-09	2,117	616	2,733	23,840	10,612	34,452	13,553	2,818	16,371
2009-10	349	144	493	2,699	8,960	11,659	8,223	234	8,457
2010-11	1,996	7,737	9,733	1,948	23,735	25,683	14,626	4,688	19,314
2011-12	4,257	18,942	23,199	3,285	23,757	27,042	20,596	10,276	30,872
2012-13	9,092	17,848	26,940	3,248	19,604	22,852	2,583	27,554	30,137
2013-14	7,177	10,265	17,442	1,945	12,885	14,830	1,042	21,502	22,544
2014-15	9,657	13,998	23,655	2,254	12,500	14,754	1,475	27,337	28,812
जांच की अवधि (वार्षिकीकृत)	9,658	15,414	25,072	1,723	9,710	11,433	1,289	23,344	24,633

मात्रा (मी. टन)	दक्षिण अफ्रीका			ताइवान		
	विचाराधीन उत्पाद	जांचाधीन उत्पाद	कुल	विचाराधीन उत्पाद	जांचाधीन उत्पाद	कुल
2008-09	3,816	2,596	6,412	6,703	2,326	9,029
2009-10	622	1,278	1,900	415	896	1,311
2010-11	624	1,606	2,230	176	5,988	6,164
2011-12	33	1,861	1,894	289	6,871	7,160
2012-13	56	3,359	3,415	211	2,114	2,325
2013-14	149	1,629	1,778	370	1,002	1,372
2014-15	2,062	2,435	4,497	632	4,026	4,658
जांच की अवधि (वार्षिकीकृत)	1,345	1,581	2,926	503	3,550	4,053

मात्रा (मी. टन)	थाइलैंड			संयुक्त राज्य अमेरिका		
	विचाराधीन उत्पाद	जांचाधीन उत्पाद	कुल	विचाराधीन उत्पाद	जांचाधीन उत्पाद	कुल
2008-09	3,022	716	3,738	368	252	620
2009-10	733	59	792	65	249	314
2010-11	797	1,451	2,248	97	1,598	1,695
2011-12	729	1,585	2,314	512	6,263	6,775
2012-13	1,320	979	2,299	1,399	7,889	9,288
2013-14	1,170	619	1,789	1,183	7,317	8,500
2014-15	1,094	2,422	3,516	1,262	4,998	6,260
जांच की अवधि (वार्षिकीकृत)	1,014	1,581	2,595	994	5,447	6,441

तालिका 2 – 2008-09 से समग्र रूप में प्रत्येक संबद्ध देश से जांचाधीन उत्पाद/विचाराधीन उत्पाद का व्यापार पैटर्न (सूचकांक)

हिस्सा (%)	चीन जन गण			यूरोपीय संघ			कोरिया		
	विचाराधीन उत्पाद	जांचाधीन उत्पाद	कुल	विचाराधीन उत्पाद	जांचाधीन उत्पाद	कुल	विचाराधीन उत्पाद	जांचाधीन उत्पाद	कुल
2008-09	77%	23%	100%	69%	31%	100%	83%	17%	100%
2009-10	71%	29%	100%	23%	77%	100%	97%	3%	100%
2010-11	21%	79%	100%	8%	92%	100%	76%	24%	100%
2011-12	18%	82%	100%	12%	88%	100%	67%	33%	100%
2012-13	34%	66%	100%	14%	86%	100%	9%	91%	100%
2013-14	41%	59%	100%	13%	87%	100%	5%	95%	100%
2014-15	41%	59%	100%	15%	85%	100%	5%	95%	100%
जांच की अवधि (वार्षिकीकृत)	39%	61%	100%	15%	85%	100%	5%	95%	100%

हिस्सा (%)	दक्षिण अफ्रीका			ताइवान			थाइलैंड		
	विचाराधीन उत्पाद	जांचाधीन उत्पाद	कुल	विचाराधीन उत्पाद	जांचाधीन उत्पाद	कुल	विचाराधीन उत्पाद	जांचाधीन उत्पाद	कुल
2008-09	60%	40%	100%	74%	26%	100%	81%	19%	100%
2009-10	33%	67%	100%	32%	68%	100%	93%	7%	100%
2010-11	28%	72%	100%	3%	97%	100%	35%	65%	100%
2011-12	2%	98%	100%	4%	96%	100%	32%	68%	100%
2012-13	2%	98%	100%	9%	91%	100%	57%	43%	100%
2013-14	8%	92%	100%	27%	73%	100%	65%	35%	100%
2014-15	46%	54%	100%	14%	86%	100%	31%	69%	100%
जांच की अवधि (वार्षिकीकृत)	46%	54%	100%	12%	88%	100%	39%	61%	100%

हिस्सा (%)	संयुक्त राज्य अमेरिका		
	विचाराधीन उत्पाद	जांचाधीन उत्पाद	कुल
2008-09	59%	41%	100%
2009-10	21%	79%	100%
2010-11	6%	94%	100%
2011-12	8%	92%	100%
2012-13	15%	85%	100%
2013-14	14%	86%	100%
2014-15	20%	80%	100%
जांच की अवधि (वार्षिकीकृत)	15%	85%	100%

66. प्राधिकारी ने जांचाधीन उत्पाद के भीतर आयातों के पैटर्न का भी विश्लेषण किया है। यह नोट किया जाता है कि अधिकतर आयात शुरुआती सीमा से कुछ अधिक हैं और जांचाधीन उत्पाद के आयात का छोटा अनुपात 1650 एमएम से अधिक है। यह तथ्य यह दर्शाता है कि संबद्ध देशों के उत्पादक/निर्यातक तकनीकी अथवा प्रयोग आधारित मूल्यांकन की अपेक्षा कुल मिलाकर चौड़ाईयों में अधिसूचित टोलरेंस को ध्यान में रखते हुए अधिक चौड़ाई ला रहे हैं।
67. उपर्युक्त से यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात की मात्रा पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद कम हुई है। इसके अतिरिक्त, संबद्ध देशों से जांचाधीन उत्पाद के आयात की मात्रा काफी बड़ी है। इस प्रकार यह देखा जाता है कि जबकि विचाराधीन उत्पाद का आयात कम हुआ है, जांचाधीन उत्पाद का आयात पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से बढ़ा है।
68. संबद्ध देशों के अलावा देशों से आयात का भी देश में परिवर्तन का पैटर्न सुनिश्चित करने के लिए विश्लेषण किया गया। निम्नलिखित तालिका गैर संबद्ध देशों से व्यापार पैटर्न को दर्शाती है:

तालिका 3 - 2008-09 से समग्र रूप में गैर-संबद्ध देशों से जांचाधीन उत्पाद/विचाराधीन उत्पाद का व्यापार पैटर्न

गैर संबद्ध देश	विचाराधीन उत्पाद/जांचाधीन उत्पाद	मात्रा (मी. टन)	हिस्सा (%)
2008-09	विचाराधीन उत्पाद	1940	47%
	जांचाधीन उत्पाद	2177	53%
2009-10	विचाराधीन उत्पाद	639	62%
	जांचाधीन उत्पाद	395	38%
2010-11	विचाराधीन उत्पाद	24123	83%
	जांचाधीन उत्पाद	4882	17%

गैर संबद्ध देश	विचाराधीन उत्पाद/जांचाधीन उत्पाद	मात्रा (मी. टन)	हिस्सा (%)
2011-12	विचाराधीन उत्पाद	31566	82%
	जांचाधीन उत्पाद	7071	18%
2012-13	विचाराधीन उत्पाद	48593	81%
	जांचाधीन उत्पाद	11440	19%
2013-14	विचाराधीन उत्पाद	32192	88%
	जांचाधीन उत्पाद	4441	12%
2014-15	विचाराधीन उत्पाद	56421	81%
	जांचाधीन उत्पाद	13169	19%
जांच की अवधि (वार्षिकीकृत)	विचाराधीन उत्पाद	55480	79%
	जांचाधीन उत्पाद	14392	21%

69. उपर्युक्त से यह नोट किया जाता है कि गैर संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात की मात्रा जांच की अवधि में कुल मिलाकर समान रही। यह दर्शाता है कि संबद्ध देशों से आयात पैटर्न में परिवर्तन का औचित्य बनाने हेतु खपत पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं है।
70. इसके अतिरिक्त, यह भी नोट किया जाता है कि एक ग्रेड अर्थात् ईएन 1.4512, जिसे 07.02.2012 से विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल किया गया था, संबद्ध देशों से आयात का पैटर्न मांग पैटर्न में बिना किसी परिवर्तन के पूरी तरह बदल गया। निम्नलिखित तालिका ग्रेड ईएन 1.4512 के विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल होने के बाद व्यापार के पैटर्न में परिवर्तन स्पष्ट रूप से दर्शाती है:

तालिका 4 – 07.02.2012 से विचाराधीन उत्पाद में शामिल होने के बाद ईएन 1.4512 के आयात में परिवर्तन

ईएन 1.4512	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	जांच की अवधि
600-1250 (मी. टन)	11134	19517	87	90	10	10
1250 और उससे अधिक (मी. टन)	1676	7924	20030	15365	11455	9902
कुल (मी. टन)	12810	27442	20117	15455	11465	9912
आयात का % हिस्सा						
600-1250	86.92%	71.12%	0.43%	0.59%	0.09%	0.10%
1250 और उससे अधिक	13.08%	28.88%	99.57%	99.41%	99.91%	99.90%

71. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों, गैर संबद्ध देशों से आयात के पैटर्न और घरेलू उद्योग द्वारा की गई बिक्री का भी विश्लेषण किया। इस पैटर्न का अनुसार यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से आयात का पैटर्न और घरेलू उद्योग द्वारा की गई बिक्री समान रेंज में हैं। तथापि, संबद्ध देशों से आयात का पैटर्न पूर्णतः भिन्न परिणाम दर्शाता है। विश्लेषण किया गया पैटर्न निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 5 – संबद्ध देशों, गैर-संबद्ध देशों और घरेलू उद्योग के लिए व्यापार पैटर्न की तुलना:

	संबद्ध देश			गैर-संबद्ध देश			घरेलू उद्योग		
मी. टन	विचाराधीन उत्पाद	जांचाधीन उत्पाद	कुल	विचाराधीन उत्पाद	जांचाधीन उत्पाद	कुल	विचाराधीन उत्पाद	जांचाधीन उत्पाद	कुल
2008-09	73%	27%	100%	47%	53%	100%	100%	0%	100%
2009-10	53%	47%	100%	62%	38%	100%	100%	0%	100%
2010-11	30%	70%	100%	83%	17%	100%	99%	1%	100%
2011-12	30%	70%	100%	82%	18%	100%	99%	1%	100%
2012-13	18%	82%	100%	81%	19%	100%	87%	13%	100%
2013-14	19%	81%	100%	88%	12%	100%	87%	13%	100%
2014-15	21%	79%	100%	81%	19%	100%	87%	13%	100%
जांच की अवधि वार्षिकीकृत	21%	79%	100%	79%	21%	100%	83%	17%	100%

तालिका 6 - विचाराधीन उत्पाद/जांचाधीन उत्पाद का व्यापार पैटर्न – पोसको (कोरिया)

	भारत को निर्यात			घरेलू बिक्री			तीसरे देशों के निर्यात		
मात्रा (मी. टन)	विचाराधीन उत्पाद	जांचाधीन उत्पाद	कुल	विचाराधीन उत्पाद	जांचाधीन उत्पाद	कुल	विचाराधीन उत्पाद	जांचाधीन उत्पाद	कुल
1 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2009	****	****	****	****	****	****	****	****	****
हिस्सा %	95-100	0-5	100%	90-95%	5-10	100%	90-95%	5-10	90-95%
1 अप्रैल, 2009 से 31 मार्च, 2010	****	****	****	****	****	****	****	****	****
हिस्सा %	95-100	0-5	100%	90-95%	5-10	100%	90-95%	5-10	90-95%
1 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011	****	****	****	****	****	****	****	****	****
हिस्सा %	95-100	0-5	100%	90-95%	5-10	100%	90-95%	5-10	90-95%

1 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012	****	****	****	****	****	****	****	****	****
हिस्सा %	75-80	20-25	100%	90-95%	5-10	100%	90-95	5-10	100%
1 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013	****	****	****	****	****	****	****	****	****
हिस्सा %	5-10	90-95	100%	90-95	5-10	100%	90-95	5-10	100%
1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014	****	****	****	****	****	****	****	****	****
हिस्सा %	5-10	90-95	100%	90-95	5-10	100%	95-100	0-5	100%
1 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2015	****	****	****	****	****	****	****	****	****
हिस्सा %	0-5	95-100	100%	90-95	5-10	100%	95-100	0-5	100%
जांच की अवधि : जुलाई, 2014 से सितंबर, 2015	****	****	****	****	****	****	****	****	****
हिस्सा %	0-5	95-100	100%	90-95	5-10	100%	90-95	5-10	100%

यह नोट किया जाता है कि भारत को व्यापार का पैटर्न विशेष रूप से पाटनरोधी उपायों के बाद विचाराधीन उत्पाद से जांचाधीन उत्पाद में चला गया। तथापि, यह प्रवृत्ति पोसको कोरिया की भारत को छोड़कर अन्य देशों तथा उनके घरेलू बाजार में की गई बिक्री में जानकारी में नहीं आई।

तालिका 7 – विचाराधीन उत्पाद/जांचाधीन उत्पाद का व्यापार पैटर्न – यीह यूनाइटेड स्टील कारपोरेशन, ताइवान

[illegible]

हिस्सा %	25-30	70-75	100%	70-75	25-30	100%	80-85	15-20	100%
1 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012	****	****	****	****	****	****	****	****	****
हिस्सा %	65-70	30-35	100%	70-75	25-30	100%	80-85	15-20	100%
1 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013	****	****	****	****	****	****	****	****	****
हिस्सा %	0	0	0	75-80	20-25	100%	75-80	20-25	100%
1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014	****	****	****	****	****	****	****	****	****
हिस्सा %	0-5	95-100	100%	70-75	25-30	100%	75-80	20-25	100%
1 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2015	****	****	****	****	****	****	****	****	****
हिस्सा %	0-5	95-100	100%	65-70	30-35	100%	70-75	25-30	100%
जांच की अवधि : जुलाई, 2014 से सितंबर, 2015	****	****	****	****	****	****	****	****	****
हिस्सा %	0-5	95-100	100%	70-75	25-30	100%	70-75	25-30	100%

प्राधिकारी नोट करते हैं कि 2012-13 के बाद भारत को निर्यात के लिए विचाराधीन उत्पाद से जांचाधीन उत्पाद तक प्रवृत्ति में दृश्यमान परिवर्तन है। प्रवृत्ति में यह परिवर्तन यस्को की तीसरे देशों की बिक्री अथवा घरेलू बिक्री में नहीं दिखाई देती।

तालिका 8 - विचाराधीन उत्पाद/जांचाधीन उत्पाद का व्यापार पैटर्न - ऑटोकम्प्यू ओई, यूरोपीय संघ

[illegible]

हिस्सा %	0-5	95-100	100%	45-50	50-55	100%	45-50	50-55	100%
1 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012	****	****	****	****	****	****	****	****	****
हिस्सा %	5-10	90-95	100%	45-50	50-55	100%	60-65	35-40	100%
1 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013	****	****	****	****	****	****	****	****	****
हिस्सा %	20-25	75-80	100%	40-45	55-60	100%	65-70	30-35	100%
1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014	****	****	****	****	****	****	****	****	****
हिस्सा %	30-35	35-70	100%	40-45	55-60	100%	50-55	45-50	100%
1 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2015	****	****	****	****	****	****	****	****	****
हिस्सा %	15-20	80-85	100%	40-45	55-60	100%	65-70	30-35	100%
जांच की अवधि : जुलाई, 2014 से सितंबर, 2015	****	****	****	****	****	****	****	****	****
हिस्सा %	0-5	95-100	100%	40-45	55-60	100%	45-45	55-60	100%

भारत को निर्यात के संबंध में विचाराधीन उत्पाद से जांचाधीन उत्पाद तक 2010-11 के बाद से जांच की अवधि तक प्रवृत्ति में परिवर्तन है जिसे ऑटोकम्पू, यूरोपीय संघ के घरेलू बाजार में भी नोट किया गया है।

72. उपर्युक्त के आधार पर प्राधिकारी मानते हैं कि संबद्ध देशों से आयात के पैटर्न में 2009-2010 से विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की अंतिम उत्पाद के प्रयोग में किसी उपयुक्त परिवर्तन के बिना परिवर्तन आया है।
73. पाटनरोधी नियमावली के नियम 25(1)(ख) में यह अपेक्षा है कि “असेंबलिंग, फिनिशिंग अथवा कम्प्लीशन प्रचालन के परिणामस्वरूप मूल्य असेंबलड, फिनिशड अथवा कम्प्लीट वस्तु की लागत के 35 प्रतिशत से कम हो।” प्राधिकारी ने पूर्णतः संतुष्ट होने के लिए अपने अधिकारियों के माध्यम से भी स्लिटिंग प्रक्रिया में शामिल वास्तविक लागत के संबंध में एक विचार प्राप्त करने के लिए जांच की शुरुआत से पूर्व स्थल सत्यापन भी किया। सत्यापित सूचना के आधार पर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मूल्य वर्धन संबद्ध देशों से आयात की जाने वाली सीरीज के आधार पर 2 प्रतिशत से 5 प्रतिशत की रेंज में होना निकला।
74. प्राधिकारी यह देखते हैं कि स्लिटिंग की प्रक्रिया में शामिल मूल्य वर्धन कानून के तहत निर्धारित सीमाओं से काफी कम है। यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद का पहुँच मूल्य आयातित जांचाधीन उत्पाद से निकला, जिसमें उत्पाद का पहुँच मूल्य समायोजित करने के बाद मूल्य वर्धन (2 प्रतिशत से 5 प्रतिशत) के साथ विचाराधीन उत्पाद के पहुँच मूल्य से कम है जिसमें संबद्ध देशों से परिष्कृत रूप में सीधे ही आयात किए जाने पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क शामिल है। अतः स्लिटिंग लागत को हिसाब में लेने के बाद भी विचाराधीन उत्पाद के बजाए जांचाधीन उत्पाद का आयात करना वाणिज्यिक रूप से लाभदायक है।

75. यह जांच यह दर्शाती है कि संबद्ध देशों में उत्पादकों/निर्यातकों के लिए विचाराधीन उत्पाद पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना करने के अलावा कोई आर्थिक औचित्य विद्यमान नहीं है। यह जांचाधीन उत्पाद के आयात में भारी वृद्धि में सिद्ध है। यह इस तथ्य के साथ कि मूल्य वर्धन निर्धारित स्तर से काफी कम है, यह दर्शाता है कि नियमावली के अनुसार मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों की प्रवंचना होती है।
76. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मैसर्स सनराइज स्टेनलेस प्रा. लि. और सनमार्क स्टेनलेस प्रा. लि. ने ही कानूनी अनुरोध दायर किए हैं, परंतु निर्धारित प्रश्नावली के अनुसार उनके द्वारा किए गए आयात के संबंध में कोई आंकड़े दायर नहीं किए हैं।
77. मैसर्स सनसिटी शीट्स प्रा. लि. और सनसिटी स्ट्रिप्स एंड ट्यूब्स प्रा. लि. ने कानूनी अनुरोध तथा आयातक प्रश्नावली, दोनों दायर किए हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि मैसर्स सनसिटी शीट्स प्रा. लि. और सनसिटी स्ट्रिप्स एंड ट्यूब्स प्रा. लि. ने उल्लेख किया है कि 2012-13 में उनकी कंपनी की शुरुआत से उन्होंने केवल जांचाधीन उत्पाद अथवा गैर विचाराधीन उत्पाद/जांचाधीन उत्पाद का ही आयात किया है न कि विचाराधीन उत्पाद का और इस प्रकार उन्होंने कोई प्रवंचना नहीं की है।
78. प्राधिकारी विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों को नोट करते हैं जिनमें से अधिकतर माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष भी किए गए थे। प्राधिकारी नोट करते हैं कि मैसर्स सनसिटी शीट्स प्रा. लि. और सनसिटी स्ट्रिप्स एंड ट्यूब्स प्रा. लि. ने 2 संबद्ध देशों अर्थात् चीन और कोरिया से आयात किया है। प्रवंचना का तथ्य उन संबद्ध देशों से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए स्थापित किया जाना अपेक्षित है जिन पर पाटनरोधी उपाय पहले से ही मौजूद है। इसके लिए नियम 25 से नियम 28 तक के विभिन्न प्रावधानों की नियम 26(4) के अनुसार और नियम 26(1) के अनुसार उसके प्रभाव तथा व्यापार पैटर्न में परिवर्तन के पहलू और पाटनरोधी नियमावली के क्रमशः 25 (1)(क) तथा 25 1(ख) के अनुसार वर्धित मूल्य के अनुसार प्रवंचना कारक उत्पाद (पीयूआई) के पाटन के संबंध में जांच की जानी चाहिए।
79. अतः उपर्युक्त मानदंडों को पहले सहयोगी उत्पादक/निर्यातक के लिए सिद्ध किया जाना है जिन्हें निर्धारित प्रश्नावली के अनुसार पूर्ण आंकड़े प्रदान करने की आवश्यकता है। मैसर्स सनसिटी शीट्स के मामले में यह नोट किया जाता है कि चीन से काफी निर्यात किए गए हैं जहां से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने उत्तर नहीं दिया है। प्राधिकारी ने सभी संगत मानदंडों के लिए सहयोगी उत्पादक/निर्यातक के व्यवहार का विशेष रूप से मूल्यांकन किया और वे सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के अनुसार विभिन्न मानदंडों पर गैर सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों का मूल्यांकन करते हैं।
80. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पोसको इंडिया पुणे स्टील प्रोसेसिंग प्रा. लि., पोसको इंडिया दिल्ली स्टील प्रोसेसिंग प्रा. लि., पोसको इंडिया चेन्नई स्टील प्रोसेसिंग प्रा. लि. जो पोसको इंडिया की सहायक कंपनियां हैं, ने दक्षिण कोरिया से जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद, जांचाधीन उत्पाद और यहां तक कि गैर विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है तथा निम्नलिखित तालिका के अनुसार स्लिटिंग क्रियाकलाप किए हैं:

तालिका 9

(राशि भारतीय रुपए में)							
क्रम सं.	कंपनी का नाम	विचाराधीन उत्पाद/जांचाधीन उत्पाद	मात्रा (मी. टन)	आयातित हिस्से पुर्जों या संघटकों का मूल्य	मूल्य वर्धन (लागत/ऐसे प्रचालनों के लिए किए गए व्यय)	असेंबलड, परिष्कृत और पूर्ण वस्तु की लागत	असेंबलड, परिष्कृत और पूर्ण वस्तु की लागत के प्रतिशत के रूप में मूल्य वर्धन
1	पोसको-आईपीपीसी	जांचाधीन उत्पाद	****	****	****	****	0-5
		विचाराधीन उत्पाद	****	****	****	****	0-5
2	पोसको-आईपीपीसी	जांचाधीन उत्पाद	****	****	****	****	0-5
		विचाराधीन उत्पाद	****	****	****	****	0-5
3	पोसको-आईपीपीसी	जांचाधीन उत्पाद	****	****	****	****	0-5
		विचाराधीन उत्पाद	****	****	****	****	0-5
			****	****	****	****	0-5
कुल			****	****	****	****	0-5
जांचाधीन उत्पाद			****	****	****	****	0-5
विचाराधीन उत्पाद			****	****	****	****	0-5
कुल			****	****	****	****	0-5

किसी विचाराधीन उत्पाद/जांचाधीन उत्पाद की सामग्री को छोटे आकारों अर्थात् विचाराधीन उत्पाद अथवा गैर विचाराधीन उत्पाद में परिवर्तित करने पर मूल्य वर्धन इस प्रकार 35 प्रतिशत से कम है।

अतः जांचाधीन उत्पाद के रूप में परिवर्तन में हुए “मूल्य वर्धन” के संबंध में प्राधिकारी ने ऐसे प्रसंस्करण केंद्रों के लिए किए गए सत्यापन और इस विषय पर उन आयातकों द्वारा दायर उत्तरों, जिन्होंने स्वीकार किया है कि स्लिटिंग लागत 5 प्रतिशत मूल्य वर्धन से अधिक नहीं है, के अनुसार सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना का संदर्भ दिया है। संबद्ध सामानों यथा चाहे वे भारत में पोसको के स्लिटिंग केंद्रों द्वारा जांचाधीन उत्पाद, विचाराधीन उत्पाद अथवा गैर विचाराधीन उत्पाद हों, के विभिन्न आकारों का निपटान निम्नलिखित है:

तालिका 10 (स्रोत: पोसको कोरिया के स्लिटिंग सेंटर्स द्वारा प्रदान किए गए आंकड़े)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	जांच की अवधि (जुलाई, 2014 - सितंबर, 2015)	जांच की अवधि (वार्षिकीकृत)
	मात्रा	मात्रा	मात्रा	मात्रा	मात्रा	मात्रा	मात्रा	मात्रा	मात्रा
1. आयात का उपयोग									
आरंभिक स्टॉक	****	****	****	****	****	****	****	****	****
जोड़े: आयात	****	****	****	****	****	****	****	****	****
क. 600 एमएम से कम	****	****	****	****	****	****	****	****	****
ख. 600-1250 एमएम	****	****	****	****	****	****	****	****	****
ग. 1250 एमएम से अधिक	****	****	****	****	****	****	****	****	****
घटाएं: अंतिम स्टॉक	****	****	****	****	****	****	****	****	****
उपयोग आयात	****	****	****	****	****	****	****	****	****
II. आयात के उपयोग के लिए व्यौरा	****	****	****	****	****	****	****	****	****
1. बेचे गए उत्पाद	****	****	****	****	****	****	****	****	****
(क) घरेलू	****	****	****	****	****	****	****	****	****
क. 600 एमएम से कम	****	****	****	****	****	****	****	****	****
ख. 600-1250 एमएम	****	****	****	****	****	****	****	****	****
ग. 1250 एमएम से अधिक	****	****	****	****	****	****	****	****	****
घ. स्ट्रैप	****	****	****	****	****	****	****	****	****
(क) निर्यात	****	****	****	****	****	****	****	****	****
हानियां	****	****	****	****	****	****	****	****	****
कुल	****	****	****	****	****	****	****	****	****

प्राधिकारी नोट करते हैं कि 2008-09 से भारत में गैर विचाराधीन उत्पाद/गैर जांचाधीन उत्पाद की उपलब्धता विचाराधीन उत्पाद को बदलकर पूरी की गई है, जो बाद में मुख्य रूप से जांचाधीन उत्पाद में आयात को परिवर्तित किए जाने पर जांचाधीन उत्पाद में परिवर्तित की गई। जांचाधीन उत्पाद को भी गैर विचाराधीन उत्पाद के अलावा विचाराधीन उत्पाद में परिवर्तित किया गया था। प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के संबंध में मौजूदा पाटनरोधी उपायों के परिणामी स्वरूप तथा प्रवंचना पर विचार करने के प्रयोजन के लिए 2008-09 से जांच की अवधि के बीच विचाराधीन उत्पाद और जांचाधीन उत्पाद के इस निपटान पैटर्न पर विचार किया।

ज. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

81. चीन जन गण, कोरिया गणराज्य, यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका, चीनी तैपई, थाइलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सामानों के विरुद्ध जांच शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने संबंधित देशों के ज्ञात निर्यातकों/आयातकों को प्रश्नावलियां भेजीं और उन्हें सलाह दी कि वे निर्धारित प्रपत्र एवं तरीके से सूचना उपलब्ध कराएं। जांच की शुरुआत की अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर किए हैं:

- (i) ऑटोकम्पू ओई, यूरोप
- (ii) यीह यूनाइटेड स्टील कारपोरेशन, ताइवान (युसको)
- (iii) बालसिन लिहवा कारपोरेशन, ताइवान
- (iv) युआन लांग स्टेनलेस स्टील कारपोरेशन, ताइवान (वाईएलएसएस)
- (v) तांग एंग आयरन वर्क्स कं. लि., ताइवान
- (vi) पोसको, एशिया
- (vii) पोसको, कोरिया
- (viii) देवू इंटरनेशनल, कोरिया
- (ix) हुंडई कारपोरेशन, कोरिया
- (x) सैमसंग सीएंडटी, कोरिया
- (xi) एसके नेटवर्क्स, कोरिया
- (xii) टोयोटा शुशो, कोरिया

82. चीन जन गण, दक्षिण अफ्रीका, थाइलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने उत्तर दायर नहीं किया। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि इन देशों/क्षेत्रों से कोई उत्तर न आने के अभाव में इन देशों/क्षेत्रों में सामान्य मूल्य घरेलू उद्योग सहित सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के अनुसार निर्मित किया जाना चाहिए।

83. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत उत्तरों पर विचार किया है और सत्यापन के बाद इन अनुरोधों, जहां भी आवश्यक समझा गया और जब तक उन्हें रद्द नहीं किया गया, के आधार पर निर्धारण किया है। सामान्य मूल्य का निर्धारण ओसीटी परीक्षण तथा पर्याप्तता परीक्षण लागू करने के बाद (व्यापार परीक्षण की साधारण अवधि) और नियमों के तहत निर्धारित सिद्धांत के अनुसार सूचना के आधार पर ग्रेड से ग्रेड/सीरीज स्तर पर उपयुक्त तुलना करके किया है। दावा की गई निर्यात कीमत और समायोजनों की, अनुरोधों तथा जहां सत्यापन किए गए हैं, वहां उनके आधार पर अनुमति दी गई है।

84. सहयोगी निर्यातकों तथा संबंधित देशों/क्षेत्रों में अन्य सहयोगी निर्यातकों के संबंध में सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण निम्नलिखित पैराग्राफों में उल्लिखित किया गया है।

(1) चीन, दक्षिण अफ्रीका, थाइलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका से सभी उत्पादक/निर्यातक

प्राधिकारी द्वारा जांच

चीन, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका और थाइलैंड से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने कोई उत्तर दायर नहीं किया है।

85. प्राधिकारी ने चीन, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका और थाइलैंड के सभी उत्पादक/निर्यातकों के संबंध में उन्हें असहयोगी माना है, क्योंकि किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने कोई उत्तर दायर नहीं किया और पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत (एक्स-ईपी और सीआईएफ) निर्मित करने के लिए उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के आधार पर इसका संदर्भ दिया है। इस संबंध में प्राधिकारी ने प्रमुख कच्ची सामग्री (एचआर कॉइल) के लिए और जांच की अवधि के दौरान जांचाधीन उत्पाद के लिए उत्पादन लागत संबंधी आंकड़ों को अपनाने वाले शेष लागत तत्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर इन देशों के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए अपनी सतत परिपाटी को अपनाया है।

निर्यात कीमत के संबंध में जांचाधीन उत्पाद के लिए जांच की अवधि के डीजीसीआईएस के लेन-देन वार आंकड़े अपनाए गए हैं। सीआईएफ के संबंध में समायोजन समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतर्देशीय भाड़ा, बैंक प्रभार, ऋण लागत तथा पत्तन प्रभार के लिए प्रदान किए गए हैं जो क्रमशः सीआईएफ का ** प्रतिशत, एफओबी के ** प्रतिशत, एफओबी के ** प्रतिशत, एफओबी के ** प्रतिशत और एफओबी के ** प्रतिशत (चीन, कोरिया, थाइलैंड, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और ताइवान के लिए क्रमशः **, **, **, **, **, ** अमेरिकी डॉलर/मी. टन) की सीमा तक सतत रूप से अपनाए गए मानदंडों/साक्ष्य के आधार पर किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, चीन के मामले में वैट समायोजन ** प्रतिशत की सीमा तक भी दिए गए हैं।

उपर्युक्त के आधार पर पाटन मार्जिन अमेरिकी डॉलर/मी. टन में निम्नलिखित रूप में परिकलित किया गया है:

तालिका 11

देश	सीएनवी	एक्स ईपी	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन रेंज
चीन	****	****	****	****	0-10
थाइलैंड	****	****	****	****	15-25
दक्षिण अफ्रीका	****	****	****	****	10-20
संयुक्त राज्य अमेरिका	****	****	****	****	40-50

(2) कोरिया गणराज्य से उत्पादक/निर्यातक

क. कोरिया से उन उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, जिन्होंने प्रश्नावली के उत्तर दायर किया हैं:-

क. पोसको कोरिया

86. मैसर्स पोसको, कोरिया, जो कोरिया में संबद्ध सामानों का प्रमुख उत्पादक/निर्यातक है, ने प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं। जांच की अवधि के दौरान, पोसको ने कोरिया और हांगकांग में स्थित अपनी संबद्ध और असंबद्ध व्यापारिक कंपनियों के माध्यम से भारत में संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। ये कंपनियां हैं, पोसको, एशिया, देवू इंटरनेशनल, कोरिया, हुंडई कारपोरेशन, कोरिया, सैमसंग सीएंडटी, कोरिया, एस के नेटवर्क, कोरिया और टोयोटा शुशो, कोरिया ने उपर्युक्त व्यापारिक/निर्यातक कंपनी के प्रश्नावली के उत्तरों द्वारा समर्थित उत्पादक के रूप में अपनी प्रश्नावली के उत्तर दायर किए। पोसको और व्यापारिक कंपनियों, जिनके नाम ऊपर दिए गए हैं, के उत्तरों का प्रक्रिया के अनुसार सत्यापन भी किया गया। कोरियन उत्पादक का पाटन मार्जिन उनके दायर किए गए उत्तरों के आधार पर निर्धारित किया गया है। कोरिया के अन्य असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन उपर्युक्त अन्य असहयोगी उत्पादकों के लिए अपनाए गए सिद्धांत तथा अन्य उपलब्ध तथ्यों के अनुसार सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्धारित किया गया है।

87. उत्पादक पोसको, कोरिया ने जांच की अवधि के दौरान और पूर्व के वर्षों में विचाराधीन उत्पाद और जांचाधीन उत्पाद के व्यापार पैटर्न और घरेलू एवं निर्यात के बीच संबंध में आंकड़े उपलब्ध कराते हुए निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं। उसके संबद्ध/ असंबद्ध निर्यातकों/व्यापारियों अर्थात् पोसको देवू कारपोरेशन, कोरिया टोयोटा शुशो कोरिया कारपो., कोरिया, सैमसंग सीएंडटी कारपोरेशन, कोरिया, हियोसांग कारपोरेशन, कोरिया, हुंडई कारपोरेशन, कोरिया, ने भी निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर तथा समान आंकड़े दायर किए हैं।

उत्पादक ने जांचाधीन उत्पाद के विभिन्न ग्रेडों/सीरीज के लिए जांच की अवधि के दौरान भी जांचाधीन उत्पाद के उत्पादन की लागत के संबंध में आंकड़े उपलब्ध कराए हैं।

प्राधिकारी द्वारा जांच**सामान्य मूल्य (एनवी)**

उत्पादक ने **** मी. टन विचाराधीन उत्पाद घरेलू बाजार में बेचा और अंतर्देशीय भाड़ा, ऋण लागत, पैकिंग लागत, वेयर हाउसिंग खर्चों और वारंटी के निमित्त समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने पोसको, कोरिया तथा उसके 6 व्यापारियों/निर्यातकों द्वारा दायर आंकड़ों का स्थल सत्यापन किया था। व्यापार परीक्षण की साधारण अवधि जांचाधीन उत्पाद की विभिन्न सीरीज के लिए घरेलू बिक्री पर किया गया है जो जांचाधीन उत्पाद भारत में जांच की अवधि में बेचे गए हैं, ताकि एक सीरीज से दूसरी सीरीज की उपयुक्त तुलना पाटन मार्जिन के मूल्यांकन के लिए की जा सके। उपर्युक्त सिद्धांत के आधार पर भारित औसत सामान्य मूल्य की गणना **** अमेरिकी डॉलर/मी. टन के रूप में की गई है।

निर्यात कीमत

उत्पादक ने जांच की अवधि के दौरान भारत में **** मी. टन के जांचाधीन उत्पाद का निर्यात किया है। अंतर्देशीय परिवहन, विदेशी परिवहन, ऋण लागत, पैकिंग लागत और शुल्क वापसी के निमित्त समायोजनों का दावा किया गया है जिसकी प्राधिकारी ने अनुमति दे दी है।

उत्पादक ने विभिन्न व्यापारिक/निर्यातक कंपनियों के माध्यम से जांच की अवधि के दौरान जांचाधीन उत्पाद का निर्यात निम्नलिखित रूप में किया है:

तालिका 12

क्रम सं.	निर्यातक/उत्पादक	सीरीज	निर्यात (मी. टन)	सीआईएफ डॉलर/मी. टन
1	पोसको देवू कारपोरेशन, कोरिया			
2	सैमसंग सीएंडटी कारपोरेशन, कोरिया			
		200	****	****
		300	****	****
		400	****	****
	कुल		****	****
3	हियोसंग कारपोरेशन, कोरिया		****	****
		200	****	****
		300	****	****
		400	****	****
	कुल		****	****
4	हुंडई कारपोरेशन, कोरिया		****	****
		200	****	****
		300	****	****

		400	****	****
	कुल		****	****
5	एसके नेटवर्क्स कं. लि., कोरिया		****	****
		200	****	****
		300	****	****
		400	****	****
	कुल		****	****
6	टोयोटा शुशो कोरिया कारपो., कोरिया		****	****
		200	****	****
		300	****	****
		400	****	****
	कुल		****	****
7	पोसको एशिया कं. लि.		****	****
		200	****	****
		300	****	****
		400	****	****
	कुल		****	****

उपर्युक्त व्यापारियों द्वारा किए गए एसएंडडी खर्चें तथा उनकी लाभप्रदता निम्नलिखित रूप में निर्धारित है:

तालिका 13

क्रम सं.	निर्यातक/उत्पादक	अमेरिकी डॉलर/मी. टन				लाभ %
		एक्स फैक्ट्री बिक्री कीमत	एसएंडए सहित व्यय	एक्स फैक्ट्री क्रय कीमत	क्रय कीमत	
1	पोसको देवू कारपोरेशन, कोरिया	****	****	****	****	0-10%
2	सैमसंग सीएंडटी कारपोरेशन, कोरिया	****	****	****	****	0-10%

3	हियोसांग कारपोरेशन, कोरिया	****	****	****	****	0-10%
4	हुंडई कारपोरेशन, कोरिया	****	****	****	****	0-10%
5	एसके नेटवर्क्स कं. लि., कोरिया	****	****	****	****	0-10%
6	टोयोटा शुशो कोरिया कारपो., कोरिया	****	****	****	****	0-10%
7	पोसको एशिया कं. लि.	****	****	****	****	0-10%

उपर्युक्त के आधार पर पोसको, कोरिया के लिए भारित औसत पाटन मार्जिन की गणना निम्नलिखित रूप में की गई है:

तालिका 14

सामान्य मूल्य	अमेरिकी डॉलर/मी. टन	****
एक्स फैक्ट्री निर्यात कीमत	अमेरिकी डॉलर/मी. टन	****
पाटन मार्जिन	अमेरिकी डॉलर/मी. टन	****
पाटन मार्जिन %	%	****
पाटन मार्जिन रेंज	%	15-25

ख. उपर्युक्त को छोड़कर कोरिया गणराज्य से उत्पादक/निर्यातक

88. कोरिया गणराज्य के अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन के संबंध में निर्मित सीएनवी सिद्धांत और डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के अनुसार सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर विचार किया गया है:

तालिका 15

उत्पादक/निर्यातक	ईपी (अमेरिकी डॉलर/मी. टन)	एनवी (अमेरिकी डॉलर/मी. टन)	पाटन मार्जिन (अमेरिकी डॉलर/मी. टन)	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन रेंज
भारित औसत	****	****	****	****	50-60

(3) यूरोपीय संघ

क. यूरोपीय संघ के उन उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, जिन्होंने प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है:-

89. प्रश्नावली का उत्तर देने वाले यूरोपीय संघ के एक मात्र उत्पादक/निर्यातक ऑटोकम्पू ओई, फिनलैंड ने उत्तर दायर किए हैं। उत्पादक/निर्यातक ने उल्लेख किया है कि उनकी ईआरपी प्रणाली चौड़ाई के आधार पर विचाराधीन उत्पाद और जांचाधीन

उत्पाद की पहचान कर सकती है। ऑटोकुम्पू को जांचाधीन उत्पाद से विचाराधीन उत्पाद में परिवर्तन के संबंध में जानकारी नहीं है। यह मिल सीधे ही भारत में अंतिम प्रयोक्ताओं को बिक्री करती है। ऑटोकुम्पू ने भारत में घरेलू बिक्री, व्यापार पैटर्न और 10 शीर्ष ग्राहकों के संबंध में सूचना प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, व्यापार पैटर्न में परिवर्तन के संबंध में उनको विचार का समर्थन करने के लिए ग्रेड/सीरीज वार, ग्राहक-वार सूचना भी दी गई है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

90. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मैसर्स ऑटोकुम्पू ने प्रश्नावली के उत्तर में जांचाधीन उत्पाद की अपनी घरेलू बिक्री की कीमतें दी हैं, परंतु संबद्ध उत्पादन लागत नहीं बढ़ाई है। अतः प्राधिकारी ने जांच की अवधि के दौरान भारत को निर्यातित जांचाधीन उत्पाद की सीरीज के लिए घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत का संदर्भ देकर और यूरोप में अंतर्राष्ट्रीय कच्ची सामग्री की कीमतों (एचआर शीट्स) का संदर्भ देकर भी सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर सीएनवी की गणना की है। सीएनवी का मूल्यांकन जांचाधीन उत्पाद की **** डॉलर/मी. टन 300/400 के रूप में किया है। कारखानागत निर्यात कीमत की गणना ऋण लागत सहित भाड़ा, बिक्री खर्चों के निमित्त समायोजनों की अनुमति देकर की गई है। कारखानागत निर्यात कीमत **** डॉलर/मी. टन आती है। पाटन मार्जिन का मूल्यांकन **** डॉलर/मी. टन (**** प्रतिशत) के रूप में किया गया है जो न्यूनतम सीमा से अधिक है।

यूरोपीय संघ के सभी अन्य निर्यातकों के लिए सभी सीरीज और डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के लिए निर्मित सीएनवी के अनुसार सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर विचार किया गया है।

तालिका 16

ऑटोकुम्पू को छोड़कर अन्य सभी उत्पादक/निर्यातक	ईपी (अमेरिकी डॉलर/मी. टन)	एनवी (अमेरिकी डॉलर/मी. टन)	पाटन मार्जिन (अमेरिकी डॉलर/मी. टन)	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन रेंज
भारत औसत	****	****	****	****	5 - 15

(4) ताइवान

क. ताइवान के उन उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, जिन्होंने प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है:-

91. ताइवान के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं:

- i. वालसिन लिहवा कारपोरेशन
- ii. यीह यूनाइटेड स्टील कारपोरेशन, ताइवान (युसको)
- iii. युआन लांग स्टेनलेस स्टील कारपो., ताइवान (वाईएलएसएस)
- iv. तांग एंग आयरन वर्क्स कं. लि., ताइवान

- i. यीह यूनाइटेड स्टील कारपोरेशन, ताइवान (युसको)

उत्पादक/निर्यातक ने उल्लेख किया है कि उन्होंने अपनी ईआरपी प्रणाली में कॉइल संख्या के माध्यम से पहचान के आधार पर विचाराधीन उत्पाद और जांचाधीन उत्पाद की पहचान की है। भारत को जांच की अवधि के दौरान संबंधित पक्षकारों के माध्यम से कोई बिक्री नहीं की गई। घरेलू बाजार में बिक्री की सूचना स्वतंत्र एवं संबद्ध ग्राहकों को दे दी गई है। निर्यात बिक्री सूचित कर दी गई है जो स्वतंत्र भारतीय ग्राहकों को की गई थी।

जांच की अवधि के दौरान मैसर्स युसको ने घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद और जांचाधीन उत्पाद, दोनों की बिक्री की है। मैसर्स युसको ने भारत को जांचाधीन उत्पाद और जांचाधीन उत्पाद, दोनों का निर्यात भी किया है तथा वह इस बात से अवगत है कि क्या

जांचाधीन उत्पाद किसी अगले प्रसंस्करण के अध्वधीन रहा है। मैसर्स युसको ने किसी मध्यवर्ती देश के माध्यम से भारत को जांचाधीन उत्पाद का निर्यात नहीं किया।

व्यापार के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं है तथा जांचाधीन उत्पाद का बिक्री मूल्य विचाराधीन उत्पाद के बिक्री मूल्य से अधिक है। विचाराधीन उत्पाद और जांचाधीन उत्पाद की विनिर्माण प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है। मैसर्स युसको ने भारत में शीर्ष 10 ग्राहकों तथा घरेलू बिक्री, व्यापार पैटर्न के संबंध में सूचना प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, विचाराधीन उत्पाद और जांचाधीन उत्पाद के व्यापार पैटर्न के संबंध में परिवर्तन के समर्थन में ग्रेड/सीरीज-वार, ग्राहक-वार सूचना दी गई है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

प्राधिकारी ने जांच की अवधि के दौरान जांचाधीन उत्पाद की उत्पादन लागत को देकर जांच की अवधि के दौरान जांचाधीन उत्पाद की घरेलू बिक्री कीमत पर ओसीटी परीक्षण लागू कर जांचाधीन उत्पाद के सामान्य मूल्य का मूल्यांकन किया है। सामान्य मूल्य **** डॉलर/मी. टन आता है। कारखानागत निर्यात कीमत का मूल्यांकन अंतर्देशीय भाड़े, विदेशी भाड़े, विदेशी बीमा, ऋण लागत और सीमा शुल्क प्रभार पर समायोजनों की अनुमति देकर **** डॉलर/मी. टन के रूप में किया गया है। पाटन मार्जिन का मूल्यांकन **** डॉलर/मी. टन (**** प्रतिशत) के रूप में किया गया है जो न्यूनतम सीमा से अधिक है।

ii. मैसर्स बालसिन लिहवा, ताइवान

मैसर्स बालसिन लिहवा ने जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद और जांचाधीन उत्पाद की घरेलू और निर्यात बिक्री के ब्यौरे देकर प्रभावली का उत्तर दायर किया है जिसमें उन्होंने यह कहा है कि उन्होंने भारत को जांच की अवधि के दौरान केवल विचाराधीन उत्पाद की बहुत छोटी मात्रा का निर्यात किया है और इसका आयात अग्रिम लाइसेंस के तहत किया गया था।

प्राधिकारी द्वारा जांच

प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादक/निर्यातक ने जांच की अवधि के दौरान भारत को जांचाधीन उत्पाद का निर्यात नहीं किया है और इसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता कि क्या जांच की अवधि में जांचाधीन उत्पाद का निर्यात पाटित हुआ। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि यह उत्पादक/निर्यातक उनके द्वारा किए गए जांचाधीन उत्पाद के निर्यात के मामले में पाटनरोधी नियमावली के नियम 28 के अनुसार समीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस जांच के प्रयोजन के लिए इस उत्पादक/निर्यातक के संबंध में उत्पादकों/निर्यातकों की शेष श्रेणी के साथ विचार किया जाएगा।

iii. मैसर्स युआन लांग स्टेनलेस स्टील कारपो., ताइवान (वाईएलएसएस)

मैसर्स वाईएलएसएस ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- हम 430 सीरीज, 304 बीए और 304 2बी, 430 वाईडी, 439, 443 सीटी और 430 जे1एल देते हैं। उत्पादन श्रृंखला 1260 एमएम (स्लिट ऐज) तथा 1280 एमएम (मिल ऐज) हो सकती है और हम 600 एमएम के तहत चौड़ाई प्रदान कर सकते हैं।
- यद्यपि स्ट्रिप कॉइल अथवा नैरो वुड्स कॉइल हमारे उत्पादन की श्रृंखला में हैं, तथापि, वाईएलएसएस ने जांच की अवधि के भारत को केवल पूरी चौड़ाई की कॉइल (अर्थात 1250 एमएम) ही बेची। उस समय बिक्री क्रियाकलाप में कोई प्रसंस्करण अथवा असेंबलिंग शामिल नहीं थी।
- हमारा घरेलू बाजार में कोई चैनल नहीं है, परंतु हम भारत में अपने ग्राहक (वितरकों) को सामग्री बेचते हैं। हमारी कीमत हमारी कच्ची सामग्री की लागत तथा प्रसंस्करण लागत के अनुसार है, अतः हमने बिना किसी लाभ के सामग्री नहीं बेची।

- जब हम घरेलू बाजार में अपने ग्राहकों से कोई पूछताछ लेते हैं तो हम अंतिम ग्राहक को नाम पूछते हैं क्योंकि हमें यह देखना होता है कि क्या ग्राहक दो हैं अथवा नहीं है। यदि ग्राहक के चैनल में कोई समस्या नहीं है तब हम उनको अपनी सरकारी पेशकश भेजते हैं तथा उनकी टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते हैं। जब हम कीमत बोली प्राप्त करते हैं तो हम कीमत के समायोजन के लिए बाजार कीमत के साथ लागत और उपयुक्त कीमत की जांच करते हैं।
- जिस कॉइल का हम उत्पादन कर सकते हैं, वह मानक कॉइल है और हमारा कारखाना बिना किसी स्लिटिंग मशीन के अगला प्रसंस्करण करता है।
- हम नहीं जानते कि जो उत्पाद हमने बेचा है, उसे अंतिम प्रयोग के लिए रखे जाने से पहले तीसरे देश में विचाराधीन उत्पाद में परिवर्तित किया जा रहा है। व्यापारिक विचारों के आधार पर ग्राहक यह अनुमति नहीं देगा अथवा सूचित नहीं करेगा कि प्रयोजन क्या है अथवा गंतव्य क्या है।
- जांच की अवधि के दौरान केवल वाईएलएसएस की भारत को सीधी बिक्री है, मध्यवर्ती देशों अथवा तीसरे देश के माध्यम से बिक्री के संदर्भ में कोई अन्य बिक्री पद्धति नहीं है। वाईएलएसएस स्टेनलेस स्टील का विनिर्माता है जो अपने स्तर पर निर्यात क्रियाकलाप करने में सक्षम है और वह सीधे ही भारतीय क्रेताओं के साथ संपर्क करता है। तथापि, भारत को हमने जो मात्रा बेची है, वह बहुत कम है अर्थात् केवल **** मी. टन प्रति माह है जिससे वास्तव में पूरे भारतीय बाजार को क्षति नहीं होती।
- भारत को हमारी बिक्री के संबंध में केवल एक ही बिक्री पद्धति है जो भारतीय क्रेताओं को वाईएलएसएस से सीधे ही होती है।
- स्लिटिंग की प्रक्रिया द्वारा सामग्री विचाराधीन उत्पाद में होगी। हमारी कंपनी स्लिटिंग प्रक्रिया द्वारा सामग्री प्रदान कर सकती है, परंतु प्रसंस्करण लागत बहुत अधिक होने के कारण भारत में वह कीमत चलने लायक नहीं है। अतः भारत को हमारी निर्यात मात्रा बहुत कम है।
- विचाराधीन उत्पाद और जांचाधीन उत्पाद की लागत आबंटित करने के लिए, टाइप, थिकनेस, सरफेस, ग्रेड, ब्राइटनेस और उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन लाइन द्वारा अलग से लागत परिकलित की जाती है। फिर प्रत्येक मालसूची लागत और बेचे गए सामान की लागत में अलग से लागत वितरित की जाती है। विचाराधीन उत्पाद और जांचाधीन उत्पाद के बीच सिद्धांत समान हैं।
- घरेलू बाजार और अन्य देशों के लिए भारत में निर्यात के लिए कारखाना लागत में कोई अंतर नहीं है। विचाराधीन उत्पाद और जांचाधीन उत्पाद के लिए हमारे पास कोई पृथक लेखाकरण प्रणाली नहीं है।
- इस प्रश्नावली के उत्तर में दिए गए उत्पादन लागत संबंधी आंकड़े और लागत का निर्धारण सामान्यतः लेखाकरण प्रणाली प्रयोग करके किया जाता है और दी गई लागत तथा हमारी लेखाकरण प्रणाली द्वारा निर्धारित लागत के बीच कोई वास्तविक अंतर नहीं है।
- 400 सीरीज के लिए संभावित उत्पादन **** मी. टन तथा 300 सीरीज के लिए **** मी. टन है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

मैसर्स वाईएलएसएस ने प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं जिसमें उन्होंने जांच की अवधि के दौरान भारत को **** मी. टन की सीमा तक विचाराधीन उत्पाद और जांचाधीन उत्पाद, दोनों का निर्यात किए जाने का उल्लेख किया है। डीजीसीआईएस के आंकड़ों के साथ उसका सह संबंध बनाने पर यह नोट किया जाता है कि **** मी. टन जांचाधीन उत्पाद का है जबकि शेष **** मी. टन विचाराधीन उत्पाद है। उत्पादक/निर्यातक ने विचाराधीन उत्पाद के लिए **** ताइवानी डॉलर/मी. टन की निवल घरेलू बिक्री कीमत का दावा किया है। उत्पादक/निर्यातक ने उल्लेख किया है कि उनकी लेखाकरण प्रणाली उन्हें विचाराधीन उत्पाद और जांचाधीन उत्पाद के बीच भेद करने की अनुमति नहीं देती तथा उन्होंने विचाराधीन उत्पाद/जांचाधीन उत्पाद के

उत्पादन की भारत औसत लागत का दावा किया है। व्यापार परीक्षण की सामान्य प्रक्रिया लागू करने के बाद घरेलू बिक्री कीमत के साथ सह संबंध सामान्य मूल्य **** अमेरिकी डॉलर/मी. टन आता है। जांच की अवधि के दौरान जांचाधीन उत्पाद की कारखानागत निर्यात कीमत **** ताइवानी डॉलर/मी. टन आती है (**** अमेरिकी डॉलर/मी. टन) जो **** प्रतिशत तक पाटन सिद्ध करती है जो कि न्यूनतम से अधिक है।

उत्पादक/निर्यातक ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में **** से अधिक विचाराधीन उत्पाद बेचा है और इसीलिए जांचाधीन उत्पाद ने परिवर्तन की प्रवृत्ति भारत में निर्यात तक ही सीमित है।

इसके अतिरिक्त, उत्पादक/निर्यातक द्वारा 2008-09 और 2009-10 में प्रस्तुत भारत को किए गए निर्यात के संबंध में आंकड़े उसकी श्रेणियों अर्थात् विचाराधीन उत्पाद और जांचाधीन उत्पाद के संबंध में संकेत नहीं देते तथा उनका डीजीसीआईएस के आंकड़ों के साथ भी कोई सह संबंध नहीं है। चूंकि, उत्पादक/निर्यातक ने इनका विचाराधीन उत्पाद अथवा जांचाधीन उत्पाद होना साफ-साफ पुष्ट नहीं किया है, अतः प्राधिकारी मानते हैं कि उत्पादक/निर्यातक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद निर्यात में भारत में जांचाधीन उत्पाद में परिवर्तित करने, विशेष रूप से जब घरेलू बाजार में इसकी अधिकतम बिक्री विचाराधीन उत्पाद की है, का साक्ष्य देते हैं।

iv. तांग एंग आयरन वर्क्स कं. लि., ताइवान (तांग एंग)

तांग एंग ने उल्लेख किया है कि उन्होंने जांच की अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद की बिक्री नहीं की और उन्होंने कभी भी किसी जांचाधीन उत्पाद का उत्पादन अथवा बिक्री नहीं की है क्योंकि उनके उत्पादन उपस्कर जांचाधीन उत्पाद का विनिर्माण करने में सक्षम नहीं हैं। अतः तांग एंग के लिए यह संभव नहीं है कि वे जांचाधीन उत्पाद की बिक्री कर पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना करें, जैसा कि उपर्युक्त अधिसूचना में आरोप लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, यह अनुरोध किया गया था कि तांग एंग शुल्क की प्रवंचना के लिए कोई कार्यवाही नहीं करता तथा विचाराधीन उत्पाद पर लगाया गया पाटनरोधी शुल्क जांचाधीन उत्पाद पर नहीं लगाया जाना चाहिए।

प्राधिकारी द्वारा जांच

प्राधिकारी मानते हैं कि संबंधित देशों के उत्पादक/निर्यातक, जिन्होंने जांच की अवधि के दौरान भारत को जांचाधीन उत्पाद का निर्यात नहीं किया, को शेष श्रेणी में माना जाएगा और जो पाटनरोधी नियमावली के नियम 28 के तहत समीक्षा के लिए पात्र हैं, यदि स्थिति इसे जरूरी समझती हो और नियमों के तहत उसका औचित्य हो।

ख. उपर्युक्त को छोड़कर ताइवान के अन्य सभी उत्पादक/निर्यातक

92. उपर्युक्त को छोड़कर ताइवान के अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए डीजीसीआईएंडएस तथा निर्मित सीएनवी के अनुसार सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर पाटन मार्जिन निर्धारित किए गए हैं:

तालिका 17

युसको और बाईएलएसएस को छोड़कर अन्य गैर सहयोगी उत्पादक/निर्यातक	ईपी (अमेरिकी डॉलर/मी. टन)	एनवी (अमेरिकी डॉलर/मी. टन)	पाटन मार्जिन (अमेरिकी डॉलर/मी. टन)	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन रेंज
भारत औसत	****	****	****	****	10 - 20

पाटन मार्जिन

93. डीजीसीआईएंडएस के अनुसार निर्धारित कारखानागत स्तर पर निर्मित सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत की तुलना करते हुए संबद्ध देशों में शेष श्रेणी के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन निम्नलिखित रूप में दर्शाए गए हैं:

तालिका 18

विवरण	यूनिट	चीन	यूरोपीय संघ	कोरिया	दक्षिण अफ्रीका	ताइवान	थाइलैंड	संयुक्त राज्य अमेरिका
सीएनवी	अमेरिकी डॉलर/मी. टन	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
एनईपी	अमेरिकी डॉलर/मी. टन	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
पाटन मार्जिन	अमेरिकी डॉलर/मी. टन	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
पाटन मार्जिन	%	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
पाटन मार्जिन	रेंज	0 - 10	5 - 15	50-60	10-20	5-15	15-25	40-50

इस प्रकार सभी उत्तर न देने वाले उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक तथा काफी है।

सभी उत्तरदायी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

तालिका 19

विवरण	यूनिट	पोसको	ऑटोकम्पू	यूस्को	वाईएलएसएस
सीएनवी	अमेरिकी डॉलर/मी. टन	*****	*****	*****	*****
एनईपी	अमेरिकी डॉलर/मी. टन	*****	*****	*****	*****
पाटन मार्जिन	अमेरिकी डॉलर/मी. टन	*****	*****	*****	*****
पाटन मार्जिन	%	*****	*****	*****	*****
पाटन मार्जिन	रेंज	15 - 25	10 - 20	15 - 25	15 - 25

उपर्युक्त उत्तरदायी उत्पादकों/निर्यातकों का पाटन मार्जिन भी 2 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर से अधिक है।

विद्यमान पाटनरोधी उपायों और घरेलू उद्योग के संबंध में प्रवंचना के प्रभाव का मूल्यांकन

घरेलू उद्योग को छोड़कर विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध:

94. यूरोपीय आयोग ने अनुरोध किया कि प्राधिकारी को घरेलू उद्योग पर प्रवंचना के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए सभी संबद्ध देशों से प्रवंचना के प्रभाव का संचयी रूप से मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। घरेलू उद्योग को जांचाधीन उत्पाद के आयात के

कारण कोई क्षति नहीं हो रही है।

95. पोसको, कोरिया और उसकी संबद्ध कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले मैसर्स डीजीएस एसोसिएट्स ने अनुरोध किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए आंकड़े आयात की प्रकृति के केवल संकेतात्मक हैं और किसी भी तरह विचाराधीन उत्पाद के आयात पर पहले से ही लगाए गए पाटनरोधी शुल्कों के उपचारात्मक प्रभाव की दुर्बलता अथवा क्षति अथवा उपयोग स्थापित नहीं करता।
96. ऑटोकम्पू और युसको का प्रतिनिधित्व करने वाले मैसर्स ईएलपी के अधिवक्ताओं और न्यायवादियों ने निम्नलिखित उल्लेख किए हैं:
 - जांच की शुरुआत की अधिसूचना के पैरा 6 में प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह दर्शाने का प्रमाण है कि “विचाराधीन उत्पाद पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों के उपचारात्मक प्रभाव, जांचाधीन उत्पाद के आयात की काफी मात्रा के कारण दुर्बल बनाए जा रहे हैं, क्योंकि वे विचाराधीन उत्पाद के आयात का स्थान लेते हुए दिखाई देते हैं।”
 - यह स्पष्ट नहीं है कि प्राधिकारी वर्तमान जांच के लिए इस साक्ष्य को कैसे और क्यों संगत मानते हैं। याचिकाकर्ता ने उल्लेख किया है कि उसने नियम 25(1) के आधार पर प्रवंचनारोधी जांच दायर की थी, जैसा कि ऊपर कहा गया है, नियम 25(1) इस बात को ध्यान में नहीं रखता कि क्या पाटनरोधी शुल्कों के उपचारात्मक प्रभाव को कमजोर बनाया जा रहा है। वस्तुतः नियम 25(3) की व्याख्या (ख) के अनुसार यह एक शर्त है जिसे यह संतोष होने के लिए पूरा किया जाना अनिवार्य है कि नियम 25(3) के तहत व्यापारी परिपाटी, व्यापार के पैटर्न अथवा बिक्री के चैनलों में परिवर्तन हुआ है। निर्यातक ने पहले ही यह उल्लेख कर दिया है और दर्शा दिया है कि नियम 25(3) आवेदन पत्र में तथाकथित रूप से दी गई सूचना पर लागू नहीं होता क्योंकि यह याचिकाकर्ता का मामला नहीं है कि विचाराधीन उत्पाद का आयात निर्यातकों अथवा उत्पादकों अथवा पाटनरोधी शुल्क से असंबद्ध देशों के माध्यम से भारत में किया जा रहा है। तदनुसार, पाटनरोधी शुल्कों के उपचारात्मक प्रभाव को कम करने वाले साक्ष्य, यदि कोई है, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर असंगत है।
 - यह मानने पर भी कि वह सूचना संगत है, इस संबंध में आवेदन पत्र में कोई साक्ष्य नहीं है कि विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क के उपचारात्मक प्रभावों को कमजोर किया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि विचाराधीन उत्पाद के आयात की मात्रा 2010-11 के बाद बहुत ज्यादा घटी है अर्थात् विचाराधीन उत्पाद के आयात की मात्रा, जो 53420 मी. टन थी, घटकर जांच की अवधि में 20682 मी. टन तक नीचे आ गई है। जो भी हो, यह दर्शाता है कि विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण विचाराधीन उत्पाद का आयात मंद हुआ है और इसीलिए हम यह देखने में असमर्थ हैं कि पाटनरोधी शुल्क के उपचारात्मक प्रभावों को कैसे कमजोर किया जाता है। याचिकाकर्ता ने अपनी मात्रा और कीमत मानदंडों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी है। यदि याचिकाकर्ता का यह मामला है कि विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद याचिकाकर्ता के वित्तीय निष्पादन में सुधार नहीं हुआ है तो याचिकाकर्ता को उस संबंध में पुष्ट प्रमाण प्रदान करने चाहिए। ऐसी किसी सूचना के अभाव में हमें आश्चर्य है कि माननीय प्राधिकारी इस संबंध में आवेदन पत्र में साक्ष्य कैसे प्राप्त कर पाए कि “पाटनरोधी शुल्कों का उपचारात्मक प्रभाव कमजोर किया जा रहा है।”

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

97. संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद/जांचाधीन उत्पाद के उत्पादकों/निर्यातकों ने फरवरी, 2010 में सरकार द्वारा लगाए गए पाटनरोधी शुल्कों के समय से ही पाटनरोधी शुल्कों का प्रवंचना की प्रक्रिया में शामिल होकर पाटनरोधी शुल्कों के उपचारात्मक प्रभाव को कमजोर किया।
98. यह कि उन्हें निरंतर क्षति हो रही है क्योंकि जांचाधीन उत्पाद के आयात विचाराधीन उत्पाद के स्थान पर शुरू हो गए। विचाराधीन उत्पाद से जांचाधीन उत्पाद में खपत पैटर्न में बिना किसी तदनुसारी परिवर्तन के इस परिवर्तन से घरेलू उद्योग भारी रूप से प्रभावित हुआ है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

99. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रवंचना संबंधी उत्पाद का प्रभाव अर्थात् जांचाधीन उत्पाद, जो यदि संबद्ध देशों से पाटित हुआ तो संबद्ध देशों से जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद (पाटनरोधी शुल्क सहित) और जांचाधीन उत्पाद (किसी उपाय के बिना) आयात के पहुँच मूल्य की तुलना करके जांच किए जाने की आवश्यकता है जिसमें घरेलू उद्योग के विचाराधीन उत्पाद की निवल बिक्री वसूली पर कीमत न्यूनीकरण प्रभाव को और जिस घरेलू उद्योग पर प्रवंचक उत्पाद का प्रतिकूल प्रभाव पड़े, उसको

भी जांच करते समय ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है। निम्नलिखित तालिका में घरेलू उद्योग के विचाराधीन उत्पाद की निवल बिक्री वसूली पर प्रवंचक उत्पाद का कीमत प्रभाव और विचाराधीन उत्पाद पर मौजूदा पाटनरोधी उपायों की दक्षता का क्षरण दर्शाया गया है। संबद्ध देशों से जांच की अवधि के दौरान पाटनरोधी शुल्क के साथ विचाराधीन उत्पाद का पहुँच मूल्य जांचाधीन उत्पाद के पहुँच मूल्य से अधिक नोट किया गया है।

तालिका 20 – घरेलू उद्योग के विचाराधीन उत्पाद की बिक्री पर जांचाधीन उत्पाद द्वारा कीमत कटौती

देश	सीरीज	जांचाधीन उत्पाद आयात मात्रा (मी. टन)	जांचाधीन उत्पाद का पहुँच मूल्य (रु./मी. टन)	घरेलू उद्योग के विचाराधीन उत्पाद की बिक्री कीमत (रु./मी. टन)	कीमत कटौती (रु./मी. टन)	कीमत कटौती %	कीमत कटौती (रेंज)
चीन जन गण	200	****	****	****	****	****	****
	300	****	****	****	****	****	****
	400	****	****	****	****	****	****
भारित औसत कीमत कटौती चीन		19268	164192	****	****	****	(5) - 5
यूरोपीय संघ	200	****	****	****	****	****	****
	300	****	****	****	****	****	****
	400	****	****	****	****	****	****
	डुपलेक्स	****	****	****	****	****	****
भारित औसत कीमत कटौती यूरोपीय संघ		12138	194073	****	****	****	(15) - (5)
कोरिया गणराज्य	200	****	****	****	****	****	****
	300	****	****	****	****	****	****
	400	****	****	****	****	****	****
भारित औसत कीमत कटौती कोरिया		29180	109320	****	****	****	10-20
दक्षिण अफ्रीका	200	****	****	****	****	****	****
	300	****	****	****	****	****	****
	400	****	****	****	****	****	****
भारित औसत कीमत कटौती दक्षिण अफ्रीका		1901	175496	****	****	****	(10) - 0

ताइवान	200	****	****	****	****	****	****
	300	****	****	****	****	****	****
	400	****	****	****	****	****	****
भारित औसत कीमत कटौती ताइवान		4437	147656	****	****	****	5-15
थाइलैंड	200	****	****	****	****	****	****
	300	****	****	****	****	****	****
	400	****	****	****	****	****	****
भारित औसत कीमत कटौती थाइलैंड		1976	138748	****	****	****	10-20
संयुक्त राज्य अमेरिका	200	****	****	****	****	****	****
	300	****	****	****	****	****	****
	400	****	****	****	****	****	****
भारित औसत कीमत कटौती संयुक्त राज्य अमेरिका		6809	144167	****	****	****	5-15

तालिका 21 – उत्तरदायी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा घरेलू उद्योग के विचाराधीन उत्पाद की बिक्री पर जांचाधीन उत्पाद द्वारा कीमत कटौती

[illegible]

युसको	200	****	****	****	****	****	****	****
	300	****	****	****	****	****	****	****
	400	****	****	****	****	****	****	****
भारित औसत		****	****	****	****	****	****	(10)-0
वाईएलएसएस	400	****	****	****	****	****	****	5-15

जहां तक मौजूदा पाटनरोधी उपायों की दक्षता पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव का संबंध है, जांचाधीन उत्पाद द्वारा विचाराधीन उत्पाद की प्रवंचना के आयात का मूल्यांकन करने के लिए जांचाधीन उत्पाद (पाटनरोधी शुल्क के बिना) के पहुँच मूल्य और विचाराधीन उत्पाद (पाटनरोधी शुल्क सहित) के पहुँच मूल्य की तुलना घरेलू उद्योग की विचाराधीन उत्पाद की निवल बिक्री वसूली के साथ की गई है। निम्नलिखित तालिका इस प्रभाव को उल्लिखित करती है।

प्राधिकारी ने मौजूदा पाटनरोधी उपायों की दक्षता पर प्रवंचक उत्पाद के प्रभाव तथा विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उद्योग की बिक्री पर परिणामी कीमत प्रभाव का निष्कर्ष निकालने के लिए उपर्युक्त दो बातों पर विचार किया।

तालिका 22 – उत्तर देने वाले उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा पाटनरोधी शुल्क पर प्रवंचना का प्रभाव

उत्पादक/निर्यातक	सीरीज	जांचाधीन उत्पाद का पहुँच मूल्य (रु./मी. टन)	शुल्कों सहित विचाराधीन उत्पाद का पहुँच मूल्य (रु./मी. टन)	पाटनरोधी शुल्क पर प्रवंचना का प्रभाव (रु./मी. टन)	पाटनरोधी शुल्क पर प्रवंचना का प्रभाव %	पाटनरोधी शुल्क पर प्रवंचना का प्रभाव (रैंज)
पोसको	300	****	****	****	****	60-70
	400	****	****	****	****	50-60
ऑटोकम्पू	300	****	****	****	****	10-20
	400	****	****	****	****	
	डुपलेक्स	****	****	****	****	
युसको	200	****	****	****	****	लागू नहीं*
	300	****	****	****	****	
	400	****	****	****	****	
भारित औसत		****	****	****	****	
	200	****	****	****	****	
वाईएलएसएस	300	****	****	****	****	
	400	****	****	****	****	75-85

* 300/400 सीरीज के लिए विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क की सीमा तक दुर्बलता

तालिका 23 – संबद्ध देशों से उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा पाटनरोधी शुल्क पर प्रवंचना का प्रभाव

देश	भारित औसत पहुँच मूल्य जांचाधीन उत्पाद (रु./मी. टन)	शुल्कों सहित भारित औसत पहुँच मूल्य विचाराधीन उत्पाद (रु./मी. टन)	पाटनरोधी शुल्क पर प्रवंचना का प्रभाव (रु./मी. टन)	पाटनरोधी शुल्क पर प्रवंचना का प्रभाव %	पाटनरोधी शुल्क पर प्रवंचना का प्रभाव (रैंज)
चीन जन गण	****	****	****	****	30-40
यूरोपीय संघ	****	****	****	****	55-65
कोरिया गणराज्य	****	****	****	****	35-45
दक्षिण अफ्रीका	****	****	****	****	15-25
ताइवान	****	****	****	****	80-90
थाइलैंड	****	****	****	****	40-50
संयुक्त राज्य अमेरिका	****	****	****	****	95-105
कुल संबद्ध देश	****	****	****	****	45-55

प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणामों में मौजूदा पाटनरोधी उपायों की दक्षता पर प्रवंचना के प्रभाव पर विचार किया।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद/जांचाधीन उत्पाद के व्यापार पैटर्न में परिवर्तन समग्र स्तर पर है। प्रवंचक उत्पाद की स्लिटिंग निर्धारित स्तर से काफी कम स्तर तक मूल्य वर्धन के साथ कम आकारों में करने के भी साक्ष्य हैं। जांच की अवधि के लिए समग्र स्तर पर विचाराधीन उत्पाद/जांचाधीन उत्पाद का पहुँच मूल्य विचाराधीन उत्पाद पर मौजूदा पाटनरोधी उपायों की प्रवंचना के कारण प्रभाव दर्शाता है। उत्तरदायी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए विचाराधीन उत्पाद से जांचाधीन उत्पाद में व्यापार पैटर्न में परिवर्तन भी है। पोसको, कोरिया के मामले में प्रवंचना की अन्य सभी अपेक्षित शर्तों को पूरा करने के बाद भी भारत में आयात के लिए विचाराधीन उत्पाद से जांचाधीन उत्पाद में काफी परिवर्तन हुआ है। ऑटोकुम्पू के लिए यद्यपि यूरोपीय संघ और तीसरे देशों ने भी भारत के अतिरिक्त विचाराधीन उत्पाद से जांचाधीन उत्पाद में परिवर्तन है, परंतु भारत के लिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है और पाटनरोधी उपायों के अनुरूप है। युसको के लिए भी व्यापार पैटर्न परिवर्तन उनके घरेलू और तीसरे देश के बाजारों से तुलना करके अधिक सशक्त है। इसके मद्देनजर, प्राधिकारी मानते हैं कि यद्यपि कुछ परिवर्तन उभरती हुई प्रयोक्ता आवश्यकताओं के कारण हो सकते हैं, परंतु अधिकतर यह पाटनरोधी उपायों के अनुरूप है।

गैर विचाराधीन उत्पाद के लिए पोसको द्वारा जांचाधीन उत्पाद के प्रयोग पर पोसको के अनुरोधों के संबंध में, आईडीपीसी, आईसीपीसी और आईपीपीसी, भारत में पोसको, कोरिया के 3 स्लिटिंग केंद्रों द्वारा दर्ज आंकड़ों के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि 2008-09 से 2011-12 अर्थात् पाटनरोधी उपाय लगाए जाने की अवधि से पूर्व के दौरान गैर विचाराधीन उत्पाद की श्रेणी के सीधे आयात द्वारा घरेलू बाजार में 20-25 प्रतिशत गैर विचाराधीन उत्पाद की बिक्री पूरी की गई थी। गैर विचाराधीन उत्पाद की शेष बिक्री के लिए विचाराधीन उत्पाद की स्लिटिंग द्वारा 45 से 50 प्रतिशत तथा जांचाधीन उत्पाद की स्लिटिंग द्वारा 30 से 35 प्रतिशत पूरी की गई थी। 2012-13 से जांच की अवधि तक के दौरान अर्थात् पाटनरोधी उपाय लगाए जाने के बाद घरेलू बाजार में गैर विचाराधीन उत्पाद की बिक्री के 0-5 प्रतिशत की पूर्ति गैर विचाराधीन उत्पाद की श्रेणी के सीधे आयातों द्वारा की गई थी। शेष 95-100 प्रतिशत की पूर्ति जांचाधीन उत्पाद की स्लिटिंग द्वारा की गई थी। जहां तक इस अवधि में घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद की बिक्री का संबंध है, घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद की बिक्री के 10-15 प्रतिशत की पूर्ति विचाराधीन उत्पाद के सीधे आयात द्वारा की गई थी और 85-90 प्रतिशत की पूर्ति जांचाधीन उत्पाद की स्लिटिंग द्वारा की गई थी। यह नोट किया जाता है कि इस अवधि के दौरान आयातित जांचाधीन उत्पाद 10-15 प्रतिशत तक “केवल जांचाधीन उत्पाद” के रूप में बेचा गया था और शेष का प्रयोग विचाराधीन उत्पाद और/अथवा गैर विचाराधीन

उत्पाद में स्लिटिंग के लिए किया गया था। उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी ने आयात के उपयोग पैटर्न को जांचाधीन उत्पाद से गैर विचाराधीन उत्पाद में स्लिटिंग को भी प्रवंचना के रूप में माना।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों (निर्यातकों तथा आयातकों) ने उल्लेख किया है कि वे किसी प्रवंचना का सहारा नहीं ले रहे हैं और वे जांचाधीन उत्पाद की स्लिटिंग उसका प्रयोग विचाराधीन उत्पाद अथवा उससे नीचे के कम आकारों की चौड़ाई के रूप में प्रयोग के लिए नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में प्राधिकारी 12.10.2015 के अंतिम जांच परिणामों उल्लिखितानुसार ट्रिम और मिल ऐज के लिए अनुमत टोलरेंस की सीमा तक को छोड़कर आगे के प्रयोग के लिए स्लिट किए बिना केवल जांचाधीन उत्पाद के उपयुक्त प्रयोग के लिए आयातित जांचाधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क न लगाए जाने की आवश्यकता को मानते हैं।

प्राधिकारी यह नोट करते हुए कि जांचाधीन उत्पाद के किसी अधिकृत प्रयोक्ता को पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए जाने के साथ रखे जाने की आवश्यकता नहीं है, यह भी मानते हैं कि किसी भी सरकारी एजेंसी के लिए यह संभव नहीं है कि वे किसी अधिकृत प्रयोक्ता को प्रदान की गई किसी छूट की मॉनीटरिंग का प्रवर्तन करें और इसीलिए इस प्रयोजन के लिए जांचाधीन उत्पाद का आयात करने वाले सभी आयातकों से अपेक्षा होगी कि वे सीमा शुल्क प्राधिकारियों को कानूनी रूप से लागू की जाने वाली घोषणा/वचनबद्धता दें कि उनके द्वारा आयात किए जा रहे जांचाधीन उत्पाद का प्रयोग, यदि वे मौजूदा पाटनरोधी शुल्क का भुगतान नहीं करना चाहते हैं, दिनांक 11.12.2015 की सीमा शुल्क अधिसूचना 61/2015-सीमा शुल्क-एडीडी द्वारा लगाए गए दिनांक 12.10.2015 के अंतिम जांच परिणाम में उल्लिखित टोलरेंस की सीमा के सिवाय बिना किसी स्लिटिंग के किया जाएगा।

प्रकटीकरण के पश्चात टिप्पणियां

100. घरेलू उद्योग और निम्नलिखित इच्छुक पक्षकारों ने प्रकटीकरण के पश्चात टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं:

- 1) मैसर्स मीना मेटल इम्पेक्स
- 2) मैसर्स विशाल ट्यूब्स एंड पाइप्स लि.
- 3) मैसर्स स्टार स्टेनलेस स्टील
- 4) मैसर्स मैक्सग्रो कोरपोरेशन
- 5) मैसर्स सेठ कार्बन एंड एलोज्य प्रा. लि.
- 6) मैसर्स सिद्धिविनायक स्टील
- 7) मैसर्स ध्रुव एक्जिम
- 8) मैसर्स शक्ति स्टील
- 9) मैसर्स स्टील इंटरनेशनल
- 10) मैसर्स सेठ आयरन एंड स्टील प्रा. लि.
- 11) मैसर्स एस्टीरॉन
- 12) मैसर्स एसर स्टील
- 13) मैसर्स डिवाइन इम्पेक्स
- 14) मैसर्स स्टील यार्ड ओवरसीज
- 15) मैसर्स रमानी स्टील हाउस
- 16) मैसर्स नॉन-फेरस मेटल एसोसिएशन
- 17) मैसर्स नेक्सस इम्पेक्स
- 18) मैसर्स राकेश मेटल्स
- 19) मैसर्स मोडेस्ट मेटल कोरपोरेशन
- 20) मैसर्स स्टीलयार्ड ओवरसीज

- 21) मैसर्स आइनोक्स स्टेनलेस
- 22) मैसर्स सरस्वती स्टील
- 23) मारुती सुजुकी इंडिया लि. की ओर से मैसर्स केएनएम एंड पार्टनर्स
- 24) मैसर्स विराना प्रा. लि., सिंगापुर
- 25) मैसर्स सनसिटी शीट्स प्रा. लि., मैसर्स सनसिटी स्ट्रिप्स एंड ट्यूब्स प्रा. लि., मैसर्स सनराइज स्टेनलेस प्रा. लि. और मैसर्स सनमार्क स्टेनलेस प्राइवेट लिमिटेड का प्रतिनिधित्व करते हुए मैसर्स जीटीसी कंसल्टेंट्स
- 26) एनजी इंडस्ट्रीज, एमपी इंडस्ट्रीज और श्री रामदेव मेटल मार्ट का प्रतिनिधित्व करते हुए मैसर्स एगोल एसोसिएट्स
- 27) पोस्को और इसकी संबंधित इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हुए मैसर्स डीजीएस एसोसिएट्स
- 28) आउटोकुम्पु ओयज, फिनलैंड और युस्को का प्रतिनिधित्व करते हुए मैसर्स ईएलपी
- 29) मैसर्स एम एम मेटल इंटरनेशनल
- 30) ताइवान एम्बेसी
- 31) मैसर्स मेटल एंड स्टील (भारत)
- 32) पेसीफिक मेटल ट्रेडिंग कंपनी
- 33) ग्लोमेट एलायज एलएलपी
- 34) स्टेनॉक्स एलायज प्रा.लि.

क. घरेलू उद्योग के विचार

101. घरेलू उद्योग की ओर से मै. एपीजे-एसएलजी ने निम्नानुसार अनुरोध किया है :

- घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि ओटोकुम्पु के उत्तर को खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि वे प्रश्नावली फार्मेट में यथोपक्षित पूरी सूचना उपलब्ध कराने में असफल रहे हैं। प्राधिकारी को इस बात की समालोचना करनी चाहिए कि लागत के बारे में पूरी सूचना के बिना प्राधिकारी व्यापार परीक्षण की सामान्य अवधि भी निष्पादित नहीं कर सकता जो सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन के परिकलन के लिए अनिवार्य है।
- प्राधिकारी का ध्यान प्राधिकारी के हाल के जांच परिणाम (सोडियम क्लोरेट फा.सं. 14/13/2015- डी जी ए डी दिनांक 10.8.2017) की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें प्राधिकारी ने मै0 आकजो नोबेल के उत्तर को केवल इसलिए अस्वीकृत कर दिया कि उन्होंने अनिवार्य परीक्षणों के लिए पर्याप्त सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। चूंकि, लागत संबंधी सूचना के बिना प्राधिकारी अनिवार्य परीक्षण आयोजित नहीं कर सकते, ओटोकुम्पु के संबंध में वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर मै0 आकजो नोबेल का अस्वीकृति का तर्क पूरी तरह से लागू होता है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, यह अनुरोध किया जाता है कि समान परिस्थितियों में प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई सामान्य पद्धति के प्रकाश में प्राधिकारी ओटोकुम्पु के उत्तर को खारिज कर सकते हैं। इससे उत्पन्न कोई भी विचलन विवेकाधिकारपूर्ण होगा। संदर्भित जांच परिणामों का संगत भाग संदर्भ की सुगमता के लिए यहां नीचे प्रस्तुत किया गया है।

“20(i)..... प्राधिकारी ने धारित किया है कि कोई भी उत्पादक/निर्यातक निर्धारित प्रश्नावली का उत्तर आंशिक रूप से देने को नहीं चुन सकता। प्राधिकारी के लिए एक समेकित मूल्यांकन करने के लिए प्रश्नावली उत्तर में प्राधिकारी द्वारा मांगे गए आंकड़ों को पूर्ण रूप से पूरा किया जाना अनिवार्य है। प्राधिकारी ने मै0 आकजो नोबेल की आंशिक रूप से प्रस्तुत की गई सूचना को स्वीकार नहीं किया है और इसलिए उन्हें असहयोगी माना गया है और उन्हें केवल अवशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत समझा गया है और सहयोगी निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत ई.यू. में और डी जी सी आई एस आंकड़ों द्वारा भी बिक्री के संबंध में उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना संदर्भित सूचना के अनुसरण में पाटनरोधी उपाय निर्धारित किए हैं।”

- इक्विटी और पद्धति की निरंतरता को ध्यान में रखते हुए यह अनुरोध किया जाता है कि ओटोकुम्पु के उत्तर को अस्वीकृत किया जाना चाहिए।
- घरेलू उद्योग ने नियम 27 की शर्तों में जांच के आरंभ की तारीख से निवारणरोधी शुल्कों की सिफारिश करने के लिए प्राधिकारी से अनुरोध किया है। प्राधिकारी इस बात की समीक्षा करना चाहेंगे कि जांच आरंभ के बाद से पूरी 18 महीने व्यतीत हो चुके हैं जबकि निर्यात करने वाले उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा लागू किए गए पाटनरोधी शुल्कों के निवारण की स्थापित गलत प्रथा के कारण घरेलू उद्योग लगातार संकट का सामना कर रहा है।
- घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि यदि प्राधिकारी केवल संदर्शी निवारणरोधी शुल्कों की सिफारिश करते हैं, तो आयातकों/निर्यातकों का जांच को अवरुद्ध कर शुल्कों के समय विस्तारण में विलंब करने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। यह अनुरोध किया जाता है कि ऐसी स्थिति में प्राधिकारी का निर्णय केवल आंशिक रूप से प्रभावी होगा और वास्तव में, यह हितबद्ध पक्षकारों के प्रति अनुचित पक्षपात होगा जो पाटनरोधी शुल्कों के निवारण के लिए किया गया है। किसी भी स्थिति में, प्राधिकारी द्वारा यह समीक्षा करने की जरूरत है कि स्थित पाटनरोधी शुल्कों का समय विस्तार, प्राधिकारी द्वारा प्रस्तावित विशिष्ट छूट को ध्यान में रखते हुए असली प्रयोक्ताओं पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। केवल वो व्यापारी/प्रयोक्ता/ आयातक जो निवारण के कार्य में सम्मिलित हैं, को उनके कदाचार से "लाभ उठाने" से रोका जाएगा। विनम्रतापूर्वक यह अनुरोध किया जाता है कि ऐसे अनैतिक पक्षकारों को डी जी ए डी द्वारा किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जा सकती।
- नियम 27 की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें यह देखा जा सकता है कि जहां कानून लेवी की तारीख के लिए "कर सकते हैं" शब्द का प्रयोग करता है, जैसे ही पूर्ण निर्णय की स्थिति अर्थात् निवारण की विद्यमानता सिद्ध होती है, स्पष्ट विवेकाधिकार अब उपलब्ध नहीं होगा। विवेकाधिकार, यदि कोई हो, का भी मनमाने ढंग से प्रयोग नहीं किया जा सकता। किसी भी स्थिति में, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में जांच के आरंभ की तारीख से शुल्कों को लागू न करने का कोई भी कारण, जो भी हो, नहीं हो सकता।
- यह अनुरोध किया जाता है कि प्राधिकारी द्वारा पीयूआई के प्रयोक्ताओं के बहिष्करण के लिए प्रस्तावित वचनबद्धता का बैंक गारंटी द्वारा (ए डी ए राशि के समकक्ष) समर्थन किया जाना चाहिए और इस बांड को आयातकों/प्रयोक्ताओं/व्यापारियों द्वारा क्षेत्राधिकार अप्रत्यक्ष कर निर्धारण प्राधिकारी से प्राप्त प्रमाण पत्र दे दिए जाने के पश्चात स्वीकृत कर देना चाहिए कि सामग्री का स्लिटिंग के बिना प्रयोग किया गया है। ये बैंक गारंटियां आम तौर पर 6 महीने या 12 महीने की आरंभिक अवधि के लिए जारी की जाती हैं जिनमें आयातक को इस समय अवधि के भीतर अंतिम प्रयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए जिसके न होने पर बैंक गारंटी को नवीकरण कराना होगा। यदि आयातक बैंक गारंटी का नवीकरण कराने में असफल रहते हैं तो सीमाशुल्क अधिकारी आयातक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई आरंभ कर सकते हैं जो आरंभ में चूक का निपटान होने की स्थिति तक आईईसी स्थगन के रूप में होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई पीयूआई आयातक अंडरटेकिंग को प्रस्तुत करने के बाद भी स्लिटिंग का आश्रय ले सकता है (जब तक कि उसका बैंक गारंटी द्वारा समर्थन न किया गया हो जैसा कि ऊपर प्रस्तावित किया गया है) यह सुनिश्चित करने के लिए एक मानीटरिंग तंत्र होना चाहिए कि अंडरटेकिंग को प्रस्तुत करने के बाद सामग्री स्लिट नहीं की जा रही है। यह कुछ हद तक सीमाशुल्क (अनंतिम शुल्क मूल्यांकन) विनियम, 2011 के तहत अनंतिम स्वीकृति के समान होगा।
- घरेलू उद्योग ने जांचाधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्कों का विस्तार करने के प्राधिकारी के प्रस्तावित निष्कर्ष की उनसे पुष्टि करने का अनुरोध किया है क्योंकि पीयूआई विचाराधीन उत्पाद पर विद्यमान शुल्कों का निवारण कर रहा है और तदनुसार, घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहा है। चूंकि, निवारण का कार्य किसी भी बिंदु के परे साबित किया गया है, हम प्राधिकारी से प्रकटीकरण विवरण के प्रस्तावित निष्कर्ष की पुष्टि करने और जांच आरंभ की तारीख से शुल्कों को लागू करने की सिफारिश करने का अनुरोध करते हैं। यदि, प्राधिकारी अपनी राय में परिवर्तन करते हैं, हम प्राधिकारी से एक नए प्रकटीकरण बयान को जारी करने और हमारे मामले को विस्तार से बताने के लिए हमें व्यक्तिगत सुनवाई देने का भी अनुरोध करते हैं।

ख. अन्य हितबद्ध पक्षकारों की राय (संबद्ध देशों के दूतावासों/संबद्ध देशों से उत्पादक/निर्यातक और आयातक)

102. ताइवान दूतावास ने निम्नलिखित अनुरोध किया है :

- प्रकटीकरण बयान में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अवलोकन किया है कि विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) पर विद्यमान पाटनरोधी शुल्कों का निवारण निश्चित रूप से 1250 मिमी. से अधिक चौड़ाई के सभी संबद्ध देशों से आयातों के कारण घटित हो रहा है, जो जांचाधीन उत्पाद है। परिणामस्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पीयूआई के आयातों पर विद्यमान पाटनरोधी शुल्कों के विस्तार का प्रस्ताव किया है।
- ताइवान को इस पृष्ठभूमि को समझाना होगा कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा सामना की जा रही क्षति के स्तर का आकलन करने के लिए वर्तमान मामले में कीमत में कटौती को परिकलित नहीं किया है और प्रकटीकरण विवरण में पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-2 के साथ पठित नियम 11 के अंतर्गत अनिवार्यताओं को परिकलित नहीं किया है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने कहीं भी आकलन नहीं किया है यदि कथित निवारण घरेलू उद्योग को क्षति का कारण बनते हैं। निवारण को केवल व्यापार के पैटर्न में परिवर्तन द्वारा स्थापित नहीं किया जा सकता। अनुबंध-2 के साथ पठित नियम 11 की अनिवार्यताओं को एक निवारणरोधी जांच में भी पूरा किया जाना होता है। ए डी नियमावली के नियम 28 के नियम 25 किसी निवारणरोधी जांच में क्षति और कारणात्मक संबंध स्थापित करने की अनिवार्यता को छोड़ता नहीं है।
- ताइवान ने अनुरोध किया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को एडी नियमावली के अनुबंध-2 के साथ पठित नियम 11 के अंतर्गत अनिवार्यताओं को पूरा करना चाहिए। विशेष रूप से यह स्थापित करने की आवश्यकता है कि पीयूआई का पाटन है, घरेलू उद्योग को क्षति है और पाटित पीयूआई के आयातों और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संबंध है। वर्तमान जांच की अवधि में घरेलू उद्योग को क्षति और कारणात्मक संबंध का आकलन किया जाना चाहिए। इस अनिवार्यता को पूरा किए बिना, यह जांच एडी नियमावली के आधार और डब्ल्यूटीओ एडी समझौते का उल्लंघन करेगा जो पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध को स्थापित करने के लिए अनिवार्यता है। इसके अतिरिक्त, निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस मामले में कीमत में कमी (जिसे क्षति मार्जिन भी कहा जाता है) की भी संगणना करनी होगी। क्षति मार्जिन के बिना, घरेलू उद्योग द्वारा सामना की जा रही क्षति के स्तर को नहीं जाना जा सकेगा।
- प्रकटीकरण विवरण के पृष्ठ 68 पर दी गई सारणी के अनुसार यूस्को (वाईयूएससीओ) ताइवान की कीमत कटौती (10-0) नकारात्मक है। प्रकटीकरण विवरण के पृष्ठ 69 पर सारणी के अनुसार विद्यमान पाटनरोधी शुल्क पर निवारण का यूस्को प्रभाव भी नकारात्मक (45-55) है। इसे ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी को यूस्को के संबंध में अपने निष्कर्षों में संशोधन करना चाहिए कि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क में यूस्को के निर्यातों के कारण कोई निवारण नहीं हो रहा है और यूस्को द्वारा 1250 मिमी. से अधिक चौड़ाई वाले निर्यातों पर कोई पाटनरोधी शुल्क नहीं लगेगा।
- ताइवान ने आशा व्यक्त की है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी उक्त पहलुओं पर विचार करेंगे और उपर्युक्त अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए एक संशोधित प्रकटीकरण विवरण जारी करेंगे।

103. विभिन्न आयातकों ने निम्नानुसार अनुरोध किया है :

- नीचे उल्लिखित दो अवधियों के लिए पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं है क्योंकि इस अवधि में ए डी शुल्क रद्द था। इसलिए, किसी निवारणरोधी शुल्क को लागू करना गैर-कानूनी होगा। 22 अप्रैल, 2014 से 12 मई, 2014 तक कोई पाटनरोधी शुल्क प्रयोज्य नहीं है। 17 अक्टूबर, 2015 से 11 दिसंबर, 2015 तक कोई पाटनरोधी शुल्क प्रयोज्य नहीं है। कानून और सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णय के अनुसार, किसी समाप्ति चाहे वह एक दिन का हो, के पश्चात पाटनरोधी शुल्क या एसएसआर की प्रयोज्यता गैर कानूनी है। अतः निर्णायक समीक्षा और निवारणरोधी शुल्क की प्रयोज्यता स्वयं ही उत्पन्न नहीं होती।
- हम उत्तर देने वालों के बहुमत द्वारा किए गए निवारण के कोई उल्लेखनीय साक्ष्य नहीं देखते जो इस बात का साक्ष्य है कि पीयूसी के स्लिटिंग कॉयल का अनुपात तब दावा किए गए से बहुत कम होना चाहिए। प्रकटीकरण में आय के विवरण के अनुसार, केवल एक कंपनी पोस्को सर्विस सेंटर है, जो केवल बहुमत 400 सीरिज सामग्रियों की स्लिटिंग करता है लेकिन वह भी 600-1250 मिमी. चौड़ाई जो पीयूसी में मात्राओं का 20 प्रतिशत है। कृपया नोट करें कि 400 सीरीज एक ग्रेड है जो अधिकतर आटो सेक्टर में कम चौड़ाई में प्रयुक्त होता है और इसलिए एक सेक्टर में उत्पादों के प्रयोग को सभी के लिए एक सामान्य उदाहरण के रूप में नहीं लेना चाहिए।

- जांच शुरूआत अधिसूचना के अनुसार, पीयूसी को स्लिटिंग की जा रही 97 प्रतिशत मात्राओं का दावा न्यायोचित नहीं है। हम आश्चर्यचकित हैं कि प्राधिकारी ने ऐसे अस्पष्ट दावों को कैसे स्वीकार कर लिया।
- 300 सीरीज और 200 सीरीज में पीयूसी को स्लिटिंग को कोई साक्ष्य, जो भी हो, नहीं है।
- 300 सीरीज ग्रेड और 200 सीरीज ग्रेडों के मामले में समाप्ति का कोई मामला नहीं है।
- प्राधिकारी ने लंबी शीट को काटने पर कोई जवाब नहीं दिया है क्योंकि उन्हें स्लिटिंग करना तकनीकी रूप से संभव नहीं है और इस पर निवारण का कोई साक्ष्य नहीं है। यदि कोई उपलब्ध हो तो कृपया उसे प्रकट करें। चूंकि, कट-टू लैथ शीट के लिए समाप्ति का कोई मामला नहीं है, इसलिए इसे निवारण जांच से निकाल देना चाहिए।
- निम्नलिखित 2 श्रेणियों पर निवारणरोधी शुल्क लागू नहीं किया जाना चाहिए जिन्हें 1250 मिमी. और अधिक की चौड़ाई और इस से अधिक की आवश्यकता है और पीयूसी के अनुसार कोई स्लिटिंग नहीं कर रहे हैं जो अधिक चौड़ाई आयात कर रहे हैं और इसे 600 मिमी. से कम में स्लिट कर रहे हैं, जिस पर कोई पाटनरोधी शुल्क नहीं है।
- उन आयातकों/प्रयोक्ताओं जिन्होंने पहले ही प्रमाणित किया है कि उन्हें किसी स्लिटिंग प्रक्रिया या स्वयं की स्लिटिंग प्रक्रिया कारखाने की आवश्यकता नहीं है उन्हें सीमाशुल्क प्राधिकारियों के समक्ष कानूनी रूप से बाध्यकारी घोषणापत्र/अंडरटेकिंग प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।
- जिन कारखानों के पास स्लिटिंग प्रसंस्करण मशीन हैं अथवा जिनके पास स्लिटिंग प्रक्रिया है। केवल उन्हीं कारखानों से घोषणा के लिए कहा जा सकता है। कानूनी रूप से प्रवर्तनीय बैंक गारंटी अथवा बॉण्डो के लिए कहना सही नहीं है। अथवा उसे चुनौती दी जा सकती है।
- यह उनके लिए एक दण्ड प्रतीत होता है जिन्होंने विचाराधीन उत्पाद अथवा प्रवंचना के लिए कोई स्लिटिंग नहीं की है।
- इस संबंध में घरेलू उद्योग से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है कि वे इतना ज्यादा जांचाधीन उत्पाद का उत्पादन क्यों कर रहे हैं, जबकि जांचाधीन उत्पाद की इतनी आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अधिक चौड़ाई वाले उत्पादों का उत्पादन करने की विशेष क्षमता वाले ऐसे बड़े संयंत्र स्थापित किये, जबकि इसके लिए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी ?
- जिंदल स्टेनलैस स्टील 23 अगस्त 2011 तक एस.ई.जेड. यूनिट थी। जिंदल स्टेनलैस स्टील का उत्पादन, बिक्री, आयात और निर्यात के आंकड़ों को भारतीय बाजार के रूप में नहीं माना जा सकता।
- साथ ही प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारतीय बाजार में उनकी बिक्री के आंकड़ों को भारत में आयात के रूप में माना जाता है और इसीलिए उन्हें आंकड़ों के विश्लेषण, आयात के पैटर्न में परिवर्तन और भारत में बिक्री की विभिन्न तालिकाओं से अलग किया जाना होता है।
- प्राधिकारी ने जांचाधीन उत्पाद के भीतर भी आयात के पैटर्न का विश्लेषण किया है। यह नोट किया जाता है कि अधिकतर आयात आरंभिक सीमाओं से अधिक है और जांचाधीन उत्पाद के आयात का बहुत कम उत्पादन ही 1650 एम.एम से अधिक है। यह तत्व यह दर्शाता है कि संबद्ध देशों से उत्पादक/ निर्यातक तकनीकी अथवा प्रयोग के आधार पर किये गये मूल्यांकन के बजाय धीरे-धीरे चौड़ाई में अधिसूचित टॉलरेंस के मद्देनजर अधिक चौड़ाई ला रहे हैं। 1250, 1650 (30 प्रतिशत की दर से अधिक) की श्रृंखला की चौड़ाई को आरंभिक सीमाओं से अधिक कैसे माना जा सकता है तथा उनकी तुलना कैसे की जा सकती है ? जबकि 1250 के बाद अगली मानक चौड़ाई 1285 एम.एम, 1300 एम.एम, 1500 एम.एम और 1524 एमएम है। उन्हें आरंभिक सीमाओं से अधिक नहीं माना जा सकता, 30 प्रतिशत से अधिक किसी श्रृंखला को आरंभिक सीमाओं से अधिक कैसे माना जा सकता है ? यह आश्चर्यजनक लगता है। जब हम यह कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं कि 1-3 प्रतिशत की श्रृंखला

होना चाहिए और पाटनरोधी शुल्क में 2.5 प्रतिशत का टॉलरेंस मार्जन लगाया गया है। पिछले सभी 2005, 2009-10 तथा 2015 की निर्णायक समीक्षा में डी.जी.ए.डी. द्वारा स्वीकार किया गया है और उन्होंने पाटनरोधी शुल्क लागू करने के लिए 1250 एम.एम की चौड़ाई रखी है। आश्चर्यजनक रूप से प्राधिकारी एसएसआर 2015, एडीडी 2010 के मामले में 1250 एम.एम की चौड़ाई की सीमा के संबंध में अपनी जांचों को चुनौती दे रहे हैं।

- व्यापार पैटर्न परिवर्तन तार्किक और व्यावहारिक हैं, यहाँ तक घरेलू उद्योग भी काफी जांचाधीन उत्पाद का उत्पादन करता रहा है क्योंकि उसके लिए मांग बड़ी है, क्योंकि अधिक चौड़ाई किफायती दर के लिए बेहतर है।
- प्रोद्योगिकी परिवर्तन, व्यापार पर्यावरण परिवर्तन पूरे विश्व में होते हैं, सन् 2008 और 2017 में भारी अंतर है। प्राधिकारी प्रयोक्ता उद्योग को 2008 के आधार पर सामग्री का प्रयोग करने के लिए जोर दे रहे हैं, न कि नवाचार अथवा परिवर्तन के लिए।
- निम्नलिखित उत्पादन को जांच के क्षेत्र से बाहर होना चाहिए क्योंकि उनका उत्पादन घरेलू रूप से नहीं किया जाता है:-
प्राधिकारी को तथ्यों की जांच करनी चाहिए और बीए फिनीस में कोल्ड रोल्ड स्टेनलैस स्टील को सभी मामलों में पाटनरोधी शुल्क के क्षेत्र से हटाए जाने चाहिए।
- स्टेनलैस स्टील सीट-सरफैस ट्रीटेड, पोलिस्ट (डेकोरेटिव टाईकलर, एच पैटर्न, पोलिस मिरर सरफैस) वे सब अत्यधिक तकनीकी आवश्यकता वाले उत्पाद हैं और उनका प्रयोग एलीवेटरों, एक्सेलेटरों, होटलो, कार्यालयों के प्रवेश द्वारों, लोवियों के नामपटों आदि में किया जाता है और इन्हें गलती से पाटनरोधी में शामिल किया गया है।
- 0.50 एमएम और उससे कम की मोटाई में स्टेनलैस स्टील सीआर कॉयल एवं सीट (0.20 एमएम, 0.30 एमएम, 0.40 एमएम आदि) भी पाटनरोधी में शामिल 1000 एमएम, 1250 एमएम में उपलब्ध नहीं है।
- चैकर्ड/टीयर ड्रॉप/एंटीस्लीप तथा अन्य ट्रीटेड स्टेनलैस स्टील का प्रयोग फ्लौर प्लेटों के रूप में किया जाता है जो भारत में उपलब्ध नहीं है।
- हमें प्राधिकारियों से उपर्युक्त के संबंध में कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि प्रवचना संबंधी सभी प्रकलन 600 एमएम से 1250 एमएम तक की चौड़ाई के कोल्ड रोल्ड स्टेनलैस स्टील फ्लैट उत्पाद जिसका आगे 4 एमएम तक की मोटाई में कोल्ड रोल्ड किया जाए, के लिए ही किया जाना चाहिए।
- अतः जांच केवल उस उत्पाद की श्रृंखला तक ही रहना चाहिए। उपर्युक्त श्रृंखला से बाहर शामिल कोई भी उत्पाद वैध नहीं है। प्रयोक्ता उद्योग को आपकी समर्थन की आवश्यकता है तथा ऐसे मामलों को बंद किये जाने के लिए समय पर कार्यवाही करने की आवश्यकता है ताकि वास्तविक प्रयोक्ता उद्योग व्यापार के विस्तार, विकास, नवाचार पर ध्यान केंद्रित कर सके, न कि ऐसे अनावश्यक कानूनी विवादों, जांच और कानूनी खर्च पर। हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे आवेदक के इस आवेदन पत्र को बंद करें, क्योंकि आवेदन पत्र में उठाये गये दावे को गलत ढंग से रखा गया है और वे किसी भी मामले में सही नहीं हैं तथा कुछ मामलों में अवैध भी हैं।

104. मैसर्स मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (एम एस आई एल) का प्रतिनिधित्व करने वाले मैसर्स के. के. एम. एम. पार्टनर्स में निम्नलिखित अनुरोध किये हैं।

- जांचाधीन उत्पाद तथा चीन जन गण, कोरिया, यूरोपीय संघ, दक्षिणी अफ्रीका, ताईवान, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा यहां से निर्यातित 600 एमएम से 1250 एमएम की चौड़ाई के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पाद (विचाराधीन उत्पाद अथवा पीयूसी) के आयात पर 11 दिसंबर, 2015 की सीमा शुल्क अधिसूचना 61/ 2015- सीमा शुल्क- एडीडी द्वारा लगाये गये 12 अक्टूबर 2015 के अंतिम जांच परिणाम (जिसे आगे मूल जांच कहा गया है।) में लगाये गये पाटनरोधी शुल्क में जांचाधीन उत्पाद तथा उत्पाद समान वस्तु नहीं हैं, क्योंकि प्राधिकारी ने मूल जांच में दोनों उत्पादों को समान वस्तु नहीं माना

है और जांच के क्षेत्र से 1250 एमएम की अधिक चौड़ाई वाले उत्पादों को बाहर किया है।

- मूल जांच की मध्यावधि समीक्षा के दौरान प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से जांचाधीन उत्पाद को बाहर रखा है। प्राधिकारी ने नोट किया कि विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को जांचाधीन उत्पाद को शामिल करने के लिए जांच की मध्यावधि समीक्षा में नहीं बढ़ाया जा सकता। प्राधिकारी ने मूल जांच में यह नोट किया कि विचाराधीन उत्पाद 1250 एमएम से अधिक चौड़ाई के कोल्ड रोलड स्टील के क्षेत्र से बाहर है।
- अतः जांचाधीन उत्पाद को मूल जांच को बाहर रखा गया था तो याचिकाकर्ता उन उत्पादन के संबंध में मूल जांच का भाग बनते हुए प्रवचना-रोधी जांच शुरुआत नहीं कर सकते जो मूल जांच के क्षेत्र से साफ तौर पर बाहर किये गये थे और जिनके संबंध में प्राधिकारी ने यह सिफारिश की थी कि कोई पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने की आवश्यकता नहीं है।
- विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र पाटन का निर्धारण करने के लिए कार्यवाही से पूर्व विचार विमर्श और विस्तृत चर्चा के बाद प्रतिबंधित किया गया है और मूल जांच उन उत्पादों के संबंध में जो विशिष्ट प्रकार के, आकार के अथवा विशिष्ट के ही हैं।
- बाद में प्राधिकारी द्वारा मूल जांच के संबंध में 12 अक्टूबर 2015 के अंतिम जांच परिणाम के आधार पर केंद्र सरकार ने जांचाधीन उत्पाद अर्थात् 1250 एमएम से अधिक के कोल्ड रोलड स्टील को 11 दिसंबर 2015 की सीमा शुल्क अधिसूचना के द्वारा माना।
- अतः जब 1250 एमएम से अधिक चौड़ाई के कोल्ड रोलड स्टील को शामिल करने के अनुरोध को मूल जांच के संबंध में प्राधिकारी द्वारा तथा उपर्युक्त अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार द्वारा अंतिम जांच परिणाम में स्पष्ट रूप से रद्द कर दिया गया था, तो याचिका कर्ता दूसरे माध्यम से जांचाधीन उत्पाद के आयात के संबंध में प्रवचना-रोधी जांच शुरू नहीं कर सकते।
- आवेदक इस बात से पूर्णतः अवगत है कि 1250 एमएम से अधिक की चौड़ाई के कोल्ड रोलड स्टेनलैस स्टील वस्तु की भिन्न श्रेणी थी तथा उसे बार-बार वही माना गया था। यदि कुल मिलाकर ऐसी वस्तु के पाटन के विरुद्ध आपत्ति थी तो ऐसे पाटन की जांच करने के लिए स्वतंत्र कार्यवाहियां की जा सकती थीं। ऐसा न कर पाने पर स्पष्ट कारणों से क्योंकि आवेदक घरेलू उद्योग के रूप में अपने आधार का औचित्य संभवतः नहीं बना पाये। अतः उस ने पिछले दरवाजे से जांच की शुरुआत करने के लिए प्रवचना-रोधी हेतु आवेदन दायर किया, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।
- याचिका-कर्ता 31 मार्च 2014 की अनामेलन योजना के अनुसरण में पाटन रोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के तहत विचाराधीन उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग नहीं थे। याचिका-कर्ता के अपने को जेएचएसएल, नयी नयी बनायी गयी कंपनी, दर्शाने के अनुसार अनामेलन के अनुसरण में हुआ है। भारत में विचाराधीन उत्पाद के भारी मात्रा में उत्पादक बन गया। क्योंकि वह कानूनी रूप से वैध है और हिसार में विचाराधीन उत्पाद के लिए उसकी अपने स्वामित्व और प्रचालन वाली कंपनी है।
- उपर्युक्त अनामेलन और घरेलू उद्योग की परिभाषा के आलोक में प्राधिकारी को यह मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि क्या याचिका-कर्ता घरेलू उद्योग के मानदंड को पूरा करते हैं या नहीं। साथ ही इस तथ्य पर विचार करते हुए भी कि आवेदन पत्र केवल याचिका-कर्ता द्वारा जारी किया गया है, न कि ज़िंदल स्टेनलैस (हिसार) लिमिटेड द्वारा।
- विचाराधीन उत्पाद का आयात कोरिया के पोसको से उत्तरदायी द्वारा किया जाता है। जब विचाराधीन उत्पाद का आयात उत्तरदायी द्वारा किया जाता है तो इसे विभिन्न आकारों की चौड़ाई में काटा जाता है। इस के अतिरिक्त स्लिटिंग की प्रक्रिया में शामिल मूल्य वर्धन की लागत बहुत भारी है, इससे प्रवचना किफायती रूप से और वाणिज्यिक रूप से गैर-अर्थक्षम हो जाती है।

- इसके अतिरिक्त कोरिया, पोसको के उत्पाद/ निर्यातक ने उल्लेख किया है कि 80 प्रतिशत चौड़ाई वाले आयातों को 600 एमएम से कम की चौड़ाई में सील्ट किया जा रहा है जो कि तकनीकी रूप से विचाराधीन उत्पाद नहीं है, अतः कोई प्रवंचना नहीं है।
- जांचाधीन उत्पाद को उन आकारों में काटा जाता है, जो ऑटोमोटिव संघटकों में उनके द्वारा प्रयोग करने के लिए उत्तरदायी के प्रयोजनों हेतु उपयुक्त हैं। चूंकि उत्तरदायी द्वारा प्रयुक्त अंतिम उत्पाद जांचाधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर पड़ता है। अतः वह वर्तमान जांच की विषय-वस्तु नहीं हो सकता।
- घरेलू बाजार में प्रयोग पैटर्न में परिवर्तन हुआ है और जांचाधीन उत्पाद की मांग में स्वाभाविक वृद्धि हुई है, जिसे घरेलू उद्योग द्वारा जांचाधीन उत्पाद के उत्पादन में वृद्धि द्वारा पुष्ट किया जा सकता है।
- ऑटोमोटिव उद्योग में, वह उद्योग जिसकी पूर्ति यहां उत्तरदायी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनिवार्य रूप से की जाती है, मांग केवल कट टु लैंथ (सीटीएल) की है। आयातकों के लिए अपेक्षित सीटीएल आकारों को सीधे ही आयात करना आर्थिक अथवा वाणिज्य रूप से अर्थक्षम नहीं है, क्योंकि कम चौड़ाई का उत्पादन और परिवहन केवल लागत प्रभावी ही नहीं है अपितु इसमें इसे रद्द किये जाने के खतरे भी हैं, क्योंकि परिवहन में क्षति हो सकती है और इस प्रकार ग्राहकों के लिए सीटीएल आकार देना बेकार होता है।
- इसके अतिरिक्त चूंकि ऑटोमोटिव उद्योग स्वरूप में साफ-तौर पर प्रभावी है अतः इस बात की संभावना है कि वह आकार को बढ़ा दे जिसके लिए उसमें कुछ माह पूर्व आर्डर दिया था साथ ही कम चौड़ाई की वांछित कायल का परिवहन भी डिब्बों में सुपुर्दगी के माध्यम से किया जाना चाहिए, जिस से लागत में भारी वृद्धि ही होगी।
- ऑटोमोटिव उद्योग के लिए वास्तविक सीटीएल आकारों का आयात करना व्यावहारिक नहीं है और व्यापक चौड़ाई के उत्पाद का आयात करना पक्षकारों के लिए एकमात्र उपलब्ध व्यावहारिक विकल्प है, इस प्रकार जांचाधीन उत्पाद का आयात आर्थिक रूप से और वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम हो जाता है। यह बात दोहराई जाती है कि भारत में वांछित आकारों में स्लिट करने के लिए अधिक चौड़ाई के उत्पाद का आयात करने से उत्पादन हानि, परिवहन लागत अवशिष्ट कम होता है तथा इससे अंतिम प्रयोक्ता वास्तविक आपूर्ति के समय अपनी मांग किये गये आकारों, आवश्यकता के आधार को आसानी से बदल सकता है।
- अतः प्राधिकारी ऑटोमोटिव उद्योग द्वारा आयात किये गये उत्पादों को उपर्युक्त जांच के क्षेत्र से हटा सकते हैं, क्योंकि उपर्युक्त उत्पाद विचाराधीन उत्पाद का भाग नहीं है।
- कई ऑटोमोटिव कंपनियां तथा ओईएम संबद्ध उत्पाद के व्यापक आयातक हैं तथा उपर्युक्त अधिसूचनाओं के अनुसरण में लगाये गये पाटनरोधी शुल्क के प्रवंचना के रूप में माने जा रहे ऐसे उत्पादों के आयात से उपर्युक्त आयातकों के व्यापारिक हितों पर काफी प्रभाव पड़ेगा।
- याचिका-कर्ता ने आवेदन पत्र में यह तर्क दिया है कि जांचाधीन उत्पाद के आयात में 2008-09 से 2014-15 तक 27 प्रतिशत से 79 प्रतिशत तक का उछाल आया है। यह नोट किया जाता है कि जांचाधीन उत्पाद के आयात में वृद्धि इस्पात में आयात में वृद्धि में सामान्य पूर्ति है। वैश्विक रूप से स्टेनलैस स्टील का उत्पादन निरंतर बढ़ता रहा है। घरेलू स्टेनलैस स्टील उद्योग भी पिछले 7-8 वर्ष से 9 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर पर बढ़ता रहा है। तथापि भारत में किसी अन्य विनिर्माण क्षेत्र की तरह स्टेनलैस स्टील उद्योग भी पिछले कुछ वर्षों में अत्याधिक कठिनाई का सामना करता आ रहा है।
- इसका एक प्रमुख कारण चीन से भारी आयात में वृद्धि है, जिस के कारण स्टेनलैस स्टील उद्योग की स्थिति प्रमुख रूप से खराब हुई है। स्टेनलैस स्टील फ्लैट उत्पाद का आयात जो 2013-14 में 3,24,460 था वह 2015-16 में 5,32,033 के उच्चतम स्तर पर दर्ज हुआ।
- यह दर्शाने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि व्यापार के पैटर्न में यह परिवर्तन भारत के किये साधारण स्लिटिंग/ कटिंग से दिखाई देता है। जहाँ विचाराधीन उत्पाद का आयात उत्तरदायी सहित ग्राहकों द्वारा अंतिम प्रयोग से पूर्व परिवर्तित किया जाता है। इसीलिए उपर्युक्त जांच को रद्द किया जाना चाहिए।

- इसके अतिरिक्त इस संबंध में आवेदन पत्र में कोई साक्ष्य नहीं है कि विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क के उपचारात्मक प्रभाव को कमजोर किया जा रहा है। याचिका-कर्ता ने उस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया है।
 - अतः प्राधिकारी नोट कर सकते हैं कि आयात की वृद्धि में प्रवृत्ति आयात मानदंड के रूप में स्वाभाविक रूप से बढ़ी है, न कि विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने के आधार पर।
 - रिट याचिका डब्ल्यू पी (सी) 3544/2016 में दिल्ली उच्च न्यायालय के जारी आदेश दिनांक 08 मार्च 2017 पर आपत्ति करते हुए सनसिटी सीट्स प्रा. लि. में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक विशेष छूट याचिका-एसएलपी (सी) संख्या 1025/2017 दायर की और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 21 अप्रैल 2017 द्वारा (सर्वोच्च न्यायालय का आदेश संलग्न है) उपर्युक्त एसएलपी को स्वीकार कर लिया। उपर्युक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई की अगली तारीख अभी अधिसूचित की जानी है।
 - यहाँ यह अनुरोध किया जाता है कि चूंकि संबद्ध प्रवंचना जांच के संबंध में मामला पहले ही सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। अतः प्राधिकारी द्वारा शुरू की गयी संबद्ध प्रवंचना जांच फिलहाल स्थगित रखी जाए अथवा जांच परिणाम अथवा आदेश आस्थगित रखी जाए अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में अंतरिम अथवा अंतिम आदेश किये जाने तक रोकी जाए।
105. मैसर्स सनसिटी शीट्स प्रा. लि., मैसर्स सनसिटी स्ट्रीप्स एंड ट्यूब्स प्रा. लि., मैसर्स सनराइस स्टेनलैस प्रा. लि. और मैसर्स सनमार्क स्टेनलैस प्रा. लि. का प्रतिनिधित्व करने वाले मैसर्स जीटीसी कंस्ट्रेंट्स ने निम्नलिखित अनुरोध किये हैं।
- जैसा कि प्रकटन विवरण की प्रष्टभूमि में नोट किया गया है वर्तमान प्रवंचना रोधी कार्यवाहियाँ घरेलू उद्योग के दिनांक 21.09.2015 के आवेदन पत्र के आधार पर शुरू की गयी हैं। यह जानकारी मिलने पर कि उपर्युक्त आवेदन पत्र सितंबर 2015 में दायर किया गया था, वर्तमान कार्यवाहियों पर यह देखते हुए कार्यवाही नहीं की गयी कि पाटन-रोधी शुल्क नियमावली के नियम 25 में निर्धारित आयात की नई प्रवृत्ति को अधिसूचना के बाद ध्यान में लाया जाना चाहिए था जिनमें अधिसूचना द्वारा लगाये गये प्रवंचनारोधी शुल्क के प्रवंचना की मांग है। वर्तमान मामले में, जिसको प्रवंचित किये जाने का आरोप लगाया गया है। 16.12.2015 को ही जारी किया गया था और प्रवंचना के लिए आवेदन 21.09.2015 को ही दायर किया गया था, अतः इसे रद्द किया जाना चाहिए।
 - प्रकटन विवरण के के अवलोकन मात्र से यह सुझाव है कि नियम 25 की क्षेत्राधिकार वाली पूर्ण शर्तों को आयातक द्वारा पूरा न किये जाने के संबंध में उठाए गये विभिन्न तर्कों पर विचार नहीं किया गया है और इस संबंध एलडी प्राधिकारी द्वारा कोई विशेष जांच नहीं की गयी है। वर्तमान मामले में कोई भी पूर्ण शर्त संतोषजनक नहीं है, यथा..
- (क) 1250 एम एम से अधिक की चौड़ाई वाला सीआरएस वस्तु की पूर्णतः भिन्न श्रेणी है और यह निर्विवाद है कि और वह पाटनरोधी शुल्क के अध्यक्षीन नहीं है तथा उसके भिन्न वाणिज्यिक प्रयोग हैं अतः 1250 एमएम से अधिक की चौड़ाई के सीआरएस के किसी भी आयात को उस वस्तु के आयात के रूप में नहीं माना जा सकता जो पाटन-रोधी शुल्क के अध्यक्षीन है। अतः नियम 25 (1) किसी भी तरह वर्तमान मामले में लागू नहीं होता।
- (ख) 1250 एमएम से अधिक की चौड़ाई के सीआरएसएस परिकृत समान हैं और उन्हें एसेंबल न किये गये, परिष्कृत न किये गये अथवा अपूर्ण रूप में आयातित नहीं किया जाता है। इस संबंध में आवेदन पत्र में कोई भी ऐसा आयात प्रकट नहीं किया गया है कि कार्यवाहियों की शुरुआत का औचित्य करने के लिए यह शर्त प्रथम दृष्टया पूरी होती हो।
- (ग) भारत में 1250 एमएम से अधिक की चौड़ाई के सीआरएसएस के संबंध में कोई एसेंबली, फिनिशिंग अथवा कम्प्लीशन की प्रक्रिया नहीं की जाती है। भारत में आयातित सीआरएसएस परिष्कृत दशा में है। और किसी भी एसेंबली, फिनिशिंग अथवा कम्प्लीशन की भारत में आवश्यकता नहीं होती है।
- किसी भी दशा में पाटन-रोधी जांच से पूर्व कोई प्रचालन शुरू नहीं किया गया अथवा उसके बाद नहीं किया गया जोकि पाटन-रोधी शुल्क की प्रवंचना बने। इस प्रकार उपर्युक्त अनुरोधों पर एलडी प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाना चाहिए। प्रकटन

विवरण का अवलोकन यह बताता है कि उपर्युक्त मौलिक पहलुओं पर कोई विचार नहीं किया गया है, जो कि वर्तमान कार्यवाहियों की जड़ में हैं।

- इसके अतिरिक्त यह भी दोहराया जाता है कि आयातक ने अपनी शुरुआत से ही कभी भी विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है और इसीलिए आयातक के विरुद्ध प्रवंचना का आरोप नहीं लगाया जा सकता।
- यह अनुरोध है कि उपर्युक्त आयातकों को रोकने के लिए प्रकटन विवरण में दिया गया सुझाव यह है कि जांचाधीन उत्पाद का आयात करने वाले सभी आयातकों को सीमा शुल्क प्राधिकारियों को एक कानूनी रूप से प्रवर्तनीय घोषणा वचनबद्धता का देने की आवश्यकता होगी कि उनके द्वारा आयात किये जा रहे जांचाधीन उत्पाद का प्रयोग दिनांक 11.12.2015 की सीमा शुल्क अधिसूचना द्वारा लगाये गये दिनांक 12.10.2015 के अंतिम जांच परिणामों में उल्लेखित टॉलरेंस की सीमा तक छोड़ कर बिना किसी स्लिटिंग के द्वारा किया जायेगा। इस संबंध में एलडी प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित पर विचार करें।
- यह सुझाव अस्पष्ट प्रतीत होता है और कार्यान्वयन का वास्तविक तरीका प्रकटन विवरण में विशेष रूप से पाटन-रोधी शुल्क नियमावली के नियम 16 के आलोक में दिया जाना चाहिए था, जिससे अनुसार प्रकटन विवरण को विशिष्ट होने की आवश्यकता है।
- किसी भी स्लिटिंग के बिना प्रयोग किया जायेगा- जैसे शब्दों के साथ सामान्य वचन-वद्धता की आवश्यकता हटाए जाने की स्वीकृति के प्रयोजन को निरर्थक करेगी। वर्तमान आयातक जैसे विभिन्न आयातकों ने यह पुष्ट किया है कि 600 एमएम से कम चौड़ाई के लिए उत्पादों को स्लिट करने के लिए जांचाधीन उत्पाद का आयात किया जा सकता है, जिनकी आयातकों को पाइपों का विनिर्माण करने के लिए आवश्यकता होती है और जिस प्रक्रिया को पाटन-रोधी शुल्क नियमावली के तहत प्रवंचना नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार प्रकटन विवरण में निर्धारित व्यापक केवल गैर-विशिष्ट उपाय में उपर्युक्त पर विचार करते हुए संशोधन किया जाना चाहिए।
- आयातक यह दोहराते हैं कि इस एलडी प्राधिकारी के सक्षम दायर आवेदन पत्र में आवेदक का गोपनीयता को दावा निराधार है और वे आयातक के अधिकारों का पूर्वाग्रह है तथा तदनुसार ऐसे दावे को रद्द किया जाना चाहिए।
- उपर्युक्त के मद्देनजर वर्तमान प्रवंचना-रोधी कार्यवाहियां कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होंगी क्योंकि एलडी प्राधिकारी द्वारा इसी प्रकार के कई मुद्दों की जांच पहले ही की जा चुकी है और आवेदक के विरुद्ध निर्णय लिया गया है तथा इस से संबंधित एकमात्र उपलब्ध विकल्प यह है कि 1250 एमएम से अधिक चौड़ाई के सीआरएसएस पर पाटन-रोधी शुल्क लगाये जाने के लिए नये सिरे से जांच की जानी चाहिए।

106. मैसर्स एन.जी. इंडस्ट्रीज, मैसर्स एम.पी. इंडस्ट्रीज और मैसर्स श्री रामदेव मेटल मार्ट का प्रतिनिधित्व करते हुए मैसर्स एगोल एसोसिएट्स ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

- इस टिप्पणी के साथ कोई पक्षपात किए बिना कि मैसर्स एन.जी. इंडस्ट्रीज, मैसर्स एम.पी. इंडस्ट्रीज और मैसर्स श्री रामदेव मेटल मार्ट ने जांचाधीन अवधि के दौरान उत्पाद के लिए कोई स्लिटिंग प्रक्रिया नहीं की है और सभी सामग्री किसी स्लिटिंग/रूपांतरण प्रक्रिया के बिना बेची गई है, यह उल्लेख किया जाता है कि निर्धारित प्राधिकरण के पास सीमा-शुल्क दर (डम्प की गई वस्तु पर एंटी-डम्पिंग शुल्क की पहचान, आकलन तथा एकत्रीकरण और नुकसान का निर्धारण) नियम, 1995 का नियम 25 लागू करने के लिए यह निर्णय करने का कोई अधिकार अथवा क्षेत्राधिकार नहीं है कि आयात किए जाने के बाद क्या होता है। यह भी कानून में स्थापित है कि वस्तुओं का आकलन उसी रूप में किया जाना होगा जिस रूप में उन्हें आयात किया जाता है और सीमा-शुल्क प्राधिकरण के समक्ष रखा जाता है और आयात के बाद किसी प्रक्रिया से निर्मित तैयार वस्तुओं के आधार पर नहीं। वरेली वीव्ज प्रा. लि. बनाम भारत संघ [1996 (83) ई.एल.टी. 255 (एस.सी.)] के रिपोर्ट किए गए निर्णय में प्रश्न यह था कि क्या निर्धारिती द्वारा किए गए आयात पर बाद में किसी प्रक्रिया के बाद तैयार होने पर उस वस्तु पर प्रतिकारी शुल्क देय है। यह कहा गया था कि ऐसी वस्तुओं पर उसी राज्य में शुल्क लगाया जा सकता है जिसमें इन्हें आयात किया गया है। यह निर्णय दिया गया था कि वस्तुओं पर प्रतिकारी शुल्क उस राज्य में लगाया जाना चाहिए जहां इन्हें आयात किया गया है। यह सीमा-शुल्क दर अधिनियम की धारा 3 के आधार पर कहा गया था। डनलप इंडिया एंड मद्रास रबड़ फैक्टरी लि. बनाम भारत संघ [1983 (13) ई.एल.टी. 1566 (एस.सी.)] मामले में भी यही दृष्टिकोण अपनाया गया था।

2008 (231) ईएलटी 385 (एस.सी.) में रिपोर्ट किए गए सीमा-शुल्क आयुक्त, नई दिल्ली बनाम सोनी इंडिया लि. मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को भी आधार बनाया जाता है।

- आवेदक द्वारा दायर किए गए आवेदन से पता चलता है कि वे एडीडी नियमों के नियम 25(1) को आधार बना रहे हैं। यह उल्लेख किया जाता है कि यह स्वीकार न करते हुए भी कि आवेदक के आरोप सही हैं, यह जांच शुरू करने का आधार नहीं हो सकता जब तक कि यह तथ्यात्मक रूप से और कानूनी रूप से प्रमाणित न किया जाए कि विचाराधीन उत्पाद अलग-अलग भागों में, अधूरा अथवा अपूर्ण स्वरूप में है और इसे भारत में जोड़ा गया, तैयार किया गया अथवा पूरा किया गया है। केवल किसी 1250 मिमी. से अधिक चौड़ाई के उत्पाद को भारत में आयात किए जाने के बाद उसकी स्लिटिंग करने से इसे जोड़ने, तैयार करने अथवा पूरा करने के लिए लागू प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती। 1250 मिमी. से अधिक चौड़ाई वाले उत्पादों को छोटे आकार के टुकड़ों में काटने से उपर्युक्त नियम के नियम 25 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। नियम 25(1) में उल्लेख किया गया है कि उप-नियम (1) में उल्लिखित प्रक्रिया एंटी-डंपिंग जांच शुरू होने से ठीक पहले शुरू अथवा बढ़नी चाहिए “और पार्ट तथा घटक” अधिसूचित देशों से आयात किए जाएं। इसलिए नियम 25(1) को पूरी तरह से पढ़ने के बाद यह स्पष्ट है कि यह केवल उन मामलों में लागू है जहां विचाराधीन उत्पाद के पार्ट अथवा घटक अलग-अलग भागों में, अधूरे अथवा अपूर्ण स्वरूप में आयात किए जाते हैं और भारत में जोड़े, तैयार किए अथवा पूरे किए जाते हैं, जो कि नियम 25(1) के क्षेत्र में आता है। न ही आवेदक ने और न ही जारी की गई अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि कैसे अलग-अलग भागों में, अधूरी अथवा अपूर्ण वस्तु को जोड़ा गया, तैयार किया गया अथवा पूरा किया गया और नियम 25(1) के प्रावधान लागू हुए। इसलिए सीमा-शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष एक कानूनी रूप से लागू घोषणा/शपथपत्र दिए जाने की आवश्यकता अनुचित है और सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 और सीमा-शुल्क दर अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के तहत इसके लिए कोई स्वीकृति नहीं है। बिना किसी पक्षपात के उन हकदारों पर ऐसी किसी घोषणा का दबाव नहीं दिया जाना चाहिए जिनके पास स्लिटिंग अथवा संसाधन की सुविधा नहीं है।
- वर्तमान मामले में अंतिम घोषणा के बाद यह उल्लेख किया गया है कि भारत में आयात के बाद पीयूसी की स्लिटिंग का प्रमाण है। यदि यह सत्य भी हो तो यह नियम 25 लागू करने का आधार नहीं है। वास्तव में जिन मामलों में वर्तमान एडीडी से बचने के लिए वस्तुएं अलग-अलग भागों अथवा टुकड़ों की स्थिति में आयात की जाती हैं न्यायालय ने यह व्याख्या की है कि सीमा-शुल्क दर की व्याख्या के सामान्य नियमों का नियम 2(क) लागू करते हुए वस्तुओं को पूर्ण वस्तु समझा जाएगा बशर्ते कि अलग-अलग भागों में अथवा टुकड़ों में एक साथ प्रस्तुत किया जाए। इस प्रकार विपरीत स्थिति को एडीडी के क्षेत्र में नहीं माना जा सकता। 2013 (287) ईएलटी 19 (दिल्ली) में रिपोर्ट किए गए नव दुर्गा एसोसिएट्स बनाम भारत संघ के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को आधार बनाया गया है।
- यह उल्लेख किया जाता है कि भारत संघ बनाम मैसर्स कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स कम्पनी लिमिटेड (2014 की एसएलपी (सी) सं. 29268-29269 से उठाई गई 2017 की सिविल अपील सं. 008309-008310) के मामले में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि वर्तमान एंटी-डंपिंग शुल्क की अवधि समाप्त होने के बाद एंटी-डंपिंग शुल्क में एक वर्ष की बढ़ोतरी अवैध होगी। वर्तमान मामले में एंटी-डंपिंग अधिसूचना 22.4.2014 तक लागू थी और सरकार ने 12.05.2014 को अधिसूचना सं. 20/2014-सीमा-शुल्क (एडीडी) जारी करके विचाराधीन उत्पादों पर एडीडी 21.04.2015 तक बढ़ा दी। समयावधि बढ़ाए जाने की अधिसूचना पूर्व अधिसूचना की अवधि समाप्त होने के दो सप्ताह से भी अधिक समय बाद जारी की गई और इसलिए कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स कम्पनी (सुप्रा) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को देखते हुए वर्तमान एंटी-डंपिंग समय की समाप्ति के बाद एंटी-डंपिंग समय को बढ़ाना अवैध होगा। इसलिए जब समय में वृद्धि ही अवैध है तो परिणामी एंटी-सर्कम्वेंशन शुल्क भी अवैध होगा। आगे यह उल्लेख किया जाता है कि दिनांक 11.12.2015 की अधिसूचना सं. 61/2015 द्वारा सनसेट समीक्षा के निष्कर्षों के अनुसार एडीडी जारी रखा गया। इसलिए एडीडी को आगे बढ़ाने के लिए दिनांक 11.12.2015 की अधिसूचना सं. 61/2015 से पहले और समय बीत चुका था। इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय इस मामले में पूरी तरह से सटीक बैठता है और इसके परिणामस्वरूप बार-बार एडीडी का समय बढ़ाना अवैध था। परिणामस्वरूप यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि जब विचाराधीन वस्तुओं पर कोई एडीडी नहीं था तो एंटी-सर्कम्वेंशन शुल्क के संबंध में जांच शुरू किया जाना अवैध होगा।

- प्राधिकरण पहले ही 1250 मिमी. से अधिक के कॉल्ड रोलड स्टेनलेस स्टील पर एडीडी लगाए जाने के प्रश्न पर विचार कर चुका है और दिनांक 24.11.2010 के अंतिम निष्कर्ष में 1250 मिमी. से अधिक के उत्पादों को प्रावधान से बाहर रखे जाने के समर्थन में विस्तृत निष्कर्ष देते हुए आवेदक के 1250 मिमी. से अधिक चौड़ाई के उत्पादों को शामिल किए जाने संबंधी दलील को खारिज कर दिया था। उपर्युक्त सिफारिशें केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई थीं और दिनांक 20.02.2010 की अधिसूचना सं. 14/2010-सीमा-शुल्क द्वारा विचाराधीन उत्पाद पर एडीडी लगाया गया था। तत्पश्चात् 23.06.2010 को मध्यावधि समीक्षा को भी केवल विचाराधीन उत्पादों तक सीमित कर दिया गया था। उसके बाद आवेदक ने माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यावधि समीक्षा के कार्यक्षेत्र को चुनौती देते हुए 2010 की रिट याचिका सं. 6544 दायर की। माननीय उच्च न्यायालय ने यह निर्देश देते हुए दिनांक 8.10.2010 के आदेश द्वारा उपर्युक्त रिट याचिका का निपटान कर दिया कि आवेदक द्वारा रिट याचिका में दी गई चुनौती पर भी मध्यावधि समीक्षा के समय विचार किया जाना था। मध्यावधि समीक्षा की कार्यवाही में निर्धारित प्राधिकारी ने निर्णय दिया कि समीक्षा केवल विचाराधीन उत्पाद की चौड़ाई के संबंध में सहयता निर्धारित करने के लिए वर्गीकरण हेतु है और न तो ज़िंदल ने उत्पाद के क्षेत्र को बढ़ाने का अनुरोध किया है और न ही इस पर विचार किया गया। निर्धारित प्राधिकारी ने दिनांक 8.6.2011 की अपनी मध्यावधि समीक्षा में निर्णय दिया कि 1250 मिमी. से अधिक चौड़ाई वाली वस्तुओं को एडीडी के क्षेत्र से बाहर रखा जाना सही था। यह उल्लेख किया जाता है कि बाद में एडीडी नियम के नियम 25 के अनुसार और ज़िंदल द्वारा विचाराधीन उत्पाद पर लागू एडीडी को जारी रखने की मांग करते हुए दायर किए गए आवेदन के आधार पर निर्धारित प्राधिकारी ने सनसेट समीक्षा के लिए अधिसूचना की कार्रवाई शुरू की। मैसर्स ज़िंदल ने निर्धारित प्राधिकारी से 1250 मिमी. से अधिक चौड़ाई के उत्पादों को शामिल करने का अनुरोध किया। उपर्युक्त अनुरोध को निर्धारित प्राधिकारी द्वारा दिनांक 12.10.2015 के अपने अंतिम निष्कर्ष द्वारा खारिज कर दिया गया और केंद्र सरकार ने पीयूसी पर एडीडी को जारी रखते हुए दिनांक 11.12.2015 की सीमा-शुल्क अधिसूचना सं. 61/2015-सीमा-शुल्क जारी कर दी। निर्धारित प्राधिकारी द्वारा दिनांक 5.12.2015 के अपने अंतिम निष्कर्ष में मैसर्स ज़िंदल की अधिक चौड़ाई की स्ट्रिप के प्रयोग को कम चौड़ाई वाली स्ट्रिप के प्रयोग से आपस में बदलने के संबंध में दी गई दलील पर विचार किया गया था, जहां यह पाया गया कि अधिक चौड़ाई के उत्पादों को आयात करने और इनकी स्लिटिंग के लिए पूरी तरह से अलग प्रचालन व्यवस्था की आवश्यकता होती है जिसके लिए प्रयोक्ता द्वारा उल्लेखनीय निवेश किया जाना होता है, जो कि व्यर्थ होने तथा उच्च लागत के कारण व्यवसायिक रूप से व्यवहार्य नहीं है विशेष रूप से लघु एवं मध्यम स्तर के प्रयोक्ताओं के लिए। उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि मैसर्स ज़िंदल के 1250 मिमी. से अधिक चौड़ाई के उत्पादों को शामिल करने के अनुरोध को निर्धारित प्राधिकारी द्वारा बार-बार इस आधार पर खारिज किया गया कि घरेलू उद्योग के इस दावे के बावजूद कि उनके पास 1550 मिमी. चौड़ाई तक के निर्माण की सुविधा उपलब्ध है, न तो 1250 मिमी. से अधिक चौड़ाई के उत्पादों का उत्पादन किया और न ही इनकी आपूर्ति की और यह कि अधिक चौड़ाई के उत्पाद को आयात करने और स्लिटिंग करने की प्रक्रिया तकनीकी तथा आर्थिक रूप से अव्यवहार्य है। मैसर्स ज़िंदल ने 2008-09 से 2014-15 की अवधि से संबंधित आयात की तारीख को आधार बनाते हुए 1250 मिमी. से अधिक चौड़ाई के उत्पादों के आयात द्वारा सर्कमवेंशन का आरोप लगाते हुए उन्हीं आधार पर वर्तमान आवेदन दायर किया है बावजूद इस तथ्य के कि उपर्युक्त अवधि के दौरान किए गए आयात पर अंतिम निष्कर्ष दिए जाने की पूर्व की कार्यवाहियों और सनसेट समीक्षा कार्यवाहियों के दौरान पहले ही विचार कर लिया गया था। दिनांक 19.2.2016 की वर्तमान कार्रवाई अधिसूचना जारी करके पूर्व में निर्धारित प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय की समीक्षा करने का प्रयास किया जा रहा है और यह स्थापित कानून है कि जो चीजें प्रत्यक्ष रूप से नहीं की जा सकती वे अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं की जा सकती। सनसेट समीक्षा में निर्धारित प्राधिकारी ने यह स्वीकार किया है कि क्षेत्र उन उत्पादों तक सीमित है जो कि अंतिम निष्कर्ष में परिभाषित किए गए हैं और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र की समीक्षा अथवा इसे बढ़ाने के लिए कोई अधिकार नहीं है। वास्तव में कथित सर्कमवेंशन के आधार में भी यह उल्लेख किया गया है कि मैसर्स ज़िंदल वर्तमान एंटी-डंपिंग शुल्क की समीक्षा की मांग कर रहे हैं।
- आगे यह उल्लेख किया जाता है कि आवेदक इस बात की पुष्टि करने में असफल रहा है कि वे उपर्युक्त नियम में परिभाषित “घरेलू उद्योग” में कैसे आते हैं। इसके अतिरिक्त यह प्रदर्शित करने के लिए कोई प्रमाण नहीं दिया गया है कि वे विचाराधीन उत्पाद का उल्लेखनीय मात्रा में निर्माण तथा आपूर्ति कर रहे हैं। पहले यह स्थापित किया जाना आवश्यक है कि कथित सर्कमवेंशन से उन्हें नुकसान हुआ है। घरेलू उद्योग से इस बात का कोई उत्तर नहीं मिला है कि वे उल्लिखित मात्रा में पीयूआई का उत्पादन क्यों कर रहे हैं जबकि घरेलू बाजार में पीयूआई का कोई बाजार अथवा आवश्यकता नहीं है। आवेदक द्वारा इस संबंध में कोई औचित्य नहीं दिया गया है कि क्यों उन्होंने अधिक चौड़ाई की वस्तुओं के उत्पादन के लिए विशेष क्षमता वाले ऐसे बड़े संयंत्र लगाए हैं जबकि स्थानीय बाजार में इसकी कोई मांग नहीं है। ये सभी पहलू आवेदक की नीयत के संबंध में शंका

पैदा करते हैं। मैसर्स जिंदल स्टेनलेस 23 अगस्त, 2011 तक एक विशेष आर्थिक जोन था। इसलिए आवेदक द्वारा उत्पादन, बिक्री, आयात तथा निर्यात के संबंध में दिए गए आंकड़ों पर घरेलू उद्योग अथवा भारतीय बाजार स्थिति का प्रतिनिधित्व करने वाले आंकड़ों के रूप में विचार नहीं किया जा सकता। उनके द्वारा दायर किया गया आवेदन केवल इस आधार पर ही उचित नहीं है। तथापि निर्धारित प्राधिकारी ने इस टिप्पणी के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं दिया है और दूसरी ओर यह उल्लेख किया कि विचाराधीन उत्पाद की घरेलू उद्योग की बिक्री पर मूल्य का प्रभाव पड़ा है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रकटीकरण वक्तव्य इस बारे में कुछ नहीं कहता और इस प्रकार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। बिना किसी पक्षपात के यह उल्लेख किया जाता है कि निर्धारित प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारतीय बाजार में आवेदक द्वारा दिए गए बिक्री के आंकड़ों में उनके द्वारा आयात की गई मात्रा शामिल है और इस मात्रा को विचारित आंकड़ों में से बाहर रखा जाना चाहिए और अंतिम प्रकटीकरण वक्तव्य में तालिका में दर्शाना चाहिए।

- यह उल्लेख किया जाता है कि मैसर्स एन.जी. इंडस्ट्रीज, मैसर्स एम.पी. इंडस्ट्रीज और मैसर्स श्री रामदेव मेटल मार्ट ने जांचाधीन अवधि के दौरान उत्पाद के साथ कोई स्लिटिंग प्रक्रिया नहीं की है और सभी वस्तुएं स्लिटिंग/रुपांतरण प्रक्रिया के बिना ही बेची गई हैं। इसके अतिरिक्त सामान्य तौर पर शीटों पर स्लिटिंग प्रक्रिया करना तकनीकी रूप से संभव नहीं है। यह नोट किया जाना चाहिए कि 1250 मिमी. से अधिक चौड़ाई के उत्पादों को आयात करना तकनीकी अथवा वित्तीय बुद्धिमता को नहीं दर्शाता। 1250 मिमी. से अधिक चौड़ाई के उत्पादों के आयात की लागत 600 मिमी. से 1250 मिमी. तक के उत्पादों की लागत से काफी अधिक होती है। यह एक स्वीकृत स्थिति है और मूल्यांकन महानिदेशक के आंकड़े यह दर्शाएंगे कि सामान्यतः 1250 मिमी. से अधिक चौड़ाई के उत्पाद का मूल्य 600 मिमी. से 1250 मिमी. तक की चौड़ाई वाले उत्पादों की तुलना में प्रति एमटी 50-100 अमेरिकी डॉलर अधिक होता है। इसलिए अधिक चौड़ाई के उत्पादों का आयात करना और उसके बाद स्लिटिंग करना अत्यधिक अव्यवहार्य है क्योंकि स्लिटिंग की क्रिया से तैयार उत्पाद की लागत में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हो जाएगी। इन लागतों में स्लिटिंग तक वस्तुओं को लाने के लिए परिवहन की लागत, स्लिटिंग की लागत, रिपैकिंग की लागत, पुनः परिवहन की लागत और स्लिटिंग से बनने वाले अपशिष्ट तथा कबाड़ की लागत शामिल है। वास्तव में 1250 मिमी. से अधिक चौड़ाई के उत्पाद की स्लिटिंग पर होने वाले व्यय की तुलना में 600 मिमी. से 1250 मिमी. तक की चौड़ाई वाली सामग्री की लागत कम है और यह घरेलू तथा विदेशी बाजार में आसानी से उपलब्ध है। स्लिटिंग की लागत और इससे बड़ी मात्रा में बनने वाले कबाड़ से यह सम्पूर्ण प्रक्रिया अव्यवहार्य हो जाती है।
- यह उल्लेख किया जाता है कि आवेदक द्वारा इस संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि भारत में अधिकतर वस्तुओं का उपभोग करने वाले उपभोक्ता 1250 मिमी. से अधिक चौड़ाई के उत्पादों का प्रयोग नहीं करते। 1250 मिमी. से अधिक चौड़ाई के उत्पादों का डेयरी तथा रसायन उद्योग में भंडारण टैंकों के फैब्रिकेशन के लिए प्रयोग किया जाता है जहां टैंक के आकार बड़े होते हैं। ऐसे मामलों में प्रयुक्त सामग्री की चौड़ाई जितनी अधिक होगी उतने ही कम जोड़ होंगे और इससे बेहतर संक्षारण गुणवत्ता तथा लम्बी अवधि के लिए कम अनुरक्षण सुनिश्चित होता है। इसलिए उपर्युक्त आयातक 1250 मिमी. से अधिक चौड़ाई के उत्पादों का आयात करते हैं और इन्हें कोई और प्रक्रिया किए बिना बेचते हैं। यह उल्लेख किया जाता है कि हमें इस आरोप के समर्थन में कोई प्रमाण अथवा समर्थन का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है कि 1250 मिमी. से अधिक चौड़ाई के 97% आयातित उत्पादों को स्लिटिंग के बाद बेचा जाता है और केवल 3% वास्तविक उपयोग में जाते हैं।
- अंतिम प्रकटीकरण वक्तव्य के अनुसार केवल एक कंपनी है अर्थात् मैसर्स पोस्को सर्विस सेंटर जो 400 सिरीज की सामग्री की स्लिटिंग करती है परंतु वह भी केवल 600-1250 मिमी. चौड़ाई की पीयूसी के 20% की। कार्रवाई शुरू करने की अधिसूचना के अनुसार आवेदक का यह दावा कि 97% मात्रा की स्लिटिंग की जा रही है उचित नहीं है। पीयूसी की 300 सिरीज और 200 सिरीज में स्लिटिंग का कोई प्रमाण नहीं है। इस प्रकार मैसर्स जिंदल द्वारा दायर किए गए आवेदन में बड़ी तथ्यात्मक विसंगतियां हैं।

107. मैसर्स विराना प्रा. लि., सिंगापुर ने उल्लेख किया है कि बीए, 2डी, 2ई, एसबी (स्कोच ब्राइट), सं. 3, सं. 4 आदि जैसी फिनिश को जांच से बाहर रखा जाना चाहिए। आयातक भी भारत के नागरिक हैं और वे रोजगार सृजन भी करते हैं।

108. पोस्को, कोरिया और उसकी संबंधित कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले मैसर्स डीजीएस एसोसिएट्स ने निम्नलिखित अनुरोध किये हैं।

- प्राधिकारी ने उत्तरदायी निर्यातकों/उत्पादकों के नामों को रिकॉर्ड करते समय हेसुंग कॉर्पोरेशन (कोरिया) के नाम को छोड़ दिया है जिन्होंने उत्तर भी दिया है और इस माननीय प्राधिकारी द्वारा इसका सत्यापन भी किया गया है। इसी प्रकार हेसुंग कॉर्पोरेशन का संदर्भ प्रकटन विवरण के पैरा- 80 और 85 में किए जाने की आवश्यकता है। परिणामस्वरूप पैरा-57 में यह उल्लेख होना चाहिए “कोरिया के मामले में उत्पादक पोसोको ने अपनी 7 निर्यातक कंपनियों और भारत में तीन स्लिटिंग केन्द्रों सहित सहयोग किया है।”
- प्राधिकारी ने उत्पादक/ निर्यातकों के अनुरोध को माना है कि विचाराधीन उत्पाद के पोसको के निर्यात उन आकारों के उत्पादों की आपूर्ति के लिए अनिवार्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं जो विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में नहीं आते हैं। यह बात दोहराया जाती है कि पोसोको द्वारा किए गए 80 प्रतिशत निर्यात गैर-विचाराधीन उत्पाद होने के नाते 600 एमएम से कम के सीपीएल आकारों अथवा कट टू लेंथ की आपूर्ति करने के लिए किया गया है और वह विचाराधीन उत्पाद तथा जांचाधीन उत्पाद दोनों के क्षेत्र से बाहर है। यह विनम्र अनुरोध है कि वर्तमान जांच में संबद्ध सामानों के प्रयोजन के लिए, जोकि महत्वपूर्ण हैं, भारत में आयातित सामानों का अंतिम प्रयोग है। जैसाकि उत्पादक/निर्यातक द्वारा पहले ही अनुरोध किया गया है, वह आटोमोटिव उद्योग की पूर्ति करता है। इस प्रयोक्ता उद्योग की प्रकृति से यह एक विकासमान और अत्यधिक सुरक्षात्मक उद्योग है। आटो संबंधी हिस्से-पुर्जों के विनिर्माण के लिए स्पष्ट आकारों के सामानों की मांग होती है और आयात किए जा रहे क्वायल की चौड़ाई को ध्यान में न रखते हुए उसे सीटीएल आकार में कटा/स्लिट किए जाने की आवश्यकता होगी।
- चूंकि सीटीएल आकार आटोमोटिव उद्योग के लिए महत्वपूर्ण हैं, अतः भारत में प्रसंस्करण केन्द्रों की भूमिका को मात्र इस कारण कमजोर/कम नहीं किया जा सकता कि लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना की दृष्टि से जांचाधीन उत्पाद को स्लिट करने के लिए स्थापित किए गए हैं। भारत में पोस्को के प्रसंस्करण केन्द्र 2006 से अस्तित्व में रहे हैं और उनकी स्थापना पर्याप्त निवेश से की गई है तथा उनमें अत्याधुनिक उपस्कर हैं। ये प्रसंस्करण केन्द्र आपूर्ति श्रृंखला में अभिन्न भूमिका निभाते हैं क्योंकि अंतिम ग्राहकों के पास व्यापक चौड़ाई वाले क्वायलों को सीटीएल में स्लिट/कट करने के लिए सुविधा नहीं होती और वे अपेक्षित आकारों में उन्हें आपूर्ति करने के लिए प्रसंस्करण केन्द्रों पर निर्भर होते हैं।
- आटोमोटिव उद्योग एक प्रभावी क्षेत्र है और आटो से संबंधित हिस्से-पुर्जों के नवीनतम डिजाइन छोटे होते जा रहे हैं, अतः उन्हें छोटे सीटीएल आकारों की आवश्यकता होती है। तथापि, यह सीधे ही वांछित सीटीएल आकारों में आयात करने के लिए ग्राहकों हेतु सार्थक अथवा किफायती नहीं हैं क्योंकि छोटी चौड़ाई के उत्पादन और परिवहन लागत प्रभावी ही नहीं है अपितु उन्हें रद्द किए जाने के खतरे भी बने रहते हैं क्योंकि परिवहन से क्षति हो सकती है और इस प्रकार सीटीएल आकार ग्राहकों के लिए बेकार हो जाते हैं। बड़े आकार का परिवहन करना भी ग्राहकों के लिए इस बात की अत्यधिक संभावना हो जाती है कि जिसका उन्होंने कुछ माह पहले आदेश दिया था। साथ ही वांछित कम आकार की चौड़ाई के क्वायल का परिवहन भी डिब्बे में सुपुर्दगी के माध्यम से किया जाना चाहिए जिससे भी लागत में काफी वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में भी जब निर्यातक सीधे ही अपेक्षित आकार के क्वायल प्रदान करता है तो क्वायल को “ऐज ट्रिमिंग प्रक्रिया” से गुजरना होता है जोकि भारत में अंतिम प्रयोग से पहले की जाती है और जिससे कचरे का भी उत्पादन होगा। अतः व्यापक चौड़ाई के उत्पादों का आयात करना ग्राहकों के लिए सार्थक विकल्प उपलब्ध है जिससे आयात किफायती और वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम हो जाते हैं। भारत में वांछित आकारों में स्लिट करने के लिए व्यापक चौड़ाई वाले उत्पादों का आयात करने से हानि, परिवहन लागत, अपशिष्ट में कमी आती है तथा इससे प्रयोक्ता वास्तविक आपूर्ति के समय आवश्यकता के आधार पर अपने मांगे गए आकारों में परिवर्तन भी ला सकते हैं।
- आयात किए जाने वाले क्वायल की चौड़ाई अपेक्षित आकारों (जो उपलब्ध हैं), के लिए की गई “नेस्टिंग के आधार पर होती है और जिससे कचरे का उत्पादन कम तथा उत्पादन की हानि होगी। ग्राहक द्वारा संबद्ध सामानों की आवश्यकता उन कारकों के साथ है जो आयात किए जाने वाले आकारों की चौड़ाई निर्धारित करते हैं। इस संबंध में प्रकटन विवरण के पैरा 63 में माननीय प्राधिकारी की टिप्पणी का भी संदर्भ लिया जाता है जिसमें प्राधिकारी ने पाया है “किसी प्रयोक्ता उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद/जांचाधीन उत्पाद के प्रयोग क्योंकि जांचाधीन उत्पाद/विचाराधीन उत्पाद की चौड़ाई पर निर्भर है, अतः फिनिशिंग/परिवर्तन की प्रक्रिया में स्लिटिंग द्वारा परिवर्तन की प्रक्रिया बनती है और इसीलिए स्लिटिंग को प्रवंचना की जांच करने के लिए संगत पाटनरोधी नियमावली के तहत शामिल किया गया है”। यह निष्कर्ष इस कारण त्रुटिपूर्ण है कि विभिन्न चौड़ाइयों के लिए ग्राहक की आवश्यकता आयात आदेश के लिए आरंभिक बिन्दु है। यह इस आवश्यकता पर आधारित है कि “नेस्टिंग” की जाती है और व्यापक चौड़ाइयों का आयात वांछित सीटीएल आकारों में करने के लिए किया जाता है जिनकी पूर्व में मांग की गई थी। व्यापक चौड़ाई का आयात केवल इसलिए किया जाता है क्योंकि उपर्युक्त निर्धारित आर्थिक कारण मौजूद हैं। तकनीकी रूप से ऐसा कोई फिनिशिंग/परिवर्तन नहीं हो रहा है जो इस प्राधिकारी की टिप्पणियों के विपरीत है।

- इसके अतिरिक्त पोसको ग्राहक की आवश्यकता के आधार पर जांचाधीन उत्पाद, विचाराधीन उत्पाद और गैर विचाराधीन उत्पाद की हमेशा पूर्ति करता रहा है। पोसको का बाजार बढ़ती हुई दर से जांचाधीन उत्पाद और गैरविचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में बदल गया तथापि बाजार क्षेत्र में इस परिवर्तन को प्रवंचना नहीं कहा जा सकता है। जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा अथवा अन्यथा आरोप लगाया गया है। यह अनुरोध है कि यदि पोसको में विचाराधीन उत्पाद, जो कि मामले में नहीं है, की आपूर्ति करने के लिए जांचाधीन उत्पाद का निर्यात किया होता तो प्रवंचना का संभवतः आरोप नहीं लगा होता। नेस्टिंग किये जाने के नाते जांचाधीन उत्पाद का आयात गैर-विचाराधीन उत्पाद होने के नाते 600 एमएम से कम के सीटीएल आकारों में स्लिट करने के लिए किया जा रहा है। ऐसे गैर-विचाराधीन उत्पाद की चौड़ाइयों की आपूर्ति न तो विचाराधीन उत्पाद के आयात पर लगाये पाटन-रोधी शुल्क प्रवंचना मानी जा सकती है और न यह माना जा सकता है कि विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में घरेलू उद्योग को कोई क्षति हो रही है।
- पोसको अपने अंतिम ग्राहकों की अपेक्षानुसार चौड़ाई की आपूर्ति हमेशा करता रहा है, चाहे वह जांचाधीन उत्पाद हो, विचाराधीन उत्पाद हो अथवा गैर-विचाराधीन उत्पाद हो। यह आयात पैटर्न रहा है और आयात पैटर्न है। यह पैटर्न ग्राहक के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तथापि प्रयोक्ता ऑटोमोटिव उद्योग की मांग बदलती है और आयात की जा रही चौड़ाई का प्रयोक्ता की आवश्यकता से सीधा संबंध है। जिसमें उत्पादन हानि, परिवहन लागत अपशिष्ट की आर्थिक आधार को ध्यान में रखते हुए तथा अंतिम प्रयोक्ता को वास्तविक आपूर्ति के समय मांग की गई आकार के आधार को बदलने के लिए अनुमति दी जाती है।
- इन बातों को ध्यान में रखते हुए प्रकटन विवरण के पैरा 74 में प्राधिकारी की टिप्पणी कि संबद्ध देशों में उत्पादक/निर्यातकों के लिए विचाराधीन उत्पाद पर लगाये गये पाटन-रोधी शुल्क के प्रवंचना को छोड़कर कोई आर्थिक औचित्य नहीं है और यह कि जांचाधीन उत्पाद के आयात में भारी वृद्धि में यह सिद्ध है, गलत रखा गया और त्रुटिकोण है। यह बात दोहराई जाती है कि जांचाधीन उत्पाद के आयात में वृद्धि अलग से नहीं देखी जा सकती, बल्कि आयात किये जा रहे जांचाधीन उत्पाद के प्रयोग में जोड़ कर उसकी जांच की जानी चाहिए। पोसको के मामले में आयात किया जा रहा जांचाधीन उत्पाद उन सीटीएल आकारों में आपूर्ति के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जा रहा है जो 600 एमएम से कम है तथा जो प्रयोक्ता ऑटोमोटिव उद्योग के वांछित आकार हैं अथवा स्वयं जांचाधीन उत्पाद के रूप में हैं। आपूर्ति का केवल एक छोटा सा भाग है जो विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में जा रहा है।
- प्राधिकारी ने उल्लेख किया है कि मौजूदा पाटनरोधी उपायों की दक्षता पर प्रवंचना संबंधी उपाय के प्रभाव और विचाराधीन उत्पाद का घरेलू उद्योग की बिक्री पर परिणामी कीमत प्रभाव पर विचार करने का प्रस्ताव है। इस संबंध में यह अनुरोध है कि चूंकि उत्पादक/निर्यातक द्वारा विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति न्यूनतम है। अतः उपर्युक्त दो मानदण्डों से घरेलू उद्योग के पक्ष में कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आयेगा। तथा कथित प्रवंचना की सार्थक जांच के लिए निष्कर्ष निकालने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि जांचाधीन उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद में स्लिट किया जा रहा है और परिणामस्वरूप मौजूदा पाटन-रोधी उपाय की दक्षता प्रभावित हो रही है तथा विचाराधीन उत्पाद की घरेलू उद्योग की बिक्री पर कीमत प्रभाव पड़ रहा है तथापि यह इस मामले के तथ्यों के विपरीत है, जहां जांचाधीन उत्पाद को गैर-विचाराधीन उत्पाद में स्लिट किया जा रहा है अथवा जांचाधीन उत्पाद के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, विचाराधीन उत्पाद क्षेत्र को अप्रभावित रखा गया है।
- यदि प्राधिकारी को गैर-विचाराधीन उत्पादों की आपूर्ति के लिए पाटन-रोधी शुल्क बढ़ाना था तो इससे घरेलू उद्योग को कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रयोक्ता उद्योग सीटीएल आकारों का सीधे ही आयात करने पर विचार कर सकता है। तथापि उपर्युक्त पैरा 4 में निर्धारित कारणों से प्रयोक्ता ऑटोमोटिव उद्योग पर इसका निश्चित रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और जिससे गंभीर कठिनाई उत्पन्न होगी। अतः सुविधा को संतुलित करते हुए यह महत्वपूर्ण है कि पाटनरोधी शुल्क स्लिटिंग और जांचाधीन उत्पाद को 600 एमएम से कम के सीटीएल आकारों में आपूर्ति पर गैर-विचाराधीन उत्पाद होने के नाते न लगाया जाए। इसके अतिरिक्त प्रकटन विवरण के पैरा 62 में प्राधिकारी ने उल्लेख किया है कि उनका विचाराधीन उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के रूप में अथवा उपाय लगाये जाने से पूर्व गैर-विचाराधीन उत्पाद के रूप में प्रयोग पैटर्न का संदर्भ देने तथा विचाराधीन उत्पाद और जांचाधीन उत्पाद के निपटान/ बिक्री पैटर्न की जांच करने के लिए उपायों के प्रयोग पैटर्न का संदर्भ देने का विचार है, यह विनम्र अनुरोध है कि इस जांच में संतुलित और वास्तविक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अनुरोधों पर विचार करें।
- उत्पादक/निर्यातक तथा आयातक भी सीमा शुल्क प्राधिकारियों को कानूनी रूप से प्रवर्तनीय घोषणा/वचनबद्धता तथा आवधिक स्वैच्छिक अनुरोध देना चाहिए कि उनके द्वारा आयात किये जा रहे जांचाधीन उत्पाद का प्रयोग स्लिटिंग प्रक्रिया के

अनुसरण में गैर-विचाराधीन उत्पाद /अथवा जांचाधीन उत्पाद के रूप में ही किया जायेगा। जांचाधीन उत्पाद की विचाराधीन उत्पाद में स्लिटिंग पाटन-रोधी शुल्क के भुगतान के अध्यक्षीन होगी। यह विनम्र अनुरोध है कि यह इस जांच का साफ और औचित्यपूर्ण परिणाम होगा तथा इससे हितवद्ध पक्षकारों के हित पूरे होंगे।

109. ओउटोकम्पुओईज और वाईयूएससीओ के प्रतिनिधि मेसर्स ईएलपी के अभिवक्ताओं और न्यायाभिकर्ताओं द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- प्राधिकारी ने पैरा 34 में यह उल्लेख किया है कि उत्पाद की विशेष श्रेणी का बहिष्करण करने से स्वतः यह स्पष्ट नहीं हो जाता है कि वे समान वस्तुओं के समान नहीं हैं।
- निर्यातक का यह निवेदन है कि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी के प्रेक्षण असंगत हैं, क्योंकि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के संबंध में दिनांक 24 नवंबर, 2009 और 5 दिसंबर, 2011 के अपने अंतिम जांच परिणामों में इस कारण से जांचाधीन उत्पाद को उत्पाद की श्रेणी में से इसलिए बाहर कर दिया है कि जांचाधीन उत्पाद और विचाराधीन उत्पाद समान वस्तुएं नहीं हैं।
- इसलिए निम्निलिखित कारणों से नियम 25 (1) लागू नहीं होता है:-
 - (क) विचाराधीन उत्पाद, पाटन-रोधी शुल्क के अध्यक्षीन नहीं है। यदि जांचाधीन उत्पाद की चौड़ाई को 122 एमएम के अंतर्गत स्लिट कर दिया जाता है, तो वह विचाराधीन उत्पाद के तुलनीय बन जाता है।
 - (ख) विचाराधीन उत्पाद स्वतः एकत्र करके जोड़ा गया, तैयार किया गया और पूर्णरूपेण उत्पाद है और इसे किसी भी प्रकार से एकत्र करके जोड़ने, निर्मित करने अथवा पूरा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है।
- निर्यातक का यह निवेदन है कि घरेलू उद्योग के आधार को स्थापित करने के लिए माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी को विचाराधीन उत्पाद का विश्लेषण करने की आवश्यकता है और न कि घरेलू उत्पादक के जांच अधीन उत्पाद की। तथापि, वर्तमान जांच में माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इसका विश्लेषण किया है कि क्या जेएसएलएल जांचाधीन उत्पाद का भी आयात कर रहा है, हालांकि वर्तमान जांच विचाराधीन उत्पाद पर जांचाधीन उत्पाद के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए शुरू की गई है।
- जेएसएलएल की पात्रता का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी को हिसार संयंत्र के स्वामित्व का निर्धारण करने की आवश्यकता है और न कि डि-मर्जर की प्रभावी तारीख की। जेएसएल से जेएसएचएल को हिसार संयंत्र का अंतरण पूर्वव्यापी प्रभाव अर्थात् 31 मार्च, 2014 से किया गया था। उपरोक्त तारीख अर्थात् 31 मार्च, 2014 से जेएसएल नियम 2 (ख) में अंतर्गत उल्लिखित परिभाषा के अंतर्गत विचाराधीन उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग माना जाना बंद हो गया था क्योंकि भारत में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में इसका अब कोई प्रमुख योगदान नहीं बनता था।
- जांच अवधि के दौरान हिसार स्थित संयंत्र जेएसएल के स्वामित्वाधीन नहीं था। इस तथ्य के बावजूद जेएसएल ने अपने आवेदन-पत्र के पृष्ठ 2 में यह दावा किया है कि वह भारत में विचाराधीन उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक है, जबकि तथ्य यह है कि उस समय कुल मिला करके सही उत्पादक जेएसएचएलएल था।
- इसके अतिरिक्त जेएसएल द्वारा आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया दिनांक 13 दिसंबर, 2013 का अधिप्रमाणन डि-मर्जर के साथ-साथ जांच अवधि से पहले का है। हालांकि आवेदन-पत्र वर्ष 2012 में प्रस्तुत किया गया है, जब कि हिसार का संयंत्र उस समय जेएसएल के पास था, आवेदन-पत्र कानून की दृष्टि से इसलिए निकृष्ट है कि (1) आवेदन-पत्र में जांच की अवधि के आंकड़े शामिल नहीं हो सकते हैं और (2) वर्तमान जांच, आवेदन-पत्र के प्रस्तुत किए जाने की तारीख के छः महीनों के भीतर शुरू नहीं की गई है।
- प्राधिकारी ने बलपूर्वक यह कहा है कि पाटन-रोधी नियमावली के नियम 26 के अंतर्गत एक आवेदन-पत्र पर 25% और 50 % के परीक्षण की शर्त लागू नहीं होती है। निर्यातक का यह निवेदन है कि पाटन-रोधी नियमावली का यह सर्वाधिक गलत प्रतिपादन है।

- पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के साथ पठित नियम 26 (1) के अनुसरण में घरेलू उद्योग को कम से कम भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल घरेलू उत्पादन के प्रमुख भाग का एक विनिर्माता होना चाहिए। माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने प्रकटन विवरण द्वारा यह बताया है कि एक मात्र जेएसएल 25% और 50 % के परीक्षण की शर्त को पूरा करता है। माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निम्नोक्त परीक्षणों से याचिकादाता को दिए गए उनके अपने निर्देश उच्छेदित नहीं होने चाहिए:
 - (क) याचिकादाता 25% के परीक्षण की अर्हता के लिए हिसार संयंत्र से उत्पादन संबंधी सूचना प्रस्तुत नहीं करता है।
 - (ख) यदि किसी भी जांच अवधि में अर्थात् जांच अवधि और जांच शुरू करने के समय याचिकादाता 25% की अवसीमा को पूरा नहीं करता है, तो उसे घरेलू उद्योग के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है और जांच को तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
 - (ग) माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी को उत्पादन संबंधी सूचना को अगोपनीय रूप में उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है।
 - (घ) याचिकादाता द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की परिशुद्धता के लिए पूर्ण रूप से जांच किए जाने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मुद्दे को उलट देने मात्र के लिए याचिकादाता द्वारा रिकार्ड पर उत्पादन के आडम्बरपूर्ण आंकड़े नहीं रखे गए हैं।
- घरेलू उद्योग के आधार को सिद्ध करने के लिए जरूरी कोई भी सूचना एक अनिवार्य तथ्य है। जेएसएल के विचाराधीन उत्पाद के आंकड़े और अन्य कोई भी आंकड़े जो कि रिकार्ड पर हैं, उन पर पाटन-रोधी नियमावली के नियम 16 के अंतर्गत अनिवार्य तथ्यों के रूप में विश्वास किया गया है। वर्तमान जांच की समयबद्ध प्रकृति को ध्यान में रखते हुए माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे कृपया उपरोक्त अनिवार्य तथ्यों का तत्काल प्रकटन करें।
- हिसार की डि-मर्जर स्कीम के अनुसार हिसार का संयंत्र, 31 मार्च, 2014 से अर्थात् जांच अवधि से पहले से जेएसएचएल के स्वामित्वाधीन है।
- जेएसएल के पास जेएसएचएल नामक पृथक कानूनी प्रयोज्यता की ओर से आंकड़े प्रस्तुत करने की उपयुक्त अनुज्ञप्ति अथवा अधिकार नहीं है।
- याचिकादाता का यह दावा कि अधिकतर ऐसी सूचना गोपनीय है, पूर्णतया अनुचित है और पाटन-रोधी नियमावली के नियम 7 के साथ-साथ यह दिनांक दिसंबर, 2013 की व्यापारिक सूचना संख्या 1/2013 का भी घोर उल्लंघन है। उत्तर में सूचित किए गए सभी आर्थिक प्राचलों की पूर्ण गोपनीयता का दावा किया गया है। इसके अतिरिक्त आवेदन-पत्र में उत्पादन के व्यौरों, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन, शुल्क को बचाने के लिए कथित प्रवंचना, परिवर्तन लागत से संबंधित समस्त सूचना की संपूर्ण गोपनीयता का भी दावा किया गया है।
- प्राधिकारी ने साक्ष्य का विश्लेषण करते समय असंगत और गलत आंकड़ों पर विश्वास किया है, जैसे कि -
 - (क) माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने वर्ष 2088 से आंकड़ों का विश्लेषण नहीं किया है, हालांकि उन्होंने हितबद्ध पक्षकारों को यह निर्देश दिया था कि वे उन्हें प्रदान करें और
 - (ख) जेएसएल द्वारा दिनांक 10 अप्रैल, 2017 के अपने अद्यतन आवेदन-पत्र द्वारा प्रस्तुत किए गए विचाराधीन उत्पाद के संबंध में आयात के आंकड़े, दिनांक 7 अगस्त, 2017 के प्रकटन विवरण में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों से अत्यधिक असंगत हैं।
- प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण के पैरा 65 पर 1650 एमएम के अंतर्गत आने वाले आयातों के प्रमुख भाग का विश्लेषण किया है। यदि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 1650 एमएम तक की चौड़ाई का विश्लेषण किया होता, तो माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए सहनीय स्तर को वर्तमान 1650 एमएम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया होता।

- व्यापार के पेटर्न में परिवर्तन होने के संबंध में प्राधिकारी द्वारा किया गया विश्लेषण जबकि वास्तविक रूप से गलत है, फिर भी यह व्यापार के पेटर्न के सुव्यवस्थित विश्लेषण का प्रतिनिधिक नहीं है। वास्तव में चार्टों में निर्दिष्ट विचाराधीन उत्पाद और निरीक्षणाधीन उत्पाद के कुल आयातों के प्रतिशत पर आधारित सापेक्षित विश्लेषण है, जो कि उस परिप्रेक्ष्य में जांच किए बिना अपूर्ण है जिसके अंतर्गत परिवर्तन हुए हैं।
- जब कि प्राधिकारी द्वारा समानुपातिक रूप से किए गए विश्लेषण पर विश्वास किया गया है, जो कि विचाराधीन उत्पाद और निरीक्षणाधीन उत्पाद की प्रवृत्तियों में परिवर्तनशील प्रवृत्तियों को दर्शाता है, इस प्रकार से समानुपातिक रूप से किए गए विश्लेषण के पीछे आंकड़ों के गहन विश्लेषण से भी यह स्पष्ट होता है कि निरीक्षणाधीन उत्पाद के आयातों में वृद्धि को निम्नोक्त कारकों के आधार पर विचाराधीन उत्पाद पर लागू किए गए पाटन-रोधी शुल्क के साथ सहयोजित नहीं किया जा सकता है:-
 - (क) विचाराधीन उत्पाद के आयातों में गिरावट स्वभाविक है: पाटन-रोधी शुल्क लागू लगाए जाने से विचाराधीन उत्पाद के आयातों में गिरावट आना स्वभाविक है और इस प्रवृत्ति को सामान्यतया अन्य उत्पादों में भी देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त इससे यह भी स्पष्ट होता है कि मूल्यांकित अवधि में असंबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों में क्यों पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है।
 - (ख) प्रवंचना के कारण निरीक्षणाधीन उत्पाद के आयातों में वृद्धि: मूल्यांकित अवधि में निरीक्षणाधीन उत्पाद के आयातों में वृद्धि, मांग में वास्तविक वृद्धि के कारण हुई थी:
 - (1) भारत में विगत चार वर्षों से ले कर जांच अवधि तक उत्पादन में वृद्धि हुई है - जबकि इसी अवधि अवधि में संबद्ध देशों से निरीक्षणाधीन उत्पाद के आयातों में गिरावट आई है।
 - (2) विगत दस वर्षों में असंबद्ध देशों से निरीक्षणाधीन उत्पाद के आयातों में वृद्धि हुई है।
- प्राधिकारी ने अपना विश्लेषण करते समय और निर्यातक द्वारा रिकार्ड पर प्रस्तुत किए गए प्रचुर आंकड़ों और किए गए विश्लेषण की अनदेखी की है।
 - (क) निर्यातक द्वारा भारत में सीधे अंत प्रयोक्ताओं को निरीक्षणाधीन उत्पाद के अधिकतर निर्यात किए गए हैं।
 - (ख) उत्पादक ने जांच अवधि के दौरान आयातों को 2 (दो) अवधियों में विभाजित किया है, अर्थात् शुल्क अवधि(1 जुलाई, 2014 से 21 अप्रैल, 2015 तक) और गैर-शुल्क अवधि (22 अप्रैल, 2015 से 30 सितंबर, 2015 तक)। इस अवधि के दौरान निर्यातक की बिक्रियों के चलन से यह स्पष्ट पता चलता है कि निर्यातक विशिष्ट मामले में कोई प्रवंचना नहीं हुई है।
 - (ग) निर्यातक जिन ग्राहकों को बिक्रियां करता है, उससे ऐसी प्रकृति प्रमाणित होती है, जिसमें अपवचना होने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- तथापि, रिकार्ड पर ऐसे पर्याप्त आंकड़े होने के बावजूद प्राधिकारी ने उपरोक्त मुद्दे पर अपना निष्कर्ष देने के समय उपरोक्त किसी भी आंकड़े पर विचार नहीं किया है।
- प्राधिकारी ने निर्यातक के सामान्य मूल्य का आकलन करने के लिए प्रयुक्त की गई परिकलन करने की कार्यप्रणाली का प्रकटन नहीं किया है। कम से कम उसे अगोपनीय रूप में प्रकट किया जा सकता था।
- यूरोपीय यूनियन मूल के निर्यातों से और विशेष रूप से निर्यातक द्वारा किए गए निर्यातों से कीमत में कोई नकारात्मक कटौती नहीं हुई है। वास्तव में निर्यातक के लिए कीमतों में नकारात्मक कटौती की सीमा (25 से ले कर 35 प्रतिशत तक की कमी) इतनी व्यापक है कि वर्तमान वास्तविक सांचे में निर्यातक द्वारा किए गए निर्यातों के कारण किसी प्रकार से कीमत में हास होने का कोई प्रभाव पड़ा हो। इसलिए यह निवेदन किया जाता है कि निर्यातक पर कोई प्रवंचना-रोधी शुल्क लगाए जाने को कोई औचित्य नहीं है।

- प्रकटन विवरण की तालिका 25 में माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह उल्लिखित किया है कि ओउटोकुम्पुओईज के मामले में निर्यातक द्वारा पाटन-रोधी शुल्क की प्रवंचना का प्रभाव 35-45% की सीमा के बीच है और वाईयूएससीओ के मामले में निर्यातक द्वारा पाटन-रोधी शुल्क की प्रवंचना का प्रभाव 45-55% की सीमा के बीच है। निर्यातक का यह निवेदन है कि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने "शुल्क सहित विचाराधीन उत्पाद के पहुंच मूल्य" के परिकलन में गलत पाटन-रोधी शुल्क पर विचार किया है। ऐसे परिकलन से ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने ऐसे शुल्कों पर विचार किया है, जिनकी निर्णायक समीक्षा जांच (एसएसआर) में सिफारिश की गई थी और लगाया गया था। निर्यातक का यह निवेदन है कि निर्णायक समीक्षा जांच (एसएसआर) में सिफारिश किए गए और लगाए गए शुल्क, 11 दिसंबर, 2015 से जांच अवधि के बाद अर्थात् जुलाई, 14 से सितंबर, 15 तक लागू किए गए थे और इसलिए इन्हें जांच अवधि के दौरान किसी भी पहुंच कीमत के परिकलन पर लागू नहीं किया जा सकता है। तदनुसार माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे कृपया उपरोक्त स्थिति पर विचार करें और अपने सभी अन्य विचारधाराओं के लिए पहुंच कीमत के अपने परिकलनों पर पुनर्विचार करें। जब तक ऐसे संशोधनों को उचित रूप से शामिल नहीं कर लिया जाता है, तब तक वर्तमान जांच में कोई आगे की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।
- प्रवंचना के विद्यमान होने का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त किए गए आर्थिक प्राचलों के संबंध में प्राधिकारी ने कीमत में कटौती होने पर ही विचार किया है।
- डिक्टोफेनाक सोडियम के मामले में प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर पड़े कीमत और मात्रा दोनों के प्रभाव का विश्लेषण किया था।
- साईट्रिक एसिड, क्रिस्टलीन सिलीकोन फोटोवोल्टेईक मॉड्यूल और प्रमुख संघटकों और ग्लास फाईबरों के ओपन मेश फैब्रिक्स जैसे कुछ मामलों में यूरोपीय यूनियन ने क्षति का विस्तृत विश्लेषण किया है।
- एडी शुल्कों के कम होने की तुलना पीओआई के दौरान यथा-प्रयोज्य शुल्कों के साथ किए जाने की आवश्यकता है, उनके साथ नहीं जो एसएसआर में लागू किए गए हैं इसे पुनः जांच किए जाने और संशोधित किए जाने की आवश्यकता है।
- ईयू मूल के आयातों से नकारात्मक कीमत कटौती का अर्थ है कि कोई मूल्यह्रास प्रभाव नहीं है और निवारणरोधी शुल्कों को लागू करने का कोई औचित्य नहीं है।
- प्राधिकारी ने मै. जिंदल स्टेनलैस लिमिटेड और मै. जिंदल स्टेनलैस हिसार लिमिटेड के उत्पादन आंकड़ों को प्रकट नहीं किया है। मै. जिंदल स्टेनलैस लिमिटेड निर्धारित तारीख अर्थात् 31/3/2014 से घरेलू उद्योग माना जाना समाप्त हो गया है। मै. जिंदल स्टेनलैस हिसार लिमिटेड ने जांच में औपचारिक रूप से भाग नहीं लिया है और मै. जिंदल स्टेनलैस लिमिटेड हिसार संयंत्र का स्वामित्व नहीं रखता। अतः प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मै. जिंदल स्टेनलैस लिमिटेड ने गुणवत्ता 25% परीक्षण के लिए हिसार संयंत्र से उत्पाद जानकारी प्रस्तुत नहीं की है।
- पीयूसी/पीयूआई पर घरेलू उद्योग द्वारा दायर आंकड़े प्रकटीकरण में दिए गए आंकड़ों के अनुरूप हैं।
- 2008 के बाद से व्यापार पैटर्न विचलन की पहचान की जानी जरूरी है।
- एडीडी की पीयूसी पश्च लेवी की मात्रा में ह्रास स्वाभावित है और यह कि पीयूआई आयात धोखे के लिए नहीं है।
- भारतीय स्टेनलैस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन (आईएसडीए), प्रोसेस प्लांट एंड मशीनरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया और अन्य आयातकों ने कहा है कि आयातित पीयूआई सही प्रयोग के लिए है और स्लिटिंग के लिए नहीं है।
- संबद्ध देशों से 2012-13 के बाद से पीयूआई के आयातों में भी कमी आई है।
- पीयूआई की मांग बढ़ रही है और ऐसा ही याचिकाकर्ता के मामले में भी है।

- मै. आटोकुम्पु के निर्यात आटो, हैवी ट्रांसपोर्ट और संसाधित मशीनरी उद्योगों को किए जाते हैं जहां धोखे की कोई गुंजाइश नहीं है।
- पीओआई में जहां दो अवधियां हैं (प्रवृत्त एडी शुल्क और जहां एडी शुल्क प्रवृत्त नहीं है), आटोकुम्पु का निर्यात व्यवहार धोखाधड़ी को प्रतिबिंबित नहीं करता।
- मै. आटोकुम्पु के भारत को प्रमुख आयात सेज युनिटों को या अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत किए जाते हैं जहां कोई एडी शुल्क लेवी योग्य नहीं है और इसलिए निर्यातक द्वारा धोखा दिए जाने की कोई जरूरत नहीं है।

- मै युस्को ने पीओआई की शून्य शुल्क अवधि के दौरान 35% पीयूआई निर्यात किया। वार्षिक आधार पर 50.14% निर्यात शून्य शुल्क अवधि के दौरान किए गए, इसका यह अर्थ निकलता है कि युस्को धोखा नहीं कर रहा है। पीयूआई को निर्यात इस तथ्य के बाद भी अनुकूल बना हुआ है कि पीओआई में एडीडी थे या एडीडी नहीं थे। युस्को के निर्यातों द्वारा नकारात्मक कीमत कटौती हुई है और इसलिए कोई कीमत ह्रास प्रभाव नहीं है।

- धोखे के प्रभाव को पीओआई के दौरान प्रवृत्त एडी शुल्क के साथ मूल्यांकित किया जाना चाहिए और न कि एसएसआर शुल्कों के साथ।

- प्राधिकारी द्वारा प्रकटन विवरण के पृष्ठ 72 में उल्लिखित विवरण निम्नानुसार है:-

"प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांचाधीन उत्पाद के किसी भी वैध प्रयोक्ता को जांचाधीन उत्पाद पर पाटन-रोधी शुल्कों के विस्तार से प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही वह यह भी समझते हैं कि किसी भी सरकारी एजेंसी के लिए ऐसा आवश्यक नहीं है कि वह किसी भी वैध प्रयोक्ता को स्वीकृत की गई कोई भी छूट का अनुवीक्षण करे और इसलिए इस प्रयोजनार्थ जांचाधीन उत्पाद का आयात करने वाले सभी आयातकों को सीमा-शुल्क प्राधिकारियों को इस आशय का कानूनी घोषणापत्र प्रस्तुत करना होगा/वचनबद्धता देनी अपेक्षित होगी कि उनके द्वारा आयातित किए जा रहे जांचाधीन उत्पाद का उपयोग, किसी स्लिटिंग के बिना ऐसी सहनीय सीमा को छोड़ कर किया जाएगा, जैसा कि दिनांक 12.10.2015 के अंतिम जांच परिणाम में उल्लिखित किया गया है और दिनांक 11.12.2015 की सीमा-शुल्क की अधिसूचना संख्या 61/2015 द्वारा लागू की गई है, यदि वे लागू मौजूदा पाटन-रोधी शुल्क अदा नहीं करना चाहते हैं।"

- मेसर्स ईएलपी ने निम्नलिखित सारांश दिया है:-

(क) जेएसएलएल घरेलू उद्योग नहीं बनता है जिसके कारण यह जांच अवैध ढंग से शुरू की गई है और इसलिए इसे तत्काल समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

(ख) जांचाधीन उत्पाद गैर-निर्मित, अपरिष्कृत अथवा अपूर्ण रूप में है, जिसके कारण वर्तमान जांच में पाटन-रोधी नियमावली का नियम 25(1) लागू नहीं होता है।

(ग) कम से कम निर्यातक के खिलाफ वर्तमान जांच को समाप्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि व्यापार के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(घ) जेएसएलएल अपने प्रवचन के दावे को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा है।

(ङ) विचाराधीन उत्पाद के आयातों की मात्रा में वृद्धि, जांचाधीन उत्पाद की खपत में वृद्धि होने के कारण हुई है।

(च) विचाराधीन उत्पाद पर मौजूदा पाटन-रोधी शुल्क के उपचारी प्रभावों को कम आंका किया गया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

- i. जहां तक घरेलू उद्योग के आधार के मुद्दे के संबंध में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का संबंध है प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै0 ज़िंदल स्टेनलैस लिमिटेड द्वारा दायर आवेदन पत्र, जिसमें मै0 ज़िंदल स्टेनलैस लिमिटेड और मै0 ज़िंदल स्टेनलैस हिसार लिमिटेड के आंकड़े शामिल हैं, अनामेलन योजना के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार है। किसी भी दशा में मै0 ज़िंदल स्टेनलैस

लिमिटेड और मै0 जिंदल स्टेनलैस हिसार लिमिटेड आवेदन पत्र में किसी भी घरेलू उत्पादक द्वारा कोई विरोध न किए जाने पर तथा आधार परीक्षण को अलग-अलग पूरा करते हैं। मै0 जिंदल स्टेनलैस लिमिटेड विचाराधीन उत्पाद के संदर्भ में पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग का मानदंड पूरा करते हैं।

- ii. जहां तक कुछ हितबद्ध पक्षकारों के इस दावे का संबंध है कि मै0 जिंदल स्टेनलैस लिमिटेड 23.8.2011 तक एसईजैड था और इसीलिए इसके उत्पादन के संबंध में समुचित विश्लेषण किया जाए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उड़ीसा यूनिट में विचाराधीन उत्पाद/जांचाधीन उत्पाद का उत्पादन उसके डीटीए यूनिट होने के बाद ही आरंभ हुआ और इसलिए एसईजैड का समाधान करने का मुद्दा आवश्यक नहीं है।
- iii. प्राधिकारी अनावश्यक प्रवंचनारोधी जांच की वचनबद्धता, जिसमें दोषपूर्ण जांच की शुरुआत तथा जांचाधीन उत्पाद द्वारा विचाराधीन उत्पाद की तथाकथित प्रवंचना का समाधान शामिल है, के संबंध में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट करते हैं और यह उल्लेख करते हैं कि इन मुद्दों का समाधान एसएसआर सहित समान उत्पाद की पूर्व की मूल जांचों में पहले ही कर दिया गया है। प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के तहत वर्तमान जांच जांचाधीन उत्पाद द्वारा विचाराधीन उत्पाद की प्रवंचना के पहलू की जांच करना है और यह कि प्रवंचना के तथ्य के विभिन्न पहलुओं को पूरा करने के लिए नियम-25 और नियम-26 की शर्तों की आवश्यकता है। विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में कुछ अपवादों और टॉलरेंस ऐसे हैं जिन्हें परिवर्तित नहीं किया गया है। प्रवंचनारोधी नियमावली में यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है कि विचाराधीन उत्पाद और जांचाधीन उत्पाद समान वस्तु हैं जैसाकि अनुरोध किया गया है। प्राधिकारी ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखा है जिसमें यह माना गया है कि जांच का मार्ग प्रवंचनारोधी जांच में भिन्न है और विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के तथ्यों और तर्कों को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखे जाने की आवश्यकता है।
- iv. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह अनुरोध किया गया है कि यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीन है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि, मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है परंतु जांच पूरी करने के लिए इस पर कोई स्थगन नहीं है।
- v. प्राधिकारी नोट करते हैं कि 1250 एम.एम. की सभी श्रेणियों तक 600 एम एम की चौड़ाई के कोल्ड रोलड स्टेनलैस स्टील फ्लैट उत्पाद को आगे 4 एमएम तक की मोटाई में कोल्ड रोलड बनाने के लिए ही प्रवंचना को रोकने के लिए अनुरोध है तथा जांच से बीए, 2बी, 2 ई, एसई (स्कॉच ब्राइट), नं. 3, नं. 4 आदि को बाहर करने का भी अनुरोध है। प्राधिकारी मानते हैं कि विचाराधीन उत्पाद और जांचाधीन उत्पाद में एकमात्र अंतर चौड़ाई का है और हटाए गए ग्रेडों में कोई परिवर्तन नहीं है अथवा कोई तकनीकी विवरण भी नहीं है जैसाकि शुरुआती जांच में तथा प्रकटन विवरण में उल्लेख किया गया है।
- vi. प्राधिकारी पहले से ही निपटाए गए मुद्दों को पुनः खोलने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा पिछले दरवाजे से प्रवेश, मूल जांच के क्षेत्र को और व्यापक करने के संबंध में किए गए अनुरोधों को नोट करते हैं और मानते हैं कि बिना किसी परिवर्तन/स्लिटिंग के जांचाधीन उत्पाद के रूप में प्रयोग के लिए आयातित जांचाधीन उत्पाद विचाराधीन उत्पाद पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना के लिए नहीं माना जा रहा है परंतु केवल उस स्थिति में जब जांचाधीन उत्पाद का आयात संबद्ध देशों से हो और जांचाधीन उत्पाद के रूप में उसका प्रयोग न हो, परंतु विचाराधीन उत्पाद अथवा गैर विचाराधीन उत्पाद के रूप में प्रयोग के लिए उसमें परिवर्तन किया गया हो।
- vii. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह अनुरोध किया गया है कि विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क के उपचारात्मक प्रभाव को कमजोर करने का कोई साक्ष्य नहीं है और साथ ही यह भी कि महानिदेशक, रक्षोपाय ने माना था कि घरेलू उद्योग को हानियां घरेलू उद्योग के आंतरिक कारणों की वजह से हैं। प्राधिकारी मानते हैं कि जांचाधीन उत्पाद के रूप में प्रयोग न किए जाने के इरादे से जांचाधीन उत्पाद के आयात के कारण प्रवंचना द्वारा विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क को कमजोर करना वस्तुतः प्राधिकारी द्वारा विचाराधीन उत्पाद के समान स्तर के क्षेत्र को प्रदान करने के लिए किया गये गये उपाय को कमजोर हो रहे हैं। विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध का मुद्दा मूल जांच में पहले ही निपटा दिया गया है और उसके बाद उसे निर्णायक समीक्षा जांचों में निपटा दिया गया है।
- viii. प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए विचाराधीन उत्पाद और जांचाधीन उत्पाद के अनुपात के संबंध में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट करते हैं तथा घरेलू उद्योग के दावे में अंतर में मै0 ईएलपी द्वारा किए गए अनुरोधों

और प्रकटन विवरण में सूचित किए गए आंकड़ों को भी नोट करते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्ष 2008 – 09 से 2012 – 13 तक के लिए जांचाधीन उत्पाद से संबंधित आंकड़े विचाराधीन उत्पाद से संबंधित निर्णायक समीक्षा के संबंध में दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 के अंतिम जांच परिणामों में पहले ही सूचित कर दिए गए थे। वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के लिए विचाराधीन उत्पाद के आंकड़े भी उपर्युक्त जांच परिणाम में सूचित कर दिए गए थे। इसे वर्तमान जांच में यथातथ्यतः स्वीकार कर लिया गया है। वर्ष 2012 – 13 से आगे के डीजीसीआईएंड आंकड़ों का आगे विश्लेषण किया गया है और उन्हें जांच परिणाम में सूचित कर दिया गया है। असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए डीजीसीआईएंड एस आंकड़े, जैसा कि ऊपर कहा गया है, वर्तमान जांच परिणाम में ध्यान में रखे गए हैं और व्यापार पैटन के लिए तथा सहयोगी/उत्तरदायी निर्यातकों के लिए 2008 – 09 से जांच की अवधि तक विचाराधीन उत्पाद और जांचाधीन उत्पाद के निर्यात, जैसाकि उनके द्वारा सूचित किया गया है, का व्यापार पैटर्न का विश्लेषण करने के प्रयोजन से संदर्भ दिया गया है।

- ix. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने मै0 ओटुकुम्पु के उत्तर को रद्द करने का अनुरोध किया है जबकि मै0 ओटुकुम्पु का प्रतिनिधित्व करने वाले मै0 ईएलपी अधिवक्ताओं ने चाहा है कि उनके लिए सामान्य मूल्य का सिद्धांत प्रकट किया जाए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रश्नावली के उत्तर में ओटुकुम्पु ने केवल घरेलू बिक्री कीमत और निर्यात कीमत के संबंध में आंकड़े दिए थे और व्यापार परीक्षण का सामान्य कार्य करने के लिए उत्पादन लागत नहीं बताई। अतः प्राधिकारी ने सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्मित सीएनवी दृष्टिकोण को अपनाया जिसे पाटन मार्जिन के मूल्यांकन के लिए सारांश में प्रकटन में उल्लिखित कर दिया गया है। चूंकि वर्तमान जांच प्रवंचनारोधी के संबंध में है जिसमें पाटन के पहले के अलावा प्रवंचना के विभिन्न पक्षों से संबंधित आंकड़े भी महत्वपूर्ण हैं, मै0 आटुकुम्पु द्वारा अपनी निर्यात प्रवृत्ति के संबंध में दिए गए आंकड़ों पर संगत पहलुओं का विश्लेषण करने के लिए विचार किया गया है।
- x. प्राधिकारी आटुकुम्पु और यूस्को के लिए सामान्य मूल्य सिद्धांत के संबंध में अन्य विवरणों से संबंधित मै0 ईएलपी के अनुरोधों को नोट करते हैं और यह नोट करते हैं कि मै. ईएलपी ने दिनांक 11/8/2017 के पत्र द्वारा प्रकटन के बाद घरेलू उद्योग से संबंधित एनसीवी आंकड़ों के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध किया था जो उन्हें 14 अगस्त, 2017 को दे दिए गए थे। सामान्य मूल्य के सिद्धांत के संबंध में कोई विवरण नहीं मांगा गया था। प्राधिकारी ने प्रकटन के गोपनीय रूपांतर में दो निर्यातकों द्वारा दायर आंकड़ों के आधार पर परिकलित संगत गोपनीय मूल्य प्रदान किए। “सामान्य मूल्य” सिद्धांत प्रकटन के एनसीवी रूपांतर में दिया गया था। प्राधिकारी दिनांक 7 अगस्त, 2017 के प्रकटन विवरण में उल्लिखितानुसार दो निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य के संबंध में परिकलन सिद्धांत को दोहराते हैं।
- xi. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने प्रकटन में पोस्को के उत्तरदायी निर्यातक मै. ह्योसुग कॉर्पोरेशन (कोरिया) का नाम छोड़ दिया था जिसका सत्यापन स्थल पर भी किया गया था। प्राधिकारी ने पोस्को के उन सभी निर्यातकों के आंकड़ों को शामिल कर दिया है जिन्होंने पाटन मार्जिन का मूल्यांकन करने के लिए उत्तर दायर किए थे। यह निर्यात कीमत के पैरा में दिए गए विवरण (प्रकटन की तालिका 15) तथा एस एंड डी खर्चों (प्रकटन की तालिका-16) से सिद्ध है जिसमें मै. ह्योसुग कॉर्पोरेशन का नाम उल्लिखित किया गया है।
- xii. प्राधिकारी विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों को नोट करते हैं कि ऑटोमोटिव क्षेत्र को विशेष रूप से “सीटीएल” आकारों की आवश्यकता होती है जिसके लिए ऐसी आवश्यकताओं हेतु बड़ी शीटों को काटा जाता है। इसके अतिरिक्त, पोस्को के स्लिपिंग केन्द्रों ने “नेस्टिंग” की संकल्पना पर भी जोर दिया है जिसमें प्रयोक्ता की आवश्यकताएं विचाराधीन उत्पाद/जांचाधीन उत्पाद के आयात की योजना बनाने के लिए आरंभिक बिन्दु हैं तथा यह जांचाधीन उत्पाद का आयात करने के लिए पाटनरोधी प्रवंचना प्रेरणा नहीं है। इस संबंध में प्राधिकारी मानते हैं कि प्रचुर आर्थिक तर्काधार होने के नाते बड़े आकार का आयात करके दक्षता को अधिकतम करने हेतु “नेस्टिंग” और “व्यापार मॉडलिंग” की आवश्यकता से भारत को छोड़कर अन्य देशों को विचाराधीन उत्पाद और जांचाधीन उत्पाद की बिक्री की सामान्य प्रवृत्तियां भी बढ़ेंगी। पोस्को तीसरे देशों में इन मॉडलों की आकस्मिक आवश्यकता को प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं रहा है। “सीटीएल” आकारों की सेवा विभिन्न विकल्पों द्वारा की जा सकती है यथा विचाराधीन उत्पाद, जांचाधीन उत्पाद अथवा गैर – विचाराधीन उत्पाद/जांचाधीन उत्पाद के आयात द्वारा। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि बिना स्लिपिंग के केवल जांचाधीन उत्पाद के रूप में जांचाधीन उत्पाद के आयात के उपयुक्त उपयोग को पाटनरोधी शुल्कों से छूट दिए जाने की आवश्यकता है। कई हितबद्ध पक्षकारों ने यह

भी तर्क दिया है कि विचाराधीन उत्पाद तथा जांचाधीन उत्पाद समान वस्तु नहीं हैं और यह कि मूल जांच में जांचाधीन उत्पाद बाहर क्यों रहा। अतः प्राधिकारी इस बात को दोहराते हैं कि जांचाधीन उत्पाद को केवल जांचाधीन उत्पाद के रूप में ही प्रयोग की अनुमति देकर ऐसे मुद्दे केवल आयातकों/प्रयोक्ताओं द्वारा आयातित जांचाधीन उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद अथवा गैर विचाराधीन उत्पाद/जांचाधीन उत्पाद के किसी भी प्रयोग के प्रयोजन से हल किया जाता है और विचाराधीन उत्पाद से जांचाधीन उत्पाद के संबंध में मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों को बढ़ाए जाने के साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है।

गैर विचाराधीन उत्पाद के लिए पोसको द्वारा जांचाधीन उत्पाद के प्रयोग पर उनके प्रकटन पश्चात् अनुरोधों के संबंध में, आईडीपीसी, आईसीपीसी और आईपीपीसी, भारत में पोसको, कोरिया के 3 स्लिटिंग केंद्रों द्वारा दर्ज आंकड़ों (तालिका 10) के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि 2008-09 से 2011-12 अर्थात् पाटनरोधी उपाय लगाए जाने की अवधि से पूर्व के दौरान घरेलू बाजार में गैर विचाराधीन उत्पाद की 21 प्रतिशत बिक्री गैर विचाराधीन उत्पाद की श्रेणी के सीधे आयात से पूरी की गई थी। गैर विचाराधीन उत्पाद की शेष बिक्री के लिए 46 प्रतिशत की पूर्ति विचाराधीन उत्पाद की स्लिटिंग द्वारा और 33 प्रतिशत की पूर्ति जांचाधीन उत्पाद की स्लिटिंग द्वारा की गई थी। 2012-13 से जांच की अवधि तक के दौरान अर्थात् पाटनरोधी उपाय लगाए जाने के बाद घरेलू बाजार में गैर विचाराधीन उत्पाद की बिक्री के 2 प्रतिशत की पूर्ति गैर विचाराधीन उत्पाद की श्रेणी के सीधे आयातों द्वारा की गई थी। शेष 98 प्रतिशत की पूर्ति जांचाधीन उत्पाद की स्लिटिंग द्वारा की गई थी। जहां तक इस अवधि में घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद की बिक्री का संबंध है, घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद की बिक्री के 14 प्रतिशत की पूर्ति विचाराधीन उत्पाद के सीधे आयात से की गई थी और 86 प्रतिशत की पूर्ति जांचाधीन उत्पाद की स्लिटिंग द्वारा की गई थी। यह नोट किया जाता है कि इस अवधि के दौरान आयातित जांचाधीन उत्पाद 11 प्रतिशत तक ही “जांचाधीन उत्पाद” के रूप में बेचा गया था और शेष का प्रयोग विचाराधीन उत्पाद और/अथवा गैर-विचाराधीन उत्पाद में स्लिटिंग के लिए किया गया था। अतः उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी आयातों के उपर्युक्त उपयोग पैटर्न के मद्देनजर प्रवंचना के रूप में जांचाधीन उत्पाद को गैर विचाराधीन उत्पाद में स्लिटिंग प्रक्रिया मानते हैं।

xiii. मै. सनसिटी शीट्स प्रा.लि., सनसिटी स्ट्रिप्स एंड ट्यूब्स प्रा.लि., मै. सनराइज स्टेनलैस प्रा.लि. और मै. सनमार्क स्टेनलैस प्रा. लि. का प्रतिनिधित्व करने वाले जीटीसी परामर्शदाताओं ने उल्लेख किया है कि प्रवंचना के लिए कोई भी शर्त पूर्ण नहीं है और पाटनरोधी जांच के बाद अथवा उससे ठीक पूर्व कोई प्रचालन आरंभ नहीं हुआ अथवा बढ़ा नहीं। इसके अतिरिक्त उन्होंने उल्लेख किया है कि उन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत से विचाराधीन उत्पाद का कभी भी आयात नहीं किया है और उन पर प्रवंचना प्रभार लागू नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रकटन में उल्लिखित आयातक द्वारा दी जाने वाली घोषणा अस्पष्ट है और इससे आयातक हतोत्साहित होंगे जैसाकि उनमें से कई आयातकों ने कहा है कि वे 600 एमएम से कम की स्लिटिंग करते हैं। प्राधिकारी इन अनुरोधों को नोट करते हुए मानते हैं कि व्यापार पैटर्न में परिवर्तन का निर्धारण निर्यातक विशिष्ट है और उसके बाद आयातक की भूमिका जांचाधीन उत्पाद से विचाराधीन उत्पाद अथवा गैर विचाराधीन उत्पाद के रूप में परिवर्तन से संबंधित है जिससे प्रवंचना की प्रक्रिया बनती है। अतः किसी भी आयातक का अलग से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। मौजूदा पाटनरोधी उपायों को जारी रखने के संबंध में सिफारिश यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त रक्षोपायों के साथ निर्यातक विशिष्ट हैं कि जांचाधीन उत्पाद के अधिकृत आयातक, जो प्रवंचना नहीं कर रहे हैं, को जांचाधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए जाने के साथ नहीं जोड़ा गया है। एक उपयुक्त आयातक द्वारा विधिक रूप से प्रवर्तनीय वचनबद्धता इस प्रकार की छूट सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र है।

xiv. प्राधिकारी मै. ईएलपी द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपायों के बाद विचाराधीन उत्पाद के आयात में कमी कुछ उदाहरणों का उल्लेख करते हुए निष्क्रिय है। जहां पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है तथा आयात कम हुए हैं और जांचाधीन उत्पाद के आयात में वृद्धि प्रवंचना के कारण नहीं है। प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी उपाय यदि प्रभावी है और प्रवंचना के तथ्य द्वारा उसकी दक्षता को कमजोर नहीं किया जाता है तो पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से किए गए उपाय से एक समान स्तर बनाने के प्रयोजन के इरादे का समाधान होगा और पाटित सामानों का आयात स्वाभाविक रूप से कम होगा। तथापि, यदि सामानों के विभिन्न रूपों का आयात, जो नियम-25 और 26 के अनुसार परिवर्तन द्वारा पाटित आयातों का स्थान ले सकते हैं, होता है तो पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव कमजोर हो जाएगा। अतः जांचाधीन उत्पाद की कोई उपयुक्त वृद्धि रोकी नहीं जानी चाहिए परंतु पाटनरोधी नियम 25 और 26 की परिधि के तहत पहचाने गए विचाराधीन उत्पाद के अंतर को पूरा करने के लिए जांचाधीन उत्पाद का परिवर्तन की ही जांच किए जाने की आवश्यकता है।

xv. प्राधिकारी मानते हैं कि जिन मामलों में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद संबद्ध पाटित आयातों का आयात पाटनरोधी शुल्क से कम हुआ है, यदि घरेलू उद्योग प्रवंचना के तथ्य के साक्ष्य के साथ याचिका दायर करता है, तो प्राधिकारी के लिए उसकी जांच करना अनिवार्य हो जाता है जैसाकि वर्तमान जांच के मामले में है।

- xvi. जहां तक मै. ईएलपी द्वारा उलिखित यूरोपीय संघ की प्रवंचनारोधी जांच संबंधी परिपाटी का संबंध है, प्राधिकारी मानते हैं कि उन्होंने देश के पाटनरोधी संगत नियमों के तहत मुद्रों का समाधान किया है।
- xvii. प्राधिकारी शुल्कमुक्त प्राधिकारों के तहत किए जा रहे उनके प्रमुख निर्यातों और एसईजैड यूनितों को किए जा रहे निर्यातों के संबंध में मै. ईएलपी के अनुरोधों को नोट करते हैं और मानते हैं कि चूंकि इन निर्यातों पर पाटनरोधी शुल्क नहीं है, अतः उनके निर्यात प्रवंचना के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं हैं और भविष्य में भी यदि इस प्रकार की कोई छूट जारी रहती है तो जांचाधीन उत्पाद को छोड़कर प्रयोग के इरादे से जांचाधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क बढ़ाकर निर्यातक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- xviii. जहां तक ओटोकुम्पु के शुल्क में निर्यात व्यवहार तथा जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की कोई शुल्क न होने की अवधि का संबंध है, प्राधिकारी मानते हैं कि जांच की अवधि के दौरान निर्यात व्यवहार अनिश्चितता की हालत में था और ऐसी स्थिति में था जब निर्णायक समीक्षा के परिणाम बीच में थे और इसीलिए एक अनिश्चितता के चरण में एक अल्पावधि के लिए निर्यात व्यवहार को बदलना समझदारी प्रतीत नहीं होता। इस संबंध में प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि चूंकि मै. आडुकुम्पु ने निर्णायक समीक्षा में भाग नहीं लिया, अतः निर्णायक समीक्षा के निष्कर्ष पर उस पर अधिकतम शेष शुल्क लगाए जा सकते थे। इसके अतिरिक्त, यदि किसी निर्यातक द्वारा निर्यात किया गया जांचाधीन उत्पाद बिना स्लिटिंग के केवल जांचाधीन उत्पाद के रूप में उपयुक्त प्रयोग के लिए बनाया जाता है, तो इससे निर्यातक को कोई पूर्वाग्रह नहीं होता, यदि संबंधित निर्यातक आयातित जांचाधीन उत्पाद को स्लिट न करने की वचनबद्धता दायर करते हैं।
- xix. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि कई हितवद्ध पक्षकारों ने यह नोट किया है कि 200 तथा 300 सीरीज की स्लिटिंग का कोई साक्ष्य नहीं है और साथ ही कई आयातकों ने यह उल्लेख किया है कि वे कोई स्लिटिंग नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि यदि मामला ऐसा है तो ऐसे अधिकृत आयातकों/अंतिम प्रयोक्ताओं के प्रति कोई पूर्वाग्रह अथवा अन्याय नहीं होगा जो संबद्ध देशों से आयातित जांचाधीन उत्पाद की स्लिटिंग नहीं कर रहे हैं तथा स्लिटिंग के बिना केवल जांचाधीन उत्पाद के उपयुक्त प्रयोजन के लिए ही जांचाधीन उत्पाद का प्रयोग कर रहे हैं।
- xx. प्राधिकारी विभिन्न आयातकों द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट करते हैं कि प्रवंचनारोधी उस अवधि के लिए न लगाया जाए जब पाटनरोधी शुल्क बंद हो गया है और मानते हैं कि विचाराधीन उत्पाद पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की पूर्व की अवधि संगत नहीं है क्योंकि प्राधिकारी अधिसूचना की तारीख से विचाराधीन उत्पाद से जांचाधीन उत्पाद पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए जाने की सिफारिश कर रहे हैं।
- xxi. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि, 400 सीरीज के लिए स्लिटिंग केन्द्रों ने सहयोगी उत्पादक/निर्यातक के साथ उत्तर दायर किए हैं तथापि, दूसरे मामलों में स्लिटिंग प्रचालनों के संबंध में कोई विशिष्ट उत्तर दायर नहीं किया गया है। यदि कुछ सीरीज की स्लिटिंग नहीं की जा रही है तो आयातकों के पास कानूनी रूप से बाध्यता/प्रवर्तनीय वचनबद्धता दायर करने के लिए कोई तर्क नहीं होना चाहिए क्योंकि वचनबद्धता दायर करने से किसी भी आयातक के लिए कोई पूर्वाग्रह किसी भी दशा में नहीं होता है, यदि उनके द्वारा जांचाधीन उत्पाद के आयात बिना किसी स्लिटिंग के केवल जांचाधीन उत्पाद के रूप में प्रयोग के लिए उपयुक्त रूप से बनाए गए हैं।
- xxii. जहां तक क्षेत्राधिकार अप्रत्यक्ष कराधान प्राधिकारी से प्रमाण-पत्र द्वारा समर्थित किसी आयातक द्वारा वचनबद्धता पूरी करने के लिए घरेलू उद्योग के अनुरोधों का संबंध है, प्राधिकारी मानते हैं कि यह उपयुक्त होगा कि वित्त मंत्रालय उनके क्षेत्रीय ढांचे तथा संसाधनों के आधार पर ऐसी किसी वचनबद्धता का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त मॉनीटरिंग तंत्र बनाए।
- xxiii. जहां तक विचाराधीन उत्पाद पर जांच की अवधि के दौरान लागू पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का संबंध है तथा दुर्बल प्रभाव निर्धारित करने के लिए विचाराधीन उत्पाद पर निर्णायक समीक्षा के दौरान न लगाए गए शुल्क को लागू करने का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि एसएसआर के दौरान लगाया गया पाटनरोधी शुल्क पिछले वर्षों में निर्धारित पाटनरोधी शुल्क की तुलना में यथामूल्य आधार पर परिवर्तित किया गया था। जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद पर भारित औसत निर्धारित पाटनरोधी शुल्क उन संबद्ध देशों के लिए निर्णायक समीक्षा में निर्धारित यथामूल्य शुल्क से अधिक नोट किया गया है जहां से उत्पादकों/निर्यातकों ने कोई उत्तर नहीं दिया है। इस प्रकार प्रवंचना के कारण इन देशों के लिए निर्धारित कम कीमत और अधिक है। जहां तक जांच की अवधि के दौरान लागू पाटनरोधी शुल्कों के आधार पर पाटनरोधी शुल्क कम होने के संबंध में मूल्यांकन के लिए मै. ईएलपी के अधिवक्ताओं द्वारा किए गए अनुरोधों का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि केवल यूस्को के मामले में 200 सीरीज के विचाराधीन उत्पाद का जांच की अवधि के

दौरान निर्यात किया गया था जिस पर जांच की अवधि के दौरान कोई पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं था और इसीलिए इस सीरीज के लिए दुर्बल प्रभाव का निर्धारण करना नगण्य है। दो अन्य सीरीज के लिए यथा 300 और 400 के लिए चूंकि जांच की अवधि के दौरान व्यापार विचाराधीन उत्पाद से जांचाधीन उत्पाद में परिवर्तित हो गया, अतः छोड़ा गया पाटनरोधी शुल्क कीमत कमजोर होने का संकेतक है। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि युस्को के लिए जांच की अवधि के दौरान लागू पाटनरोधी शुल्क के आधार पर कीमत का कमजोर होना सकारात्मक है। जहां तक मै. आटुकुम्पु के निर्यात द्वारा विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क कम होने को पुनः देखे जाने का संबंध है, जांच की अवधि के दौरान लागू पाटनरोधी शुल्क लगाकर उसकी पुनः गणना की गई है और उसे भी सकारात्मक नोट किया गया है, जैसाकि मै. आटुकुम्पु द्वारा दायर प्रकटन के उत्तर से भी उसका सह-संबंध बनता है। आगे के पैराओं में संगत तालिका में संशोधित रेंज का भी उल्लेख कर दिया गया है। जांच की अवधि के दौरान लागू पाटनरोधी शुल्क लागू करने के आधार पर प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के लिए संबंधित तालिका में संशोधन किया है जो सकारात्मक सिद्ध होती है तथा पाटनरोधी शुल्कों के कम होने से सामान्यतः अधिक है।

xxiv. प्राधिकारी कुछ उत्पादकों/निर्यातकों तथा संबद्ध देशों के लिए सूचित की गई नकारात्मक कीमत कटौती के संबंध में मै. ई.एल.पी. सहित विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट करते हैं। प्राधिकारी इस संबंध में नोट करते हैं कि नियम-26(4) के अनुसार, प्राधिकारी को “लागू पाटनरोधी शुल्क की तथाकथित किसी प्रवंचना की मौजूदगी और प्रभाव निर्धारित करना” होता है। अधिनियम की धारा 9 क(1 क) में भी परिकल्पना की गई है कि प्रवंचना के कार्य से लगाया गया पाटनरोधी शुल्क अप्रभावी नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में घरेलू उद्योग को कीमत संबंधी प्रभाव सहित वास्तविक क्षति के कारकों की जांच करने की सामान्य आवश्यकताएं पाटनरोधी शुल्कों की प्रवंचना से संबंधी प्रवंचनारोधी जांच के प्रयोजन के लिए यथापरिकल्पित हैं और सीमित दायित्व पाटनरोधी शुल्कों की प्रवंचना के “प्रभाव” की जांच करना है। अतः इस जांच का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हितबद्ध पक्षकार केन्द्र सरकार द्वारा लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव को शुल्कों की प्रवंचना में किसी प्रकार से शामिल होकर नकार नहीं रहे हैं अथवा कम नहीं कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रवंचना से संबंधित नियमों में प्रवंचनारोधी जांच के लिए अनुबंध-2 अथवा नियम 11 के स्पष्ट प्रावधान नहीं हैं। इसके मद्देनजर प्राधिकारी का यह मत है कि विचाराधीन उत्पाद की प्रभावी कीमत से कहीं कम कीमत पर जांचाधीन उत्पाद में मात्रा के व्यापक स्तर पर परिवर्तन से विचाराधीन उत्पाद पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क काफी अप्रभावी हुए हैं।

निष्कर्ष

110. घरेलू उद्योग तथा विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों की जांच करने के बाद तथा उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:

i. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांचाधीन उत्पाद का आयात अर्थात् “सभी सीरीज के 1250 एमएम से अधिक की चौड़ाई के कोल्ड रोलड फ्लैट प्रोडक्ट्स ऑफ स्टेनलैस स्टील जिनमें आगे कोल्ड रोलड (कम कोल्ड किया गया) 4 एमएम तक की मोटाई में (मिल एज्ड के लिए +30 की चौड़ाई का टॉलरेंस तथा ट्रिम्ड एज्ड के लिए +4 एमएम) काम किया गया”, निम्नलिखित को छोड़कर:

- ग्रेड्स एआईएसआई 420 अत्यधिक कार्बन, 443, 441, ईएन 1.4835, 1.4547, 1.4539, 1.4438, 1.4318, 1.4833 तथा ईएन 1.4509;
- क्रोमियम-निकिल मैगनीज-कॉपर आस्टेनिटिक स्टेनलैस स्टील से युक्त निम्न निकेल वाले सामानों के संबंध में भारतीय पेटेंट सं. 223848 के तहत आपूर्ति किए गए उत्पाद तथा चीनी ताइपेई (ताइवान) के मै. यीह युनाइटेड स्टील कॉर्प (युस्को) द्वारा उत्पादित एवं आपूर्ति किए गए प्रतिनिधिकारक ग्रेड वाईयू 1 और वाईयू 4”

का पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद बढ़ गया है।

- ii. जांचाधीन उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद में बदलने में मूल्यधन नियमावली में निर्धारित शुरुआती स्तर से कम है।
- iii. जांच की अवधि के दौरान जांचाधीन उत्पाद का निर्यात पाटित कीमतों पर किया गया है।

- iv. जांचाधीन उत्पाद में 20 फरवरी, 2010 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं.14/2010-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा लगाए गए विचाराधीन उत्पाद पर मौजूदा पाटनरोधी उपायों को दुर्बल किया है।

सिफारिशें

111. प्राधिकारी उपर्युक्त के मद्देनजर दिनांक 11 दिसंबर, 2015 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं.. 61/2015-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा विचाराधीन उत्पाद पर लगाए गए मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को निम्नलिखित के अध्यक्षीन अनुबंध-1 में संलग्न किए गए अनुसार दिनांक 11 दिसंबर, 2015 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 61/2015-सीमाशुल्क (एडीडी) में निहित शुल्क तालिका में तालिकाबद्ध किए गए अनुसार जांचाधीन उत्पाद पर भी लगाए जाने की सिफारिश करते हैं :

- i. जांचाधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क वित्त मंत्रालय अर्थात केन्द्र सरकार द्वारा उसकी अधिसूचना की तारीख से लागू होगा।
- ii. जांचाधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क की वैधता दिनांक 11 दिसंबर, 2015 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं.. 61/2015-सीमाशुल्क (एडीडी) के माध्यम से लगाए गए विचाराधीन उत्पाद पर शुल्क के समनुरूपी होगा।
- iii.(क) जांचाधीन उत्पाद, जिसका आयात किसी आयातक द्वारा बिना स्लिटिंग के उसी रूप में अंतिम प्रयोग के लिए किया जाता है (दिनांक 11 दिसंबर, 2015 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं.. 61/2015-सीमाशुल्क (एडीडी) में उल्लिखित टालरेंस की सीमा तक को छोड़कर) पर दिनांक 11 दिसंबर, 2015 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 61/2015-सीमाशुल्क (एडीडी) के अनुसार लागू पाटनरोधी शुल्क का भुगतान देय नहीं होगा।
(ख) इसके अतिरिक्त, यदि जांचाधीन उत्पाद को 2 अथवा अधिक जांचाधीन उत्पाद में अर्थात 1250 एमएम से अधिक के आकारों में (अनुमति योग्य टालरेंस के साथ) में स्लिट किया जाता है तो उसे किसी भी पाटनरोधी शुल्क के अध्यक्षीन नहीं रखा जाएगा। (उदाहरण के लिए 2600 एमएम के टुकड़े को 1300 एमएम के आकार के टुकड़ों में बांटना)
(ग) तथापि, यदि जांचाधीन उत्पाद के संयोजन के लिए तथा जांचाधीन उत्पाद के आकर से कम अथवा जांचाधीन उत्पादों के आकारों से कम में स्लिट किया जाता है तो उस पर पाटनरोधी शुल्क देय होगा (उदाहरण के लिए 1800 एमएम के टुकड़े को 1400 एमएम तथा 400 एमएम के टुकड़े में स्लिट करते हुए अथवा 2200 एमएम के टुकड़े को 1400 एमएम तथा 800 एमएम के टुकड़े में स्लिट करते हुए अथवा 1400 एमएम के टुकड़े को 600, 500 तथा 300 एमएम के आकारों में स्लिट करना)
- iv. उपर्युक्त(iii) (क) और/अथवा(iii) (ख) के तहत आने वाले मामलों के लिए आयातक संबंधित सीमाशुल्क प्राधिकारियों को कानूनी रूप से प्रवर्तनीय वचनबद्धता देगा।
- v. वित्त मंत्रालय अपनी उपर्युक्त एजेंसियों द्वारा उपर्युक्त वचनबद्धता के आधार पर पाटनरोधी शुल्क के भुगतान के बिना (iii) (क) और/अथवा (iii) (ख) के तहत आने वाली श्रेणियों के लिए इस प्रकार आयातित जांचाधीन उत्पाद के प्रयोग की उपयुक्तता की मॉनीटरिंग करने के लिए एक उपर्युक्त मॉनीटरिंग तंत्र बना सकता है।

आगे की प्रक्रिया

112. इस अंतिम जांच परिणाम की अधिसूचना के कारण उत्पन्न होने वाली केन्द्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील, सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद तथा सेवाकर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

डॉ. इन्द्रजीत सिंह, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

अनुबंध- 1

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली 11 दिसंबर, 2015.

अधिसूचना सं. 61/2015-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि.(ई).- – जबकि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जन. गण., कोरिया गणराज्य, यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका, चीनी ताइपेई, थाइलैंड और संयुक्त राज्य अमरीका (जिसे आगे संबद्ध देश/क्षेत्र कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित तथा सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (जिसे यहां आगे सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम कहा गया है) के अंतर्गत आने वाले कोल्ड रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स ऑफ स्टेनलैस स्टील (जिसे यहां आगे संबद्ध सामान कहा गया है), के आयात के मामले में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-1, खंड-1 में 17 अप्रैल, 2014, की अधिसूचना सं. 15/04/2014-डीजीएडी, द्वारा एक समीक्षा की शुरुआत की थी, वित्त मंत्रालय में भारत के राजपत्र सं. 14/2010-सीमाशुल्क, दिनांक 20 फरवरी, 2010 द्वारा सीमाशुल्क लगाया गया था और जिसे 20 फरवरी, 2010 के सा.का.नि. (ई) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपधारा (I) द्वारा प्रकाशित किया गया था;

और जबकि, केन्द्र सरकार ने वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचना सं. 20/2014-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 12 मई, 2014 जिसे 12 मई, 2014 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 337(ई) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपधारा (I) में प्रकाशित किया गया था, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 21 अप्रैल, 2015 को शामिल करते हुए और संबद्ध देशों/क्षेत्रों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने को बढ़ाया था ;

और जबकि, संबद्ध देशों/क्षेत्रों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयात पर पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा के मामले में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-1, खंड-1 में 12 अक्टूबर, 2015 को अधिसूचना सं. 15/04/2015-डीजीएडी द्वारा प्रकाशित अधिसूचना को शामिल करते हुए कि-

- (i) संबद्ध देशों/क्षेत्रों से शुल्क लगाए जाने के बाद आयात की मात्रा कम होने पर संबद्ध सामानों का निरंतर पाटन रहा है ;
- (ii) घरेलू उद्योग का निष्पादन संबद्ध देशों से पाटित आयातों के आयात तथा विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर आयातों का उत्पाद रेंज में बदलने के कारण वर्तमान क्षति अवधि में कम हुआ है ;
- (iii) पाटन जारी रहने की संभावना है और घरेलू उद्योग का निष्पादन खराब होने की संभावना है, यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क लगाया गया;

और संबद्ध देशों/क्षेत्रों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है ।

अतः अब सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर सीमाशुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 के साथ पठित सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9 क की उपधारा(1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम जांच परिणामों पर विचार करने के बाद संबद्ध सामानों पर, जिसका विवरण निम्नलिखित तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट किया गया है, जिसकी विशिष्टी कॉलम-4 में विनिर्दिष्ट की गई है, जो कॉलम (2) में समनुरूपी प्रवृष्टि में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार सीमा प्रशुल्क अधिनियम की प्रथम अनुसूची के प्रशुल्क शीर्ष के तहत आता है, जो कॉलम (5) में समनुरूपी प्रवृष्टि में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार देशों/क्षेत्रों से निर्यातित किए जाते हैं, जो कॉलम (7) में समनुरूपी प्रवृष्टि में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार उत्पादकों द्वारा उत्पादित किए जाते हैं, जो कॉलम (8) में समनुरूपी प्रवृष्टि में निर्दिष्ट किए गए अनुसार निर्यातकों द्वारा निर्यातित किए जाते हैं और भारत में आयात किए जाते हैं, उपर्युक्त तालिका के कॉलम-9 में तदनुसूची, प्रवृष्टि में निर्दिष्ट किए गए अनुसार संबद्ध सामानों के आयात के पहुंच मूल्य की प्रतिशतता के रूप में निकाले जाने के लिए उस दर पर पाटनरोधी शुल्क लगाती है :-

तालिका

क्र.सं.	टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	विनिर्देशन	मूलता का देश/भूभाग	निर्यात का देश/भूभाग	उत्पादक	निर्यातक	पहुंच मूल्य का %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	7219	स्टेनलेस स्टील के कोल्ड – रोल्ड फ्लैट उत्पाद	नीचे पाद टिप्पणी के अनुसार छोड़े गए उत्पादों के अलावा सभी ग्रेड सभी सीरिज	चीन जन. गण.	कोई भी	कोई भी	कोई भी	57.39%
2	-वही-	-वही-	-वही-	संबद्ध देशों/क्षेत्रों से इतर कोई अन्य देश	चीन जन.गण.	कोई	कोई	57.39%
3	-वही-	-वही-	-वही-	कोरिया जन.गण.	कोरिया जन.गण.	पोसोको	1.हुंडई कार्पोरेशन 2. देवू इंटरनेशनल कार्पोरेशन	5.39%
4	-वही-	-वही-	-वही-	कोरिया जन.गण.	कोरिया जन.गण.	उपरोक्त से इतर कोई संयोजन		13.44%
5	-वही-	-वही-	-वही-	कोरिया जन.गण.	कोई	कोई	कोई	13.44%
6	-वही-	-वही-	-वही-	संबद्ध देशों/क्षेत्रों से इतर कोई अन्य देश	कोरिया जन.गण.	कोई	कोई	13.44%
7	-वही-	-वही-	-वही-	चीनी ताइपेई	कोई	कोई	कोई	15.93%
8	-वही-	-वही-	-वही-	संबद्ध देशों/क्षेत्रों से इतर कोई अन्य देश	चीनी ताइपेई	कोई	कोई	15.93%
9	-वही-	-वही-	-वही-	दक्षिण अफ्रीका	दक्षिण अफ्रीका	कोलंबस स्टेनलैस(प्रा.) लि.	कोलंबस स्टेनलैस(प्रा.) लि	12.34%
10	-वही-	-वही-	-वही-	दक्षिण अफ्रीका	दक्षिण अफ्रीका	उपरोक्त से इतर कोई संयोजन		36.91%
11	-वही-	-वही-	-वही-	दक्षिण अफ्रीका	कोई	कोई	कोई	36.91%
12	-वही-	-वही-	-वही-	संबद्ध देशों/क्षेत्रों से इतर कोई अन्य देश	दक्षिण अफ्रीका	कोई	कोई	36.91%
13	-वही-	-वही-	-वही-	थाइलैंड	थाइलैंड	पोसोको थाइनौक्स	1. पोसोको थाइनौक्स 1. हुंडई कार्पोरेशन	4.58%
14	-वही-	-वही-	-वही-	थाइलैंड	थाइलैंड	उपरोक्त से इतर कोई संयोजन		5.39%
15	-वही-	-वही-	-वही-	थाइलैंड	कोई	कोई	कोई	5.39%
16	-वही-	-वही-	-वही-	संबद्ध देशों/क्षेत्रों से इतर कोई अन्य देश	थाइलैंड	कोई	कोई	5.39%
17	-वही-	-वही-	-वही-	यू एस ए	कोई	कोई	कोई	9.47%

18	-वही-	-वही-	-वही-	संबद्ध देशों/क्षेत्रों से इतर कोई अन्य देश	यू एस ए	कोई	कोई	9.47%
19	-वही-	-वही-	-वही-	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ	एसीरोनॉकस यूरोपा एसएयू, स्पेन	एसीरोनॉकस यूरोपा एसएयू, स्पेन	29.41%
20	-वही-	-वही-	-वही-	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ	उपरोक्त से इतर कोई संयोजन		52.56%
21	-वही-	-वही-	-वही-	यूरोपीय संघ	कोई	कोई	कोई	52.56%
22	-वही-	-वही-	-वही-	संबद्ध देशों/क्षेत्रों से इतर कोई अन्य देश	यूरोपीय संघ	कोई	कोई	52.56%

पाद टिप्पणी :

** संबद्ध सामानों में निम्नलिखित को छोड़कर “सभी सीरिज के 600 मि.मी. से 1250 मि. मी. तक की चौड़ाई वाले स्टेनलेस स्टील के कोल्ड- रोल्ड फ्लैट उत्पाद जो आगे 4 मि.मी. तक की मोटाई वाले कोल्ड रोल्ड (कम किए गए कोल्ड) से आगे काम के नहीं (मिल एज्ड के लिए +30 मि. मी. का चौड़ाई टोलरेंस और ट्रिम एज्ड के लिए +4 मि. मी. का चौड़ाई टोलरेंस) शामिल हैं :

- i. 1250 मि मी से अधिक चौड़ाई वाली संबद्ध सामान (प्लस टोलरेंस)
 - ii. ग्रेड एआईएसआई 420 हाई कार्बन, 443, 441, ई एन 1.4835, 1.4547, 1.4539, 1.4438, 1.4318, 1.4833 तथा ई एन 1.4509
 - iii. चीनी ताइपेई (ताइवान) के मैसर्ज यी यूनाइटेड स्टील कोर्प (युस्को) द्वारा उत्पादित और आपूर्ति की गई क्रॉनियम- निकल मैंगनीज- कॉपर ऑस्टेनितिक स्टेनलेस स्टील और वाई यू 1 तथा वाई यू 4 ग्रेड की लो निकल की वस्तुओं के संबंध में भारतीय पेटेंट नं. 223848 के तहत आपूर्ति किए गए उत्पाद।
2. इस अधिसूचना के तहत लगाया गया पाटनरोधी शुल्क सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 5 वर्षों की अवधि (जब तक कि उसे हटाया, रद्द अथवा संशोधित न किया गया हो) के लिए लगाया जाएगा और भारतीय मुद्रा में देय होगा।

व्याख्या : इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए “पहुंच मूल्य” सीमाशुल्क अधिनियम, 1962, 1962 का 52 के तहत निर्धारित मूल्यांकन योग्य मूल्य और सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 3, 3क, 8 ख, 9 और 9क के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सभी सीमाशुल्क होंगे।

[फा.सं. 354/87/2009-टीआरयू(पीटी.-III)]

के.कलीमुथु, अवर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING AND ALLIED DUTIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th August, 2017

Final Findings**(Anti-Circumvention Investigation)**

Subject: Anti-Circumvention investigations concerning imports of Cold-Rolled Flat Products of Stainless Steel originating in or Exported from China PR, Korea, European Union, South Africa, Taiwan, Thailand and USA.

No. 14/1/2014-DGAD.— Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) thereof;

A. Background of the Case

1. Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) the Designated Authority, in the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, Govt. of India, appointed under the Rules supra, (hereinafter referred to as “the Authority”), vide Notification No. 14/06/2008-DGAD dated 25th November, 2008, initiated an anti-dumping investigation concerning import of Cold-rolled Flat products of stainless steel of the width above 600 mm of all series not further worked than Cold rolled (cold reduced) with a thickness of up to 4mm (width tolerance of +30 mm for Mill Edge and +4mm for Trimmed Edge) of ASTM A240/A480M." "C R Coils" (hereinafter also referred to as the subject goods) from China PR, Korea, European Union, South Africa, Taiwan, Thailand and USA (hereinafter also referred to as the subject countries).
2. The Preliminary Findings were issued by the Authority, vide Notification No. 14/06/2008-DGAD dated 27th March, 2009 and provisional duty was imposed by the Central Government, vide Notifications No. 38/2009-Customs, dated 22nd April, 2009. The Final Findings were issued by the Authority vide Notification No. 14/06/2008-DGAD dated 24th November, 2009. On the basis of the recommendations made by the Authority in the final findings, definitive anti-dumping duties were imposed by the Central Government, vide Notifications No. 14/2010-Customs, dated 20th February, 2010 effective from the date of the imposition of the provisional anti-dumping duty i.e., 22nd April, 2009 on the imports of the of the above goods, originating in or exported from the subject countries.

3. The Domestic industry had filed application for mid-term review of the anti-dumping duties and the mid-term review was initiated on 23rd June, 2010. The Authority vide its final findings No. 15/16/2010 dated 8th June 2011, clarified the Product under Consideration by specifying tolerances of +30mm for mill edge and 4 mm for trim edge. These clarifications were accepted and amendments carried out by Ministry of Finance vide Customs Notification No. 86/2011 dated 6.9.2011.
4. The Authority reviewed the Final Findings dated 24th November, 2009 subsequent to the Order by Hon'ble High Court of Punjab & Haryana Dated: October 8, 2010. These revised recommendations of the Designated Authority vide File No. 14/6/2008 dated 5th December, 2011 were accepted by the Central Government and Corrigendum was issued on 7. 2.2012.
5. The Domestic industry had filed application for sunset review petition of the anti-dumping duties and the mid-term review was initiated on 23rd June, 2010 and based on the duly substantiated application filed by the domestic industry, Authority vide Notification No. 15/04/2014-DGAD, dated 17th April 2014, initiated a sunset review of the antidumping investigation. The Authority vide its final findings No. 15/05/2014 dated 12th October, 2015, recommended the extension of duties of another five years which were accepted by Central Government vide Custom Notification 61/2015 dated 11.12.2015.
6. In the ongoing Anti-Circumvention investigation, regarding imports of Cold Rolled flat product of widths not covered under Custom Notification 61/2015 dated 11.12.2015, M/s Jindal Stainless Limited (herein referred as "petitioner" or "Applicant") filed an updated application dated 21.9.2015 before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Section 9A of the Act read with Rule 26(1) Customs Tariff (Identification, Assessment & Collection of Anti-Dumping Duty on the Dumped Articles & for Determination of Injury) Rules, 1995 (AD Rules) for initiation of Anti-Circumvention Investigation concerning imports of Cold Rolled flat product of widths not covered under Custom Notification 61/2015 dated 11.12.2015 (hereinafter also referred to as the "Product under Investigation" or "PUI"), originating in or exported from China PR, Korea, European Union, South Africa, Taiwan, Thailand and USA (herein referred as subject countries). The applicant requested for extension of existing anti-dumping duties on the imports of the subject goods to the PUI, originating in or exported from the subject country
7. Whereas, in view of the duly substantiated application filed by the petitioner under Rules 26 (1), the Authority initiated the investigation vide notification no 14/1/2014-DGAD sated 19th February, 2016 to determine the existence and effect of the alleged circumvention of the ADD levied and to consider recommendation of extension of ADD on imports of PUC to imports of PUI.

B. Procedure

8. The procedure described below has been followed with regard to the subject investigation:
 - i. The embassies of the subject countries in New Delhi were informed about the initiation of the investigations in accordance with Rule 6(2).
 - ii. The Authority provided copies of the non-confidential version of the application to the known exporters and the embassy of the subject countries in accordance with Rules 6(3) supra. A copy of the non- confidential version of the application was also made available in

the public file and provided to other interested parties, wherever requested.

- iii. The Authority forwarded a copy of the public notice to the following known manufacturers/exporters in the subject countries (whose names and addresses were made available to the Authority) and gave them opportunity to make their views known in writing within forty days from the date of the letter in accordance with the Rules 6(2) & 6(4):

CHINA

1. M/s Shanghai Krupp Stainless.
2. M/s Zhangjiagang POSCO Stainless Steel Co., Ltd

EU

1. M/s. ALZ NV, Belgium
2. Ugine (Division of Usinar), Immeuble Pacific, France
3. Acerinox SA, Spain
4. Acerinox SA, Italy
5. ThyssenKrupp Nirosta GmbH, Germany
6. ThyssenKrupp ACCAi Specialtereni SPA, Italy
7. Outokumpu Stainless, U.K.
8. Outokumpu Stainless, Finland
9. Outokumpu Stainless AB, Sweden.

USA

1. A.K. Steel Corporation, USA
2. Allegheny Ludlum, USA
3. North American Stainless, USA
4. J & L Specialty Steel, Inc., USA

Taiwan

1. Yieh United Steel Corporation (YUSCO)
2. Walsin Lihwa Corporation

South Africa

1. Columbus Stainless (Pty) Ltd

Korea

1. POSCO

9. In response to the initiation notifications following exporters / producers from subject countries have responded:

- i. Outokumpu Oyi, Europe
- ii. Yieh united Steel Corporation, Taiwan (YUSCO)
- iii. Walsin Lihwa Corporation, Taiwan
- iv. Yuan Long Stainless Steel Corporation, Taiwan (YLSS)
- v. Tang Eng Iron Works Co. Ltd., Taiwan
- vi. POSCO Asia

- vii. POSCO, Korea
- viii. Daewoo International, Korea
- ix. Hyundai Corporation, Korea
- x. Samsung C&T, Korea
- xi. SK Networks, Korea
- xii. Toyota Tshusho, Korea

10. The Authority forwarded copies of the public notice to the following known importers/consumers/associations of subject goods in India (whose names and addresses were made available to the authority) and advised them to make their views known in writing within forty (40) days from the date of issue of the letter in accordance with the Rule 6(4):

- 1. Honest Enterprise Ltd., Vadodara
- 2. Kuber Steel Impex, Mumbai
- 3. M.M. Enterprises, Raigadh
- 4. Advance Metal Corporation, Mumbai
- 5. Bhandari Foils Pvt. Ltd., Dewas
- 6. Angel Pipes & Tubes Pvt. Ltd., Mumbai
- 7. IDMC Ltd., Gujarat
- 8. M.K. Steel Centre, Raigad
- 9. Riddhi Siddhi Impex, Mumbai
- 10. Salem Stainless Steel Suppliers, Chennai
- 11. Western Metal (India), Mumbai
- 12. Star Stainless Steel, Mumbai
- 13. Advance Metal Corporation
- 14. Arihant Steel Enterprises, Mumbai
- 15. Jindutt Steel, Mumbai
- 16. Madras Steel Agencies, Chennai
- 17. Nobel Impex, Mumbai
- 18. All India Stainless Steel Industries Association
- 19. Stainless Steel Exporters Welfare Association
- 20. Process Plant and Machinery Association of India

11. The Authority has received questionnaire response/submissions from the following importers/users/other interested parties.

- 1. POSCO India Chennai Steel Processing Private Limited (Questionnaire & Submissions)
- 2. POSCO India Delhi Steel Processing Private Limited (Questionnaire & Submissions)
- 3. POSCO India Pune Steel Processing Private Limited (Questionnaire & Submissions)
- 4. Sun Mark Stainless Pvt. Ltd (Submissions)
- 5. Suncity Strips & Tubes Pvt. Ltd. (Questionnaire & Submissions)
- 6. Sunrise Stainless Pvt. Ltd. (Submissions)
- 7. Suncity Sheets Pvt. Ltd. (Questionnaire & Submissions)
- 8. Shree Ramdev Metal Mart (Questionnaire & Submissions)
- 9. M/s Maxgrow Corporation (Questionnaire & Submissions)

10. M/s Shakti Steel (Questionnaire & Submissions)
11. M/s Ramani Steel House (Questionnaire & Submissions)
12. M/s Metal & Steel (India) (Questionnaire & Submissions)
13. M/s NG Industries (Questionnaire & Submissions)
14. The Tamilnadu Stainless Steel Merchants and Manufacturers Association
15. Metal & Stainless Steel Merchant's Association
16. M/s Maruti Suzuki India Limited (MSIL)
17. M/s Hero Moto-Corp Ltd.
18. Representation from European Commission
19. Representation from Government of the Republic of Korea
20. Representation from Government of Taiwan
21. M/s Aesteiron Steels Pvt. Ltd.
22. All India Stainless Steel Industries Association
23. M/s Saraswati Steel (India)
24. M/s Ashwin Impex -
25. M/s Inox Stainless
26. M/s Jayesh Metal Corporation
27. M/s Dhanera Impex
28. M/s Honesty Impex
29. M/s NG Industries
30. M/s Dhruv Exim
31. M/s Siddhivinayak Steel
32. M/s Navnidhi Steel & Engg. Co. Pvt. Ltd.
33. M/s B.V.S. Overseas
34. M/s Ambuja Metal Industries Pvt. Ltd.
35. M/s R.M. Metal Industries
36. M/s New Manak Overseas Limited
37. M/s All India Metal Corporation
38. M/s Navyug Metal Corporation
39. M/s Precision Impex
40. M/s Neptune Steel Impex
41. M/s Nenava Metal Corporation
42. M/s Meena Metal Impex Pvt. Ltd. (India)
43. M/s MaxGrow Corporation
44. M/s Divine Impex
45. M/s Acer Steel
46. M/s Metal & Steel (India)
47. M/s Stainox Alloys Pvt. Ltd.
48. M/s Siddhant Steel
49. M/s Sanghvi Enterprise
50. M/s Tradeport Stainless Alloys
51. M/s Saachi Impex
52. M/s Glomet Alloys LLP
53. M/s Inter Sales Enterprise
54. M/s Steel Line (India)

55. M/s United Stainless
56. M/s Ratnaravi Metal Impex
57. M/s Modest Metal Corporation
58. M/s Ashok Metal Corporation
59. M/s M M Metal International
60. M/s M M Metatrade Pvt. Ltd.
61. M/s Shubhlaxmi Metals and Tubes Pvt. Ltd.
62. M/s World Stainless
63. M/s Good Luck
64. M/s Inco Steel
65. M/s Non- Ferrous Metal Association (Karnataka)
66. M/s PS Raj Steels Pvt. Ltd.
67. M/s Inox Stainless
68. M/s Glomet Alloys LLP
69. M/s M.P. Industries
70. M/s Divine Impex
71. M/s Ashok Metal Corporation
72. M/s Navnidhi Steel and Engg. Co. Pvt. Ltd.
73. M/s Pacific Metal Trading Co.
74. M/s Acer Steel
75. M/s Nixon Steelium LLP
76. M/s Vishal Tubes & Pipes P. Ltd.
77. M/s Accurate Steel
78. M/s Modest Metal Corporation
79. M/s Star Stainless Steel
80. M/s Ashwin Impex
81. M/s Siddhivinayak Steel
82. M/s Merinox Inox
83. M/s NG Industries
84. M/s SI Pavan Steel (India)
85. M/s Ubique Alloys Pvt. Ltd.
86. M/s United Steel (India)
87. M/s Dhruv Exim
88. M/s Domet Trading Pvt. Ltd.
89. M/s The Tamilnadu Stainless Steel Merchants and Manufacturers Association,
90. M/s Saraswati Steel (India)
91. M/s Marvel Impex
92. M/s precision Impex
93. M/s Stainox Alloys Pvt. Ltd.
94. M/s Steel International
95. M/s United Stainless
96. M/s Nocil Steels
97. M/s Neon Metals Impex Pvt. Ltd.
98. M/s S.C. Shah Enterprises
99. M/s Agol Associates

100. M/s Salem Steel Trading Co.
 101. M/s Ratnaravi Metal Impex
 102. M/s Trust Impex
 103. M/s Ganesha Impex
 104. M/s Shakti Pumping Life
 105. M/s Shiva Trading Co.
 106. M/s Navnidhi Steel & Engg. Co. Pvt. Ltd.
 107. M/s Santosh Steel Industries
 108. M/s Navpad Steel Centre
 109. M/s Metal Trading Corporation
 110. M/s Angel Pipes & Tubes Pvt. Ltd.
 111. M/s Siddhivinayak Steel
 112. M/s Anmol Stainless Pvt. Ltd
 113. M/s Minox Metal Private Limited
 114. M/s Shah Foils Limited
 115. M/s M. P. Industries
 116. M/s Balaji Impex
 117. M/s M/s KPV Impex
 118. M/s BRG Iron & Steel Co. Pvt. Ltd.
 119. M/s Reliance Fabrications Pvt. Ltd
 120. M/s All India Stainless Steel Importers Association
 121. M/s Metal & Stainless Steel Merchant's Association
 122. M/s CMS Stainless Company
 123. M/s Vikram Metal (India)
 124. M/s Sharda Motor Industries Ltd.
 125. M/s All India Stainless Steel Industries Association
 126. M/s Remi Edelstahl Tubulars Ltd.
 127. M/s Faurecia Emissions Control Technologies India Private Limited
 128. M/s Shakti Steel
 129. M/s Ramani Steel House
 130. M/s Shah Foils Limited
 131. M/s Vedik Ispat Pvt. Ltd.
 132. M/s Stainless Steel Impex
 133. M/s Regency Impex (India)
 134. M/s Nexus Impex
 135. M/s Kamlesh Metal & Alloy
 136. M/s Anil Metal Corporation
 137. M/s Greenline Pipe & Fitting
 138. M/s Shri Aanand Metal
 139. M/s Parag Metals
12. A large number of responses have been filed by various importers/users and their associations. The Authority in the disclosure clarified that while all relevant issues and all such responding entities have been individually included, in case of any submissions by any applicant, which may have got inadvertently missed out may be pointed out so as to address the same in the final findings.

13. Transaction-wise imports data procured from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCIS) has been relied upon for the analysis in present circumvention investigation.
14. Exporters, producers, importers and other interested parties, who have neither responded to the Authority nor supplied information relevant to this investigation, have been treated as non-cooperating interested parties by the Authority.
15. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to reasonableness of the claim of confidentiality. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
16. Non-confidential versions of the evidence presented by interested parties were made available in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties as per Rule 6(7).
17. In accordance with Rule 6(6) of the AD Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a public hearing held on 3.7.2017. The interested parties were requested to file written submissions of their views expressed orally.
18. The submissions made by the interested parties during the course of the investigations have been addressed in this finding to the extent they are relevant and backed by evidence.
19. Verification of the information and data submitted by the participating domestic producer was carried out to the extent deemed necessary.
20. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has used "best information available" and has treated such parties as non-cooperative.
21. On the Writ Petition [W.P. (C) No. 3544/2016, CM NOS. 15209/2016 and 25402/2016] filed by one of the importers i.e. M/s Suncity Sheets Pvt. Ltd., the Hon'ble High Court of Delhi through order dated 27.04.2016 stayed the investigation. The writ petition along with the above mentioned CM numbers were dismissed vide order dated 08.03.2017 of Hon'ble High Court thereby leading to vacation of stay on 8.3.2017.
22. The Authority issued a disclosure statement under Rule 16 on 7th August, 2017 and provided an opportunity to give comments to the disclosure statement till 16th August, 2017. Comments received from Domestic Industry/various interested parties have been appropriately addressed in this finding and certain corrections in tabulations also incorporated.
23. In this Final Findings, *** represents information furnished by the interested parties on confidential basis, and so considered by the Authority under the AD Rules.
24. For the purpose of this investigation the period of investigation was taken as July 2014 to September 2015 (15 months) and for the purpose of analyzing circumvention data was taken for the period 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 and POI has been

considered.

25. The exchange rate for the POI has been taken by the Authority as Rs.63.44 = 1 US\$ wherever the actual rate of conversion was not available.

C. Procedure related/Judicial proceedings:

26. On the basis of Writ Petition No. 3544/2016 filed by M/s Suncity Sheets Ltd., stay was granted by the High Court of Delhi through order dated 27/04/2016. Operative para of the order are as follows:

“10. Rule 25 (1) of the CTA ADD Rules envisages import of an article which is subject to anti-dumping in an ‘unassembled, unfinished or incomplete form’ which is thereafter ‘assembled, finished or completed in India’. It is not the case of Respondent No. 4 that the CRSS of width 1250mm and above that is imported is ‘in an unassembled, unfinished or incomplete form’. Consequently, the Court is prima facie of the view that the investigation undertaken pursuant to the impugned notification dated 19th February, 2016 is not permissible even in terms of Rule 25 (1) of the CTA ADD Rules.”

Hearings have been held on 27.04.2016, 19.07.2016, and 03.08.2016. The counter affidavits and the stay vacation petitions filed by the Designated Authority before the Hon’ble Division Bench of Delhi High Court. The Hon’ble Division Bench heard the matters in its final hearing on 15.09.2016 the writ petition was dismissed vide order dated 8.3.2017 of Hon’ble High Court thereby leading to vacation of stay. . The total period of stay in the case is 316 days. As one year had expired on 18.02.2017, Designated Authority in accordance with Rule 26 (6) of AD Rules extended the time for 6 months i.e. till 18.08.2017.

The key observations made by Hon’ble High Court of Delhi in its Judgment dated 08.03.2017 are as under:

“10. The initiation of investigation has not caused any prejudice to any of the parties including the petitioner as the determination in terms of Rule 27 would only be made after full data and material is obtained from all the parties. The Authority has no jurisdiction to recommend anti-circumvention duty on any of the importers including the petitioner if the Petitioner through the questionnaire response substantiates that the imports of widths above 1250 mm is not circumvention of existing anti-dumping duties.

15. It is common ground that ADD has been levied on CRSS with a width less than 1250 mm; that duty was maintained in final findings, review of such findings and sunset review proceedings. The petitioner (and interveners) complains that initiation of circumvention proceedings is factually unfounded and also legally indefensible. It is also common ground that anti-circumvention measures can be taken under Rule 25-26 of the Anti-Dumping Rules. Therefore, the grievance here is not regarding the complete absence of jurisdiction, rather, to its unwarranted exercise, given – what according to the petitioners is, the history of the case. The petitioners rely on the observations- repeated at least in two proceedings, by the DA, about the technical and commercial unviability of importing 1250 mm or more wide CRSS and then cutting or slitting it to smaller width for use in India.

22. The petitioner is correct in contending that the DA had gone into the question, and returned specific findings with respect to the improbability of importation of CRSS strips wider than 1250 mm and their size reduction for use as articles that are the subject of ADD. However, the nature of the inquiry that led to those findings (and observations) were in the context of likelihood of injury. The period covered in respect of those proceedings were 2009-2015. The nature of materials considered during those investigations focused on all those elements that make up the injury. However, in circumvention proceedings, the trajectory of the inquiry is altogether different. It is whether, given the existence of ADD (and the established existence of injury), there is any behaviour – in the form of import of other products, which can be adapted or altered for use as the product or articles that are subject to ADD. Whilst the decisive nature of the observations of the DA in past instances is facially compelling for a court to hold that there should not be a fresh inquiry, yet one cannot be oblivious to the nuanced nature of the circumvention procedure. The power to resort to it should be based on objective material. In the present case, the information, which the respondents rely upon is the stagnancy in demand of the article which is subject to ADD, and the pattern of increase in import of CRSS that is wider than 1250 mm. The Petitioners' argument that the subject matter of the previous orders and observations are the same in circumvention proceedings, is unpersuasive to this court.

The inquiry of the process of slitting and cutting of a steel strip, as well as if it amounts to “assembling” a disassembled or incomplete article, would then become an issue in respect of which neither party addressed arguments on merits, nor presented the necessary facts. Given the fact that this would be the subject matter of inquiry and arguments before the competent forum, a ruling in this proceeding is neither desirable nor warranted having regard to the established limitations of judicial review under Article 226, which is confined to questions of legality, procedural regularity, fairness and a reasonable decision.”

The High Court's Judgment dated 8.3.2017 was challenged in Supreme Court by M/s Suncity Sheets Pvt. Ltd. and M/s Outokumpu Oyj through Special Leave Petition. The Hon'ble Supreme Court granted the leave vide its order dated 21.04.2017. The Hon'ble Supreme Court did not stay the investigations.

D. Product under consideration / Product under Investigation and like article

Product under Consideration

27. The product under consideration for the purpose of this circumvention investigation is the same as defined in the previous sunset review investigation whose final findings were issued vide Notification No. 15/04/2014 dated 12.10.2015 has been defined as follows:

“Cold-rolled Flat products of stainless steel of width of 600 mm upto 1250mm of all series not further worked than Cold rolled (cold reduced) with a thickness of up to 4mm (width tolerance of +30 mm for Mill Edged and +4mm for Trimmed Edged)”, excluding the following:

- i. The subject goods of width beyond 1250 mm (plus tolerances).
- ii. Grades AISI 420 high carbon, 443, 441, EN 1.4835, 1.4547, 1.4539, 1.4438, 1.4318, 1.4833 and EN 1.4509
- iii. Product supplied under Indian Patent No. 223848 in respect of goods comprising Low Nickel containing Chromium-Nickel Manganese-Copper Austenitic Stainless

steel and representing Grades YU 1 and YU 4, produced and supplied by M/s Yieh United Steel Corp (Yusco) of Chinese Taipei (Taiwan).

Product under Investigation

28. The Product under Investigation alleged to be circumventing the anti-dumping duties is Cold-rolled Flat products of stainless steel of the same description as the Product under Consideration defined in paragraph 27 above but having widths above those described and covered under the scope of the Product under Consideration. These products i.e. product under investigation are also classifiable under Chapter 72 of the Customs Tariff Act, 1975 under the same sub-heading 7219.31, 7219.32, 7219.33, 7219.34, 7219.35 and 7219.90. The Customs classification is indicative only and not binding on the scope of this investigation. The product under investigation which is the subject matter of the alleged circumvention has all the essential and basic characteristics of the product subject to anti-dumping duties with the only difference being in terms of its width.

Submissions made by the Producers/ Exporters/ Importers and Associations

29. Some of the interested parties have submitted that the PUI and PUC are not like articles as the Authority in the original investigation had not treated both products as like articles and excluded widths of above 1250mm from the scope of the investigation. In view thereof, interested parties had requested the Authority not to treat PUC and PUI as like articles.
30. M/s ELP Advocates & Solicitors representing Outokumpu Oyj and YUSCO have stated that the Petitioner has filed the Petition for anti-circumvention in December 2016 claiming to be the producer of the PUC despite the fact that it has hived off the plant at Hisar in its entirety to JSHL prior to the aforesaid filing and even before the Period of Investigation. The claim of the Petitioner is therefore blatantly false and unjustified.
31. M/s GTC Consultants representing M/s Suncity Sheets Pvt. Ltd., M/s Suncity Strips and Tubes P Ltd, M/s Sunrise Stainless Pvt. Ltd and M/s Sunmark Stainless Private Limited have submitted the following:
- The Applicant has initiated the proceedings as it had failed to get the PUC scope expanded in the last proceedings. It is incorrect for the Applicant to assume that the ADD Rules provide for multiple proceedings on the very same cause of action. The Applicant has filed its appeal against the Notification No. 61/2015-Cus dated 11.12.2015 and cannot be allowed to pursue multiple proceedings on the very same cause of action. As indicated earlier, there is no event subsequent to the issuance of the Notification dated 11.12.2015 which could provide a cause of action for the present proceedings to be initiated.
 - The Applicant was fully aware that CRSS exceeding a width of 1250 mm was a different class of article and it had been repeatedly held to be so. If at all, there was a grievance against dumping of such an “article”, independent proceedings could have been initiated to investigate such dumping. Having failed to do so, for obvious reasons as the Applicant could possibly not justify its standing as a domestic industry, it filed an application for anti-circumvention, to get an initiation through the back door, which is not permissible.

- In view of the above, the present anti-circumvention proceedings would amount to an abuse of the process of law as the very same issues have already been examined by this Ld. Authority and decided against the Applicant and the only recourse available to it is to initiate fresh investigations for imposition of ADD on CRSS of width above 1250mm.

Submissions made by the Domestic Industry

32. The Domestic Industry submitted that during the original investigations, the wider coils were excluded from the scope of the investigation on the ground that the same were not actually produced and sold by the Domestic Industry during the period of investigation despite treated them technically substitutable. Domestic Industry further submitted that after imposition of the anti-dumping duties large quantities of the widths above 1250mm are being imported into the country without payment of anti-dumping duties even though the same are ultimately slit into narrower widths. According to Domestic Industry, the goods are now brought in widths exceeding 1250mm which are incomplete products as the same are necessarily slit into narrower widths (final complete product) for use by the ultimate customer. The changed composition of the imports bears testimony to the fact that the above arrangement has been made only to circumvent the anti-dumping duties on the subject goods. In view thereof, the Domestic Industry requested the Authority to kindly treat PUC and PUI as like article.

Examination by the Authority

33. The Authority after noting various submissions holds that the product under consideration for the purpose of circumvention investigation stands defined as follows:

“Cold-rolled Flat products of stainless steel of width of 600 mm upto 1250mm of all series not further worked than Cold rolled (cold reduced) with a thickness of up to 4mm (width tolerance of +30 mm for Mill Edged and +4mm for Trimmed Edged)”, excluding the following:

- The subject goods of width beyond 1250 mm (plus tolerances).*
 - Grades AISI 420 high carbon, 443, 441, EN 1.4835, 1.4547, 1.4539, 1.4438, 1.4318, 1.4833 and EN 1.4509*
 - Product supplied under Indian Patent No. 223848 in respect of goods comprising Low Nickel containing Chromium-Nickel Manganese-Copper Austenitic Stainless steel and representing Grades YU 1 and YU 4, produced and supplied by M/s Yieh United Steel Corp (Yusco) of Chinese Taipei (Taiwan).*
34. The Product under Investigation alleged to be circumventing the anti-dumping duties is Cold-rolled Flat products of stainless steel of the same description as the Product under Consideration defined above but having widths above those described and covered under the scope of the Product under Consideration. These products i.e., product under investigation are also classifiable under Chapter 72 of the Customs Tariff Act, 1975 under the same sub-heading 7219.31, 7219.32, 7219.33, 7219.34, 7219.35 and 7219.90 even though the Customs classification is indicative only and not binding on the scope of this investigation. The Authority notes that the product under investigation which is the subject matter of the alleged circumvention has all the essential and basic characteristics of the product subject to anti-dumping duties. The only difference is in terms of its width.

35. As regards the issue of like article, the Authority notes that under the provisions relating to circumvention, the Authority is not required to *per se* examine whether the PUC and the PUI are like articles or not. The only requirement in terms of rule 25(1) is to examine whether an article subject to anti-dumping duty is imported into India from any country including the country of origin or country of export notified for the purposes of levy of anti-dumping duty, in an unassembled, unfinished or incomplete form and is assembled, finished or completed in India or in such country. Nevertheless, it is observed that the rationale for excluding the PUI from the scope of anti-dumping duties was the finding of the Authority that the PUI was not being produced and sold by the Domestic Industry during the original period of investigation. Therefore, the exclusion of a particular category of a product does not *per se* imply that they are not like articles. As the exclusion was on the basis of width only with production process being the same, there is enough evidence on record to establish that the PUI imports have replaced the PUC imports substantially without any economic or commercial justification. Therefore, the Authority holds that the submissions of the interested parties on the issue of like article are not relevant either in terms of the legal provisions or the facts of this case.

E. Domestic Industry and Standing

36. The application for the circumvention investigation has been filed by M/s Jindal Stainless Limited who accounted for a major proportion of the total domestic production during the period of investigation. As per the information available with the Authority, there are three other known producers of the product under consideration in the country i.e., M/s BRG, M/s Salem Steel Plant (SAIL) and M/s Shah Alloys. There is no opposition to the domestic industry's application from any other producer in the country in the present investigation.

Submissions made by the Producers/Exporters/Importers and Associations

37. It has been stated by the interested parties that Jindal Stainless Limited (JSL) ceased to be the domestic industry for the PUC under Rule 2(b) pursuant to the de-merger scheme dated March 31, 2014. They have further contended that pursuant to the de-merger JSHL, the newly formed company became the major proportion producer of the PUC in India since it is the legal entity that owned and operated the plant for the PUC in Hisar.
38. It is submitted that the petitioner had filed the petition for anti-circumvention investigations in December 2016 claiming to be the producer of PUC despite the fact that it had hived off the plant at Hisar in its entirety to JSHL prior to the aforesaid filing and even before the Period of Investigation.
39. It is submitted that the Petitioner should provide its production figures in order to determine if the PUC produced by the Petitioner at the time of initiation accounts for more than 25% of the total domestic production. Moreover, they requested the Authority to carry out 25% test at the time of initiation and POI.
40. M/s ELP Advocates & Solicitor submitted that as per Rule 26(1) and Rule 2(b) of the AD Rules, the 'domestic industry' must at least be a manufacturer of the major proportion of the total domestic production of the PUC in India. The current Petitioner, Jindal Stainless Ltd. ('JSL'), ceased to be the domestic industry for the PUC under Rule 2(b) of the AD Rules pursuant to the de-merger scheme dated March 31, 2014. Pursuant to the de-merger as per the Petitioners' own

showing, JSHL, the newly formed company, became the major proportion producer of the PUC in India since it is the legal entity that owned and operated the plant for the PUC in Hisar. Therefore, Jindal Stainless Hisar Ltd. ('JSHL') became the domestic industry, if at all, in its stead since it formally owned and operated the plant at Hisar which had been the basis for Petitioner being deemed the 'domestic industry' in prior investigations and it is trite in law that when a party approaches a tribunal for discretionary relief, he must not only come with clean hands but must also show utmost good faith and disclose all material facts which are within his knowledge. It is submitted that the Petitioner itself failed to provide information on Jindal Stainless Hisar Ltd., which is a related party to the Petitioner and JSHL is also the major producer of the PUC in India.

41. M/s ELP Advocates & Solicitor further submitted that the onus to prove its standing as the 'domestic industry' solely rests on the Petitioner and the Petitioner cannot shift the onus of proof on other interested parties. Moreover, the Petitioner has completely disregarded the directions of the Hon'ble Designated Authority at the public hearing wherein the Hon'ble Designated Authority directed the Petitioner to provide its production figures in order to determine if the PUC produced by the Petitioner at the time of initiation accounts for more than 25% of the total domestic production.

Submissions made by the Domestic Industry

42. The petitioner submitted that the contention of the interested parties that JSL ceased to be a Domestic Industry is completely misconceived and based on flawed premises of law and facts. They further submitted that the Interested parties are attempting to mislead the Authority by ignoring the fact that on the date of the application, both the plants were operated under the same legal entity namely Jindal Stainless Ltd. (JSL). Therefore, it is completely incorrect to state that the application was not filed on behalf of the Domestic Industry as defined under Rule 2(b) of the Anti-dumping Rules. It is further submitted that the interested parties also ignored the fact that the Demerger Scheme, as approved by the Hon'ble High Court, was made effective from November 1, 2015. In other words, all operations and actions upto after 31st October, 2015 were undertaken by the transferor entity. It is pertinent to note that the entire scheme of arrangement for demerger was to become effective only when conditions as per Clause 1.5(a) of Section V of the Scheme are met with. As can be seen from the scheme of arrangement itself, the scheme was to be effective from the date of the last approval. The filing of the HC order with ROC was the last approval which was done on 1st November 2015. Hence, it is submitted by the Domestic Industry that the scheme became operationally effective only from 1st November 2015. In other words, the date on which the application for circumvention was filed, the demerger scheme was not operational and in the eyes of law only JSL was in existence. In view thereof, it cannot be said that the application was not filed by domestic Industry.
43. The petitioner submitted that in any case, scheme has been sanctioned by the Hon'ble High Court with a specific direction that the same is binding on all concerned. Therefore, all legal, tax regulatory, quasi-judicial, administrative proceedings, suits, appeal, applications or other proceedings of whatsoever nature initiated by JSL in connection with the Hisar Unit were to continue as if they were initiated by the JSHL itself. Therefore, under the arrangement of scheme, all actions taken by JSL are to be treated as actions taken by JSHL under the scheme.

44. Domestic Industry submitted that the issue of standing is not applicable in the circumvention investigations. However, the Domestic Industry has stated that they are eligible industry to file anti-circumvention petition as they are well above the threshold of 25% of the total production of PUC and PUI both at any given point of time.
45. In view thereof, it is clear beyond any doubt that as of the date of filing, the application in September 2015, JSL had the full legal authority to do so. That being the case, petitioner submitted that the requirement of Rule 26 that the application has to be “by or on behalf of the Domestic Industry” was fully satisfied. Without prejudice, it is submitted that JSL alone also satisfies the conditions of filing an application on behalf of the Domestic Industry. Therefore, the submissions of the interested parties are devoid of any merit either in law or on facts.

Examination by the Authority

46. The Authority notes that the petition for anti-circumvention investigation and extension of existing ADD on imports of PUC to the imports of PUI is filed by M/s Jindal Stainless Limited as per Rule 26(1) which reads as under;

“(1) Except as provided herein below, the designated authority may initiate an investigation to determine the existence and effect of any alleged circumvention of the anti-dumping duty levied under section 9A of the Act , upon receipt of a written application by or on behalf of the domestic industry.”

47. The Authority notes that Rule 26 (1) requires an anti-circumvention petition to be filed by the Domestic Industry of the ADD already levied. In this investigation, the Domestic Industry of the existing ADD comprised of M/s Jindal Stainless Limited who had neither imported the PUI nor the PUC from any of the subject countries during entire investigation period nor were they related to any importer or exporter of the PUI or the PUC.
48. As regards eligibility of JSL as Domestic Industry notes that the Authority the order regarding demerger of JSL was effective from November 1, 2015, i.e., post the filing of application for anti-circumvention investigation by JSL and that period of investigation being 1.7.2014 to 30.9.2015, is also prior to November 1, 2015. In any case, the Authority in the present investigation had considered data filed on behalf of both JSL and JSHL.
49. In any case, the Authority notes that JSL alone also qualifies the test of 25% and 50% even though the said conditions are not per se applicable for an investigation initiated under Rule 26. In view of the aforesaid, it is considered that the application in this case filed by JSL did not suffer from any legal infirmity and the same is considered to have been filed by and or on behalf of the Domestic Industry for the purpose of this circumvention investigation.

F. Confidentiality and Other Issues

Submissions made by the Domestic industry

50. With regard to the confidentiality, the domestic industry while quoting Rule 7 of the Rules and WTO Panel in its report in the case of Guatemala — Cement II (WT/DS156/R) has submitted as follows:
- (i) Domestic Industry have claimed confidentiality only on the information which is related to its cost and prices. They also provided the indexed figures for the cost and prices.

- (ii) None of the exporters had provided the non-confidential version which is supposed to be an exact replica of their responses in confidential version. Further, the producers/exporters had kept even the volume related information confidential even, the statement of claiming confidentiality was not provided.
- (iii) Many interested parties have kept even the Annexures to their written submissions as confidential thereby not allowing the domestic industry an opportunity to provide comments on the same.

Submissions made by the Producers/Exporters/Importers and Associations

- (i) Excessive confidentiality has been claimed by the Domestic Industry on a number of details without showing good cause for the same or providing non- confidential summary of the same.
- (ii) M/s DGS Associates representing POSCO, Korea and its related entities have submitted that they have claimed confidentiality in accordance with the guidelines prescribed by the Hon'ble Designated Authority in its Trade Notice No 1/2013 dated December 09, 2013 and as per Rule 7 of the Anti-dumping Rules. To the contrary, the Petition is based on mere conjectures rather than substantiation by submission of evidence as is the mandate of the AD Rules.
- (iii) The matter is since pending before the Supreme Court, the investigation may be kept in abeyance till the orders are pronounced by the Supreme Court.
- (iv) M/s Wirana Pte. Ltd., Singapore stated that they would like to be an interested party and that POI be extended by 5 month, scope of investigation be restricted to 304 and 316 only as the imports are of few grades only and this investigation would adversely affect users.
- (v) M/s Suncity Sheets Pvt. Ltd. has challenged the initiation of the present proceedings before the Hon'ble Delhi High Court in Writ Petition (C) No. 3544 of 2016, *inter alia*, on the grounds that this Ld. Authority does not have the jurisdiction to initiate the present proceedings. It is submitted that while dismissing the said writ petition, the Hon'ble High Court has made categorical observations to the effect that this Ld. Authority is required to go into the inquiry of the process of slitting and cutting of a steel strip, as well as if it amounts to "assembling" a disassembled or incomplete article or not. Further, where this Hon'ble Authority comes to a conclusion that the threshold specified under Rule 25 and 26 are not met in the present case, the Application for Anti-Circumvention will have to be dismissed, inasmuch as, the existence of pre-conditions of Rule 25 and 26 is *sine qua non* for proceeding with the present investigations. Accordingly, on the basis of a limited enquiry, as is also contemplated in the order of the Hon'ble Delhi High Court, a finding with respect to satisfaction of the pre-conditions of Rule 25 are required to be given.
- (vi) M/s ELP Advocates & Solicitors representing Outokumpu Oyj and YUSCO have stated the following:
 - In response to Domestic Industry Questionnaire, filed additional information with the Hon'ble Designated Authority vide communication dated 10th April, 2017. It is the Exporter's submission that the Petitioner has claimed most of this information confidential unjustifiably, which is in gross violation of Rule 7 of the AD Rules and Trade Notice No. 1/2013 dated December 2013.

- The Designated Authority vide the initiation notification of the present investigation at paragraph 17 has specifically stated that “any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.”
- The Hon’ble CESTAT in the matter of *Alkali Manufacturers Association of India vs. Designated Authority* 2006 (194) E.L.T. 161 (Tri. - Del.) held as follows:

“15.1 ...The interested parties should not be denied the basis on which decision has been arrived at by the Designated Authority. Reasons cannot be confidential, only the data or figures which may harm the party claiming confidentiality in their business dealings are to be kept confidential. But the reasons for arriving at a conclusion or reason for accepting or rejecting any ground in the representation made by other interested parties cannot be the confidential and proper reasons for accepting or rejecting the point of view or the information furnished should be given by the Designated Authority in his order.”

- Further, the Hon’ble Supreme Court has also addressed the issue of excessive confidentiality in the landmark case of *Reliance Industries vs. Designated Authority* 2006 (202) ELT 23 (SC) held that:

“43 ...In our opinion, excessive and unwarranted claim of confidentiality defeats the right to appeal. In the absence of knowledge of the consequences, grounds, reasoning and methodology by which the DA has arrived at its decision and made its recommendation, the parties to the proceedings cannot effectively exercise their right to appeal either before the Tribunal or this Court.

The Anti Dumping Law is extremely important for the country's industrial progress and hence there should be total transparency and fairness in its implementation.”

- Furthermore, the Ministry of Commerce vide Trade Notice No. 1/2013 dated December 2013 at paragraph vi has stated that data upon which excessive confidentiality is claimed, shall be disregarded:

“Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on by the authority.”

- Therefore, it is a settled principle that when a party to an investigation provides confidential information, the party must also provide meaningful non-confidential summaries thereof. In the event that information cannot be summarized, the party in question is required to state the reasons for such non-summarization.
- M/s ELP Advocates & Solicitors has stated that an unsubstantiated and completely illogical link between the non-participation of the Exporter in the sunset review of the anti-dumping duty imposed on the PUC and the participation now in circumvention investigation has been drawn. Outokumpu did not participate in the sunset review for commercial reasons, particularly in view of the extreme burden placed on exporters/producers from subject countries to file data for the period of investigation, post-POI period, as well as other likelihood information. The Exporter submits that non-participation in the abovementioned sunset review was due to a business decision with respect to the PUC and has no bearing on the PUI that is imported into India. In fact, even if the assumption is made (without

conceding) that the Exporter was engaged in circumvention, the Exporter would not have participated so extensively in the present proceeding, having filed a copious amount of information and opening its confidential data to the Authority prove the absence of circumvention. As explained above, Outokumpu is an internationally renowned and legacy manufacturer of stainless steel, and the Petitioner's spurious allegations should be out rightly rejected by the Authority.

Examination by the Authority

51. The Authority notes that with regard to confidentiality of information, Rule 7 of Anti-dumping Rules provides as follows:-

Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) of rule 12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.

52. Submissions made by the domestic industry and other opposing interested parties with regard to confidentiality to the extent considered relevant were examined by the Authority and addressed accordingly. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis was directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file. The Authority also notes that all interested parties have claimed their business related information as confidential, which has been kept confidential as per Rule and consistent practice of the Authority.

53. The Authority notes that it had sent questionnaires to all known producers/exporters of subject countries and also to the embassies of the subject countries in India to make the questionnaires, relevant application available to all those who desired to participate. Any producer/exporter from a non-subject country is not considered as an interested party, as per Rules.

54. As regards the issues on legality of the investigation, non-fulfillment of conditions of circumvention stipulated in AD Rules, the Authority notes that in the judgment dated 8th March,

2017, the Hon'ble High Court of Delhi has dismissed the petition filed by the importer/exporter which primarily contained issues on legality as stated above. The Authority notes the submissions made by various interested parties, most of which were also made before the Hon'ble High Court. The Authority notes that the Hon'ble High Court in its judgment dated 8th March, 2017 has held that the trajectory of the inquiry is altogether different in an Anti-Circumvention investigation and that the facts and arguments of various interested parties need to be placed before the competent Authority. The Authority in view of the operative para of the aforesaid judgment, notes various submissions and evaluated all relevant parameters as per relevant AD Rules 25 – 28 in this final findings.

Determination of Circumvention

G. Evidence of Circumvention

Submissions made by the Producers/Exporters/Importers and Associations/Embassies of Subject Countries

55. Following submissions have been made by the exporters/importers/users and associations with regard to circumvention are as follows:

- a. The Product under Investigation is not in unassembled, unfinished or incomplete form and, therefore, the provisions of Rule 25(1) cannot be invoked.
- b. Value addition involved in the process of slitting is huge, this makes circumvention economically and commercially unviable.
- c. The producer / exporter from EU has submitted that they are selling widths above 1250 MM, even prior to the imposition of the anti-dumping duties. Further, their goods of width above, 1250MM is using as such in the applications which genuinely requires widths above 1250MM.
- d. The producer/exporter from Korea, POSCO has stated that **% of the wider width imports are being slit into widths below 600mm which is technically not PUC, therefore there is no circumvention. They have further stated that they have been slitting the imported articles into widths below 600mm even prior to the imposition of duties.
- e. That there has been a change in the usage pattern in the domestic market and there is a natural increase in demand of PUI which can be substantiated by the increase in production of PUI by the domestic industry as well.
- f. That the fact that the petitioner has set up a plant to manufacture PUI which is an evidence of the fact that there is adequate demand of PUI. They have further contended that there has been no change in the import pattern and there is a simultaneous increase in imports of both PUC & PUI.
- g. That the circumvention is not commercially viable as there are wastages and there are issues related to welding which can increase the cost and also raise safety issues.
- h. Interested parties have also contended that in order to apply anti-circumvention provisions, the article that is being imported must be subject to anti-dumping duty and since there is no anti-dumping duties on imports of PUI, this clause is not applicable.

- i. Interested parties made representations that they are not slitting the PUI nor they have any intend to circumvent the anti-dumping duties.
- j. M/s DGS Associates representing POSCO Korea and its related entities have submitted the following:
 - The petition is contrary to the explicit provisions of the AD Rules, as it fails to establish the prerequisites of Rule 25, being that the goods be imported in unassembled, unfinished or incomplete form and as such the instant Investigation is sans jurisdiction;
 - More than **% of the Product under Investigation (PUI) imported into India from POSCO is being utilized to supply products that do not fall either within the ambit of the PUI or the Products under Consideration, being products of width between 600mm to 1250mm (PUC). As claimed by the Petitioner itself, the wider widths of the subject goods have limited application. In the automotive industry, being the industry that is essentially catered to by the answering interested parties herein the demand is only of cut to length or CTL sizes. It is not economical or commercially viable for the importers to import the desired CTL sizes directly as the production and transportation of the smaller widths is not only cost ineffective but also thwart with the dangers of rejection as transportation can result in damage, thus rendering the CTL size useless for the customers. Furthermore, since the automotive industry is fairly dynamic by nature there is a high possibility of it having outgrown the size that it had ordered a few months back. Also for transportation of desired narrow width of the coil should be done through container delivery, which would only result in substantial increase in cost.
 - Furthermore, in the event that the exporter directly provides coils of requested dimensions, the coils must undergo an “edge trimming process” prior to final use in India, which would further lead to production of scrap. Therefore, it is simply not pragmatic for the automotive industry to import the exact CTL sizes and importing wider widths of the product is the only pragmatic option available to the parties, making the imports economically and commercially viable. It is reiterated that importing wider widths, to be slit to the desired sizes in India, reduces yield loss, transportation cost, wastage and also allows end user the flexibility to alter its demanded sizes basis the requirement at the time of actual supply.
 - It is evident that there exists valid economic justification for importing wider widths into India to be supplied as CTL sizes. It is also submitted that there has not been any change in trade pattern as the subject goods have always been imported in wider widths to be slit into CTL sizes for the consumption of the automotive industry. As has already been stated in the written submissions, the automotive industry has evolved over the years and is now primarily using widths below 600mm for the production of the exhaust systems where the PUI supplied by POSCO is used. This is a shift in the user industry and cannot be termed as circumvention, as alleged by the Petitioner, or otherwise. The Petitioner can possibly not be suggesting that the entire market forces have undergone a change consequent to the imposition of anti-dumping duty. Such a suggestion would be too absurd and far-fetched.

- While trying to invoke the express provisions pertaining to Anti-Circumvention under the AD Rules, the Petitioner has completely failed to satisfy the prerequisites laid down in law. Further, while alleging circumvention, the petitioner has not bothered to examine the end-use trend of the PUI being imported, which analysis would have sufficiently established that the PUI being imported is primarily used either as PUI or widths below 600mm making it a non PUC for purposes of this Investigation.
- The Petitioner's specific contention w.r.t. the increased imports of grade EN1.4512 is again misplaced in as much as the said grade is being imported specifically for meeting the requirements of the automotive industry and is being imported as PUI to be supplied in CTL sizes of widths below 600mm, being outside the scope of both PUC and PUI. It may be noted that the said grade is used by the automotive industry for the manufacture of the exhaust systems and the CTL sizes being currently used for the said manufacture are below 600mm. It is submitted that the Petitioner's sole objective is to misguide this Hon'ble Authority into believing that there is circumvention in existence, when in fact no circumvention of anti-dumping duty exists. Petitioner's bald assertion that the imports of PUI have increased is insufficient to establish circumvention since what must be considered is the final utilization of the PUI.

k. M/s ELP Advocates & Solicitors representing Outokumpu Oyj and YUSCO have stated the following:

- The Petitioner has failed to provide the following information which is important for analysing the PUI and the possibility of circumvention of the various series or widths that are exported into India:
 - a) No segregation of the series or widths produced by the Petitioner
 - b) Import data segregation

Without the abovementioned information, the import trend of the PUC and the PUI cannot be effectively addressed as the present submitted data fails to show which products of a particular width have been imported and are truly circumventing the anti-dumping duty imposed on the PUC, if at all.

- Product under Investigation is not unassembled, unfinished or incomplete form due to which Rule 25(1) of the Anti-dumping Rules does not apply to the present investigation,
- The present investigation should be terminated the anti-circumvention proceeding, at least against the Exporter as there has been no change in pattern of trade;
- Circumvention as alleged by the Petitioner is commercially unviable as the Petitioner has failed to provide any evidence to substantiate its circumvention claim;
- Increase in the volume of imports of Product under Investigation is due to an increase in the consumption of the Product under Investigation and is not due to slitting the Product under Investigation for converting it into the Product under Consideration.
- The Petitioner is unable to meet the demands of the user industry with respect to the Product under Investigation due to which the present investigation should be terminated.

1. M/s GTC Consultants representing M/s Suncity Sheets Pvt. Ltd., M/s Suncity Strips and Tubes Pvt. Ltd, M/s Sunrise Stainless Pvt. Ltd and M/s Sunmark Stainless Private Limited have submitted the following:
 - M/s Suncity Strips and Tubes Pvt. Ltd has imported the CRSS other than PUC from China PR, Malaysia and Korea RP. The width wise imports of CRSS is as under:

Width – wise Imports of Suncity Strips and Tubes Pvt. Ltd

CHINA			
Year	Width 0-600	600-1250 (Incl. Tolerance)	1250 and above (Excl. Tolerance)
	QTY in(MT)	QTY in(MT)	QTY in(MT)
2008-09	NOT APPLICABLE		
2009-10			
2010-11	*****	-	-
2011-12	*****	*****	*****
2012-13	*****	*****	*****
2013-14	*****	*****	*****
2014-15	*****	*****	*****
2015-16	*****	*****	*****
Jul'14 to Sep'15	*****	*****	*****
MALAYSIA			
Year	Width 0-600	600-1250 (Incl. Tolerance)	1250 and above (Excl. Tolerance)
	QTY in(MT)	QTY in(MT)	QTY in(MT)
2008-09	NOT APPLICABLE		
2009-10			
2010-11	-	-	-
2011-12	-	-	-
2012-13	-	-	*****
2013-14	-	-	*****
2014-15	-	-	*****
2015-16	-	-	*****
Jul'14 to Sep'15	-	-	*****

KOREA			
Year	Width 0-600	600-1250 (Incl. Tolerance)	1250 and above (Excl. Tolerance)
	QTY in(MT)	QTY in(MT)	QTY in(MT)
2008-09	NOT APPLICABLE		
2009-10			
2010-11	-	-	-
2011-12	-	-	-
2012-13	-	-	-
2013-14	-	-	-
2014-15	-	-	-
2015-16	-	-	****
Jul'14 to Sep'15	-	-	-

From the above table, it is pertinent to note that M/s Suncity Strips and Tubes Pvt. Ltd. has never and ever imported PUC since its inception. Hence, the circumvention of PUC cannot be alleged on the part of the M/s Suncity Strips and Tubes Pvt. Ltd. and since they are the manufacturer of stainless steel pipes, wherein, CRSS is the main raw material. For manufacturing of pipes, the respondent requires the width of not more than 400mm and not from 600mm to 1250mm.

- M/s Suncity Sheets Pvt. Ltd. has never imported the PUC since its inception in 2012-13. Further, the respondent has only imported the CRSS other than PUC only from China, PR. The width wise imports of CRSS is as under:

Width – wise Imports of Suncity Sheets Pvt. Ltd

Year	Width 0-600	600-1250 (Incl. Tolerance)	1250 and above (Excl. Tolerance)
	QTY in(MT)	QTY in(MT)	QTY in(MT)
2008-09	NOT APPLICABLE		
2009-10			
2010-11			
2011-12			
2012-13			
2013-14	****	****	****
2014-15	****	****	****
2015-16	****	****	****
Jul'14 to Sep'15	****	****	****

From the above it may be noted that M/s Suncity Sheets Pvt. Ltd. has never and ever imported PUC since its inception. Hence, the circumvention of PUC cannot be alleged on the part of the respondent.

- Impugned Notification has been issued without fulfilling the jurisdictional pre-conditions and is wholly without jurisdiction. By their very nature, anti-circumvention proceedings are such that a new trend of imports specified in Rule 25 of the ADD Rules ought to have been noticed subsequent to the notification, which are seeking to circumvent the ADD imposed by the notification. In the present case, the final notification which is alleged to be circumvented, was issued only on 16.12.2015 and the application for circumvention was filed within a couple of months of that notification. The application does not rely on any new fact or data and discloses that the trend of imports prevalent presently has continued for long. Therefore, the present Anti-circumvention investigations are liable to be dropped, being without jurisdiction.
- Rule 25 (1) of the ADD Rules requires the following jurisdictional pre-conditions to be satisfied for initiation of Anti-circumvention investigation under Rule 26 of the ADD Rules:-
 - An “article” should already be subjected to ADD is imported into India from any country;
 - The said “article” should be imported into India in an unassembled, unfinished or incomplete form and is assembled, finished or completed in India;
 - The said operations of assembly, finishing or completion started or increased after, or just prior to the Anti-dumping investigation and the parts and components are imported from the country of origin or country of export notified for the purpose of levy of ADD; and
 - The value consequent to assembly, finishing or completion operation is less than 35% of the cost of assembled, finished or complete article.
- In the present case, none of the aforesaid conditions are satisfied, inasmuch as:-
 - CRSS of width more than 1250mm is a completely different class of article and it is undisputed that the same is not subjected to ADD and has a distinct commercial usage- therefore, any import of CRSS of width more than 1250mm cannot be regarded as import of the “article” which is subject to ADD. Rule 25(1), therefore, does not apply at all to the present case;
 - CRSS of width above 1250mm are finished goods and are not imported in an unassembled, unfinished or incomplete form. There is no basis whatsoever, disclosed in the Application to the effect that this condition is even prima facie satisfied to justify initiation of proceedings;
 - There is no assembly, finishing or completion process undertaken in India in respect of CRSS of width more than 1250mm. The CRSS imported in India are in finished condition and no further ‘assembly’, ‘finishing’ or ‘completion’ is required in India;
- In any case, such operations have not started or increased after or just prior to the Anti-dumping investigations so as to constitute circumvention of ADD, in as much as:-

- The data relied upon by the Applicant in support of the application filed before this Ld. Authority shows that high volumes, in excess of 70% of the total imports of CRSS were of width more than 1250mm above from the year 2010-2011 onwards;
- There is no demonstrable change in import pattern after the initiation of proceedings which resulted in imposition of ADD pursuant to final findings dated 12.10.2015. It is important to note that the final findings dated 12.10.2015 in the sunset review, pursuant to which the Customs Notification No. 61/2015 dated 16.12.2015 was issued, was a full-fledged investigation as is also evident from Rule 23 (3) wherein, the entire procedure under the ADD Rules in terms of Rule 6,7,8,9,10,11,16,17,18 and 20 was required to be followed. It is, these proceedings that the Applicant has claimed in its application that were being circumvented. No data showing any demonstrable change in the import pattern after the issuance of the final findings has been filed by the Applicant to justify initiation and the initiation was made on a complete non-application of mind by merely accepting the statements in the application without even testing whether the jurisdictional conditions were satisfied to justify initiation.
- As there is no assembly, finishing or completion operation even alleged in the application, the question of testing the value addition consequent to such operation does not arise. Even otherwise, the cost of slitting operation relied upon in the initiation notification, apart from being incorrect, is contrary to the findings in earlier proceedings where this Ld. Authority itself had found that there was a heavy cost involved in such operations and the losses of high priced material that would be incurred would make such operations unviable.[Para 9 of Findings dated 24.11.2009]
- The jurisdictional pre-conditions contained in Rule 25 (1) of ADD Rules have not been satisfied in the present case. It is submitted even on the limited enquiry, the present proceedings can be dropped, inasmuch as, none of the threshold conditions are satisfied in the present case. It is incumbent upon the Ld. Authority to examine the question of jurisdiction before proceeding to decide on the other issues in the present case, if any. It is a settled position in law that before deciding a case on merits, jurisdictional issue has to be decided. Reliance in this regard is placed on the decision of the Hon'ble Supreme Court in Union of India v. Adani Exports Ltd. 2001 (134) ELT 596 (SC) wherein the Hon'ble Supreme Court set aside the judgment of the Hon'ble Gujarat High Court on the sole ground that the Gujarat High Court proceeded to decide the matter on merits by assuming jurisdiction. The Hon'ble Supreme Court categorically held that the question of jurisdiction should be first decided as a preliminary issue before going into the merits of the case. It is humbly submitted that in the present case also, this Ld. Authority may decide the issue of jurisdiction as a preliminary issue instead of giving findings on the merits of the present case.
- The import data supplied by the Applicant discloses that there is no demonstrable change in import pattern after the initiation of proceedings which resulted in imposition of ADD pursuant to final findings dated 12.10.2015. Further, even with respect to the data relied upon by the Applicant for the period prior to 2015, it is pertinent to note that there is a

simultaneous change in quantum of imports from time to time which is consistent for both PUI as well as PUC.

- The increase in the quantum of imports of the PUC clearly appears to be natural and not on account of any alleged circumvention, inasmuch as:-
 - There is an overall/simultaneous increase in the PUI as well as PUC;
 - There is an increase of import of PUIs even from non-subject countries;

Therefore, there is no unusual change in pattern of imports of the PUC and the increase is natural.

- it is submitted that most of the data which allegedly is the basis for alleging circumvention has been claimed by the Applicant as 'confidential' without any rationale and such claim is without any merits and further, contrary to Rule 7 of the ADD Rules. It is submitted that there is no explanation forthcoming from the Application as to why should the claim of the Applicant be accepted. It is a settled principle of law, inter alia, laid down in the case of Reliance Industries vs. Designated Authority, 2006 (194) ELT 673 (SC) that the Designated Authority should not automatically accept the claim of the parties regarding confidentiality of information and the authority is expected to apply its mind on the nature of information. In the present case, the claim of 'confidentiality' of the Applicant in the Application filed before this Ld. Authority is without any basis and prejudices the rights of the Importer and accordingly, ought to be rejected such a claim.
- It is submitted that the issue whether CRSS of width more than 1250mm is a commercially substitutable article or whether the process of slitting etc. is viable, have already been decided in the earlier investigations. Once CRSS of width more than 1250mm were expressly excluded by this Ld. Authority for the purpose of imposition of ADD on CRSS by rendering detailed findings, it is not open for the Applicant to re-agitate the very same issues under the garb of the present application and reopening the findings rendered in the earlier investigations which were given after considering detailed evidence and investigations. The submissions of the Applicant to include CRSS of width more than 1250mm in the scope of PUC were specifically rejected time and again by this Ld. Authority and this aspect is not disputed by the Applicant. The findings at each stage of the earlier investigations are tabulated herein below for the sake of brevity:-

Details of Previous Investigation stage-wise

Particulars	Findings
Notification 14/06/2008-DGAD dated 24.11.2009 with recommendation of Final Findings the contention of the Applicant to include CRSS of width above 1250mm in the scope of PUC was rejected	<ul style="list-style-type: none"> • Importing the PUC in higher width and then attempting the process of slitting will result in wastages and higher costs [Para 9]; • User industry imports in almost exact length for the end use application in order to economise and remain competitive [Para 9]; • Analysis of the import data and information provided by interested parties shows significant volume of imports of higher width plates [Para 10]; • Price of higher width plates is higher than lower width material [Para 10]; • Even it might be technically feasible for consumers to cut the sheet

	<p>into smaller width plates, it has not been established that the same is commercially as well as technically feasible [Para 10];</p> <ul style="list-style-type: none"> Both technical and commercial substitutability of a product are important in order to establish that the product offered by the domestic industry is indeed like article to the imported product [Para 10]; The authority maintains the restriction of PUC up to 1250mm (width) as no evidence of actual supply of width beyond 1250mm has been provided by the domestic industry [Para 12.2a].
Order dated 05.12.2011 in pursuance of Order of P&H High Court dated 08.10.2010 in relation to its Final Findings No. 14/06/2008-DGAD dated 24.11.2009	<ul style="list-style-type: none"> Even though it is claimed by the domestic industry that slitting of higher widths into smaller widths is technically and commercially feasible, no evidence has been placed on record to establish that it is technically and commercially feasible to convert the smaller widths into higher widths [Para k]; Even if the claim of substitutability of higher width to lower widths by slitting is accepted, the vice-versa cannot be established [Para k]; Subject goods of width beyond 1250mm were rightly excluded from ambit of ADD [Para 21a].
Final Findings to the Sun-Set review <i>vide</i> Notification No. 15/04/2024-DGAD dated 12.10.2015	<ul style="list-style-type: none"> It is further observed that in this case, the review has been initiated for the scope of the product as defined in the final finding and as modified by subsequent reviews. The domestic industry did not file any application for the review of the scope of the product under consideration as it did in 2011 [Para 27]; The authority cannot accept the arguments of the domestic industry for inclusion of the excluded grades within the scope of the product under consideration [Para 27].

- A perusal of the above tabulated findings disclose that the following issues have attained finality on account of the categorical findings:-
 - The CRSS of width above 1250mm are not technically or commercially substitutable with the CRSS of width lesser than 1250mm; and
 - Slitting of CRSS above 1250mm to manufacture CRSS of lesser width is not commercially or economically viable.

Once the aforementioned findings have been rendered on the basis of import data as well as detailed investigations, it is most respectfully submitted that the re-agitating the very same issues should not be allowed more-so, when the Applicant has filed an appeal under Section 9C of the Customs Tariff Act, 1975 before the CESTAT, New Delhi against the final findings of the Ld. Authority in terms of which CRSS of width above 1250mm were excluded from scope of PUC for the purpose of imposition of ADD.

- m. The issue of PUI has already been examined in earlier main examination and investigation be therefore terminated.
- n. The NCV version of petition does not provide data on usage pattern which does not give a fair understanding.
- o. Initiation has not legal basis as PUI is assembled, finished and in complete from.

- p. The application alleges that there is evidence to show that only about 3% of imports of widths of above 1250 mm is going into a genuine usage and the balance 97% of the imports are used only after slitting. The applicant further alleges that the value addition required to convert the PUI into PUC is way below the threshold limit of 35% and there is a further allegation that there is a change of pattern of trade due to the above process. These claims are not substantiated.
- q. There is no demonstrable change in the pattern of trade after initiation of proceedings which culminated in final finding dated 12/10/2015.
- r. The surge in PUI is a general growth trend and in fact imports of Stainless Steel flat products increased from 324460 MT in 13-14 to 532033 MT in 15-16.
- s. Volume of imports from subject countries be examined individually and not cumulatively.
- t. Many traders have submitted that no processing/slitting have been done on PUI before selling them.
- u. Importing higher width and slitting is not economical as it adds 15-20% on cost, when PUC (600-1250 mm) is easily available from DI.
- v. M/s Metal and Stainless Steel Merchant's Association who have more than 5000 merchant entities as their members have filed submissions as under on behalf of a large number of their members.
- M/s Metal & Stainless Steel Merchant's Association submission filed dated 23.6.2016
More than 5000 merchants/exporters/importers and manufacturers are our members and are engaged in Trade of Metal & Stainless Steel various products in Mumbai. Our members are having about 5000 Shops and Establishment.
 - Members have not done any slitting activity on the PUI and that it may not be viable to do so with cost of slitting being Rs. 10 to Rs. 15 for a local centre.
 - Domestic Industry is just making repeated application since last 10-12 years with New Cases of Anti-Dumping, Safeguard Duties etc. M/s Jindal Stainless Ltd. enjoys monopoly in controlling supplies and pricing power with 85% Market Share. The Prices of Stainless Steel are kept Artificially Higher over International prices as there is No Competition now.
 - Domestic User Industry consists of small units/SME/MSME and due to higher Cost of Raw Materials (Stainless Flat Products) Limited Resources of Trade/Distribution, There is a suffering. There is large scale drop in Manufacturing Activities of Domestic User Industry – which comprises of :
Kitechenware, Cutlery, Cookware; Home Appliance Mfg (Sinks, Washing Machine, Geysers, Chimney, Hobbs; Welded Pipe & Tubes Mfgs; Building Hardware, Fitting, Railings and Accessories; Industrial Tank, Vessel, Heat Exchangers, Boilers; Pharma Machinery and Lab Equipments; Elevators and Escalators; Various Engineering Equipment & Machineries; Milk Dairy and Food Industries Equipments; Automobile Industries and

their Parts supplies; Tools, Office Supplies, Blades, Scissors, Gift & Accessories; Heavy Engineering, Power Plant, Petro Chemical & Fertilizer Industries; Water Treatment Plants, Pumps and Water Tanks; Railways, Ship Building; Various other very small scale units.

- Import of all above Finished Articles itself has Risen continuously in last 5-7 Years at the cost of closure of Indian Manufacturers of above product due to High Cost of Raw materials and unavailability of varieties in Size, Finish, Thickness Range.
- Price of Stainless Steel Flat Product is cheaper in other countries by about 20-30%.
- Overseas Mfg's has easy access to source with Wide Range of option of Finish, Thickness, and Width, Lower Wastages, Timely Delivery, Low Cost Materials etc. help them to be more Efficient.
- Importing into India Finished Articles itself is cheaper in cost and of Better Quality & Finish.
- On one side the finished goods are being flooded in Indian market with Newly Developed Designed, Finishes and Low Cost with Concessional Import duty under Free Trade Agreement, On the other side the domestic manufacturers are left with Monopoly in their basic raw material at Artificially Higher Prices and limited scope of supply chain resources.
- STS Railing Pipes, Welded Tubes & Pipes are Cheaper to Import then Produced here; Cookware, Kitchenware, Flasks and High End Cutleries are Import is rising into India; Heavy Engineering Unites are Established outside India. (Middle East); Building Hardware, Accessories Imported are of Cheaper in Cost & Better Finish then India; Elevators and its parts are imported now and just Assembling & Servicing Part is done in India.
- Our Manufacturer are Slowing Down, Could not grow in past few years, Hence No new investments seen, some of them are just now importing finished articles and marketing them. Remaining will either Closed Down or Go Bankrupt.
Indian Distributor/Supply Chain Service have not Grown in last few years, almost collapsed and moving toward speculative Business from Service Oriented Businesses.
- Important service from Trade/Distribution is not available to above USER Industry, as limitation of availability of Range of varieties (Width, Thickness, Finish, DDQ etc), Extreme higher prices compared to International market prices, shortage and Difficulties in timely deliveries enhance the problem further.
This is the main reason Indian Manufacturers are losing their competitive edge. Government must secure the interest of small and medium manufacturers by not paralyzing them by buying material Higher prices from uncompetitive sources.
- The application of Anti-Circumvention duty should be verified subject to Monopolies and Restrictive Trade Practices ACT, 1969. Jindal Stainless Ltd, is only Manufacturer having fully integrated plant in India, Manufacturing CR Flat Products of Stainless Steel of 200, 300, & 400 series. Controlling 85% Market Share by Jindal Stainless Ltd. (Jindal Stainless (Hissar) and Orissa Units) and many sizes, grades are 100% Controlled & Monopoly of Jindal Stainless Ltd.
- Non-Manufactured Product in India is also included in Anti-Dumping:

Bright Annealed CR Stainless Steel Coils & Sheet in Width of 1000 MM, 1250 MM, & 1500 MM width in 200, 300, & 400 Series was included in Anti-Dumping Duty, Even though it is not being produced in India by any of the Manufactures.

“BA” surface stainless steel is much premium over normal CR 2B Stainless Steel because of shinny surface finish, saves cost and times as there is no need of manual polishing used in Kitchenware, Cookware, Cutlery, Sinks, Pipe & Tubes, Elevators, Home Appliances.

Due to Non-Availability of “BA” Finish Stainless Steel we are still using 2B surface with Conventional polishing which is uneven and Manual/Labor Orient process; Reduced the Total production due to time consuming process; Increasing the Cost and Higher Rejection Quantities; Lost Export Orders and Customer whereas “BA” Finish is must; and Import of Finished Articles from overseas which has been made of “BA” Finish had increased.

The Authority should verify the facts and cold Rolled Stainless Steel in “BA” Finish should be removed from Scope of Anti-Dumping Duties on all case.

- Stainless Steel Sheet – Surfaced Treated – Polished (Decorative Ti Clor, Etch Pattern, Polish Mirror Surface) they are all High Technical needed product and used in Elevators, Escalators, Hotels/Offices Entrance, Lobby’s, Name Plates etc by default it was included in Anti-Dumping.
- Stainless Steel CR Coils & Sheet in Thickness of 0.50 mm & Below (0.20 mm, 0.30mm, 0.40mm,etc) is also not available in with of 1000 mm, 1220mm, Still included in Anti-Dumping.
- Checkered/Tear Drop/Anti Slip and other Treated Stainless Steel – is used as floor plates which is not available in India.
- Circumventing is completely unviable and baseless be cause
- Cut length Sheet cannot be slitted they are ready to use. They are cut to length supplied and imported, so it should be excluded from the Initiation itself.
- Worldwide Standard Width is 1220mm, 1250mm, 1500mm, 2000mm. Price of 1500mm, 2000mm is always higher side by 3-7%. Slitting to Narrow Width involved extra work load, Transportation, Cutting Expense and 10-20% Wastage/Scraps.
- There is no Economical sense in cutting 3-7% High priced Coils to Low Priced Coils + Generate Scraps of 10-20%+ Incur expenses like slitting, Re-Packing, Loading& Transportation. This will increase Total cost by about 20-25%.
- Customer is King, the requirement of Customer goes on changing depending upon Consumer choice and Technical Changes & Innovation, Quality controls etc. We have to supply what customer needs.
- Total Import Volume is dropping and import of Anti-Dumping product (CR Stainless Steel Flat Product 600mm-1250mm width is drop by 70%, from 53240 Tons in 2008-09 to 18437 Tons in 2014-15 Infact, It should have grown average 8-10% every year should have reached 80000-100000 Tons to maintain User Industry Price Competitiveness and growth.
- Anti-circumvention case is just based on 1 Large Scale Importer 7 Service Center – POSCO India Service Centers in India for 400 Series – Automobile Grade Stainless Steel.
- As 400 Series Coils are processed in Width Below 600 mm for Automobile Industry, hence No Point in applying Anti-Circumvention Duty for All Grade of 200, 300, 400 Series in CR

Stainless Flat Product for 600 mm – 1250 mm under Notification No. 61/2015-Customs dated 11.12.2015.

- Multiplier Effect on Revenue & Growth: Stainless Steel is not Luxury Good like High end watches, Cell Phone, LED TV or Luxury Car or other Luxury Consumer Goods.
 - Stainless Steel is Raw Materials to Industry – Procurement and Storage, De-coiling, Cutting, Slitting, Polishing, Warehousing, Wholesale-Distribution to Retail Sales, End-Consumer Supplies across India and Export to Worldwide Customer, Shipping & Transportation are step involved.
 - Further, it is 100% RECYCLABLE and its SCRAP is REUSED again by smelting and making new Stainless Steel. Therefore Anti-Circumvention duties should not be imposed.
- w. M/s Agol Associates representing M/s N.G. Industries, M/s M.P. Industries, and M/s Shree Ramdev Metal Mart have submitted that these companies have not done any slitting process of the product during the period of investigation and all the quantities have been sold without any slitting/conversion process.
- x. The cost of materials of width between 600 mm to 1250 mm is lesser and easily available in the domestic and overseas market when compared to the expenses incurred in slitting the product of width more than 1250 mm. General cost of slitting is Rs 1 per kg at a normal small local service centre, but the service centre of M/s POSCO charges Rs 3 per kg. In addition a substantial amount is generated as scrap if slitting is resorted to.
- y. M/s All India Stainless Steel Importers Association, who are members as a part of metals and stainless steel merchant association, members have also reiterated the submissions made by M/s Metal & Stainless Steel Merchant's Association.
- z. POSCO is exporting wider width to maximise production and distribution. 80% of the PUI is sold below 600 mm and only 20% of it is sold as PUC.
- aa. All PUI are used as it is cut to length in sheet and coils. Some of the importers have mentioned that they have been importing widths of higher size now for many years.
- bb. M/s Sharda Motor Industries Limited for Korea have also stated that Cold Rolled Stainless Steel (CRSS) imported from Korea for automobile exhaust systems is not locally available and also the domestic suppliers product is not approved and their test trails have failed. Therefore Anti-circumvention duty not be imposed on such imports.
- cc. M/s Faurecia Emission Control Technologies have stated that Cold Rolled Stainless Steel imported from Korea for automotive exhaust system are not locally available nor have quality, which meet their requirements and also there are delivery issues. There Anti-circumvention duty may not be levied on CRSS for automotive exhaust system.
- dd. M/s Reliance Fabrications Pvt. Ltd. have stated that they stated that they use widths greater than 1250 and AD duty should not be extended beyond 1250 mm.

- ee. M/s Remi Edelstahl Tubulars Ltd. Have stated that they require coils beyond 1250 mm for higher diameter pipes these are used without slitting. Techno economy calls for importing such sizes.
- ff. M/s Nexus Impex reiterating the legal submissions on faulty initiation, no circumvention due to slitting have stated that cost of slitting is generally Rs. 1/Kg at a local center and Rs. 3/kg. at POSCO's center. The DI's has in their company's brochure/website material accepted that requirement of higher width is growing.
- gg. Most of the higher width imports are sold to user industry like Thyssenkrupp/schindler/Sulzer/Koch chemical/France Faber without slitting or cutting.
- hh. Higher width sheets lead to a better yield in Dairy Tanks/Chemical equipment/elevators/Oil and gas and Automobile sector.
- ii. The levy of AD on imports from POSCO will adversely affect Indian Automobile industry. The losses suffered by the petitioner are due to its inefficiencies. This has been investigated and also published by the DG safeguards.
- jj. Imposition of Anti-circumvention duties will adversely affect make in India programme.
- kk. Conditions for extending duties to PUI from EU are not met as imports from EU of PUI have decreased by 10% since 2009. Even if a number of exporting producers have circumvented the measures, extending measures on PUI to all countries will be disproportionate.

Views of the Domestic Industry

56. The domestic industry has made the following submissions:

- a. The interested parties have failed to appreciate that the words “unassembled, unfinished or incomplete form” have to be interpreted in the context of the fact whether such products require any further operations in the form of “assembly, finishing or completion”. Once the imported goods are subject to certain operations in India before being finally used, it cannot be said that the imported goods were finished or complete. It is further submitted that the PUI would not be a ‘complete’ or ‘finished’ product if they require further process of ‘slitting’ before being put to the use and that too when the whole process of slitting is being carried out purely and solely for the purpose of avoiding the anti-dumping duties levied by the Hon’ble Authority on the articles below 1250mm width.
- b. The producer/exporter from Korea, POSCO has accepted that 80% of the wider width imports are being slit into narrower widths. However, the producer / exporter has failed to answer the pointed question of the Hon’ble Designated Authority during the Oral Hearing about why input pattern has changes. Domestic Industry also submitted that in an anti-circumvention investigation the requirement under law is to examine whether there has been a change in the imports pattern in order to avoid the existing anti-dumping duties. It is clear

from POSCO's own submissions that they are admittedly slitting the PUI into lesser widths. Even assuming but not accepting that prior to the imposition of the anti-dumping duties, the slitting operations were carried out to obtain widths below 600mm, no justification has been offered by any of the interested parties as to why the import pattern has changed from PUC to PUI only after the imposition of anti-dumping duties.

- c. It is established that there is no change in the pattern of trade or applications which could justify the complete change in the pattern of imports from lower widths (PUC) to higher widths (PUI) other than circumvention of anti-dumping duties. However, none of the interested parties has been able to provide any plausible economic justification other than to avoidance of anti-dumping duties in the context of the changed pattern of imports. As per the Domestic Industry the ratio of the PUC and the PUI imports from the countries not subject to anti-dumping duties remained the same as it was prior to the imposition of anti-dumping duties. However, the ratio of PUC and PUI imports for the subject countries, changed in a manner so as to completely circumvent the anti-dumping duties. This phenomena completely proves circumvention of anti-dumping duties beyond any doubt.
- d. Domestic Industry submitted that the contention of the interested parties regarding operations of Odisha plant that it primarily produce PUI is incorrect. As can be seen from the information already on record, that despite having the capability to produce higher widths in Odisha, majority of the sales are made in PUC segment only which clearly establishes that there is no surge in demand of PUI alone as is being attempted to be projected by the interested parties.
- e. Domestic Industry submitted that the ratio between PUC and PUI of the imports from non-subject countries is similar to the sales pattern of the Domestic Industry. As per the Domestic Industry these facts establish beyond any doubt that the ratio of imports changed completely in favour of PUI post imposition of anti-dumping duties only from the subject countries. The only inescapable conclusion is that unscrupulous exporters and importers have resorted to circumvention of the existing anti-dumping duties on the PUC.
- f. Domestic Industry submitted that interested parties are once again misleading the Authority by mentioning that that the circumvention process is not commercially viable. They submitted that as per the material on record, it can be clearly seen that the whole process of slitting of PUI requires cost ranging from 2% to 3%, which is minimal as compared to the existing anti-dumping duties. Moreover, the data has been verified by the Authority.
- g. Domestic Industry submitted that the contention of interested parties that in order to apply anti-circumvention provisions, the article that is being imported must be subject to anti-dumping duty, is completely misplaced and devoid of any merit. It is further submitted that if the provision has to be read in the manner proposed by the interested parties, it would make the entire law trite as there is no need for any kind of anti-circumvention duties if the concerned goods are already subject to anti-dumping duties. Any interpretation which makes the entire scheme of anti-circumvention law otiose, is to be rejected in terms of the settled principles of interpretation of statutory provisions.

Examination by the Designated Authority

57. The Authority has noted the aforesaid submissions and alleged circumvention phenomena under relevant Act/Rules i.e. section 9 A (1) of the Customs Tariff Act, 1975 and Rule 25 of the AD Rules which state as follows—

Section 9A(1A) of the Customs Tariff Act Where the Central Government, on such inquiry as it may consider necessary, is of the opinion that circumvention of anti-dumping duty imposed under sub-section (1) has taken place, either by altering the description or name or composition of the article subject to such antidumping duty or by import of such article in an unassembled or disassembled form or by changing the country of its origin or export or in any other manner, whereby the anti-dumping duty so imposed is rendered ineffective, it may extend the anti-dumping duty to such article or an article originating in or exported from such country, as the case may be.”

Rule 25 of AD Rules.” Circumvention of anti-dumping duty. - (1) Where an article subject to anti-dumping duty is imported into India from any country including the country of origin or country of export notified for the purposes of levy of anti-dumping duty, in an unassembled, unfinished or incomplete form and is assembled, finished or completed in India or in such country, such assembly, finishing or completion shall be considered to circumvent the anti-dumping duty in force if,-

(a) the operation started or increased after, or just prior to, the anti dumping investigations and the parts and components are imported from the country of origin or country of export notified for purposes of levy of anti-dumping duty;
and

(b) the value consequent to assembly, finishing or completion operation is less than thirty-five percent of the cost of assembled, finished or complete article.

Explanation I. – ‘Value’ means the cost of assembled, complete or finished article less value of imported parts or components

Explanation II. - For the purposes of calculating the ‘value’, expenses on account of payments relating to intellectual property rights, royalty, technical know-how fees and consultancy charges, shall not be taken into account.

58. The Authority notes various submissions filed by the user industry on non-slitting, actual genuine use of higher widths of PUI by users. The Authority notes that the AD measures are producer/exporter specific and in an Anti-Circumvention investigation, the producers/exporters who are subjected to an AD investigation need to participate so that the shift in trade pattern specifically by them post levy of a measure can be evaluated. Also the Value addition related to such a circumvention phenomena being investigated by a process needs to be computed. The Authority notes that in case of Korea the producer, POSCO along with its 6 exporting entities

and 3 slitting centres in India has cooperated. The Authority has been examined the trade pattern shift, the Value addition in converting PUI further to lower sizes and its disposal due to the data provided by the cooperating entry.

59. The value addition evaluated for one of the slitting centres of POSCO is to be considered as representative and the submissions made by various importers/importer association also corroborate that Value addition is below 35% which is the threshold stated in the concerned AD Rules. The concerns of importers that the higher widths are not slitted and are for genuine use are not substantiated by their actual disposal. Further the change in trade pattern of PUC and PUI require justification by the producers/exporters.
60. As regards excluding certain grades on quality, non-availability and delivery schedules the Authority holds that the present investigation's scope is restricted to examine 'PUC' and 'PUI' with respect to the aspect of widths only and not other parameters which may have been appropriately dealt in the original findings. As regards issue of wider public interest/make in India programme, the Authority holds that the scope of the present investigation is to evaluate the undermining of existing AD measure due to the phenomena of established circumvention which may not be counterproductive to any public interest or make in India programme.
61. The Authority referenced the trade pattern shift of PUC to PUI for the subject countries post levy of ADD since February 2010 for subject-countries on an overall basis as per DGCIS data from where there is no response filed by any producer/exporter.
62. In case of producers/exporters who have filed response to the Questionnaire, the Authority referenced the trade pattern shift of PUC to PUI as per producers/exporters data and related submissions for the same to evaluate this shift. The trade pattern shift has been submitted by M/s POSCO, Korea, Outokumpu, EU and YUSCO, Taiwan. The exports stated by YLSS during 2008-09 and 2009-10, are not specifically categorized as PUC or PUI and those also do not get correlated with the DGCIS data and therefore they have not been considered.
63. As regards submissions of M/s POSCO, Korea and its processing centres, the Authority notes the disposal of imported PUC, PUI and non-PUC/non-PUI since 2008-09 till POI. The Authority referenced the usage pattern of PUC as PUC or as non-PUC prior to levy of measure and usage pattern of PUC and PUI post the measure to examine the disposal/sale patterns of PUC and PUI.
64. As regards slitting activity construing change of form of PUC as per AD Rules on circumvention, the Authority notes that as the usage of PUC/PUI by an user industry is dependent on the width of PUC/PUI, the conversion process by slitting tantamount to a process of finishing/conversion and therefore the process of slitting is covered under relevant AD Rules, to examine circumvention.
65. The Authority notes that Rule 25 (1) requires that the finishing, completion and assembly of any unassembled, unfinished or incomplete should be done in India or any such country, further, the Rule 25 (1) (a) requires to establish the onset and increase in phenomena of circumvention and further the Rule 25 (1) (b) requires to establish that 'value addition' associated with the said phenomena is in accordance with the stipulated threshold in this sub Rule. The Authority's notes ADD was earlier imposed on imports of the PUC from the subject countries vide notification no. 20/2010 dated 20.2.2010. Sunset review investigations were initiated on the imports of the PUC and after determination, ADD was extended on by the

Central Government vide Customs Notification No. 61/2015 dated 11.12.2015. The duties so imposed are still in force. The Authority has examined noted the change in trade pattern to evaluate circumvention of existing ADD after the imposition of ADD i.e., from February 2010 till POI. The Authority also has examined whether there is change in pattern of trade and whether this change has stemmed from a practice, process or work for which there was insufficient due cause or economic justification other than the imposition of duty. The tables below depict the trade pattern.

Table 1 – Trade Pattern of PUI/PUC from subject countries as a whole from 2008-09

MT	Subject Countries					
	PUC	PUI	Total	PUC %	PUI %	Total
2008-09	53420	19936	73356	73%	27%	100%
2009-10	13105	11820	24925	53%	47%	100%
2010-11	20263	46804	67066	30%	70%	100%
2011-12	29700	69555	99255	30%	70%	100%
2012-13	17908	79346	97254	18%	82%	100%
2013-14	13037	55219	68256	19%	81%	100%
2014-15	18437	67716	86152	21%	79%	100%
POI	20657	75785	96442	21%	79%	100%
POI Annualized	16525	60628	77153	21%	79%	100%

Table 1A – Trade Pattern of PUI/PUC from each of the subject countries as a whole from 2008-09

Quantity (MT)	China PR			EU			Korea		
	PUC	PUI	Total	PUC	PUI	Total	PUC	PUI	Total
2008-09	2,117	616	2,733	23,840	10,612	34,452	13,553	2,818	16,371
2009-10	349	144	493	2,699	8,960	11,659	8,223	234	8,457
2010-11	1,996	7,737	9,733	1,948	23,735	25,683	14,626	4,688	19,314
2011-12	4,257	18,942	23,199	3,285	23,757	27,042	20,596	10,276	30,872
2012-13	9,092	17,848	26,940	3,248	19,604	22,852	2,583	27,554	30,137
2013-14	7,177	10,265	17,442	1,945	12,885	14,830	1,042	21,502	22,544
2014-15	9,657	13,998	23,655	2,254	12,500	14,754	1,475	27,337	28,812
POI (Annualized)	9,658	15,414	25,072	1,723	9,710	11,433	1,289	23,344	24,633

Quantity (MT)	South Africa			Taiwan		
	PUC	PUI	Total	PUC	PUI	Total
2008-09	3,816	2,596	6,412	6,703	2,326	9,029
2009-10	622	1,278	1,900	415	896	1,311
2010-11	624	1,606	2,230	176	5,988	6,164

2011-12	33	1,861	1,894	289	6,871	7,160
2012-13	56	3,359	3,415	211	2,114	2,325
2013-14	149	1,629	1,778	370	1,002	1,372
2014-15	2,062	2,435	4,497	632	4,026	4,658
POI (Annualized)	1,345	1,581	2,926	503	3,550	4,053

Quantity (MT)	Thailand			USA		
	PUC	PUI	Total	PUC	PUI	Total
2008-09	3,022	716	3,738	368	252	620
2009-10	733	59	792	65	249	314
2010-11	797	1,451	2,248	97	1,598	1,695
2011-12	729	1,585	2,314	512	6,263	6,775
2012-13	1,320	979	2,299	1,399	7,889	9,288
2013-14	1,170	619	1,789	1,183	7,317	8,500
2014-15	1,094	2,422	3,516	1,262	4,998	6,260
POI (Annualized)	1,014	1,581	2,595	994	5,447	6,441

Table 2 – Trade Pattern of PUI/PUC from each of the subject countries as a whole from 2008-09 (Index)

Share (%)	China PR			EU			Korea		
	PUC	PUI	Total	PUC	PUI	Total	PUC	PUI	Total
2008-09	77%	23%	100%	69%	31%	100%	83%	17%	100%
2009-10	71%	29%	100%	23%	77%	100%	97%	3%	100%
2010-11	21%	79%	100%	8%	92%	100%	76%	24%	100%
2011-12	18%	82%	100%	12%	88%	100%	67%	33%	100%
2012-13	34%	66%	100%	14%	86%	100%	9%	91%	100%
2013-14	41%	59%	100%	13%	87%	100%	5%	95%	100%
2014-15	41%	59%	100%	15%	85%	100%	5%	95%	100%
POI (Annualized)	39%	61%	100%	15%	85%	100%	5%	95%	100%

Share (%)	South Africa			Taiwan			Thailand		
	PUC	PUI	Total	PUC	PUI	Total	PUC	PUI	Total
2008-09	60%	40%	100%	74%	26%	100%	81%	19%	100%
2009-10	33%	67%	100%	32%	68%	100%	93%	7%	100%
2010-11	28%	72%	100%	3%	97%	100%	35%	65%	100%

2011-12	2%	98%	100%	4%	96%	100%	32%	68%	100%
2012-13	2%	98%	100%	9%	91%	100%	57%	43%	100%
2013-14	8%	92%	100%	27%	73%	100%	65%	35%	100%
2014-15	46%	54%	100%	14%	86%	100%	31%	69%	100%
POI (Annualized)	46%	54%	100%	12%	88%	100%	39%	61%	100%

Share (%)	USA		
	PUC	PUI	Total
2008-09	59%	41%	100%
2009-10	21%	79%	100%
2010-11	6%	94%	100%
2011-12	8%	92%	100%
2012-13	15%	85%	100%
2013-14	14%	86%	100%
2014-15	20%	80%	100%
POI (Annualized)	15%	85%	100%

66. The Authority has also analyzed the pattern of imports within the PUI also. It is noted that the majority of the imports are just above the threshold limits and only a small proportion of imports of the PUI are above 1650mm. This fact indicates that the producers/exporters from the subject countries are bringing higher widths keeping in view the notified tolerances in widths by and large rather than technical or usage based assessment.

67. It is noted from the above that the volume of imports of PUC from subject countries declined post imposition of the anti-dumping duties. Further, volume of imports of PUI from subject countries increased significantly. It is thus seen that whereas imports of PUC declined, imports of PUI increased since the imposition of anti-dumping duties

68. Imports from countries other than subject countries also analyzed to ascertain the pattern of change in the country. The tables below depicts the trade pattern from non-subject countries:

Table 3 – Trade Pattern of PUI/PUC from non- subject countries as a whole from 2008-09

Non Subject Country	PUC/PUI	Quantity (MT)	Share (%)
2008-09	PUC	1940	47%
	PUI	2177	53%
2009-10	PUC	639	62%
	PUI	395	38%
2010-11	PUC	24123	83%
	PUI	4882	17%

Non Subject Country	PUC/PUI	Quantity (MT)	Share (%)
2011-12	PUC	31566	82%
	PUI	7071	18%
2012-13	PUC	48593	81%
	PUI	11440	19%
2013-14	PUC	32192	88%
	PUI	4441	12%
2014-15	PUC	56421	81%
	PUI	13169	19%
POI (Annualized)	PUC	55480	79%
	PUI	14392	21%

69. It is noted from the above that the volume of imports of PUC from non-subject countries remained more or less the same in the investigation period. This indicates that there is no change in the consumption pattern so as to justify the change in the import pattern from the subject countries.

70. It is further noted that one of the grade i.e., EN 1.4512 which was included in the scope of the PUC with effect from 7.2.2012, the pattern of imports from subject countries changed completely without any change in demand pattern. The Table below clearly shows the shift in pattern of trade for grade EN 1.4512 post inclusion in scope of PUC.

Table 4 – Change in Imports of EN 1.4512 post inclusion in PUC w.e.f. 7.2.2012

EN 1.4512	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	POI
600-1250 (MT)	11134	19517	87	90	10	10
1250& Above (MT)	1676	7924	20030	15365	11455	9902
Total (MT)	12810	27442	20117	15455	11465	9912
% Share of Imports						
600-1250	86.92%	71.12%	0.43%	0.59%	0.09%	0.10%
1250 & Above	13.08%	28.88%	99.57%	99.41%	99.91%	99.90%

71. The Authority has also analyzed the pattern of imports from subject countries, non-subject countries and sales made by the Domestic Industry. According to the pattern, it is noted that the pattern of imports from subject countries and sales made by Domestic Industry are in the same range. However, the pattern of imports from subject countries shows totally different results. The pattern analyzed is depicted in Table below:

Table 5 – Comparison of Trade pattern for Subject Countries, Non-Subject Countries and Domestic Industry:

	Subject Countries			Non-Subject Countries			Domestic Industry		
MT	PUC	PUI	Total	PUC	PUI	Total	PUC	PUI	Total
2008-09	73%	27%	100%	47%	53%	100%	100%	0%	100%
2009-10	53%	47%	100%	62%	38%	100%	100%	0%	100%
2010-11	30%	70%	100%	83%	17%	100%	99%	1%	100%
2011-12	30%	70%	100%	82%	18%	100%	99%	1%	100%
2012-13	18%	82%	100%	81%	19%	100%	87%	13%	100%
2013-14	19%	81%	100%	88%	12%	100%	87%	13%	100%
2014-15	21%	79%	100%	81%	19%	100%	87%	13%	100%
POI Annualized	21%	79%	100%	79%	21%	100%	83%	17%	100%

Table 6 - Trade Pattern of PUC/PUI - POSCO (Korea)

	Exports to India			Domestic Sales			Exports to Third Countries		
Quantity (MT)	PUC	PUI	Total	PUC	PUI	Total	PUC	PUI	Total
1 April 2008 to 31 March 2009	****	****	****	****	****	****	****	****	****
Share %	95-100	0-5	100%	90-95%	5-10	100%	90-95%	5-10	90-95%
1 April 2009 to 31 March 2010	****	****	****	****	****	****	****	****	****
Share %	95-100	0-5	100%	90-95%	5-10	100%	90-95%	5-10	90-95%
1 April 2010 to 31 March 2011	****	****	****	****	****	****	****	****	****
Share %	95-100	0-5	100%	90-95%	5-10	100%	90-95%	5-10	90-95%
1 April 2011 to 31 March 2012	****	****	****	****	****	****	****	****	****
Share %	75-80	20-25	100%	90-95%	5-10	100%	90-95%	5-10	100%
1 April 2012 to 31 March 2013	****	****	****	****	****	****	****	****	****
Share %	5-10	90-95	100%	90-95%	5-10	100%	90-95%	5-10	100%
1 April 2013 to 31 March 2014	****	****	****	****	****	****	****	****	****
Share %	5-10	90-95	100%	90-95%	5-10	100%	95-100	0-5	100%

1 April 2014 to 31 March 2015	****	****	****	****	****	****	****	****	****
Share %	0-5	95-100	100%	90-95	5-10	100%	95-100	0-5	100%
POI : July 2014 to September 2015	****	****	****	****	****	****	****	****	****
Share %	0-5	95-100	100%	90-95	5-10	100%	90-95	5-10	100%

It is noted that the pattern of trade to India especially post AD measure has shifted from PUC to PUI. This trend is however not noticed in sales of POSCO Korea to countries other than India and their domestic market.

Table 7 - Trade Pattern of PUC/PUI - Yieh United Steel Corporation, Taiwan

	Exports to India			Domestic Sales			Exports to Third Countries		
Quantity (MT)	PUC	PUI	Total	PUC	PUI	Total	PUC	PUI	Total
1 April 2008 to 31 March 2009	****	****	****	****	****	****	****	****	****
Share %	30-35	65-70	100%	80-85	15-20	100%	70-75	25-30	100%
1 April 2009 to 31 March 2010	****	****	****	****	****	****	****	****	****
Share %	0-5	95-100	100%	80-85	15-20	100%	80-85	15-20	100%
1 April 2010 to 31 March 2011	****	****	****	****	****	****	****	****	****
Share %	25-30	70-75	100%	70-75	25-30	100%	80-85	15-20	100%
1 April 2011 to 31 March 2012	****	****	****	****	****	****	****	****	****
Share %	65-70	30-35	100%	70-75	25-30	100%	80-85	15-20	100%
1 April 2012 to 31 March 2013	****	****	****	****	****	****	****	****	****
Share %	0	0	0	75-80	20-25	100%	75-80	20-25	100%
1 April 2013 to 31 March 2014	****	****	****	****	****	****	****	****	****
Share %	0-5	95-100	100%	70-75	25-30	100%	75-80	20-25	100%
1 April 2014 to 31 March 2015	****	****	****	****	****	****	****	****	****
Share %	0-5	95-100	100%	65-70	30-35	100%	70-75	25-30	100%
POI : July 2014 to September 2015	****	****	****	****	****	****	****	****	****
Share %	0-5	95-100	100%	70-75	25-30	100%	70-75	25-30	100%

The Authority notes that there is a visible shift in trend from PUC to PUI for exports to India post 2012 – 13. This change in trend is not visible in domestic sales or third country sales of YUSCO.

Table 8 - Trade Pattern of PUC/PUI - Outokumpu Oyj, EU

	Exports to India			Domestic Sales			Exports to Third Countries		
Quantity (MT)	PUC	PUI	Total	PUC	PUI	Total	PUC	PUI	Total
1 April 2008 to 31 March 2009	****	****	****	****	****	****	****	****	****
Share %	50-55	45-50	100%	50-55	45-50	100%	50-55	45-50	100%
1 April 2009 to 31 March 2010	****	****	****	****	****	****	****	****	****
Share %	40-45	55-60	100%	50-55	45-50	100%	40-45	55-60	100%
1 April 2010 to 31 March 2011	****	****	****	****	****	****	****	****	****
Share %	0-5	95-100	100%	45-50	50-55	100%	45-50	50-55	100%
1 April 2011 to 31 March 2012	****	****	****	****	****	****	****	****	****
Share %	5-10	90-95	100%	45-50	50-55	100%	60-65	35-40	100%
1 April 2012 to 31 March 2013	****	****	****	****	****	****	****	****	****
Share %	20-25	75-80	100%	40-45	55-60	100%	65-70	30-35	100%
1 April 2013 to 31 March 2014	****	****	****	****	****	****	****	****	****
Share %	30-35	35-70	100%	40-45	55-60	100%	50-55	45-50	100%
1 April 2014 to 31 March 2015	****	****	****	****	****	****	****	****	****
Share %	15-20	80-85	100%	40-45	55-60	100%	65-70	30-35	100%
POI : July 2014 to September 2015	****	****	****	****	****	****	****	****	****
Share %	0-5	95-100	100%	40-45	55-60	100%	45-45	55-60	100%

There is a shift in trend post 2010-11 to POI from PUC to PUI on exports to India which is also noted in domestic market of Outokumpu, EU.

72. Based on the above, the Authority holds that the pattern of imports from the subject countries have changed without any genuine change in the usage of the final product since the imposition of anti-dumping duties on the PUC from 2009-2010.
73. Rule 25(1) (b) of AD Rules requires that “value consequent to assembly, finishing or completion operation is less than thirty-five percent of the cost of assembled, finished or complete article”. In order to fully satisfy itself, the Authority through its officers also undertook onsite verification prior to initiation of the investigation to get an idea about the actual cost involved in the slitting process. The value addition ascertained by the Authority based on the verified information works out to be in the range of 2% to 5% depending upon the series which is imported from the subject countries.
74. The Authority observes that the value addition involved in the process of slitting is much below the limits prescribed under the law. It is noted that the landed value of PUC worked out from

the imported PUI i.e., after adjusting the landed value of PUI with value addition (2% to 5%) is lower than the landed value of PUC including existing ADD when imported directly in finished form from the subject countries. It is therefore commercially advantageous to import PUI instead of PUC even after the slitting costs are taken into account.

75. The investigation indicates that there exists no economic justification other than to circumvent the anti-dumping duties imposed on the PUC for the producers/exporters in the subject countries. This is evident in the steep rise in the imports of PUI. This along with the fact that the value addition is much lower than the prescribed thresholds indicates circumvention of existing anti-dumping duties in terms of the Rules.
76. The Authority notes that M/s Sunrise Stainless Pvt. Ltd and Sunmark Stainless Private Limited have only filed legal submissions but have not filed any data regarding imports made by them as per the prescribed questionnaire.
77. M/s Suncity Sheets Pvt. Ltd. and Suncity Strips and Tubes Pvt. Ltd. have filed both legal submissions and also the importers questionnaire. The Authority notes that M/s Suncity sheets and M/s Suncity Strips M/s Suncity Sheets Pvt. Ltd. and Suncity Strips and Tubes Pvt. Ltd. have stated that since inception of their company in 2012 – 13, they have only imported PUI or non PUC/PUI but not PUC and have therefore not resorted to circumvention.
78. The Authority notes the submissions made by various interested parties, most of which were also made before the Hon'ble High Court of Delhi. The Authority notes that M/s Suncity Sheets Pvt. Ltd. and Suncity Strips and Tubes Pvt. Ltd. have imported from 2 subject countries viz. china and Korea. The phenomena of circumvention is required to be established for producers/exporters from subject countries on whom an AD measure is already in existence. For this various provisions of Rule 25 to Rule 28 have to be examined regarding the dumping of the circumventing product (PUI) as per Rule 26 (4) and its effect as per Rule 26 (1) and aspects of change in trade pattern and value added as per AD Rule 25 (1) (a) and 25 (1) (b) respectively.
79. Therefore the aforesaid parameters are firstly to be established for a cooperating producer/exporter who needs to provide complete data as per the prescribed questionnaire. In case of M/s Suncity Sheets, it is noted that significant exports have been made from China from where none of the producers/exporters have responded. The Authority evaluated specific behaviour of a cooperating producer/exporter for all relevant parameters and evaluate the non-cooperating producers/exporters on various parameters as per the best available information.
80. The Authority notes that Posco India Pune Steel Processing Pvt. Ltd., Posco India Delhi Steel Processing Pvt. Ltd., Posco India Chennai Steel Processing Pvt. Ltd. who are the subsidiaries of Posco Korea have imported PUC, PUI and even non PUC during POI from South Korea and undertaken slitting activities as tabulated below:

Table 9

(Amount in INR)							
S. No.	Company Name	PUC/PUI	Qty(MT)	Value of Imported parts or Components	VALUE ADDITION (Cost/ Expenses Incurred for Such Operations)	Cost of assembled, finished or complete article	Value Addition As % of Cost of assembled, finished or complete article
1	POSCO-ICPC	PUI	****	****	****	****	0-5
		PUC	****	****	****	****	0-5
2	POSCO-IDPC	PUI	****	****	****	****	0-5
		PUC	****	****	****	****	0-5
3	POSCO-IPPC	PUI	****	****	****	****	0-5
		PUC	****	****	****	****	0-5
			****	****	****	****	0-5
TOTAL			****	****	****	****	0-5
PUI			****	****	****	****	0-5
PUC			****	****	****	****	0-5
TOTAL			****	****	****	****	0-5

The value addition on account of converting any PUC/PUI material to smaller sizes viz. PUC or Non PUC is thus less than 35 %.

Therefore as regards 'value addition' incurred in changing the form of PUI further, the Authority has referenced the best available information as per verification conducted for such processing centres, and also responses filed by importers on this aspect, who have admitted that slitting costs are not more than 5% value addition. The disposal of various sizes of the subject goods viz. be it PUI, PUC or non PUC by the slitting centres of POSCO in India is as under:

Table 10 (Source: data provided by slitting centers of POSCO Korea)

The Authority notes that availability of non PUC/non PUI in India since 2008-09 has been catered

Particulars	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	POI (July 2014 - September 2015)	POI (Annualised)
	Qty.	Qty.	Qty.	Qty.	Qty.	Qty.	Qty.	Qty.	Qty.
1. Utilization of Imports									
Opening Stock	****	****	****	****	****	****	****	****	****
Add: Imports	****	****	****	****	****	****	****	****	****
A. Less than 600mm	****	****	****	****	****	****	****	****	****
B. 600-1250mm	****	****	****	****	****	****	****	****	****
C. Above 1250mm	****	****	****	****	****	****	****	****	****
Less: Closing Stock	****	****	****	****	****	****	****	****	****
Utilization I	****	****	****	****	****	****	****	****	****
II. Break-up of utilization of Imports	****	****	****	****	****	****	****	****	****
1. Product Sold	****	****	****	****	****	****	****	****	****
(a) Domestic	****	****	****	****	****	****	****	****	****
A. Less than 600mm	****	****	****	****	****	****	****	****	****
B. 600-1250mm	****	****	****	****	****	****	****	****	****
C. Above 1250mm	****	****	****	****	****	****	****	****	****
D. Scrap	****	****	****	****	****	****	****	****	****
(a) Export	****	****	****	****	****	****	****	****	****
Losses	****	****	****	****	****	****	****	****	****
Total	****	****	****	****	****	****	****	****	****

to by conversion of PUC, which later on, shifted to PUI when imports shifted mainly to PUI. PUI was also converted to PUC besides non PUC. The Authority considered this disposal pattern of PUC and PUI between 2008 – 09 to POI for the purpose of considering circumvention and consequential undermining of existing AD measures on PUC.

H. Determination of Normal Values, Export Prices and Dumping Margins

81. The investigation was initiated against the goods originating in or exported from Peoples Republic of China, Republic of Korea, the European Union, South Africa, Chinese Taipei, Thailand and the United States of America. The Authority sent questionnaires to the known exporters/producers from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed. In response to the initiation notification the following producers/exporters have filed their questionnaire responses:

- (i) Outokumpu Oyi, Europe
- (ii) Yieh united Steel Corporation, Taiwan (YUSCO)
- (iii) Walsin Lihwa Corporation, Taiwan
- (iv) Yuan Long Stainless Steel Corporation, Taiwan (YLSS)
- (v) Tang Eng Iron Works Co. Ltd., Taiwan
- (vi) POSCO Asia
- (vii) POSCO, Korea
- (viii) Daewoo International, Korea
- (ix) Hyundai Corporation, Korea
- (x) Samsung C&T, Korea
- (xi) SK Networks, Korea
- (xii) Toyota Tshusho, Korea

82. No response has been filed by any producer/exporter from Peoples Republic of China, South Africa, Thailand and the United States of America. Domestic industry has submitted that in the absence of response from these countries/territories normal values in these countries/territories should be constructed as per the best information available, including that of the domestic industry.

83. The Authority has considered the responses submitted by various interested parties and have arrived at the determination based on these submissions after verification, wherever considered necessary and unless rejected summarily. The Normal value has been arrived at by undertaking appropriate comparison at grade to grade/ series level based on the information, after applying the (ordinary course of trade test) OCT test and sufficiency test and as per the methodology prescribed under the rules. The export price and adjustments claimed have been allowed on the basis of submissions and verification, wherever undertaken.

84. Determination of Normal Values and Export Prices with respect to the cooperating exporters and other non-cooperating exporters in the subject countries/territories have been outlined in the following paragraphs.

(1) All Producers/ Exporters from China, South Africa, Thailand and USA

Examination by the Authority

None of the producers/exporters have filed any response from China, South Africa, USA and Thailand.

85. The Authority in respect of all the producers/exporters from China, South Africa, USA and Thailand as considered non-cooperative, since none of the producers/exporters have filed any response has referenced, the best available information for constructing normal value and export price (Ex-EP and CIF) as per Rule 6 (8) of AD Rules. In this regard the Authority has adopted its consistent practice of constructing the normal value for all producer/exporter of

these countries on the basis of international prices for major raw materials (HR Coils) and for rest of the cost elements adopting domestic industry's data on cost of production for PUI during POI.

Regarding export price, the DGCIS transaction wise data of POI for PUI has been adopted. The adjustments on CIF have been provided for ocean freight, ocean insurance, commission, inland freight, bank charges & credit cost and port charges on the basis of evidence/consistently adopted norms to an extent of (USD/MT **, **, **, **, **, ** for China, Korea, Thailand, South Africa, USA, EU and Taiwan respectively),, **% of CIF, **% of FOB, **% of FOB, **% of FOB and **% of FOB respectively. Further, in case of China, 'VAT' adjustment to an extent of **% has also been provided.

Based on the above the dumping margin in US\$/MT is computed as under:

Table 11

Countries	CNV	Ex EP	DM	DM %	DM Range
China	****	****	****	****	0-10
Thailand	****	****	****	****	15-25
South Africa	****	****	****	****	10-20
USA	****	****	****	****	40-50

(2) Producers/Exporters from Korea RP

A. For Producers/Exporters from Korea who have filed questionnaire responses

a. POSCO Korea

86. M/s POSCO, Korea, who is a major producer and exporter of the subject goods in Korea has filed questionnaire response. During the POI, POSCO has exported the subject goods to India through its related and unrelated Trading Companies situated in Korea and Hong Kong. These companies are POSCO Asia, Daewoo International, Korea, Hyundai Corporation, Korea, Samsung C&T, Korea, SK Networks, Korea and Toyota Tshusho, Korea. POSCO Korea has filed its questionnaire response as producer supported by the questionnaire responses of the above trading/exporting companies. The responses of POSCO and the trading companies named above were also verified in accordance with the procedure. The dumping margins of the Korean producer have been determined on the basis of the responses filed by them. Dumping margins for other non-cooperating producer/exporters from Korea are determined on the basis of the best available information as per the methodology adopted for other non-cooperating producers/mentioned above and other facts available.

87. POSCO Korea the producer has filed the exporter questionnaire response providing data on trade pattern shift, domestic and export sales of PUC and PUI during the POI and prior years. Its related/unrelated exporters/traders i.e. Posco Daewoo Corporation, Korea, Toyota Tsusho Korea Corp, Korea, Samsung C&T Corporation, Korea, Hyosung Corporation, Korea, Hyundai Corporation, Korea have also filed the exporter questionnaire response and similar data.

The producer has provided data on the cost of production of PUI during POI also, for different series/grades of PUI.

Examination by the Authority

Normal Value (NV)

The producer has sold **** MT of PUI in the domestic market and has claimed adjustments on account of Inland freight, credit cost, packing cost, warehousing expenses and warranty. The Authority had carried out onsite verification of the data filed by POSCO Korea and its 6 traders/exporters. The ordinary course of trade test has been carried out on the domestic sales for different series of PUI which have been sold during POI to India, so that appropriate series to series comparison for dumping margin evaluation could be undertaken. Based on the above methodology, the ex-factory weighted average normal value has been computed as **** US\$/MT.

Export Price

The producer has exported PUI of **** MT to India during POI. Adjustments have claimed on account of Inland transportation, overseas transportation credit cost, packing cost and duty drawback have been allowed by the Authority.

The producer has exported PUI during POI through different trading/exporting entities as under:

Table 12

S. No.	Exporter/producer	Series	Exports (MT)	CIF \$/MT
1	Posco Daewoo Corporation, Korea			
2	Samsung C&T Corporation, Korea			
		200	****	****
		300	****	****
		400	****	****
	Total		****	****
3	Hyosung Corporation, Korea		****	****
		200	****	****
		300	****	****
		400	****	****
	Total		****	****
4	Hyundai Corporation, Korea		****	****
		200	****	****
		300	****	****
		400	****	****
	Total		****	****
5	SK Networks Co. Ltd., Korea		****	****

		200	****	****
		300	****	****
		400	****	****
	Total		****	****
6	Toyota Tsusho Korea Corp, Korea		****	****
		200	****	****
		300	****	****
		400	****	****
	Total		****	****
7	Posco Asia Co. Ltd		****	****
		200	****	****
		300	****	****
		400	****	****
	Total		****	****

The S & D expenses incurred by the above traders and their profitability is determined as under:

Table 13

S. No.	Exporter/producer	US\$/MT				Profit %
		Ex factory selling price	Expenses including S&A	Ex factory Purchase price	Purchase price	
1	Posco Daewoo Corporation, Korea	****	****	****	****	0-10%
2	Samsung C&T Corporation, Korea	****	****	****	****	0-10%
3	Hyosung Corporation, Korea	****	****	****	****	0-10%
4	Hyundai Corporation, Korea	****	****	****	****	0-10%
5	SK Networks Co. Ltd., Korea	****	****	****	****	0-10%
6	Toyota Tsusho Korea Corp, Korea	****	****	****	****	0-10%
7	Posco Asia Co. Ltd	****	****	****	****	0-10%

Based on the above, the weighted average dumping margin for POSCO, Korea is computed as under:

Table 14

Normal Value	USD/ MT	****
Exfactory Export Price	USD/ MT	****
Dumping margin	USD/ MT	****
Dumping Margin %	%	****
Dumping Margin Range	%	15-25

B. Producers/exporters from Korea RP other than above

88. For all other producers/exporters from the Korea RP dumping margins are considered on the basis of best information available as per constructed CNV methodology and DGCI&S data:

Table 15

Producers/exporters	EP (US\$/MT)	NV (US\$/MT)	DM (US\$/MT)	DM%	DM Range
Wt. Average	****	****	****	****	50 - 60

(3) **European Union**

A. For Producers/Exporters from European Union who have filed questionnaire response

89. Outokumpu Oyj, Finland, only responding producer/exporter from European Union has filed questionnaire response. The producer/exporter has stated that their ERP system can identify PUC and PUI on the basis of width. Outokumpu is not aware about conversion of PUI to PUC. The Mill sells directly to end users in India. Outokumpu has provided information regarding domestic sales, pattern of trade and top 10 customers in India. Further grade/series wise, customer wise information has also been provided to support their view the shift in trade pattern.

Examination by the Authority

90. The Authority notes that M/s Outokumpu has provided their Domestic selling prices of PUI in the Questionnaire response but not the Associated Cost of Production. The Authority has therefore computed CNV on the basis of best available information by referencing COP of the DI for the series of PUI exported to India during POI and also referencing international Raw Material Prices (HR Sheets) in Europe. The CNV is evaluated as ****\$/MT 300 /400 series of PUI. The ex-factory Export Price has been computed by allowing adjustments on account of freight, Selling Expenses including Credit Cost. The ex-factory Export Price comes to ****\$/MT. The Dumping Margin is evaluated as ****\$/MT (****%), which is above the de minimis limit.

For all other exporters from the EU dumping margins are considered on the basis of best information available as per constructed CNV for all series and the DGCI&S data:

Table 16

All Producers/exporters other than Outokumpu	EP (US\$/MT)	NV (US\$/MT)	DM (US\$/MT)	DM%	DM Range
Wt. Average	****	****	****	****	5 - 15

(4) Taiwan**A. For Producers/Exporters from Taiwan who have filed responses to the Questionnaire:**

91. The following producers/exporters from Taiwan have filed questionnaire responses:

i. Walsin Lihwa Corporation

ii. Yieh United Steel Corporation, Taiwan (YUSCO)

iii. Yuan Long Stainless Steel Corp., Taiwan (YLSS)

iv. Tang Eng Iron Works Co. Ltd., Taiwan

i. Yieh United Steel Corporation, Taiwan (YUSCO)

The producer/exporter has stated that it has identified PUC and PUI on the basis of identification through coil number in their ERP system. No sales were made through related parties during POI to India. Sales in domestic market have been reported to independent and related customers. Export sales have been reported which are made to independent Indian customers.

During POI M/s YUSCO has sold both PUC and PUI in domestic Market. M/s YUSCO has also exported PUC and PUI to India and is not aware if PUI has been subjected to any further processing. M/s YUSCO did not export PUI to India through any intermediary countries.

There is no change in pattern of trade and that sales value of PUI is greater than sales value of PUC. There is no difference in manufacturing process of PUC or PUI. M/s YUSCO has provided information regarding domestic sales, pattern of trade and top 10 customers in India. Further grade/series wise, customer wise information has also been provided in support of change regarding trade pattern of PUC and PUI.

Examination by the Authority

The Authority has evaluated the Normal Value of PUI by applying OCT test on the Domestic Selling Price of PUI during POI by adopting the COP of PUI during POI. The Normal Value comes to ****\$/MT. The ex-factory Export Price is evaluated as **** \$/MT by allowing adjustments on Inland Freight, Overseas Freight, Overseas Insurance, Bank Charges, Credit Cost, and Customs Charges. The Dumping Margin is evaluated as ****\$/MT (****%) which is above the *deminimis* limit.

ii. M/s Walsin Lihwa, Taiwan

M/s Walsin Lihwa has filed questionnaire response providing details of domestic and export sales of PUC and PUI during POI stating that it has exported very small quantity of PUC only during POI to India and that further this was imported under the advance license.

Examination by the Authority

The Authority notes that the producer/exporter has not exported PUI to India during POI and it cannot be evaluated whether PUI exports in POI is dumped. The Authority therefore holds that this producer/exporter may apply for a review as per Rule 28 of AD Rules in case of exports of PUI made by them. For the purpose of this investigation, this producer/exporter will be considered along with the residual category of producers/exporters.

iii. M/s Yuan Long Stainless Steel Corp., Taiwan (YLSS)

M/s YLSS has made following submissions:

- We provide 430 series, 304-BA & 304-2B, 430YD, 439, 443CT and 430J1L. The production range can be 1260mm (slit edge) and 1280mm (mill edge), and we can provide the width under 600mm.
- Although strip coil or narrow width coil is in our product range, YLSS only sold full width coil (i.e. 1250mm) to India during the investigation period. No processing or assembly was involved in the sales activity then.
- We don't have the channels in the domestic market, but we sold the materials to our customer (distributors) in India. Our price is according to our cost of raw material plus the processing cost; therefore, we didn't sell the material without any profit.
- When we get inquiries from our customers in domestic market, we ask the final customer name because we have to check whether the customers are double or not. If the customer's channel is no problem, then we send our official offer to them, and wait for their comments. When we get the price bid, then we will check the cost and reasonable price with market price to adjust the price.
- The coil we produce is standard coil and our factory without any slitting machine for further processing.
- We do not know the product we sold are being converted into PUC in a third country before being put to final use. Based on business consideration customer will not allow or inform what is the purpose is or where is the destination.
- During the investigation period, YLSS only has direct sales to India, no other sales methods in terms of through intermediate countries or third country. YLSS is a stainless steel manufacturer able to conduct export activity on his own and directly deal with Indian buyers. However, the volume we sold to India is very less, only ****MT per month, which literally do not cause damage to the whole Indian market.
- There is only one sales method regarding our sales to India, which directly from YLSS to Indian buyers.
- The material by process of slitting will be in product under consideration. Our company can provide the material by slitting process, but the price is not workable in India due to the processing cost is very high, therefore, our export quantity to India is very few.

- For allocating cost to PUC and PUI, separate cost is calculated by types, thickness, surface, grade, brightness and production line in production process. Then separate cost is distributed to each inventory cot and cost of goods sold. The methodology is the same between PUC and PUI.
- There is no difference in factory cost for exports to India, for domestic market and for other countries. We do not have separate accounting system for PUC and PUI.
- The production cost data supplied in reply to this questionnaire and costs is normally determined by using accounting system and there is no material difference between costs provided and as determined by our accounting system.
- The potential production for 400 series is *****MT, 300 series is ***** MT.

Examination by the Authority

M/s YLSS has filed questionnaire response wherein they have stated having exported both PUC and PUI to an extent of *****MT to India during POI. On correlating the same with DGCIS data it is noted that ***** MT is of PUI while rest is ***** MT is PUC. The producer/exporter has claimed net domestic selling price of *****Taiwanese \$/MT for PUC. The producer/exporter have stated that their accounting system does not allow them to distinguish between PUC and PUI and have claimed weighted average cost of production of PUC/PUI. The normal value correlated with the domestic selling price after applying ordinary course of trade test comes to *****US\$/MT. The exfactory export price of PUI during POI comes to ***** Taiwanese \$/MT (***** US\$/MT), thereby evidencing dumping to an extent of *****% which is above de minimus.

The producer/exporter has sold PUC to an extent of more than ***** in the domestic market during POI and therefore the trend of shift to PUI is only limited to exports to India.

Further the data on exports made to India submitted by the producer/exporter in 2008 – 09 and 2009 – 10 does not indicate about its categories i.e. PUC and PUI and also does not correlate with the DGCIS data. Since the producer/exporter has not categorically confirmed these to be PUC or PUI, the Authority holds that the producer/exporter evidences a shift of exports post levy of ADD to PUI to India especially when its majority sales in domestic market is of PUC.

iv. Tang Eng Iron Works Co. Ltd., Taiwan (Tang Eng)

Tang Eng have stated that they did not sell the PUC to India during the POI and that they have never produced or sold any PUI because its production equipment is not capable of manufacturing the PUI. Therefore, it is unlikely for Tang Eng to circumvent the anti-dumping duty by way of selling the PUI as alleged in the above notification. It was further submitted that Tang Eng does not conduct any action to circumvent the duty and that the anti-dumping duty imposed on the PUC should not be extended to the PUI.

Examination by the Authority

The Authority holds that producer/exporter from subject countries who did not export PUI to India during POI will be considered in the residual category and who are eligible for review under Rule 28 of AD Rules if the situation so warrants and as per merits under the Rules.

B. All Producers/Exporters from Taiwan other than above

92. For all other producers/exporters from Taiwan other than the above the dumping margins are determined on the basis of best information available as per DGCI&S and constructed CNV:

Table 17

Non-Cooperative Producers/exporters other than YUSCO and YLSS	EP (US\$/MT)	NV (US\$/MT)	DM (US\$/MT)	DM %	DM Range
Wt. Average	****	****	****	****	10 - 20

Dumping Margins

93. Comparing the Constructed Normal Value and the Export price at ex-factory level determined as per DGCI&S, the Dumping Margin for the residual category producers/exporters in the subject countries are depicted as under:

Table 18

<u>Particulars</u>	<u>Unit</u>	<u>China</u>	<u>EU</u>	<u>Korea</u>	<u>South Africa</u>	<u>Taiwan</u>	<u>Thailand</u>	<u>USA</u>
CNV	USD/ MT	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
NEP	USD/ MT	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Dumping Margin	USD/ MT	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Dumping Margin	%	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Dumping Margin	Range	0 - 10	5 - 15	50-60	10-20	5-15	15-25	40-50

Thus for all non-responding producers/exporters dumping margin is above *de minimis* and significant.

For all responding producers/exporters, the dumping margin is tabulated as below:

Table 19

Particulars	Unit	POSCO Korea	Outokumpu, EU	YUSCO, Taiwan	YLSS, Taiwan
NV/CNV	USD/ MT	****	****	****	****
NEP	USD/ MT	****	****	****	****
Dumping Margin	USD/ MT	****	****	****	****
Dumping Margin	%	****	****	****	****
Dumping Margin	Range	15-25	10-20	15-25	15-25

The dumping margin of above responding producers/exporters is also above *de minimis* level of 2%.

Assessment of effect of circumvention on existing Anti-dumping measures and Domestic Industry.

Submissions made by various interested parties other than Domestic Industry:

94. European commission submitted that the Authority should not cumulatively evaluate the impact of circumvention from all the subject countries, in order to analyze the impact of circumvention on Domestic Industry. Domestic Industry is not suffering any injury on account of imports of PUI.
95. M/s DGS Associates representing POSCO, Korea and its associated entities have submitted that the data provided by the Petitioner is merely indicative of the nature of imports and in no way establishes either utilization or injury or an undermining of the remedial effect of anti-dumping duties already imposed on the imports of the PUC.
96. M/s ELP Advocates & Solicitors representing Outokumpu Oyj and YUSCO have stated the following:
- The Authority in paragraph 6 of the Initiation Notification, notes that there is evidence to show that “the remedial effects of the existing anti-dumping duties on the product under consideration are being undermined on account of the significant volumes of imports of the product under investigation appear to having replaced imports of the product under consideration.”
 - It is not clear, how and why the Authority considers this evidence to be relevant for the present investigation. The Petitioner has stated that it has filed the anti-circumvention investigation on grounds of Rule 25(1). As stated above, Rule 25(1) does not take into account whether the remedial effects of the anti-dumping duties are being undermined. In fact, in terms of Explanation (b) to Rule 25(3), this is a condition which must be met to satisfy if there has been a change in trade practice, pattern of trade or channels of sales under Rule 25(3). The Exporter has already stated and shown that Rule 25(3) does not apply to the information alleged in the Application as this is not the case of the Petitioner that PUC is being imported into India through exporters or producers or countries not subject to anti-dumping duty. Accordingly, evidence on undermining the remedial effects of anti-dumping duties, if any, is irrelevant on the basis of information submitted by the Petitioner.
 - Even assuming that such information is relevant, there is no evidence in the Application to the effect that remedial effects of the anti-dumping duty on PUC are being undermined. The Petitioner has submitted that volume of imports of PUC have seen a steep fall from 2010-11 onwards i.e. volume of imports of PUC which stood at 53420 MT has come down to 20682 MT in the POI. If anything, it shows that due to the imposition of anti-dumping duty on PUC, the imports of PUC have been retarded and therefore, we are unable to see how the remedial effects of anti-dumping duty are undermined. The Petitioner has not provided any information on its own volume and price parameters. If it is the case of the Petitioner that despite the levy of anti-dumping duty on PUC, Petitioner’s financial performance has not improved, then the Petitioner must provide duly substantiated evidence to that effect. In absence of any such information, we are surprised how the Hon’ble Authority was able to find evidence in the Application to the effect that ‘remedial effects of anti-dumping duties are being undermined’.

Submissions made by Domestic Industry:

97. The producers / exporters of PUC/PUI from subject countries have undermined the remedial effect of anti-dumping duties by indulging in the process of circumventing the anti-dumping duties since the time anti-dumping duties imposed by the government in February, 2010.
98. That they are continued to suffer injury as imports of PUI started in place of PUC. This shift in pattern from PUC to PUI without any corresponding change in consumption pattern has impacted Domestic Industry severely.

Examination by the Authority

99. The Authority notes that the impact of circumventing product i.e., PUI which if dumped from the subject countries needs to be examined by comparing the landed values of imports PUC (with ADD) and PUI (with no measure) during POI from the subject countries with its price depressing effect on the net sales realization of PUC of Domestic Industry on which the circumventing product would cause an adverse effect. The following Tables depict the price impact of circumventing product on net sales realization of PUC of Domestic Industry and the erosion of efficacy of existing anti-dumping measures on PUC. The landed value of product under consideration with anti-dumping duty during POI from the subject countries are noted to be higher from the landed value of PUI.

Table 20 - Price undercutting by PUI on Domestic Industry's PUC Sales

Countries	Series	PUI Import Quantity (MT)	Landed value of PUI (Rs/MT)	Selling Price of DI PUC (Rs/MT)	Price Undercutting (Rs/MT)	Price Undercutting %	Price Undercutting (Range)
China PR	200	****	****	****	****	****	****
	300	****	****	****	****	****	****
	400	****	****	****	****	****	****
Weighted Average Price Undercutting China		19268	164192	****	****	****	(5) - 5
EU	200	****	****	****	****	****	****
	300	****	****	****	****	****	****
	400	****	****	****	****	****	****
	Duplex	****	****	****	****	****	****
Weighted Average Price Undercutting EU		12138	194073	****	****	****	(15) - (5)
Korea RP	200	****	****	****	****	****	****
	300	****	****	****	****	****	****
	400	****	****	****	****	****	****

Weighted Average Price Undercutting Korea		29180	109320	****	****	****	10-20
South Africa	200	****	****	****	****	****	****
	300	****	****	****	****	****	****
	400	****	****	****	****	****	****
Weighted Average Price Undercutting South Africa		1901	175496	****	****	****	(10) - 0
Taiwan	200	****	****	****	****	****	****
	300	****	****	****	****	****	****
	400	****	****	****	****	****	****
Weighted Average Price Undercutting Taiwan		4437	147656	****	****	****	5-15
Thailand	200	****	****	****	****	****	****
	300	****	****	****	****	****	****
	400	****	****	****	****	****	****
Weighted Average Price Undercutting Thailand		1976	138748	****	****	****	10-20
USA	200	****	****	****	****	****	****
	300	****	****	****	****	****	****
	400	****	****	****	****	****	****
Weighted Average Price Undercutting USA		6809	144167	****	****	****	5-15

Table 21 - Price Undercutting by PUI on Domestic Industry's PUC sales by responding Producers/Exporters

Producers/ Exporters	Series	Quantity of Imports of PUI MT	CIF (RS/MT)	Landed Value (Rs/MT)	NSR of Domestic Industry - PUC (Rs/MT)	Price Under- cutting (Rs./MT)	Price Under- cutting %	Price Under- cutting (Range)
POSCO	300	****	****	****	****	****	****	****
	400	****	****	****	****	****	****	****
Weighted Average		****	****	****	****	****	****	20-30
	300	****	****	****	****	****	****	****
Outokumpu	400	****	****	****	****	****	****	****
	Duplex	****	****	****	****	****	****	****
Weighted Average		****	****	****	****	****	****	(25-35)
YUSCO	200	****	****	****	****	****	****	****
	300	****	****	****	****	****	****	****
	400	****	****	****	****	****	****	****
Weighted Average		****	****	****	****	****	****	(10) -0
YLSS	400	****	****	****	****	****	****	5-15

As regards effect of anti-dumping duty on the efficacy of existing AD measures, the landed value of PUI (without ADD) and landed value of PUC (with ADD) has been compared with net sales realization of PUC sales of domestic industry to evaluate the effect of circumvention of PUC by PUI. The table below highlights this effect/impact.

The Authority considered the above two phenomena to conclude the effect of circumventing product on efficacy of existing anti-dumping measures and a consequential price effect on Domestic Industry's sales of product under consideration.

Table 22- Effect of circumvention on Anti-Dumping Duty by responding producers /exporters

Producers/Exporters	Series	Landed Value of PUI (Rs/MT)	Landed Value of PUC with Duties (Rs/MT)	Effect of circumvention Anti-Dumping Duty (Rs./MT)	Effect of circumvention Anti-Dumping Duty %	Effect of circumvention on Anti-Dumping Duty (Range)
POSCO	300	*****	*****	*****	*****	60-70
	400	*****	*****	*****	*****	50-60
Outokumpu	300	*****	*****	*****	*****	10-20
	400	*****	*****	*****	*****	
	Duplex	*****	*****	*****	*****	
YUSCO	200	*****	*****	*****	*****	NA*
	300	*****	*****	*****	*****	
	400	*****	*****	*****	*****	
Weighted Average		*****	*****	*****	*****	
	200	*****	*****	*****	*****	
YLSS	300	*****	*****	*****	*****	
	400	*****	*****	*****	*****	75-85

*Undermining to the extent of anti-dumping on PUC for 300/400Series

Table 23 - Effect of circumvention on Anti-Dumping Duty by producers /exporters from subject countries

	Wt. Average Landed Value PUI (Rs/MT)	Wt. Average Landed Value PUC With Duties (Rs./MT)	Effect of circumvention Anti-Dumping Duty (Rs./MT)	Effect of circumvention Anti-Dumping Duty %	Effect of circumvention on Anti-Dumping Duty (Range)
China PR	*****	*****	*****	*****	30-40
EU	*****	*****	*****	*****	55-65
Korea RP	*****	*****	*****	*****	35-45
South Africa	*****	*****	*****	*****	15-25
Taiwan	*****	*****	*****	*****	80-90
Thailand	*****	*****	*****	*****	40-50
USA	*****	*****	*****	*****	95-105
Total Subject Country	*****	*****	*****	*****	45-55

The Authority has considered the effect of circumvention on the efficacy of existing AD measures in the final findings.

The Authority notes that there is a shift in trade pattern of PUC/PUI from subject countries at an aggregate level. There is also an evidence of slitting of the circumventing product to lower sizes with a value addition much lower than the prescribed threshold. The landed values of PUC/PUI at aggregate level for POI indicates effect due to circumvention of existing AD measures on PUC. For the responding producers/exporters there is also a shift in trade pattern from PUC to PUI. In case of POSCO Korea, there is quite significant shift from PUC to PUI for imports to India with all other required conditions of circumvention also being met. For Outokumpu though there is a shift from PUC to PUI besides India in EU and third countries also, but for India it is much more significant and coinciding with AD measures. For YUSCO also the trade pattern shift is stronger as compared to their domestic and third country markets. In view of this the Authority holds that while some shift may be due to emerging user requirements but largely it is coinciding with AD measures.

With regard to the submissions of POSCO on usage of PUI by them for non PUC the Authority on the basis of data filed by IDPC, ICPC and IPPC, the three slitting centres of POSCO Korea in India notes that during 2008-09 to 2011-12, i.e. pre-AD measure levy period, 20-25% of non-PUC sales in domestic market was met by direct imports of non-PUC category. For the remaining sales of non-PUC, 45-50% was met by slitting of PUC and 30-35 % by slitting of PUI. During 2012-13 to POI, i.e. post levy of AD measure, 0-5% of non-PUC sales in domestic market was met by direct imports of non-PUC category. The remaining 95-100% was met by slitting of PUI. As regards PUC sales in domestic market during this period, 10-15% of sales of PUC in domestic market was met by direct imports of PUC and 85-90% was met by slitting of PUI. It is noted that the PUI imported during this period was sold as 'PUI only' to an extent of 10-15% and the rest was used for slitting into PUC and/or non-PUC. The Authority in view of the aforesaid utilization pattern of imports considered the slitting operation of PUI to non PUC also as circumvention.

The Authority notes that various interested parties (Exporters as well as Importers) have stated that they are not resorting to any circumvention and that they are not slitting the PUI to use it as widths of lower sizes either to PUC or below that. The Authority in this regard also appreciates the need of not imposing Anti-dumping duty on the PUI imported for genuine use of PUI only without being slitted further for use except to the extent of tolerances allowed for trim and mill edge as stated in the final findings dated 12/10/2015.

The Authority noting that any bona fide user of PUI need not be saddled with extension of Anti-dumping duties on PUI, also appreciates that it is not possible for any Government agency to enforce monitoring of any exemption granted to any bona fide user and therefore for this purpose all importers importing PUI will be required to give a legally enforceable declaration/undertaking to customs authorities that the PUI being imported by them will be used without any slitting except to the extent of tolerances as mentioned in final finding dated 12/10/2015 imposed vide custom notification 61/2015 CUS-ADD dated 11/12/2015 if they desire not to pay existing ADD .

Post Disclosure Comments

100. The Domestic Industry and the following interested parties has filed the post disclosure comments:

- 1) M/s Meena Metal Impex
- 2) M/s Vishal Tubes & Pipes Ltd.
- 3) M/s Star stainless steel
- 4) M/s Maxgrow Corporation
- 5) M/s Seth carbon & Alloys Pvt. Ltd.
- 6) M/s Siddhivinayak Steel
- 7) M/s Dhruv Exim
- 8) M/s Shakti Steel
- 9) M/s Steel International
- 10) M/s Seth Iron & Steel Pvt. Ltd.
- 11) M/s Aesteiron
- 12) M/s Acer Steel
- 13) M/s Divine Impex
- 14) M/s Steel Yard Overseas
- 15) M/s Ramani Steel House
- 16) M/s Non-ferrous Metal Association
- 17) M/s Nexus Impex
- 18) M/s Rakesh Metals
- 19) M/s Modest Metal Corporation
- 20) M/s Steelyard Overseas
- 21) M/s Inox Stainless
- 22) M/s Saraswati Steel
- 23) M/s KNM & Partners on behalf of Maruti Suzuki India Ltd.
- 24) M/s Wirana Pte. Ltd., Singapore
- 25) M/s GTC Consultants representing M/s Suncity Sheets Pvt. Ltd., M/s Suncity Strips and Tubes P Ltd, M/s Sunrise Stainless Pvt. Ltd and M/s Sunmark Stainless Private Limited
- 26) M/s Agol Associates representing NG Industries, MP Industries and Shree Ramdev Metal Mart
- 27) M/s DGS Associates representing POSCO and its related entities
- 28) M/s ELP representing Outokumpu Oyj, Finland and YUSCO
- 29) M/s M M Metal International
- 30) Taiwan Embassy
- 31) M/s Metal & Steel (India)
- 32) Pacific Metal Trading Co.
- 33) Glomet Alloys LLP
- 34) Stainox Alloys Pvt. Ltd.

A. Views of Domestic Industry

101. M/s APJ-SLG Law offices on behalf of Domestic Industry have submitted the following:

- Domestic Industry submits that the response of Outokumpu ought to be rejected as they have failed to provide complete information as required in the questionnaire format. The Authority would like to appreciate that without complete information about cost, the Authority cannot even

perform “Ordinary Course of Trade Test” which is mandatory for calculating normal value and dumping margin.

- Attention of the Authority is invited to the recent findings of the Authority [Sodium Chlorate F. No. 14/13/2015 – DGAD dated 10.8.2017] wherein the Authority has rejected response of M/s. Akzo Nobel only because they have not provided sufficient information for carrying out the mandatory tests. Since without costing information, the Authority cannot conduct mandatory OCT test, the ratio of rejection of M/s. Akzo Nobel is fully applicable to the facts and circumstances of the present case with regard to Outokumpu. In view of the above, it is requested that the Authority may reject the response of Outokumpu in view of the general practice adopted by the Authority in similar circumstances. Any departure from this would be discriminatory. The relevant portion of the referred findings are produced herein below for the ease of reference:

“20(i).The Authority holds that any producer/exporter cannot partially choose to respond to the prescribed questionnaire. The data sought by the Authority in the questionnaire response is required to be fully completed for the Authority to take a composite assessment. The Authority does not accept partially filed information of M/s Akzo Nobel and therefore treats them non-cooperative and consider them only under the residual category and determine AD measure in accordance with the best available information referencing information available regarding the sales in EU filed by the cooperating exporter and also the DGCIS data.”

- In view of the equity and consistency of practice, it is requested that the response of Outokumpu be rejected.
- Domestic Industry requests the Authority to recommend the anti-circumvention duties from the date of initiation of the investigation in terms of the Rule 27. The Authority would like to appreciate that good 18 months have lapsed since the initiation of the investigation while the Domestic Industry continued to suffer because of the established malpractice of circumvention of the Anti-dumping duties carried out by the exporting producers/exporters.
- Domestic Industry submits that if the Authority recommends only prospective anti-circumvention duties, the motive of importers / exporters to delay the extension of duties by blocking the investigation will be achieved. It is submitted that in such a situation the decision of the Authority will only be partially effective and in fact, would amount to an undue favor to the interested parties who have been found to be circumventing the Anti-dumping duties. In any case, the Authority needs to appreciate that extension of anti-dumping duties would not have any impact of genuine users in view of the specific exemption proposed by the Authority. Only those traders / users / importers who are involved in the act of circumvention shall be prevented from “gaining” from their malpractices. It is humbly submitted that such unscrupulous parties cannot be given any concession of any sort by the DGAD.
- Attention is also invited to Rule 27 wherein it may be seen that while the law uses the term “may” for the date of levy, the apparent discretion is no longer available as soon as the condition precedent i.e., the existence of circumvention, is proved. The discretion, if any, also cannot be used arbitrarily. In any case, there is no reason whatsoever not to impose the duties from the date of initiation of the investigation in the facts and circumstances of this case.

- It is submitted that the undertaking proposed for exclusion of users of PUI by the Authority should be backed by a bank guarantee (equivalent to the ADD amount) and this bond should be cleared once importers/user/trader gives a certificate from the jurisdictional indirect taxation authority that the material has been used without slitting. These bank Guarantees are typically issued for an initial period of 6 months or 12 months wherein the importer should submit the end-use certificates within this time period failing which the bank guarantee will have to be renewed. If the importer fails to renew the bank guarantee, the Customs may initiate legal proceedings against the importer which could primarily be in the form of IEC suspension till the situation of default is cleared. This is very important, as a PUI importer may resort to slitting even after submission of undertaking (unless it is backed by a bank guarantee as proposed above). There should be a monitoring mechanism to ensure that the material is not being slit after submission of undertaking. This would be somewhat similar to provisional clearance under Customs (Provisional Duty Assessment) Regulations, 2011.
- Domestic Industry requests the Authority to confirm their proposed conclusion of extending anti-dumping duties on the product under investigation as PUI is circumventing the existing duties on the product under consideration and thereby injuring the Domestic Industry. Since the act of circumvention is proved beyond any point, we request the Authority to confirm their proposed conclusion of disclosure statement and recommend levy of duties from the date of initiation. In case, the Authority changes its view, we request the Authority to issue a fresh disclosure statement and also give us a personal hearing to explain our case.

B. Views of Other Interested Parties (Embassies of subject countries, producers/exporters from subject countries and importers)

102. Taiwan Embassy have submitted the following:

- In the disclosure statement, the designated authority has observed that circumvention of exiting anti-dumping duties on the product under consideration (“PUC”) is indeed happening from all subject countries due to imports of widths higher than 1250mm, which is the product under investigation (“PUI”). As a result, the designated authority has proposed to extend existing anti-dumping duties on imports of the PUI.
- Taiwan would like to understand the background designated Authority has not calculated price underselling in the present case to assess the level of injury being faced by the domestic industry and the requirements under Rule 11 read with Annexure II of the AD Rules have not been satisfied in the disclosure statement. The Designated Authority has nowhere assessed if the alleged circumvention has caused injury to the domestic industry. Circumvention cannot be merely established by change in the pattern of trade. The requirements of Rule 11 read with Annexure II ought to be met in an anti-circumvention investigation as well. Rules 25 to Rule 28 of the AD Rules do not dispense with the requirement of establishing injury and causal link in an anti-circumvention investigation.
- Taiwan submits that the Designated Authority ought to satisfy the requirements under Rule 11 read with Annexure II of the AD Rules. Specifically, there is a requirement to establish that there is dumping of the PUI, there is injury to the domestic industry and there is causal link between imports of the dumped PUI and injury to the domestic industry. Injury to the domestic industry and causal link ought to be assessed in the period of investigation of the present investigation. Without satisfying this requirement, this investigation would violate the very

fundamental of the AD Rules and the WTO AD Agreement, which is, the requirement of establishing dumping, injury and causal link. Further, the Designated Authority ought to calculate price underselling (also called injury margin) as well in this case. Without an injury margin, the level of injury being faced by the domestic industry would not be known.

- YUSCO, Taiwan's price undercutting is negative (10-0), as per the table on page 68 of the disclosure statement. YUSCO's effect of circumvention on existing anti-dumping duty is also negative (45-55) as per the table on page 69 of the disclosure statement. In view of this, the Designated Authority should amend its observations regarding YUSCO and hold that exports of YUSCO are causing no circumvention of existing anti-dumping duty and exports of widths above 1250 mm by YUSCO would not attract any anti-dumping duty.
- Taiwan hopes that the Designated Authority would consider the above aspects and issue a revised disclosure statement taking into account the above submissions.

103. Various Importers have submitted the following:

- The Anti-Dumping Duty is not Applicable for the 2 periods mentioned below as there is Lapse of AD Duty in this period. Therefore applying any Anti circumvention duty will be Illegal. 22nd April 2014 up to 12th May 2014; No Anti-Dumping Duty Applicable. 17th Oct 2015 up to 11th Dec 2015; No Anti-Dumping Duty Applicable. According to Laws and recent Supreme Court Judgement, the Applicability of Anti-Dumping Duty or SSR after Any Lapse even of 1 day is Illegal. Hence the Applicability of Sun Set Review and Anti Circumvention itself does not arise.
- We did not see any substantial evidence of circumvention done by majority of respondents, which makes it evident that the ratio of slitting coils to PUC must be much lower than claimed. As per your statement in disclosure, There is Only one company POSCO service centres, who does slitting of majority 400 series materials only but that too 20% of Quantities in PUC of 600-1250mm width. Please note that, 400 series is one grade which is mostly used in small widths in the auto sector and hence use of products in one sector should not be taken as general example for all (POSCO specialises in it).
- As per Initiation notification, the Claim of 97% Quantities being Slitted to PUC is not justified. We are surprised, how did Authorities get convinced on such vague claims.
- There is no Evidence whatsoever of Slitting to PUC in 300 Series and 200 Series.
- There is no case for circumvention in case of 300 series grade and 200 series grades.
- The authorities has not respond on cut to length sheet, as they are technically not possible to get slitted and there is no evidence for circumvention on the same. If any available, please disclose the same. As there is no case for circumvention for cut-to length sheet, hence it should be excluded from the circumvention investigation.

- The following 2 categories should not be levied with Anti-circumvention duty i.e. who need higher widths 1250mm & up and are not doing any Slitting as per PUC and who Import Higher width and slit it to below 600 mm which does not have any dumping duty.
- There should not be any need of a legally enforceable declaration/undertaking to customs authorities, for those Importers/Users who had already certified that they do not do any Slitting Process or Own Slitting Process factories.
- Only those Factories who are having Slitting Processing Machinery or Doing Slitting Process can be asked for Declaration Only. Asking for Legal Enforceable Bank Guarantees or Bonds is not correct or can be legally challenged.
- This seems to be punishment to those who even did not did any Slitting to PUC or Circumvention.
- There is no reply from Domestic industry on why are they producing so much of PUI when there is no such genuine requirement of PUI , why have they set up such big plant with special capacity to produce higher widths when there is no such need for it ?
- Jindal Stainless was SEZ Unit until 23rd August 2011. Jindal Stainless Production, Sales, Import and Export Figure cannot be considered as Indian market.
- Also, Authorities should make sure that their Sales Figure to Indian market are considered as IMPORT into India and hence to be excluded from the Various Table of Data Analysis, Change in Pattern of Imports and Sales in India.
- The Authority has also analyzed the pattern of imports within the PUI also. It is noted that the majority of the imports are just above the threshold limits and only a small proportion of imports of the PUI are above 1650mm. This fact indicates that the producers/exporters from the subject countries are bringing higher widths keeping in view the notified tolerances in widths by and large rather than technical or usage based assessment.
- How can a width range of 1250-1650 (more than 30% range) being considered just above threshold limits and compared, the next standard width after 1250, is 1285mm, 1300mm, 1500 mm and 1524mm. They cannot be considered as just above Threshold limits, how can a 30% range be considered as just above the threshold limits? This looks strange. When we say just – we believe it should be 1-3% range and there is already a 2.5% tolerance margin imposed in the anti-dumping duty. This is well accepted by DGAD in all previous Investigation of 2005, 2009-10 and Sun Set Review of 2015, and they kept the Width of 1250mm for application of ADD. Surprising, the Authorities are challenging their own Investigation in SSR 2015, ADD 2010 case, with regards to Width limit of 1250mm.
- Trade pattern changes are logical and practical – Even DI has been producing lots of PUI as the demand for the same has risen, the bigger the width it's better for scale of economy.

- The Technological change, business environment changes happens around the world, there is big difference in 2008 and 2017. Authorities are forcing the User Industry to use the materials based on 2008 and not to Innovate or Change?
- The products below should be out of scope for investigation as they are not produced domestically :

The Authority should verify the facts and cold Rolled Stainless Steel in “BA” Finish should be removed from Scope of Anti-Dumping Duties on all case.

- Stainless Steel Sheet – Surfaced Treated – Polished (Decorative Ti Color, Etch Pattern, Polish Mirror Surface) they are all High Technical needed product and used in Elevators, Escalators, Hotels/Offices Entrance, Lobby’s, Name Plates etc. by default it was included in Anti-Dumping.
- Stainless Steel CR Coils & Sheet in Thickness of 0.50 mm & Below (0.20 mm, 0.30mm, 0.40mm,etc) is also not available in with of 1000 mm, 1220mm, Still included in Anti-Dumping.
- Checkered/Tear Drop/Anti Slip and other Treated Stainless Steel – is used as floor plates which is not available in India.

- We did not find any comment on above from Authorities, We request the Authorities to make sure that all the calculation on Circumvention should only be for “cold rolled stainless steel flat product of width of 600mm up to 1250mm of all series further worked then Cold Rolled with a thickness of up to 4mm.”
- Hence Investigation should be restricted to that product range only. Any product included outside above range is Illegal. User Industry needs your support and timely action to discontinue such cases, so that the Actual user Industry can concentrate on Business Expansion, Development, Innovation and not such unwanted litigations, investigation and legal expenses. We request the Authorities to discontinue this application of Applicant as the Claim Raised in the application are misrepresented and does not hold true in any Aspect, and in some cases Illegal.

104. M/s KNM & Partners representing M/s Maruti Suzuki India Limited (MSIL) have submitted the following:

- The PUI and products in the anti-dumping imposed on the import of Cold Rolled flat product of widths 600 mm to 1250 mm originating in or exported from China PR, Korea, European Union, South Africa, Taiwan, Thailand and USA (“Product Under Consideration” or “PUC”) in final finding dated October 12, 2015 (hereinafter referred to as “Original Investigation”), imposed vide Custom’s Notification 61/2015 CUS-ADD dated December 11, 2015 are not like articles, as the Authority in the original investigation had not treated both products as like articles and excluded widths of above 1250mm from the scope of the investigation.
- The Authority, during the mid-term review of the Original Investigation, explicitly excluded the PUI from the scope of Product Under Consideration. The Authority noted that the scope of the Product Under Consideration cannot be expanded in the mid-term review of an investigation to include the PUI. The Designated Authority noted in the Original Investigation that the PUC excludes from its scope the Cold Rolled Steel of width more than 1250 mm.

- Therefore, where the PUI was explicitly excluded in the Original Investigation, the Petitioner cannot initiate the anti-circumvention investigation, forming a part of the Original Investigation, in respect of the products which were explicitly excluded from the scope of Original Investigation and in respect of which the Authority recommended that no levy of anti-dumping duty is required.
- The scope of the PUC has itself been restricted after the deliberate consideration and detailed deliberation before proceeding for determination of dumping and the Original Investigation is in respect of those included products of specific types, sizes, shape or specification only.
- Subsequently, based on the final finding dated October 12, 2015 in respect of the Original Investigation by the Authority, the Central Government vide Custom's Notification 61/2015 CUS-ADD dated December 11, 2015 also recognized the exclusion of PUI, i.e., the cold rolled steel of widths greater than 1250 mm.
- Therefore, where the request for inclusion of the Cold Rolled Steel of widths greater than 1250 mm was explicitly rejected by the Authority in the above final finding in respect of the Original Investigation and by the Central Government vide the above notification, the Petitioner cannot through another window initiate anti-circumvention investigation in respect of import of PUI.
- The Applicant was fully aware that Cold Rolled Stainless Steel exceeding a width of 1250 mm was a different class of article and it had been repeatedly held to be so. If at all, there was a grievance against dumping of such an "article", independent proceedings could have been initiated to investigate such dumping. Having failed to do so, for obvious reasons as the Applicant could possibly not justify its standing as a domestic industry, it has now filed an application for anti-circumvention, to get an initiation through the back door, which is not permissible.
- The Petitioner ceased to be the domestic industry for the PUC under Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules pursuant to the de-merger scheme dated March 31, 2014. Pursuant to the de-merger as per the Petitioners' own showing JHSL, the newly formed company, became the major proportion producer of the PUC in India, since it is the legal entity that owned and operated the plant for the PUC in Hisar.
- In the light of the above demerger and the definition of domestic industry, the Authority needs to evaluate whether the Petitioner fulfils the criteria of Domestic Industry or not, also considering the fact the application has been filed only by the Petitioner and not by Jindal Stainless (Hisar) Limited.
- The Product Under Investigation is imported by the Respondent from POSCO of Korea. Once the Product Under Investigation is imported by the Respondent, it is cut to width of various sizes. Further, the cost of value addition involved in the process of slitting is huge, this makes circumvention economically and commercially unviable.
- Furthermore, the producer/exporter from Korea, POSCO has stated that 80% of the wider width imports are being slit into widths below 600mm, which is technically not PUC, therefore there is no circumvention.
- The Product Under Investigation is cut to sizes, which are suitable for the purposes of Respondent in using them in automotive components. Since the ultimate product used by the Respondent falls outside the scope of the Product Under Investigation, the same cannot be

subject matter of the present investigation.

- There has been a change in the usage pattern in the domestic market and there is a natural increase in demand of PUI, which can be substantiated by the increase in production of PUI by the domestic industry as well.
- In the automotive industry, being the industry that is essentially catered to by the answering interested parties herein, the demand is only of cut to length (“CTL”) sizes. It is not economical or commercially viable for the importers to import the desired CTL sizes directly as the production and transportation of the smaller widths is not only cost ineffective but also fraught with the dangers of rejection as transportation can result in damage, thus rendering the CTL size useless for the customers.
- Furthermore, since the automotive industry is fairly dynamic by nature, there is a high possibility of it having outgrown the size that it had ordered a few months back. Also for transportation of desired narrow width of the coil should be done through container delivery, which would only result in substantial increase in cost.
- It is not pragmatic for the automotive industry to import the exact CTL sizes and importing wider widths of the product is the only pragmatic option available to the parties, thus making the imports of PUI economically and commercially viable. It is reiterated that importing wider widths, to be slit to the desired sizes in India, reduces yield loss, transportation cost, wastage and also allows end user the flexibility to alter its demanded sizes, basis the requirement at the time of actual supply.
- The Authority may therefore exclude the products imported by the Automobile industry, as the said products do not form part of the Product Under Consideration, from the scope of Said Investigation.
- A number of Automobile companies and OEMs are extensive importers of the subject product, and such import of the products being termed as circumvention of the anti-dumping duty imposed pursuant to the Said Notifications, will affect the business interests of the said importers substantially.
- The Petitioner has contended in the application that there has been a surge in the import of the PUI from 27% to 79% from 2008-2009 to 2014-2015. It may be noted that this increase in import of PUI is a general trend in increase of import of steel. Globally, stainless steel production has been growing steadily. The domestic stainless-steel industry has also been growing at a Compound Annual Growth Rate of 9% for the last seven-eight years. However, like any other manufacturing sector in India, the stainless-steel industry has also been facing extreme difficulty in the last few years.
- One of the main reasons for this is the huge import surge from China, which has primarily contributed to the deteriorating condition of the stainless-steel industry. The imports of stainless steel flat products rose from 3,24,460 million tonnes in 2013-14 to the highest ever record of 5,32,033 MT in 2015-16.
- There is no evidence furnished by the Domestic Industry to indicate that this change in the pattern of trade appears to stem from a simple slitting/cutting operation carried out in India,

whereby imports of the Product Under Investigation are converted into Product Under Consideration before final usage by the customers including the Respondent, and therefore, the Said Investigation should be terminated.

- Further, there is no evidence in the Application to the effect that remedial effects of the anti-dumping duty on PUC are being undermined. The Petitioner has not provided any evidence to that effect.
- Therefore, the Authority may note that the trend in increase of the import has increased naturally as an import norm and not on the ground of imposition of anti-dumping duty on the Product Under Consideration.
- Aggrieved by the order dated March 08, 2017 of the Delhi High Court passed in writ petition W.P. (C) 3544/2016, Suncity Sheets Pvt. Limited have filed a Special Leave Petition bearing SLP (Civil) No. 10252/2017 before the Hon'ble Supreme Court and the Hon'ble Supreme Court has admitted the said Special Leave Petition vide its order dated April 21, 2017 (Supreme Court order attached herewith). The next date of hearing before the Supreme Court in the said matter is yet to be notified.
- It is hereby submitted that since the matter regarding the initiation of the subject circumvention investigation is already pending before the Supreme Court, the subject circumvention investigation initiated by the Authority be presently stayed or kept in abeyance till the finding or order, interim or final, of the Supreme Court in the said matter is pronounced.

105. M/s GTC Consultants representing M/s Suncity Sheets Pvt. Ltd., M/s Suncity Strips and Tubes P Ltd, M/s Sunrise Stainless Pvt. Ltd and M/s Sunmark Stainless Private Limited have submitted the following:

- As noted in the background of the Disclosure Statement, the present anti-circumvention proceedings have been initiated on the basis of Application of the Domestic Industry ("DI") dated 21.09.2015. Having noticed that the said Application was filed as early as in September, 2015, the present proceedings could not have been proceeded with given that a new trend of imports specified in Rule 25 of the ADD Rules ought to have been noticed subsequent to the notification, which are seeking to circumvent the ADD imposed by the notification. In the present case, the final notification which is alleged to be circumvented, was issued only on 16.12.2015 and the application for circumvention having been filed on 21.09.2015, the same ought to have been rejected.
- A bare perusal of the Disclosure Statement suggests that the specific contentions raised by the Importer regarding non-fulfilment of the jurisdictional preconditions of Rule 25 have not been considered and no specific examination by the Ld. Authority has been done in this regard. In the present case, none of the pre-conditions of are satisfied, inasmuch as:-
 - a. CRSS of width more than 1250mm is a completely different class of article and it is undisputed that the same is not subjected to ADD and has a distinct commercial usage- therefore, any import of CRSS of width more than 1250mm cannot be regarded as import of the "article" which is subject to ADD. Rule 25(1), therefore, does not apply at all to the present case;
 - b. CRSS of width above 1250mm are finished goods and are not imported in an unassembled, unfinished or incomplete form. There is no basis whatsoever, disclosed in the Application to the effect that this condition is even *prima facie* satisfied to justify initiation of proceedings;

- c. There is no assembly, finishing or completion process undertaken in India in respect of CRSS of width more than 1250mm. The CRSS imported in India are in finished condition and no further 'assembly', 'finishing' or 'completion' is required in India;
- In any case, no operations have not started or increased after or just prior to the Anti-dumping investigations so as to constitute circumvention of ADD. Thus, the above submissions ought to be considered by the Ld. Authority. A perusal of the Disclosure Statement that no consideration has been given to the above fundamental aspects which goes to the very root of initiation of the present proceedings.
 - It is further reiterated that the Importer has never imported the PUC since its inception and hence, no circumvention can be alleged against the Importer.
 - It is submitted that the suggestion contemplated in the Disclosure Statement to prevent genuine importers is that 'all importers importing PUI will be required to give a legally enforceable declaration/undertaking to customs authorities that the PUI being imported by them will be used without any slitting except to the extent of tolerances as mentioned in the Final findings dated 12.10.2015 imported vide Customs Notification dated 11.12.2015'. In this regard, the Ld. Authority is requested to consider the following:-
 - The suggestion appears to be vague and the actual manner of implementation ought to have been provided in the Disclosure Statement especially in the light of Rule 16 of the ADD Rules, which requires the Disclosure Statement to be specific;
 - The requirement of a general undertaking with words such as '*will be used without any slitting*' will frustrate the very purpose of granting the exclusion. Various importers such as the present Importer have substantiated that the PUI can be imported to slit the products for widths less than 600mm, which is required by the importers for manufacturing pipes etc. and which process cannot be considered to be 'circumvention' under Rule 25/26 of the ADD Rules. Thus, the expansive and non-specific measure contemplated in the Disclosure Statement should be modified by considering the above.
 - The Importer reiterates that the claim of 'confidentiality' of the Applicant in the Application filed before this Ld. Authority is without any basis and prejudices the rights of the Importer and accordingly, ought to be rejected such a claim.

In view of the above, the present anti-circumvention proceedings would amount to an abuse of the process of law as the very same issues have already been examined by this Ld. Authority and decided against the Applicant and the only recourse available to it is to initiate fresh investigations for imposition of ADD on CRSS of width above 1250mm.

106. Submission by M/s AGOL ASSOCIATES representing M/s N.G. Industries, M/s M.P. Industries and M/s Shree Ramdev Metal Mart submitted the following:

- Without prejudice to the submission that M/s N.G. Industries, M/s M.P. Industries and M/s Shree Ramdev Metal Mart have not done any slitting process of the product during the period under investigation and all the quantities have been sold without any slitting/conversion process, it is submitted that the Designated Authority has no power or jurisdiction to consider as to what happens post-importation to invoke Rule 25 of the customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995. It is a settled proposition that goods imported have to be assessed to duty 'as

presented'. It is also a settled position in law that the goods would have to be assessed in the form in which they are imported and presented to the customs and not on the basis of the finished goods manufactured after subjecting them to some process after the import is made. In the reported decision in *Vareli Weaves Pvt. Ltd. v. Union of India* [1996 (83) E.L.T. 255 (S.C.)] the question was as to whether the countervailing duty was liable to be left on the imports made by the assessee at a stage they would reach subsequent to their import after undergoing a process. It was contended that such goods could be subjected to duty only in the state in which they were imported. It was held that the countervailing duty must be levied on goods in the state in which they are when they are imported. This was on the basis of Section 3 of the Customs Tariff Act. Similar view was taken in *Dunlop India and Madras Rubber Factory Ltd. v. UOI* [1983 (13) E.L.T. 1566 (S.C.)]. Reliance is also placed on the decision of the Hon'ble Supreme Court in the case of *Commissioner of Customs, New Delhi Vs. Sony India Ltd.* reported in 2008 (231) ELT 385 (S.C.).

- It is seen from the application filed by the applicant that they are placing reliance on Rule 25(1) of the ADD Rules. It is submitted that even assuming without conceding that the allegations of the applicant are true, the same cannot be a ground to initiate investigation unless it is proved factually as well as legally that the product under consideration is being imported in an unassembled, unfinished or incomplete form and is assembled, finished or completed in India. Mere slitting of products of width of more than 1250mm after their import into India will not lead to a process of either an assembly, finishing or completion. The slitting of the products having width of more than 1250 mm into smaller sizes will not attract the provisions of Rule 25 of the said Rules. Rule 25(1)(a) states that the operation mentioned in sub-rule (1) should have started or increased after or just prior to the anti-dumping investigation "and that the parts and components" are imported from the notified countries. Therefore, on a complete reading of Rule 25(1) it is clear that it is only those cases where parts and components of the product under consideration are imported in an unassembled, unfinished or incomplete form and are assembled, finished or completed in India, which come under the purview of Rule 25(1). Neither the applicant nor the initiation notification explains as to how an unassembled, unfinished or incomplete article is assembled, finished or completed to attract the provisions of Rule 25(1). Therefore, the requirement to execute a legally enforceable declaration/undertaking to customs authorities is unjustified and has no sanction in terms of the provisions of the Customs Act, 1962 and the Customs Tariff Act, 1975. Without prejudice no such declaration should be insisted on entities who have not facility for slitting or processing.
- In the present case as per the final disclosure, it is stated that there is evidence of slitting of the PUC after import into India. Even if this were to be true, it is not a ground to invoke Rule 25. In fact in cases where goods are imported in a disassembled or unassembled condition to evade existing ADD, Court have interpreted that applying Rule 2(a) of the General Rules of Interpretation of the Customs Tariff, goods have to be considered as complete article provided the disassembled or unassembled goods are presented together. Thus, the converse situation cannot be held to be within the ambit of ADD. Reliance is placed on the decision of the Delhi High Court in the case of *Nav Durga Associates Vs. Union of India* reported in 2013 (287) ELT 19 (Del.).

- It is submitted that the Hon'ble Supreme Court of India in the case of Union of India vs M/s Kumho Petrochemicals Company Limited [Civil Appeal Nos. 008309-008310 of 2017 arising out of SLP (C) Nos. 29268-29269 of 2014] has held that one-year extension of antidumping duty after the expiry of existing antidumping duty would be illegal. In the present case the antidumping notification no. 14/2010-Cus. Dated 20.02.2010 was in force till 22.4.2014 and the Government issues a notification no. 20/2014-Customs (ADD) on 12.05.2011 extending the ADD on the subject products till the period 21.04.2015. This extension notification was issued more than two weeks after the expiry of the earlier notification and therefore, in terms of the decision of the Hon'ble Supreme Court in the case of Kumho Petrochemicals Company (Supra), the extension of the anti-dumping duty after the expiry of the existing anti-dumping would be illegal. Therefore, when the extension itself is illegal then the consequent initiation of anti-circumvention duty would also be illegal. It is further submitted that as per the findings of the sunset review, ADD was continued, vide notification no. 61/2015 dated 11.12.2015. Therefore, there was a further lapse before notification no. 61/2015 dated 11.12.2015 was issued extending the ADD. Therefore, the decision of the Hon'ble Supreme Court squarely fits into the case and consequently, the repetitive extension of ADD was illegal. Consequently, it must be held that when initiation of investigation into the anti-circumvention duty itself would be illegal when there was not ADD on the subject goods in the first place.
- The Authority has already gone into the question of leviability of ADD on Cold Rolled Stainless Steels of more than 1250 mm and in the final findings dated 24.11.2010, and rejected the arguments of the applicant relating to the inclusion of products of width more than 1250 mm by rendering detailed findings in support of the exclusion. The said recommendations were accepted by the Central Government and ADD was imposed on the product under consideration, vide notification No. 14/2010-Cus. Dated 20.02.2010. Thereafter, on 23.06.2010, mid-term-review was also limited with regard to the products under consideration only. The applicant then approached the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and filed a writ petition No. 6544 of 2010 by challenging the scope of the mid-term review. The Hon'ble High Court, vide order dated 8.10.2010 disposed the aforesaid writ petition by directing that the challenge raised by the applicant in the writ petition was also to be considered at the time of mid-term review. In the mid-term review proceedings, the Designated Authority held that the review was only for classification with regard to prescribing tolerances in respect of width of the product under consideration and that neither had Jindal requested for enhancement for scope of the product nor was it been considered. The Designated Authority held in its mid-term review dated 8.6.2011 that the goods of width beyond 1250 mm were rightly excluded from the ambit of ADD. It is submitted that subsequently, in terms of Rule 25 of the ADD Rules and on the basis of application filed by Jindal seeking continuation of ADD imposed on the product under consideration, the Designated Authority initiated the notification for sunset review. During the proceedings in the sunset review, M/s Jindal requested the Designated Authority for inclusion of products of width more than 1250 mm. The said request was rejected by the Designated Authority, vide its final findings dated 12.10.2015 and the Central Government issued the Customs Notification No. 61/2015-Cus dated 11.12.2015 continuing the imposition of ADD on PUC. The contention of M/s Jindal with respect to inter-changeability or use of strips with larger width with those of smaller width was considered by the Designated authority in its final findings dated 5.12.2011, where it was observed that importing products of higher width and

slitting requires a complete different operational set up in turn calling for substantial investment by the user, which too was commercially unfeasible especially small and medium scale users due to the wastages and higher costs involved. From the above it is clear that the request of M/s Jindal to include products of width more than 1250 mm was repeatedly rejected by the Designated Authority on the ground that domestic industry has neither produced nor supplied goods of width more than 1250mm despite the claim of the domestic industry that they have the facility to manufacture width upto 1550mm and also for the reason that the process of importing higher width and slitting the same was technically and economically unviable. M/s Jindal has filed the present application raising the same grounds alleging circumvention by import of products of width above 1250mm by relying upon the date of import relating to the period 2008-09 to 2014-15 despite the that the imports made during the period were already considered during the earlier proceedings of rendering final findings and the sunset review proceedings. By issuing the present initiation notification dated 19.2.2016, an attempt is being made to review the decision earlier taken by the Designated Authority and it is a settled law that things which cannot be done directly cannot also be done indirectly. In the sunset review, the Designated Authority has admitted that the scope is restricted to the products as defined in the final finding and that there is no power to review or expand the scope of the product under consideration. In fact, even in the grounds for alleged circumvention, it is stated that M/s Jindal is seeking to review the exiting anti-dumping duties.

- It is further submitted that the applicant has failed to substantiate as to how they constitute “domestic industry” as defined in the Rules above. Further, no evidence has been filed to demonstrate that they are manufacturing and supplying in substantial quantities product under investigation. This is necessary to first establish that injury is being caused to them by the alleged circumvention. There is no reply from the Domestic Industry as to why they are producing the stated quantity of the PUI when there is no market or requirement of the PUI in the domestic market. No justification has been given by the applicant as to why have they set up such big plant with special capacity to produce higher widths when there is no demand for it in the local market. All these aspects raise doubt on the bonafides of the applicant. M/s Jindal Stainless was a Special Economic Zones Unit till August 23, 2011. Therefore, the statistics produced by the applicant with regard to production, sales, Import and Export Figure cannot be considered as that representing the domestic industry or the Indian market position. The application filed by them is not maintainable on this ground alone. However, the Designated Authority has not given any finding on this submission and on the other hand had proceeded to hold that there has been price effect on Domestic Industry’s sales of product under consideration. Needless to mention that the disclosure statement has been non-speaking to this extent and thus violative of the principles of natural justice. Without prejudice it is submitted that the Designated Authority should make sure that the sales figure to Indian market given by the applicant include the quantity of imports made by them this quantity should be excluded from the data considered and tabulated in the final disclosure statement.
- It is submitted that M/s. N.G. Industries, M/s M.P. Industries and M/s Shree Ramdev Metal Mart have not done any slitting process of the product during the period under investigation and all the quantities have been sold without any slitting/conversion process. Further, it is technically not possible to carry out any slitting process on sheets in general. It is to be noted that it does not make any technical or financial prudence to import the products of width of more than

1250mm. The import cost of products of width more than 1250mm is expensive when compared to products having width of more than 600mm to 1250mm. It is an admitted position and the data of the Director General of Valuation would reveal the fact that the price for product of width more than 1250mm is usually higher by USD 50-100 per MT as compared to products width 600mm to 1250mm. Therefore, it is extremely unviable to import products of higher width and then carry out slitting as the operation of slitting would add considerable cost to the end product. These costs include cost of transportation for movement of goods to the slitter, cost of slitting, cost of repacking, cost of re-transportation and waste and scrap generated on slitting. In fact, the cost of materials of width between 600mm to 1250mm is lesser and easily available in the domestic and overseas market when compared to the expenses incurred in slitting the product of width more than 1250mm. The cost of slitting and the substantial amount of scrap that is generated make the entire process unviable.

- It is submitted that no evidence has been produced whatsoever by the applicant that majority of the end users in India do not use the products of width above 1250 mm. The products of width more than 1250mm have application for fabrication of storage tanks in dairy and chemical industry, where the tank sizes are bigger. In such cases higher the width of the material used, lesser are the number of joints and this ensures better corrosion properties and lesser maintenance for long period of time. Therefore, the importers mentioned above import products of width more than 1250mm and sell them as such without subjecting them into any further process. It is submitted that we have not been furnished with the evidence and support of the allegation that 97% of the imported products having width more than 1250mm are sold after slitting and that only 3% goes into genuine usage as such.
 - As per the final disclosure statement, there is only one company, viz. M/s POSCO Service Centre, who does slitting of 400 series materials but that too only 20% of the quantity of the PUC of width of 600-1250mm. As per Initiation notification, the claim of the applicant that 97% quantities were being slit is thus not justified. There is No Evidence whatsoever of Slitting to PUC in 300 Series and 200 Series. The application filed by M/s. Jindal is thus writ with huge factual discrepancies.
107. M/s Wirana Pte. Ltd, Singapore has submitted that finishes like BA, 2D, 2 E, SB (Scotch Brite), No. 3, No. 4 etc. should be excluded from investigation. Importers are also citizen of India and that they also generate employment.
108. M/s DGS Associates representing POSCO, Korea and its related entities have submitted the following:
- The Authority while recording the names of the responding exporters / producers, has missed out on the name of Hyosung Corporation (Korea) who has also responded and has been verified by this Hon'ble Authority. Similarly, reference to Hyosung Corporation is also required to be made in para 80 and 85 of the Disclosure Statement. As a consequence, para 57 should state, "in case of Korea, the producer, POSCO along with its 7 exporting entities and 3 slitting centres in India has cooperated".
 - The Authority has acknowledged the Producer / Exporters submission that POSCO's exports of the PUI are essentially used to supply products of sizes that do not fall within the scope of PUC. It is reiterated that 80% of the exports made by POSCO have been utilized for supplying Cut to

Length or CTL sizes below 600mm, being non-PUC and the same are beyond the scope of both PUC and PUI. It is respectfully submitted that for purposes of the subject goods in the instant Investigation what is critical is the end use of the goods imported into India. As has already been submitted the Producer / Exporters primarily cater to the automotive industry. By very nature of this user industry, it is an ever evolving and high safety industry. The manufacture of auto parts demand precise sizes of the subject goods and irrespective of the coil width being imported, the same would require to be cut / slit to CTL sizes.

- Since CTL sizes are critical to the automotive industry, the role of the processing centres in India cannot be undermined and/or reduced merely to treat them as centres set up to slit the PUI with a view to circumvent the ADD imposed. POSCO's processing centres in India have been in existence since 2006 and have been set up with substantial investment, being equipped with state-of-art equipment. These processing centres play an integral role in the supply chain as the end customers lack the wherewithal to slit / cut the wider width coil to CTL sizes and are dependent on the processing centres to supply them the requisite sizes.
- The automotive industry is dynamic and the latest designs of the auto parts are becoming smaller, hence requiring smaller CTL sizes. It is, however, neither pragmatic nor economical for the customers to import the desired CTL sizes directly as the production and transportation of the smaller widths is not only cost ineffective but also thwart with the dangers of rejection as transportation can result in damage, thus rendering the CTL size useless for the customers. There is also a high possibility of the customer having outgrown the size that it had ordered a few months back. Also transportation of desired narrow width of the coil should be done through container delivery, which would only result in substantial increase in cost. Furthermore, in the event that the exporter directly provides coils of requested dimensions, the coils must undergo an "edge trimming process" prior to final use in India, which would further lead to production of scrap. Therefore, importing wider widths of the product is the only pragmatic option available to the customers, making the imports economically and commercially viable. Importing wider widths, to be slit to the desired sizes in India, reduces yield loss, transportation cost, wastage and also allows end user the flexibility to alter its demanded sizes basis the requirement at the time of actual supply.
- Width of the coil to be imported is on the basis of "nesting" done for the requisite sizes (which are variable) and which would result in least generation of scrap and yield loss. It is the requirement of the subject goods by the customer coupled with these factors that determine the width sizes to be imported. In this regard, reference is also drawn to this Hon'ble Authority's observation in para 63 of the Disclosure Statement, where the Authority has observed "that as the usage of PUC/PUI by an user industry is dependent on the width of PUC/PUI, the conversion process by slitting tantamount to a process of finishing/conversion and therefore the process of slitting is covered under relevant AD Rules, to examine circumvention." This conclusion is erroneous for the reason that the customer's requirement for various widths is the starting point for an import order. It is only basis this requirement that "nesting" is done and wider widths are imported to be eventually cut into the desired CTL sizes that were previously requisitioned. A wider width is imported only because of the economic reasons set out above. There is technically no finishing/conversion happening, contrary to this Authority's observations.
- Further, POSCO has always been catering to the PUI, PUC and the non-PUC segment depending on the customer's requirement. Increasingly, POSCO's market has shifted to PUI and

non-PUC segment. However, this shift in the market segment cannot be termed as circumvention, as alleged by the Domestic Industry or otherwise. It is submitted that circumvention could possibly have been alleged, had POSCO been exporting PUI to supply PUC, which is not the case. Basis the “nesting” being done, PUI is being imported to be slit into the CTL sizes of less than 600mm, being non-PUC. Such supply of non-PUC widths can neither be termed as circumvention of the ADD imposed on the imports of PUC nor be held to be causing any injury to the Domestic Industry in the PUC segment.

- POSCO has always been supplying the widths required by its end customers, be it PUI, PUC or non-PUC. This has been the import pattern and it remains the import pattern. The pattern is demonstrated graphically. However, the demands of the user automotive industry changes and the widths being imported are directly linked to the user requirement, bearing in mind the economic considerations of yield loss, transportation cost, wastage and allowing the end user the flexibility to alter its demanded size basis the requirement at the time of actual supply.
- In view of the foregoing, the Authority’s observation in para 74 of the Disclosure Statement, that there exists no economic justification other than to circumvent the anti-dumping duties imposed on the PUC for the producer/exporters in the subject countries and that the same is evident in the steep rise in the imports of PUI is misplaced and erroneous. It is reiterated that the increase in imports of PUI cannot be viewed in isolation but must be examined in conjunction with the usage of the PUI being imported. In POSCO’s case, the PUI being imported is primarily being used to supply CTL sizes that are below 600mm, being the desired sizes of the user automotive industry or as PUI itself. There is only a small portion of the supply that is going into the PUC segment.
- The Authority has stated that it proposes to consider the impact of circumventing product on efficacy of existing anti-dumping measures and a consequential price effect on Domestic Industry’s sales of PUC. In this regard it is submitted that since the supply of PUC by the Producer / Exporters is minimal, the said two parameters will not yield a positive outcome in favour of the Domestic Industry. For a meaningful examination of the alleged circumvention it is critical to conclude that the PUI is being slit into PUC and consequently impacting the efficacy of existing anti-dumping measures and a consequential price effect on Domestic Industry’s sales of PUC. However, this is contrary to the facts of this case where PUI is being primarily slit into non-PUC or used as PUI itself, leaving the PUC segment unaffected.
- If the Authority was to extend the ADD even to the supply of non-PUC, it would not benefit the Domestic Industry as the user industry may just consider importing the CTL sizes directly. However, such extension will have a definite adverse impact on the user automotive industry for the reasons set out in paragraph 4 above causing it grave hardship. Hence, on a balance of convenience it is critical that the ADD be not extended to slitting and supply of PUI into CTL sizes below 600mm, being non-PUC. Further to para 62 of the Disclosure Statement, the Authority has stated that it proposes to reference the usage pattern of PUC as PUC or as non-PUC prior to levy of measure and usage pattern of PUC and PUI post the measure to examine the disposal / sales pattern of PUC and PUI, it is respectfully submitted that the Authority may consider the foregoing submissions to arrive at a dispassionate and objective conclusion in this investigation.
- The Producer / Exporters and the Importers would also like to volunteer submission of periodic and legally enforceable declaration / undertaking to customs authorities that the PUI being

imported by them would be used only as PUI and/or non-PUC pursuant to the slitting process. Any slitting of the PUI into PUC would be subject to payment of ADD. It is respectfully submitted that this would be a fair and justified outcome of this Investigation and would serve the interests of all interested parties.

109. M/s ELP Advocates & Solicitors representing Outokumpu Oyj and YUSCO have stated the following:

- The Authority at paragraph 34 has stated that “the exclusion of a particular category of a product does not per se imply that they are not like articles.”
- The Exporter submits that the Hon’ble Designated Authority’s observation is inaccurate as the Hon’ble Designated Authority vide its final finding dated November 24, 2009 and December 5, 2011, with regard to the PUC, has excluded the PUI from the product on account the PUI and PUC not being “like articles”.
- Therefore Rule 25(1) does not apply due to the following reasons:
 - (a) Product under Investigation is not subject to the anti-dumping duty. Only after the Product under Investigation is slit into widths under 1250 mm, does it become comparable to the Product under Consideration.
 - (b) Product under Investigation is in itself an assembled, finished and complete product and it does not require any assembling, finishing or completion operation to be used.
- The Exporter submits that the Hon’ble Designated Authority is required to analyse the production of PUC and not PUI of domestic producer for the standing of the domestic industry. However in the present investigation, the Hon’ble Designated Authority has analysed whether JSL is importing the PUI as well even though the present investigation has been initiated to analyse the effect of the PUI on the PUC.
- For determining the eligibility of JSL as the domestic industry, the Authority is required to determine the ownership of the Hisar plant and not the effective date of de merger. The transfer of the Hisar plant from JSL to JSHL was effective retrospectively from March 31, 2014. From the above appointed date i.e. March 31, 2014, JSL ceased to be the domestic industry for the PUC under Rule 2(b) since it no longer constituted a major proportion of the production of the PUC in India.
- JSL did not own the Hisar plant during the period of investigation. Despite the same, JSL has claimed that it is the largest producer of the PUC in India at page 2 of the Application, when in fact the rightful producer, if at all, was JSHL.
- Additionally, the certification filed by JSL in the Application was dated December 13, 2013, which is well before the de-merger as well as the Period of Investigation. Therefore, even if the application was made in 2012 when the Hisar plant was with JSL, the application is bad in law because (i) the application could not have had the data for period of investigation and (ii) the initiation of the present investigation has not taken place within six months of the date of filing the application.
- The Authority has asserted that the test of 25% and 50% are not conditions applicable for an application made under Rule 26 of the Anti-dumping Rules. The Exporter submits that this is a highly inaccurate interpretation of the Anti-dumping Rules.

- Pursuant to Rule 26(1) read with Rule 2(b) of the Anti-dumping Rules, the 'domestic industry' must at least be a manufacturer of the major proportion of the total domestic production of the PUC in India. The Hon'ble Designated Authority vide its Disclosure Statement has stated that JSL alone qualifies the test of 25% and 50%. The Hon'ble Designated Authority must ensure that its directions to the Petitioner are not subverted by carrying out the following tests:
 - (a) The Petitioner does not file production information from the Hisar plant to qualify for the 25% test;
 - (b) If in either of the examined periods i.e. period of investigation and time of initiation, the Petitioner does not meet the 25% threshold, it cannot be classified as domestic industry and the investigation must be terminated with immediate effect;
 - (c) The Hon'ble Designated Authority must require the production information to be made available in a non-confidential form; and
 - (d) The information filed by the Petitioner should be fully verified for accuracy to ensure that inflated production figures are not placed on record by the Petitioner merely to overturn the issue.
- Any information that is required for establishing the standing of the domestic industry is an essential fact. PUC data of JSL and any other data that is on record that has been relied upon are essential facts under Rule 16 of the Anti-dumping Rules. Given the time bound nature of the present proceeding, the Hon'ble Designated Authority is requested to kindly disclose the above essential facts immediately.
- As per the de-merger scheme the Hisar plant belonged to JSHL from 31st March 2014 i.e. prior to the period of investigation.
- JSL does not have the appropriate authorisation or right to file data on behalf of a separate legal entity i.e. JSHL.
- The Petitioner has claimed most of this information confidential unjustifiably, which is in gross violation of Rule 7 of the AD Rules and Trade Notice No. 1/2013 dated December 2013. All the economic parameters reported in the response have been claimed completely confidential. Additionally, information with respect to production breakup, Normal Value, Export Price, Dumping Margin, alleged saving of duty circumvented, conversion cost have been completely claimed confidential in the Application.
- The Authority has relied on inconsistent and inaccurate data while analysing the evidence of circumvention such as:
 - (a) The Hon'ble Designated Authority has not analysed the data from 2008 even though it had directed the interested parties to provide the same; and
 - (b) The import data with respect to the PUC provided by JSL vide its updated Petition dated April 10, 2017, is highly inconsistent to the data referred to in the Disclosure Statement dated August 7, 2017.
- The Authority at paragraph 65 of the Disclosure Statement had analysed major proportion of imports falling under 1650mm. If the Hon'ble Designated Authority has analyzed widths up to 1650mm, then the tolerance level that was set by the Hon'ble Designated Authority has at ad hoc been replaced by the present 1650 mm.

- The analysis carried out by the Authority with respect to change in pattern of trade, while factually correct, does not represent a holistic analysis of the pattern of trade. In fact, the charts merely indicate a relative analysis based on the percentage of total Imports of PUC and PUI, which is incomplete without examining the context under which these changes took place.
- While the proportionality analysis relied upon by the Authority reflects the changing trends in PUI and PUC trends, a deeper analysis of the data behind this proportionality test also clarifies that the increase of PUI imports cannot be correlated to the anti-dumping duty levied on the PUC, based on the following factors.
 - (a) The Decline in PUC imports is Natural: A decline in product under consideration imports is bound to occur upon imposition of anti-dumping duty, and is a commonly seen occurrence in other products as well. This also explains why there is a substantial increase in PUC imports in the assessed period from non-subject countries.
 - (b) Increase in Imports of PUI is not on account of Circumvention: The increase in PUI imports over the assessed period was due to a genuine increase in demand:
- i. Production in India has increased in the last four years leading up to the POI – Imports of PUI from subject countries have declined in the same period.
- ii. Imports of the PUI from non-subject countries have increased over the last ten years
- While conducting its analysis the Authority neglected the copious data and analysis placed on record by the Exporter.
 - (a) An overwhelming majority of the exports of PUI to India made by the Exporter are directly to end users;
 - (b) The Producer has divided the Imports during the period of investigation into two (2) periods i.e. Duty period (July 1, 2014 to April 21, 2015) and No Duty Period (April 22, 2015 to September 30, 2015). The behaviour of the Exporter's sales during this period clearly demonstrates that there is no circumvention taking place in the Exporter's specific case.
 - (c) The customers to whom the Exporter sells are established to be of a nature where there is no requirement of circumvention.
- However, despite such substantial data being placed on record, the Authority has not taken any of the above into consideration while coming to its conclusion in the above issue.
- The Authority has not provided the calculation methodology that has been used for arriving at the Normal Value of the Exporter. In the least, the same ought to be provided at least in non-confidential form.
- There is negative price undercutting from EU-origin exports and particularly from exports made by the Exporter. In fact, the extent of negative undercutting for the Exporter (minus 25 to minus 35 percent) is so vast that there could not possibly have been any depressing price effect due to the exports made by the Exporter in the present factual matrix. It is therefore submitted that there is no justification for an anti-circumvention levy on the Exporter.
- At table 25 of the Disclosure Statement, the Hon'ble Designated Authority has indicated that the effect of circumvention on anti-dumping duty by the Exporter is in the range of 35-45% in case of Outokumpu and in the range of (45) – (55) % in case of YUSCO. The Exporter submits that,

the Hon'ble Designated Authority has taken into consideration the wrong Anti-dumping duty in the calculation of "Landed value of PUC with duties". It appears from the calculation that the Hon'ble Designated Authority has considered duties which were recommended and levied in the SSR. The Exporter submits that, duties recommended and levied in SSR came in effect from December 11, 2015 onwards which is beyond the period of investigation i.e. (July 14 to Sept 15) and therefore cannot be applied for any landed price calculation during the POI. The Hon'ble Designated Authority is accordingly requested to kindly take the above into consideration and revisit its landed price calculations for all other considerations as well. Until such corrections are appropriately incorporated, the present investigation should not be allowed to proceed.

- With respect to the economic parameters used to determine the existence of circumvention, the Authority has taken into consideration only price undercutting.
- The Authority in case of Diclofenac Sodium had analysed both price and volume effect in domestic industry.
- EU in some cases like citric Acid, crystalline silicon photovoltaic modules and key components and open mesh fabrics of glass fibres have undertaken detailed injury analysis.
- The comparison of undermining of AD duty need to be made with duties as applicable during POI and not those imposed in SSR. This needs to be revisited and corrected.
- The negative price undercutting from EU origin imports imply that there is no price depressing effect and there is no justification for imposing Anti-circumvention duties.
- The Authority has not disclosed production figures of M/s Jindal stainless Limited and M/s Jindal Stainless Hisar Limited. M/s Jindal Stainless Limited ceased to be domestic industry w.e.f. appointed date i.e. 31/3/2014. M/s Jindal Stainless Hisar Limited has not formally participated in the investigation and M/s Jindal Stainless Limited does not own up the Hisar plant. Therefore the Authority must ensure that M/s Jindal Stainless Limited does not file production information from Hisar plant to quality 25% test.
- Data filed by Domestic Industry on PUC/PUI in its petition is in consistent with data in the disclosure.
- Trade pattern shift needs to be identified from 2008 onwards.
- The decrease in volume of PUC post levy of ADD is natural and that PUI imports are not for circumvention.
- Indian Stainless Steel Development Association (ISDA), process plant and machinery association of India and other importers have stated that PUI imported is for genuine use and not for slitting.
- Imports of PUI have also came down since 2012-13 from subject countries.
- Demand of PUI is growing and so is the case with petitioner.
- M/s Outokumpu's exports are to Auto, Heavy transport and process machinery industries where there is no scope of circumvention.

- In the POI when there were two periods (AD Duty in force and no AD Duty in force), the Outokumpu's export behaviour does not reflect circumvention.
- M/s Outokumpu's major exports to India have been to SEZ units or under Advance License where no AD duty is leviable and hence there is no need to circumvent by the exporter.
- M/s YUSCO exported 35% of PUI during no duty period of POI. On an annualised basis 50.14% of exports were in no duty period implying YUSCO is not circumventing. Exports of PUI remained consistent irrespective of the fact that ADD or no ADD was there in POI. There is a negative price undercutting by YUSCO's exports and hence there is no price depressing effect.
- Effect of circumvention should be evaluated with actual AD Duty in force during POI and not SSR duties.
- The Authority has stated as follows at page 72 of the Disclosure Statement:
"The Authority noting that any bonafide user of PUI need not be saddled with extension of anti-dumping duties on PUI, also appreciates that it is not possible for any government agency to enforce monitoring of any exemption granted to any bonafide user and therefore for this purpose proposes that all importers importing PUI will be required to give a legally enforceable declaration/undertaking to customs authorities that the PUI being imported by them will be used without any slitting except to the extent of tolerances as mentioned in final finding dated 12/10/2015 imposed vide custom notification 61/2015 CUS-ADD dated 11/12/2015 if they desire not to pay existing ADD."
- M/s ELP has summarized as follows:
 - a) JSL does not constitute domestic industry due to which the investigation has been illegally initiated and therefore should be terminated immediately;
 - b) Product under Investigation is not unassembled, unfinished or incomplete form due to which Rule 25(1) of the Anti-dumping Rules does not apply to the present investigation;
 - c) The present investigation ought to be terminated, at least against the Exporter as there has been no change in pattern of trade;
 - d) JSL has failed to provide any evidence to substantiate its circumvention claim;
 - e) An increase in the volume of imports of Product under Investigation is due to an increase in the consumption of the Product under Investigation; and
 - f) Remedial effects of the existing anti-dumping duties on the product under consideration are not undermined.

Examination by the Authority

- i. As regards the submissions made by various interested parties on the issue of standing of Domestic Industry, the Authority notes that the application filed by M/s Jindal Stainless Ltd. which includes data of both M/s Jindal Stainless Limited and M/s Jindal Stainless Hisar Limited is in accordance with various provisions of the demerger scheme. In any case both M/s Jindal Stainless Limited and M/s Jindal Stainless Hisar Limited independently meet the standing test and with no opposition by any domestic producer to the application, M/s Jindal Stainless

Limited meets the criteria of domestic industry as per Rule 2 (b) of AD Rules, with reference to PUC.

- ii. As regards claim of certain interested parties that M/s Jindal Stainless Ltd/ was a SEZ unit till 23/8/2011 and therefore appropriate analysis regarding its production be done, the Authority notes that the production of PUC/PUI in the Orissa unit only started after it became a DTA unit and therefore the issue of addressing the SEZ aspect is not necessary.
- iii. The Authority notes the submissions made by various interested parties regarding undertaking unwarranted anti circumvention investigation, including faulty initiation and addressal of alleged circumvention of PUC by PUI stating that these issues have already been settled in the earlier original investigations of the same product including the SSR. The Authority holds that the present investigation under the AD Rules is to examine the aspect of circumvention of PUC by PUI and that this requires conditions of Rule 25 and Rule 26 to be satisfied on various aspects of circumvention phenomena. The scope of PUC which includes certain exceptions and tolerances remains unaltered. The Anti-Circumvention Rules do not require establishing that PUI and PUC are like article as has also been submitted. The Authority has kept in view the judgment of Hon'ble High Court of Delhi wherein it has been held that the trajectory of the inquiry is altogether different in an Anti-Circumvention investigation and that the facts and arguments of various interested parties need to be placed before the competent Authority.
- iv. The Authority also notes that it has been submitted that the matter is subjudiced in the Hon'ble Supreme Court. The Authority however notes that though the matter is pending before Hon'ble Supreme Court but it is not stayed for completion of investigation.
- v. The Authority notes that there are submissions to restrict circumvention only to cold rolled stainless steel flat product of width of 600mm up to 1250mm of all series further worked then Cold Rolled with a thickness of up to 4mm. and also to exclude finishes like BA, 2D, 2 E, SB (Scotch Brite), No. 3, No. 4 etc. from investigation. The Authority holds that the only difference in the PUC and PUI is the width and that there is no change in excluded grades or any technical description as has been mentioned in the initiation notification and in the disclosure.
- vi. The Authority notes the submissions regarding broadening the scope of original investigation, back door entry by Domestic Industry to reopen the already settled issues, and holds that PUI imported for use as PUI only without any alteration/splitting is not being considered for continuation of existing Anti-dumping duty on PUC but only to situation where PUI imported from subject countries is not used as PUI but altered for use as PUC or non PUC.
- vii. The Authority notes that it has been submitted that there is no evidence of undermining of remedial effects of Anti-dumping duty on PUC and also that DG Safeguards had held that losses to Domestic Industry were due to internal reasons of Domestic Industry. The Authority holds that undermining of Anti-dumping duty on PUC by circumvention due to imports of PUI not intended to be used as PUI is in fact undermining the remedy provided by the Authority to provide a level playing field to PUC. The issue of Dumping, Injury and Causal Link on PUC has already been settled in the original investigation and thereafter in Sunset Review investigations.
- viii. The Authority notes the submissions made by various interested parties on the proportion of PUC and PUI imports claimed by Domestic Industry and that by M/s ELP in variations in claim of domestic industry and data reported in the disclosure. The Authority notes that data regarding

PUI for the years 2008 – 09 to 2012 – 13 was already reported in the final findings dated 12th October, 2015 regarding Sunset Review related to PUC. Data for PUC for the years 2010-11, 2011-12 and 2012-13 was also reported in the aforesaid finding. This has been adopted ipso facto in the present investigation. DGCI&S data beyond 2012 – 13 to POI has been further analysed and reported in the finding. For the non-cooperative producers/exporters the DGCI&S data as stated above has been considered in the present finding and referenced for trade pattern and for the cooperative/responding exporters the exports of PUC and PUI from 2008 – 09 to POI as reported by them has been referenced for the purpose of analysing the trade pattern.

- ix. The Authority notes that the Domestic Industry has submitted to reject the response of M/s Outokumpu while M/s ELP Advocates representing M/s Outokumpu has desired that methodology for the normal value for them be disclosed. The Authority notes that Outokumpu in the questionnaire response had provided data on the domestic selling price and export price only and not cost of production to undertake ordinary course of trade test. The Authority has therefore adopted constructed CNV approach on the basis of the best available information which has so been mentioned in the disclosure in the summarisation for evaluation of dumping margin. As the present investigation is on Anti-Circumvention wherein data on various attributes of circumvention are also of significance besides the aspect of dumping, the data provided by M/s Outokumpu on its export trend has been considered to analyse such relevant aspects.
- x. The Authority notes submissions of M/s ELP regarding further details on normal value methodology for Outokumpu and YUSCO and notes that M/s ELP after the disclosure vide letter dated 11/8/2017 had requested for certain clarification on the NCV data related to Domestic Industry which was provided on 14th August, 2017. No details regarding methodology of normal value were sought. The Authority has in the confidential version of disclosure provided the relevant confidential values computed on the basis of data filed by the two exporters. The 'normal value' methodology was narrated in the NCV version of the disclosure. The Authority reiterates the computation methodology on the normal value for the two exporters as mentioned in the disclosure statement dated 7th August, 2017.
- xi. The Authority notes that it has omitted the name of the POSCO's responding exporter M/s Hyosung Corporation (Korea) in the disclosure which was also verified on site. The Authority has included the data of all exporters of POSCO who filed response to evaluate the dumping margin. This is evidenced from the description in paragraph of export price (table 15 of disclosure) and S&D expenses (table 16 of disclosure) wherein the name of M/s Hyosung Corporation is mentioned.
- xii. The Authority notes arguments by various interested parties that Automotive sector in particular needs 'CTL' sizes for which larger sheets are cut to such requirements. Further POSCO's slitting centres have also emphasized the concept of 'nesting' wherein the user requirements are the starting point to plan imports of PUC/PUI and that it is not the AD circumvention motivation to import PUI. In this regard the Authority holds that the requirement of 'nesting' and business modelling to maximize efficiency by importing larger sizes being prudent economic rationale should also trigger similar trends of PUC and PUI sales to countries other than India. POSCO has not been able to demonstrate emergence of such models in third countries. 'CTL' sizes can be serviced by various options viz. by imports of PUC, PUI or non PUC/PUI. The Authority therefore holds that genuine use of PUI imports as PUI only without slitting needs to be exempted from AD Duties. Many interested parties have also argued that

PUC and PUI are not like article and that is why PUI remained excluded in original investigation. The Authority therefore reiterates that by allowing PUI for use as PUI only such issues are also addressed as any use of imported PUI for PUC or Non PUC/PUI purpose by the importers/users only needs to be saddled with extension of existing AD Duties on PUC to PUI.

With regard to the post disclosure submissions of POSCO on usage of PUI by them for non PUC application the Authority reiterates its earlier observations made on the basis of data filed by IDPC, ICPC and IPPC, the three slitting centers of POSCO Korea in India (table 10) that during 2008-09 to 2011-12, i.e. pre-AD measure levy period, 21% of non-PUC sales in domestic market was met by direct imports of non-PUC category. For the remaining sales of non-PUC, 46% was met by slitting of PUC and 33% by slitting of PUI. During 2012-13 to POI, i.e. post levy of AD measure, 2% of non-PUC sales in domestic market was met by direct imports of non-PUC category. The remaining 98% was met by slitting of PUI. As regards PUC sales in domestic market during this period, 14% of sales of PUC in domestic market was met by direct imports of PUC and 86% was met by slitting of PUI. It is noted that the PUI imported during this period was sold as 'PUI only' to an extent of 11% and the rest was used for slitting into PUC and/or non-PUC. The Authority therefore in view of the aforesaid utilization pattern of imports considers the slitting operation of PUI to non PUC also as circumvention.

xiii. M/s GTC Consultants representing M/s Suncity Sheets Pvt. Ltd., M/s Suncity Strips and Tubes P Ltd, M/s Sunrise Stainless Pvt. Ltd and M/s Sunmark Stainless Private Limited have stated that none of the conditions for circumvention are satisfied and that no operations started or increased after or just prior to the AD investigation. Further they have stated that they have never imported PUC since inception of their company and that no charge of circumvention is applicable to them. Further the declaration to be given by importer as stated in disclosure is vague and will frustrate importers as many of them have stated that they slit below 600 mm. The Authority noting these submission holds that determination of change in trade pattern is exporter specific and that thereafter the role of an importer pertains primarily to the change of form of PUI to PUC or non PUC which may lead to the process of circumvention. An importer can therefore cannot be evaluated in isolation. The recommendation on continuation of existing AD measures are exporter specific with appropriate safeguards to ensure that bona fide importers of PUI who are not circumventing are not saddled with the extension of AD duties on PUI. The legally enforceable undertaking by a genuine importer is a mechanism to ensure such an exemption.

xiv. The Authority notes the submissions by M/s ELP that decline in imports of PUC post AD measures is natural citing certain examples where Anti-Dumping Duty is levied and imports have come down and that increase in imports of PUI is not on account of circumvention. The Authority holds that if levy of an AD measure is effective and its efficacy is not undermined by phenomena of circumvention the remedy provided by AD imposition will address the intended purpose to create a level of playing field, and imports of dumped goods will naturally decrease. However if imports of different form of goods which can substitute the dumped goods by alterations as per Rule 25 and 26, then the efficacy of AD Duty is undermined. Any genuine increase of PUI is therefore not to be obstructed but only the diversion of PUI to fill the gap of PUC as identified under the ambit of AD Rules 25 and 26 needs to be checked.

- xv. The Authority holds that in cases where AD Duty has reduced imports of dumped subject goods after levy of AD Duty, if the Domestic Industry files a petition with evidence of circumvention phenomena, the Authority is obligated to investigate the same as is the case in the present investigation.
- xvi. As regards practice on anti-circumvention investigation of EU cited by M/s ELP, the Authority holds that it has addressed issues under the relevant AD Rules of the country.
- xvii. The Authority notes the submissions of M/s ELP regarding their major exports being under duty free authorisations and to SEZ units and holds that as these exports do not attract AD Duty, their exports are not within the realm of circumvention and in future also if such kind of exemptions continue, the exporter will not be impacted by extension of AD Duty on PUI intended for use other than PUI.
- xviii. As regards the Outokumpu's export behaviour in duty and no duty period of PUC during POI, the Authority holds that export behaviour during POI was in a state of uncertainty and in a situation where results of Sunset Review were in pipeline, and therefore switching export behaviour for a short duration in a phase of uncertainty does not appear to be a convincing. In this regard the Authority further notes that since M/s Outokumpu did not participate in the Sunset Review, on conclusion of sunset review, it would have been saddled with highest residual duties. Further if PUI exported by an exporter is destined for genuine use as PUI only without slitting, it does not cause any prejudice to the exporter if the concerned importer files an undertaking not to slit the imported PUI.
- xix. The Authority also notes that it has been submitted by many interested parties that there is no evidence of slitting of 200 and 300 series and also many importers have stated that they are not undertaking any slitting. In this regard the Authority notes that if this is the case, there would be no prejudice caused or injustice to such bonafide importers/end users who are not slitting PUI imported from subject countries and are using PUI for genuine PUI purpose only without slitting.
- xx. The Authority notes submissions by various importers that Anti circumvention be not levied for the period when AD Duty has ceased and holds that the earlier period of existing Anti-dumping duty on PUC is not relevant as Authority is recommending extension of existing Anti-dumping duty on PUC to PUI from the date of notification.
- xxi. The Authority notes that while for 400 series the slitting centres have filed response along with the cooperating producer/exporter, in other cases, there is no specific response filed on slitting operations. In case certain series are not being slitted, the importers should not have any reservation to file a legally binding/enforceable undertaking, as filing of an undertaking in no way causes any prejudice to any importer if the imports of PUI by them are genuinely destined for usage as PUI only without any further slitting.
- xxii. As regards submissions of domestic industry for supplementing undertaking by an importer backed by a certificate from the jurisdictional indirect taxation Authority, the Authority holds that it would be appropriate the Ministry of Finance to formulate an appropriate monitoring mechanism to ensure compliance of such an undertaking based on their field structures and resources.

- xxiii. As regards applying the applicable AD Duty during POI on PUC and not that imposed during sunset review on PUC to determine undermining effect, the Authority notes that AD Duty during SSR was changed to ad valorem basis as compared to fixed AD Duty in the earlier years. The weighted average fixed AD Duty on PUC during POI is noted to be higher than the ad valorem duty fixed in sunset review for the subject countries from where there has been no response by producers/exporters. Thus price undermining determined for these countries due to circumvention is further higher. As regards the submissions by M/s ELP Advocates to evaluate undermining of AD Duty on the basis of the applicable AD Duties during POI, the Authority notes that in case of YUSCO only 200 series of PUC was exported during POI on which there was no AD Duty applicable during POI and hence determining undermining effect for this series is trivial. For other two series viz. 300 and 400 as the trade has shifted from PUC to PUI during POI, the AD Duty foregone is the indicator of the extent of price undermining. Therefore the Authority holds that for YUSCO, the price undermining on the basis of applicable AD Duty during POI is positive. As regards revisiting undermining of AD Duty on PUC by exports of M/s Outokumpu, the same has been recomputed by applying the applicable AD Duties during POI and the same is noted to be positive as also correlated with the response to disclosure filed by M/s Outokumpu. The revised range has been mentioned in the relevant table in the foregoing paras. The Authority based on application of applicable Anti-Dumping Duties during POI, has revised the concerned tables for subject countries which evidences positive and generally higher undermining of AD Duties.
- xxiv. The Authority notes the submissions made by various interested parties including M/s ELP on negative price undercutting reported for certain producers/exporters and subject countries. The Authority in this regard notes that in terms of Rule 26(4), the Authority is required “to determine the existence and effect of any alleged circumvention of the antidumping duty in force”. Section 9A(1A) of the Act also envisages that the act of circumvention should not make the anti-dumping duties so imposed ineffective. In other words, the normal requirements of examining the factors of material injury including price effect to the Domestic Industry are not per se envisaged for the purpose of an anti-circumvention investigation relating to circumvention of anti-dumping duties and the limited obligation is to examine the “effect” of circumvention of AD duties. Therefore, the primary objective of this investigation is to ensure that the interested parties are not negating or diluting the effect of the anti-dumping duties imposed by the Central Government by indulging in any kind of circumvention of duties. Further the Rules relating to circumvention do not have explicit provisions of either Rule 11 or Annexure II for anti-circumvention investigations. Keeping this in view, the Authority is of the view that the large scale shift of volumes to PUI at prices much lower than the effective prices of PUC has rendered the existing Anti-Dumping Duties on PUC largely ineffective.

Conclusions

110. Having examined the contentions of the Domestic Industry and various interested parties and on the basis of the analysis as above, the Authority concludes that:
- i. The Authority notes that imports of PUI i.e. ***“Cold-rolled Flat products of stainless steel of width greater than 1250 mm of all series not further worked than Cold rolled (cold reduced) with a thickness of up to 4mm (width tolerance of +30 mm for Mill Edged and +4mm for Trimmed Edged)”***, excluding:

- *Grades AISI 420 high carbon, 443, 441, EN 1.4835, 1.4547, 1.4539, 1.4438, 1.4318, 1.4833 and EN 1.4509;*
- *Product supplied under Indian Patent No. 223848 in respect of goods comprising Low Nickel containing Chromium-Nickel Manganese-Copper Austenitic Stainless steel and representing Grades YU 1 and YU 4, produced and supplied by M/s Yieh United Steel Corp (Yusco) of Chinese Taipei (Taiwan)”*

have increased post levy of Anti-Dumping Duty.

- ii. The value addition in converting PUI to PUC is less than the prescribed threshold in the Rule
- iii. The PUI has been exported at dumped prices during the POI.
- iv. The PUI has undermined the existing AD measure on PUC imposed vide Custom Notification No. 14/2010-Customs (ADD) dated 20th February, 2010.

Recommendations

111. The Authority keeping in view the aforesaid, recommends extension of the existing Anti-Dumping Duty on PUC imposed vide Custom Notification No. 61/2015-Customs (ADD) dated 11th December, 2015 on PUI also as tabulated in the duty table in the Custom Notification No. 61/2015-Customs (ADD) dated 11th December, 2015, as enclosed at Annexure 1, subject to following:
 - i. The Anti-Dumping Duty on PUI will be applicable from the date of its notification by the Ministry of Finance i.e. Central Government.
 - ii. The validity of the Anti-Dumping Duty on PUI would be co-terminus with the duty on PUC levied through Custom Notification No. 61/2015-Customs (ADD) dated 11th December, 2015.
 - iii. (a) The PUI which is imported by an importer for end use in the same form without slitting (except to the extent of tolerances as mentioned in the Custom Notification No. 61/2015-Customs (ADD) dated 11th December, 2015) will not be liable for payment of the applicable AD Duty as per Custom Notification No. 61/2015-Customs (ADD) dated 11th December, 2015.
 - (b) Further in case a PUI is slitted into 2 or more PUI only i.e. sizes above 1250 mm (with permissible tolerances), it will not be subjected to any Anti-Dumping Duty (For example a 2600 mm piece slit into two 1300 mm size pieces)
 - (c) However if PUI is slit for a combination of PUI and below PUI size or below PUI sizes, it will be liable for applicable AD Duty. (For example a 1800 mm piece being slit into a 1400 mm and a 400 mm piece or a 2200 mm piece is slit into 1400 mm and 800 mm or a 1400 mm piece being slit into 600, 500 & 300 mm sizes)
 - iv. For the cases falling under (iii) (a) and/or (iii) (b) above, the importer will give a legally enforceable undertaking to the concerned Custom Authorities.
 - v. The Ministry of Finance may put in place an appropriate monitoring mechanism to monitor the genuineness of the usage of the PUI so imported for categories falling under (iii) (a) and/or (iii) (b) above without payment of AD Duty on the basis of aforesaid undertaking by its appropriate agencies.

Further Procedure

112. An appeal against the order of the Central Government that may arise out of this Final Findings Notification shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

Dr.INDER JIT SINGH, Addl. Secy. & Designated Authority

Annexure 1

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 11th December, 2015.

Notification No. 61/2015-Customs (ADD)

G.S.R. (E).- Whereas, the designated authority, *vide* notification No. 15/04/2014-DGAD, dated the 17th April, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, had initiated a review in the matter of import of Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel, (hereinafter referred to as the subject goods), falling under heading 7219 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act) and originating in, or exported from the People's Republic of China, Korea, European Union, South Africa, Taiwan (Chinese Taipei), Thailand and United States of America (USA) (hereinafter referred to as the subject countries / territories), imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 14/2010-CUSTOMS, dated the 20th February, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 95(E), dated the 20th February, 2010;

And whereas, the Central Government had extended the anti-dumping duty on the subject goods, originating in or exported from the subject countries / territories upto and inclusive of the 21st April, 2015, *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 20/2014-Customs (ADD), dated the 12th May, 2014, published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R 337(E), dated the 12th May, 2014;

And whereas, in the matter of review of anti-dumping duty on import of the subject goods, originating in or exported from the subject countries / territories, the designated authority in its final findings, published *vide* notification No. 15/04/2014-DGAD, dated the 12th October, 2015, in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, has come to the conclusion that -

- (i). there is continued dumping of the subject goods from the subject countries/territories though the volume of imports has declined after imposition of duties;
- (ii). the performance of the domestic industry has deteriorated in the current injury period due to the impact of the dumped imports from the subject country and diversion of imports to product ranges outside the scope of the product under consideration;
- (iii). the dumping is likely to continue and the performance of the domestic industry is likely to deteriorate, should the present anti-dumping duty is revoked,

and has recommended the imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods originating in, or exported, from the subject countries / territories;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the

designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, the specification of which is specified in column (4), falling under tariff heading of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries/territories as specified in the corresponding entry in column (5), exported from the countries/territories as specified in the corresponding entry in column (6), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (7), exported by the exporters as specified in the corresponding entry in column (8), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate to be worked out as percentage of the landed value of imports of the subject goods as specified in the corresponding entry in column (9) of the said Table, namely:-

TABLE

Sl. No.	Tariff heading	Description of goods	Specification	Countries/ Territories of origin	Countries/ Territories of export	Producer	Exporter	% of landed value
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	7219	Cold-rolled Flat products of stainless steel	All Grades, All Series except the exclusions as per Note below	People's Republic of China	Any	Any	Any	57.39%
2	-Do-	-Do-	-Do-	Any country other than the subject countries/territories	People's Republic of China	Any	Any	57.39%
3	-Do-	-Do-	-Do-	Korea RP	Korea RP	POSCO	1. Hyundai Corporation 2. Daewoo International Corporation	5.39%
4	-Do-	-Do-	-Do-	Korea RP	Korea RP	Any combination other than above combination		13.44%
5	-Do-	-Do-	-Do-	Korea RP	Any	Any	Any	13.44%
6	-Do-	-Do-	-Do-	Any country other than the subject countries/territories	Korea RP	Any	Any	13.44%
7	-Do-	-Do-	-Do-	Chinese Taipei	Any	Any	Any	15.93%
8	-Do-	-Do-	-Do-	Any country other than the subject countries/territories	Chinese Taipei	Any	Any	15.93%
9	-Do-	-Do-	-Do-	South Africa	South Africa	Columbus Stainless (Pty) Ltd	ColumbusStainless (Pty) Ltd	12.34%
10	-Do-	-Do-	-Do-	South Africa	South Africa	Any combination other than above combination		36.91%
11	-Do-	-Do-	-Do-	South Africa	Any	Any	Any	36.91%
12	-Do-	-Do-	-Do-	Any country other than subject countries/territories	South Africa	Any	Any	36.91%
13	-Do-	-Do-	-Do-	Thailand	Thailand	POSCO Thainox	1. POSCO Thainox 1. Hyundai Corporation	4.58%
14	-Do-	-Do-	-Do-	Thailand	Thailand	Any combination other than above combination		5.39%
15	-Do-	-Do-	-Do-	Thailand	Any	Any	Any	5.39%

Sl. No.	Tariff heading	Description of goods	Specification	Countries/ Territories of origin	Countries/ Territories of export	Producer	Exporter	% of landed value
16	-Do-	-Do-	-Do-	Any country other than the subject countries/territories	Thailand	Any	Any	5.39%
17	-Do-	-Do-	-Do-	USA	Any	Any	Any	9.47%
18	-Do-	-Do-	-Do-	Any country other than the subject countries/territories	USA	Any	Any	9.47%
19	-Do-	-Do-	-Do-	European Union	European Union	Acerinox Europa SAU, Spain	Acerinox Europa SAU, Spain	29.41%
20	-Do-	-Do-	-Do-	European Union	European Union	Any combination other than the above combination		52.56%
21	-Do-	-Do-	-Do-	European Union	Any	Any	Any	52.56%
22	-Do-	-Do-	-Do-	Any country other than the subject countries/territories	European Union	Any	Any	52.56%

Note

The subject goods include cold-rolled Flat products of stainless steel of width of 600 mm upto 1250 mm of all series not further worked than Cold rolled (cold reduced) with a thickness of up to 4 mm (width tolerance of +30 mm for Mill Edged and +4 mm for Trimmed Edged), excluding the following:

- (i) the subject goods of width beyond 1250 mm (plus tolerances);
- (ii) Grades AISI 420 high carbon, 443, 441, EN 1.4835, 1.4547, 1.4539, 1.4438, 1.4318, 1.4833 and EN 1.4509;
- (iii) product supplied under Indian Patent No. 223848 in respect of goods comprising Low Nickel containing Chromium-Nickel Manganese-Copper Austenitic Stainless steel and representing Grades YU 1 and YU 4, produced and supplied by M/s Yieh United Steel Corp (Yusco) of Chinese Taipei (Taiwan).

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

Explanation .- For the purposes of this notification, "Landed Value" shall be the assessable value as determined under the Customs Act 1962 (52 of 1962) and all duties of customs except duties levied under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act.

[F. No. 354/87/2009-TRU(Pt.-III)]

K.KALIMUTHU, Under Secy.